Seventeenth Series, Vol. XXIX No. 8

Friday, February 9, 2024
Magha 20, 1945 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Fifteenth Session

(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XXIX contains Nos.1 to 9)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Mamta Kemwal

Joint Secretary

Bishan Kumar

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Maneesha Bhushan

Pankaj Kumar Singh

Editor

© 2024 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XXIX, Fifteenth Session, 2024/1945 (Saka)
No. 8, Friday, February 9, 2024/ Magha 20, 1945 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
OBITUARY REFERENCES	7
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 101 to 106	8-33
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 107 to 120	34-118
Unstarred Question Nos. 1151 to 1380	119-892

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 893-928

MESSAGES FROM RAJYA SABHA 929-930

STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE

156th and 157th Reports 931

MATTERS UNDER RULE 377 932-937

(i) Regarding four-laning of national highway and conversion of state highways to national highways in Tiruchirappalli Parliamentary Constituency

Shri Su. Thirunavukkarasar 932-933

(ii) Regarding refund of money to people who invested in Sahara Group

Shri Shyam Singh Yadav 933

(iii) Regarding revival of match factory in Dhubri, Assam

Shri Abdul Khaleque 934

(iv) Need to constitute a committee to control shrimp prices in the country

Shri Raghu Rama Krishna Raju 935

(v) Regarding restoration of Old Pension Scheme

Shri Vinayak Bhaurao Raut 936

(vi) Need to introduce passenger train services in Kendrapara district, Odisha

Shri Anubhav Mohanty 937

MOTION UNDER RULE 342

White Paper on Indian Economy 939-1134

Shrimati Nirmala Sitharaman 939, 944-956, 1111-1133

Shri N.K. Premachandran 939-941, 1104-1111

Prof. Sougata Ray 942, 989-993

Shri Manish Tewari 957-964

Dr. Nishikant Dubey 965-981

Dr. Kalanidhi Veeraswamy 981-988

Shrimati Vanga Geetha Viswanath 994-998

Shri Girish Chandra 999-1001

Shri Gaurav Gogoi 1002-1010

Shri Rajiv Ranjan Singh ' Lalan' 1011-1015

Shri Ravi Shankar Prasad 1016-1024

Shri Om Pavan Rajenimbalkar 1025-1028

Shri E. T. Mohammed Basheer 1029-1033

Shri S. Venkatesan 1034-1038

Dr. Shrikant Eknath Shinde 1039-1045

Shri Jayant Sinha 1046-1054

Shrimati Harsimrat Kaur Badal 1055-1059

Shri Asaduddin Owaisi 1059-1065

Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu 1066-1070

Dr. DNV Senthilkumar S.	1071-1073
Shri Anubhav Mohanty	1074-1078
Shrimati Supriya Sadanand Sule	1079-1081
Sushri Sunita Duggal	1082-1084
Shri Vijay Kumar Hansdak	1084-1086
Dr. Sanjay Jaiswal	1087-1089
Shrimati Navneet Ravi Rana	1090-1092
Shri Ramesh Bidhuri	1093-1095
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	1096-1103

*__ANNEXURE – I__

Member-wise Index to Starred Questions	1068
Member-wise Index to Unstarred Questions	1069-1072

__*ANNEXURE – II__

Ministry-wise Index to Starred Questions	1073
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	1074

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Shrirang Appa Barne

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, February 9, 2024/ Magha 20, 1945 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

11.0½ hrs

OBITUARY REFERENCES

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुःख के साथ, अपने दो पूर्व साथियों के निधन के बारे में सभा को सूचित करना है।

श्री हरमोहन धवन चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के चंडीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नौवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री धवन नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) रहे और उन्होंने विशेषाधिकार समिति के सदस्य के रूप में भी सेवाएं प्रदान की।

श्री हरमोहन धवन का निधन 27 जनवरी, 2024 को 83 वर्ष की आयु में हुआ।

श्रीमती रुबाब सईदा उत्तर प्रदेश के बहराइच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चौदहवीं लोक सभा की सदस्य थीं।

श्रीमती सईदा ने उद्योग संबंधी समिति तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्रीमती रुबाब सईदा का निधन 6 फरवरी, 2024 को 73 वर्ष की आयु में हुआ।

हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। यह सभा उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है।

अब, यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर के लिए मौन रहेगी।

11.02 hrs

The Members then stood in silence for a short while.

माननीय अध्यक्ष: ॐ शांति: शांति: शांति:।

11.04 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल, क्वैश्चन नंबर 101.

डॉ. संजीव कुमार शिंगरी – उपस्थित नहीं

श्री विष्णु दत्त शर्मा - उपस्थित नहीं

श्रीमती अपरूपा पोद्दार

(Q. 101)

SHRIMATI APARUPA PODDAR: Hon. Speaker, Sir, I thank you for giving me an opportunity to ask a supplementary question.

Sir, through you, I would ask the Government whether the Government is aware of the fact that even though India has the lowest number of mental health professionals and lack of awareness regarding the issue, the Ministry has Rs. 2,899 crore unspent that had been initially allocated to them in the financial year 2023-24. If so, please tell the reason for the same.

Thank you.

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल: स्पीकर सर, मानसिक रोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इस शताब्दी की जो सबसे अच्छी योजना है- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड की शुरूआत की गई है और उसमें इस बीमारी को कवर किया गया है। इसके लिए राशि पर्याप्त है और सभी राज्यों को राशि भेजी गयी है। जितनी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके लिए भी राशि भेजी गयी है। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सीएससी और पीएससी हैं, उनके लिए भी इस मामले में धन का प्रावधान है। हर जगह मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक हैं। इसके अलावा, जो एनजीओज़ हैं, वे भी काम कर रहे हैं।

महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय सदस्या ने मानसिक रोगियों के बारे में चिंता व्यक्त की है, लेकिन उनके राज्य पश्चिम बंगाल में विश्व की सबसे अच्छी योजना प्रधानमंत्री जन आयोग्य योजना - आयुष्मान कार्ड को लागू ही नहीं किया गया है। ... (व्यवधान) उनको ऐसा लगता है कि इस आयुष्मान कार्ड में जब मोदी जी की फोटो होगी, तब आयुष्मान कार्ड लोग जेब में रखेंगे तो मोदी जी की फोटो उन तक पहुंच जाएगी। वे तो दूसरे माध्यम से भी पहुंच गए हैं।

मेरा महोदया से अनुरोध है कि वह अपनी राज्य सरकार को आयुष्मान कार्ड योजना लागू करने के लिए कहें। ... (व्यवधान) यदि इनकी कोई योजना है, तो उसमें 5 लाख रुपये केंद्र वाली सहायता भी हो जाएगी, क्योंकि कई ऐसी बीमारियां हैं जिनमें 5 लाख रुपये से ज्यादा खर्च होते हैं। अगर वे हमारी योजना को भी लागू कर लेंगे तो पश्चिम बंगाल के गरीबों की बहुत बड़ी मदद होगी।

श्री अधीर रंजन चौधरी : यह सवाल पूछा गया कि India has one of the lowest number of mental health care professionals per capita. इस जवाब में पर कैपिटा प्रोफेशनल्स का कोई जिक्र नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में मानसिक रोगियों की संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही हैं। अब जॉइंट फेमिली खत्म हो गई हैं, न्यूक्लियर फेमिली हो गई हैं। आजकल देखभाल में असुविधा होती है, उनकी देखभाल नहीं हो पाती है। सामाजिक वातावरण जिस दिशा में जा रहा है, उसमें यह संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। खासकर देखिए, पार्किंसन्स डिसीज, अल्जाइमर्स डिसीज भी बढ़ती जा रही हैं। क्या पार्किंसन्स और अल्जाइमर्स डिसीज का भी अलग से उपचार करने के लिए सरकार का कोई प्रबंध है?

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : अध्यक्ष महोदय, जो मनोविकार, डिप्रेशन या मानसिक रोगी हैं, उनके लिए हमारे पास बहुत सारी संस्थाएं हैं। लगभग 45 हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें उनका इलाज होता है। सभी एम्स में उनका इलाज होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सीएचसी और पीएचसी में भी इलाज होता है। एक टेली मेडिसिन योजना भी सरकार की है कि यदि इस प्रकार की कोई बीमारी है तो टेली मेंटल योजना के तहत वे टेलीफोन के द्वारा भी परामर्श ले सकते हैं। आयुष्मान कार्ड योजना में भी सभी प्रकार की बीमारियां कवर्ड हैं। मानसिक रोगियों के लिए भी आयुष्मान कार्ड उपलब्ध है। सरकार

उनके रीहैबिलिटेशन के लिए भी काम कर रही है। हम उनको ट्रेस भी कर रहे हैं। हमारे देश में कई ऐसी संस्थाएं हैं, जिनमें भर्ती होकर भी इलाज होता है और तमाम एनजीओज़ भी इस दिशा में काम कर रहे हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री मनसुख मांडविया): अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी मंत्री रिप्लाई कर रहे थे, मैं उसमें थोड़ा सा पूरक करूंगा। आपने पूछा कि क्या पार्किंसन्स, अल्जामइर्स सहित जो डिसीज हैं, उनको मेंटल हेल्थ में शामिल करेंगे? मेंटल हेल्थ एक अलग टाइप की डिसीज है। देश में उसका बर्डन आज, ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस के बाद स्टडी की गई तो 10 पर्सेंट से ज्यादा लोग आज मेंटल हेल्थ के शिकार हैं। एक स्टिग्मा होता है, कोई व्यक्ति मेंटल हेल्थ से पीड़ित हैं तो वे बताते भी नहीं हैं। इससे भी कई इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, फेमिली इश्यू क्रिएट होता है, शारीरिक हेल्थ का इश्यू भी क्रिएट हो जाता है। ऐसी स्थिति में कौन सी डिसीज को मेंटल हेल्थ में रखना है या नहीं रखना है, वह साइंटिफिक पैनल के आधार पर तय किया जाता है। साइंटिफिक पैनल की रिकमेंडेशन आएगी, तो अवश्य उसको शामिल करेंगे। वर्तमान समय में यह बहुत एड्रेस करने जैसा इश्यू है, डिसीज है और उसको अच्छी तरह से एड्रेस करके हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 102,

श्री सुनील कुमार सिंह।

(Q. 102)

श्री सुनील कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत विस्तार से प्रश्न के जवाब में सदन को जानकारी उपलब्ध कराई है। माननीय मंत्री जी के जवाब से स्पष्ट है कि हमारी सरकार ने विशेष त्वरित निपटान न्यायालयों की योजना के अंतर्गत देश भर में 414 ई पॉक्सो न्यायालयों सहित 757 विशेष त्वरित न्यायालय कार्यरत किए हैं, जिन्होंने 2 लाख 14 हजार से अधिक मामलों का निपटान किया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि विशेष न्यायालयों में किसी मामले के निपटान की औसत समयावधि कितनी है तथा इस समयावधि को कम करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

श्री अर्जुन राम मेघवाल: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, जैसे इन्होंने खुद ही जिक्र किया कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट और पॉक्सो के माध्यम से जो कोर्ट स्थापित हुए हैं, इसकी संख्या 757 एफटीसी की है और पॉक्सो की 411 है । अगर आप डिस्पोजल देखेंगे तो 2 लाख 14 हजार 63 केस का डिस्पोजल हुआ है। आपने समयावधि के बारे में ठीक कहा है, कई बार सालों का विषय रहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेज हैं, जैसे मथुरा के केस का जिक्र करूं, पन्द्रह दिन में केस का डिस्पोजल हुआ। एक केरल का केस है, जिसमें 100 दिन से कम में डिस्पोजल हुआ है।

ये स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट है, इसमें डिस्पोजल और इन्फ्रास्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराया है। कोर्ट इस दिशा में तेजी से काम रही है और अवेयरनेस भी आया है। यह ठीक बात है, आप बंगाल के बारे में दूसरे प्रश्न में कुछ कह रहे थे, जैसे बंगाल को कोर्ट स्थापित करना था, लेकिन तीन ही कोर्ट स्थापित किए हैं। केरल इसमें तेजी से आगे बढ़ गया है।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो हमने समय सीमा निर्धारित की है, उस दिशा में कई बार स्पीडी ट्रॉयल होने के बावजूद भी थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन यह समय सीमा में ही केस

निर्धारित हो, इसलिए जुडिश्यिरी से संबंधित जो पैरामीटर्स हैं, जैसे बात करने का तरीका है, उसके अनुसार बात करके इसके समय में भी कमी लाएंगे।

श्री सुनील कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लोगों तक न्याय की पहुंच आसान करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। हाल ही में कानून मंत्रालय ने कानून और कार्मिक संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों में सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंच स्थापित करने की मांग स्वीकार की है। इसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंच स्थापित होने से न्यायपालिका पर बढ़ते मामलों का बोझ कम किया जा सकता है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि देश भर में सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंच स्थापित करने के लिए सरकार ने क्या कार्य योजना बनायी है?

श्री अर्जुन राम मेघवाल: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदस्य को बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंच स्थापित हो, यह इस विषय से टोटली संबंधित नहीं है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, जिस संसदीय समिति लॉ एंड जस्टिस की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं, उनकी सिफारिश आना एक अलग बात है। लेकिन जब मामला कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री खगेन मुर्मु : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं, सरकार देश के सभी जिलों में अति संवेदशील मामलों में न्याय दिलाने में पीड़ित के साक्ष्य, गवाहों की गवाही को रिकार्ड करने की प्रक्रिया को बेहतर और सुविधाजनक बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है? क्या सरकार बाल अपराधी को रोकने के लिए बाल मनोविज्ञानी को नियुक्त करने की सोच रही है?

श्री अर्जुन राम मेघवाल: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हम इसके लिए साइकॉलिजिस्ट भी रखते हैं। आजकल गवाहों के लिए बहुत अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, उनकी बात को दूसरा कोई सुन भी नहीं सकता है। माननीय सदस्य ने जो चिंता प्रकट की है, यह फास्ट ट्रैक कोर्ट का एक हिस्सा भी है।

श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) : अध्यक्ष जी, स्पेशल कोर्ट में शायद अच्छा काम हो रहा है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि अगर कोई तीन सौ रुपये भी चोरी करे या पिक-पॉकेट करे तो उसको जेल में जितना दिन रोक कर रखते हैं तो उसके पीछे तीन लाख रुपये का खर्च हो जाता है। यह पैसा सरकार का जाता है, यह किसका पैसा है? इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं? जो क्राइम किया, उस क्राइम से ज्यादा उसके पीछे पैसा खर्च हो जाता है। रूल्स और रेगुलेशन, यह पेपर नहीं आया, खबर नहीं आयी, ट्रायल नहीं हुआ इत्यादि, इसका क्या सॉल्यूशन है आप इस बारे में बताइए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: माननीय अध्यक्ष, यह फास्ट ट्रैक कोर्ट से संबंधित मसला है। माननीय सदस्या ने जनरल प्रश्न पूछा है जैसे किसी ने छोटी चोरी की, उसे जेल में ज्यादा लंबा रख दिया और इस पर सरकार का ज्यादा खर्च होता है। ऐसे विषयों पर हमारी कंसलटेशन ऑन है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में जितने भी संवेदनशील केसेज़ हैं, होल ऑफ गवर्नमेंट एप्रोच द्वारा उनका हल किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष : आप बताएं कि विधि सहायता देते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी सहायता दी जाती है।

… (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: माननीय अध्यक्ष जी, आपने सही कहा कि इसमें नालसा, रालसा और डालसा भी है, लेकिन यह एक्सेस टू जस्टिस है। माननीय सदस्य ने जो कहा है कि छोटे से अपराध के लिए जेल में रखा जाता है, खर्चा होता है, यह दूसरा विषय है। यह ज्यूडिशियल सिस्टम रिफार्म का विषय है। सब विषयों पर हमारा कंसलटेशन प्रॉसेस ऑन है।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सवाल तो अच्छा है, आपको इस बारे में सोचना चाहिए।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: It is a very important question on POCSO cases. As directed by the hon. Minister. Shrimati Smriti Irani ji, we, the Members of Parliament, are reviewing the POCSO cases in the DISHA meetings and the police officials have reported to us that the main problem they are facing is that

almost all the witnesses are becoming hostile due to political pressure as well as financial pressure.

The conviction rate has not been spelt out in the answer. If you see the conviction rate, it is just below 25 per cent. The people in most of the cases are being acquitted. This is the prevailing position. The Indian Institute of Public Administration has gone through all these issues and submitted so many recommendations that are well stated in this answer.

The recommendations have been given by the Indian Institute of Public Administration regarding the speedy trial as well as the conviction rate to be increased. So, I would like to know from the hon. Minister whether those recommendations have been implemented. If yes, will the Government of India give any assistance to the State Government for implementing those recommendations?

श्री अर्जुन राम मेघवाल: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, यह थर्ड पार्टी इवॉल्यूशन से संबंधित है । हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इवाल्यूशन करवाया। आप जो विषय रखना चाहते हैं, ठीक है, कई बार गवाहों की स्थिति भी होती है, महिला और बच्चों से संबंधित कानून है, इसका इम्पेक्ट सोसाइटी में बहुत अच्छा है । आप दूसरे केसेज़ में कन्विक्शन रेट देखेंगे तो यह उससे बेहतर है, नहीं तो सरकार इसे आगे कैसे बढ़ाती। इसे तीन साल के लिए सरकार ने आगे बढ़ाया है। सरकार ने इसे इवॉल्यूशन के आधार पर ही वर्ष 2026 तक आगे बढ़ा दिया है। इवॉल्यूशन में जो विषय आपने रखे हैं, इसमें आए हैं, हमने इसमें इन्सर्ट किए हैं।

आपने जो प्रश्न पूछा है कि समय ज्यादा लगता है। मैं कहना चाहता हूं, जैसे रेप केस है, इसका फैसला फास्ट ट्रैक के बाद एवरेज 417 दिन में हो जाता है। पोकसो में 542 दिन रखे गए हैं। इस तरह

से एवरेज इम्प्रूव हुई है। महिला संरक्षण, महिलाओं का सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाना माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की हाइएस्ट प्रियारिटी है।

जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में संशोधन किया है ताकि ज्यादा लगने वाले समय को कम किया जा सके। आपको इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में नजर आएगा। महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाना नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की हाइएस्ट प्रियारिटी है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जिला कलक्टर रहे हैं, आईएएस अफसर रहे हैं। क्या आपको जानकारी है?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न 103, श्री दीपक बैज :

उपस्थित नहीं।

(Q. 103)

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका : धन्यवाद स्पीकर सर। मेरा सवाल था कि एम्स में कितनी सैंक्शन पोस्ट्स हैं तथा कितनी भर्तियां हुई हैं, लेकिन यदि आप जवाब देखें, तो इसमें केवल यह लिखा गया है कि टोटल फैकल्टी पोस्ट्स कितनी हैं और नॉन फैकल्टी पोस्ट्स कितनी हैं। मेरा प्रश्न यह है कि एम्स, जो देशभर में हैं, उनमें कितनी सैंक्शन पोस्ट्स हैं, भर्तियां कितनी हुई हैं और इनमें एससी-एसटी, ओबीसी के कितने डॉक्टर्स हैं?

डॉ. भारती प्रवीण पवार : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा था कि कितने फैकल्टी या नॉन फैकल्टी पद भरे हैं, तो उनकी डिटेल दे दी गयी है, जो पोजीशन पर हैं। उनका कहना है कि जो नहीं हैं, तो हमने डिटेल दे दी है कि ... (व्यवधान) जो मेंटीनेंस ऑफ द कॉस्ट है, जैसे डेवलपमेंट होता है, इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, वहां की फैसिलिटीज बढ़ती हैं, अकॉर्डिंगली पोजीशन पर सैंक्शन पोस्ट्स होती हैं। माननीय सदस्य से मैं नम्रतापूर्वक कहती हूं कि जो पोजीशन है, वह दी है। जैसे-जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर्स बढ़ रहे हैं, कुछ कॉलेजों के काम अभी जारी हैं और बेडों की संख्या के आधार पर पोस्ट्स आती हैं। कहीं पर यूजी के बैच शुरू हैं, पीजी के बैच नहीं शुरू हुए हैं। वह फैकल्टी पोस्ट्स तो बाद में आएंगी। ... (व्यवधान) मुझे लगता है कि पहली बार देश ने 22 एम्स का आंकड़ा देखा है, तो उसे आपको एप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार ने पहली बार एम्स का इतना बड़ा आंकड़ा दिया है कि भारत में 22 एम्स खड़े हो रहे हैं। ... (व्यवधान) ये पद भरे जाएंगे। आप चिंता न करें। प्राइमरी, सेकेंड्री, टर्शियरी केयर पर पूरा ध्यान है। धन्यवाद।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : शुक्रिया सर। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। मंत्री जी ने कहा कि एम्स में जैसे-जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी, उसी तरह से उधर से पोस्टें भी भरी जाएंगी। मैं उम्मीद करती हूं कि वर्ष 2019 में एम्स भठिंडा में स्टैबलिश होकर पूरी तरह से चल पड़ा। यह 750 बेडों का अस्पताल है, लेकिन हैरानी की बात है कि यहां पर तीन नैशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज के बावजूद 750 बेड हैं, जहां दो हजार ओपीडीज रोज होती हैं। यहां पर रोज करीब 40 केसेज इमरजेंसी के आते हैं, लेकिन इमरजेंसी में केवल 28 बेड हैं। मैं मंत्री जी से कई बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूं कि यहां कम से कम 300

बेडों का एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। जहां तक इधर की फैकल्टी की डिमांड की बात है, मैं मंत्री जी को जरूर बताना चाहूंगी कि 4 साल हो गए, यहां पर सारे नर्सिंग के, मेडिकल के स्टूडेंट्स हो गए, लेकिन यहां पर पोस्टों की काफी कमी है। जो पोस्टें ऑथराइज्ड 765 फैकल्टी में हैं, केवल 156 की कमी है और नॉन फैकल्टी में करीब 50 फीसदी की कमी है। ये पोस्टें कब तक भरी जाएंगी?

सर, एक अन्य जरूरी बात मैं कहना चाहूंगी। बहुत मान की बात है कि इस एम्स में इन्होंने अपना लिवर ट्रांसप्लाट भी शुरू कर दिया है। चिट्ठी लिखकर भेजी हुई है कि अब स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट भी शुरू करना चाहती है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, आप एम्स का जो री-प्लान है, जो पूरा का पूरा नया होने वाला है, वह सबको बता दीजिए, ताकि ध्यान में रहे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री मनसुख मांडविया): स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने भठिंडा, एम्स में फैकल्टी रिक्रूट करने की जो चिंता व्यक्त की है, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एक तो आपको एम्स मिल गया है, उसी तरह से बाकी जरूरतें भी हम पूरी करेंगे। सवाल यह है कि जब कोई नया एम्स या इंस्टीट्यूट बनता है, तो जैसे-जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है, वैसे-वैसे पोस्ट क्रिएट होती है और हम उसे आगे बढ़ाते हैं। आज भठिंडा, एम्स सहित सभी एम्स में जब फैकल्टी पोजीशन की बात आ रही है, तो प्रधान मंत्री जी ने अभी मिशन रिक्रूटमेंट चलाया है। पिछले 6 महीनों में सभी एम्स में 29 हजार पोजीशन्स पर रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, रोटेशन के अनुसार रिक्रूटमेंट्स हुई हैं तथा एससी-एसटी, ओबीसी की रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं। सभी पोजीशनों के लिए रोस्टर के मुताबिक रिक्रूटमेंट करनी होती है, इसका काम गति के साथ सभी एम्स में चल रहा है। हम चाहते हैं कि सभी एम्स अच्छी तरह से टाइम पर फुल फंक्शनल हो जाएं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जहां-जहां आपके क्षेत्र में एम्स हैं, आप अवश्य एम्स के चक्कर लगाएं और यदि आपका कोई सुझाव है और कोई अन्य व्यवस्था खड़ी करने की आवश्यकता है, तो हम अवश्य खड़ी करेंगे।

मोदी गवर्नमेंट का इरादा है कि देश में सभी नागरिकों को अपने स्टेट में बेस्ट टर्शिएरी के ट्रीटमेंट मिलने चाहिए। देश में राज्य में टर्शिएरी के ट्रीटमेंट मिले। किसी भी पेशेंट को दिल्ली एम्स में

आने की आवयश्कता न पड़े, उसके लिए सभी स्टेट्स में एम्स बनाने के कार्य किये गये हैं, जो आज गति से चल रहे हैं।

डॉ. मोहम्मद जावेद : सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आदरणीय प्रधान मंत्री का वादा था कि हर जिले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होगा। बिहार में भी उन्होंने एक एम्स दिया है। लेकिन, जहां जमीन मिली है, वहां पर एम्स बनाने में जितना खर्च होगा, उससे ज्यादा खर्च उसकी मिट्टी भराई में लग जाएगा। किशनगंज ही एक ऐसा जिला है, जिसके पास 200 एकड़ जमीन है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किशनगंज में जो जमीन उपलब्ध है, उसमें एम्स बनाना शुरू कर दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : इसके लिए राज्य सरकार प्रस्ताव करेगी।

डॉ. मोहम्मद जावेद : सर, वैसे भी आदरणीय प्रधान मंत्री का वादा है कि हर जिले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होगा। धन्यवाद।

श्री मनसुख मांडविया : माननीय स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने बिहार में एम्स खोलने के सबंध में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रेज किया है। भारत सरकार की ओर से राज्य से पूछा जाता है कि हम आपके राज्य में एक एम्स खोलना चाहते हैं, आप इसके लिए जगह दीजिए। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट हमें लैंड देती है। वैसी ही वहां भूतकाल में स्टेट गवर्नमेंट ने एक लैंड दी थी। हमने उस लैंड की बाउंड्री कराई और वहां फिलिंग करने का काम चालू किया। लेकिन, वहां सरकार बदल गई। उसके बाद सरकार ने जगह बदलकर दूसरी लोकेशन दे दी। जो दूसरी लोकेशन दी, वह बहुत गड्ढे वाली लोकेशन थी। जब हमें लैंड दी जाती है तो आईआईटी, मिनिस्ट्री और तीन-चार टेक्निकल लोग वहां लैंड का एग्जामिनेशन करने के लिए जाते हैं। मैंने भी यहां से एक एक्सपर्ट टीम भेजी थी। एक्सपर्ट टीम ने आकर मुझे रेक्मेंडेशन दिया कि मंत्री जी, वहां तो एम्स बन ही नहीं सकता है। वहां वाटर बॉडी है। ऐसी स्थिति में मैंने राज्य सरकार को लेटर लिखा कि प्लीज आप अच्छी लैंड दीजिए, मोदी जी वहां एम्स बनाना चाहते हैं। लेकिन, स्थिति ऐसी हुई कि स्टेट गवर्नमेंट ने लिखकर दिया कि अभी हम यही लैंड देना चाहते हैं। मैंने फिर से लेटर दिया कि हम तो बिहार में एम्स बनाना चाहते है और आप वही

लैंड देना चाहते हैं तो उन्होंने कहा हम 300 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से गड्ढा भरने के लिए देंगे। हमने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे डिजाइन बदलनी पड़ेगी। मैंने फिर एक्सपर्ट टीम से कहा कि आप डिजाइन को बदल दीजिए। अभी फिर से वहां सरकार में परिवर्तन हुआ है। हम चाहते हैं कि हमें अच्छी लैंड मिल जाए तो हम तुरंत ही वहां आपके किसी भी सिटी में, स्टेट गवर्नमेंट हमें किसी भी सिटी के लिए रेक्मेंड करेगी, वहां हम एम्स बनाएंगे।

स्पीकर सर, यह पॉलिटिकल इश्यू नहीं है। यह पॉलिटिकली डिबेट का भी इश्यू नहीं है। यह देश की, राज्य की जनता की हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ इश्यू है। बिहार में पॉलिटिक्स हो गयी थी। लाइकिंग-डिसलाइकिंग में जहां हमने एम्स बनाने के लिए टेंडर ओपन कर दिया था, हम वहां कंस्ट्रक्शन वर्क चालू करने की पोजिशन में थे, फिर लेटर आ गया कि यहां नहीं, हमें गड्ढे वाली लैंड एलांट कर दी। … (व्यवधान) हम चाहते हैं कि हमें अच्छी लैंड मिल जाए। हम तुरंत ही एम्स का काम चालू करेंगे।

SHRI B. MANICKAM TAGORE: Thank you, Sir. The hon. Minister is a learned Minister and he has been working hard. He has told that if there an AIIMS in your constituency, the MP should visit and see that thing. In my constituency also, there is an AIIMS. Its foundation stone was laid in 2019 before elections. But still there is no work started. I would like to request the hon. Minister whether he can assure the House when the Madurai AIIMS work will start and when the completion will be there. This is because five years have passed and Madurai AIIMS is still waiting for it.

डॉ. भारती प्रवीण पवार : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से एक बार धन्यवाद देती हूं कि लगातार आपके सवाल एम्स, मदुरई के बारे में आते हैं। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने यही सोच-विचार करके एम्स की गति बढ़ाई है। मैं शुरुआत से कह दूं कि जो लैंड एक्वीजिशन हुआ वह थोड़ा लेट हुआ,

जो कि राज्यों की तरफ से होता है। लैंड एक्वीजिशन के बाद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हम कोविड के इंफेक्शन से गुजरे थे।

सर, यह जीका के साथ होने वाला प्रोजेक्ट है। वहां जीका का इंस्पेक्शन भी हुआ है। उसमें बजट भी बढ़ाया गया है। जो बजट पहले 1200 करोड़ रुपये था, उसको हमने रिवाइज्ड करके 1900 करोड़ रुपये कर दिया है, ताकि वहां पर एक अच्छा एम्स खड़ा हो। उसके बाद, उसका प्री इंवेस्टमेंट वर्क भी कम्प्लीट हुआ है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंट भी अप्वाइंट हुए हैं। अभी उसका मास्टर प्लान फाइनालाइज हुआ है। टेंडर भी अवार्ड हुआ है और मुझे लगता है कि यह काम शुरू होने वाला है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ... (व्यवधान) इसका बजट बढ़ने में तो टाइम लगता है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 104,

श्री रामदास तडस।

(Q. 104)

श्री रामदास तडस : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कोविड-19 की महामारी के बाद देशभर में मुफ्त टीकाकरण अभियान संपन्न हुआ है। पहला तथा दूसरा डोज बड़े पैमाने पर नागरिकों को दिया गया, लेकिन दोनों डोजों की तुलना में बूस्टर डोज को कम सफलता मिली। क्या यह सही है? क्या इस संदर्भ में सरकार के पास कोई जानकारी है और सरकार इस विषय पर क्या कार्रवाई कर रही है?

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : अध्यक्ष महोदय, हमारी दोनों वैक्सीन्स पूरी तरह से विश्वस्तर की थीं और भारत में निर्मित थीं। वैक्सीन का निर्माण 8 से 12 साल में होता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मनसुख मांडविया जी के अथक प्रयासों और हमारे वैज्ञानिकों के सहयोग से तथा वे डब्ल्यूएचओ के साथ निरंतर संपर्क कर रहे थे। डॉ. मनसुख मांडविया जी विश्व के सभी वैक्सीन निर्माताओं से निरंतर संपर्क कर रहे थे, इसलिए वैक्सीन का निर्माण हुआ था। इसलिए किसी भी प्रकार से वैक्सीन की कमी नहीं थी, जिसने जो चाहा और जो प्रोटोकॉल था, उसके अनुसार वैक्सीन दी गई है।

श्री रामदास तडस : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या नया कोरोना वायरस हमारे देश में आ रहा है? यदि आ रहा है, तो अभी तक महाराष्ट्र में इस नए वायरस से कितनो लोगों की मृत्यु हुई है एवं क्या विदेशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट्स पर जांच की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री मनसुख मांडविया) : अध्यक्ष महोदय, कोविड एक ऐसा वायरस है, कोई भी वायरस म्यूटेट होता है। कोविड वायरस भी कई बार म्यूटेट होता रहा है। अगर कोई भी वायरस 100 बार से ज्यादा म्यूटेट होता है, तो उसके बाद उसकी घातकता कम हो जाती है। आज तक पूरी दुनिया में कोविड वायरस 223 बार म्यूटेट हो चुका है। जैसे इन्फ्लूएंजा वायरस की वजह से प्रतिवर्ष हमें एक-दो बार खांसी होती है। वैसे ही कोविड वायरस हमारे बीच में है, वह रहेगा, क्योंकि वह वायरस अभी डोमिनेट हो गया है। हर साल उसका कई बार म्यूटेशन होता है, तब हमें कई बात उसके सिम्टम्स दिखते हैं। वर्तमान समय में जो 'बीए.6' के एक

सब वैरिएंट का भी सब वैरिएंट था, वह घातक नहीं है। उसका ऐसा कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं है, इसलिए हमें उस पर कोई विशेष एक्शन नहीं लेना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मदुरै एम्स के बारे में बात हो रही थी। मैं बताना चाहूंगा कि यह मोदी सरकार है, जो कहती है, वह करती है। हमने मदुरै एम्स का शिलान्यास किया था और हमारी मजबूरी थी कि उसका प्रोग्राम 'जाइका फंड' से चल रहा था। इसलिए फॉर्मेलिटी में समय लग गया, लेकिन अब सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं। उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल डिबेट या इश्यू उठाने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट समय में उसका टेंडर भी फाइनल हो गया है, एजेन्सी भी फाइनल हो गई है और उसका काम भी चालू होना है। आप निश्चिंत रहिए, मदुरै में एम्स बनेगा।

श्रीमती पूनमबेन माडम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि चाहे डब्ल्यूएचओ हो...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सदन है। आप पिछले 5-10 मिनट्स से खड़े होकर बात कर रहे हैं। कृपया आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्रीमती पूनमबेन माडम : अध्यक्ष महोदय, चाहे डब्ल्यूएचओ हो या विशेषज्ञों सहित कई वैश्विक सार्वजनिक संगठन महामारी को रोकने के लिए एक स्वास्थ्य आधारित दृष्टिकोण की वकालत कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्वास्थ्य मंत्रालय को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए दिशा-निर्देश दिए हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय इस संबंध में क्या-क्या पहल कर रही है? जो भी वैश्विक संस्थाएं हैं, कैसे उनके सुझावों को सम्मिलित करके आगे बढ़ रही हैं? हालांकि हर देश की परिस्थिति अलग होती है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि इनके सुझावों को कैसे सम्मिलित किया जाता है?

श्री मनसुख मांडविया : स्पीकर साहब हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिसमें सारी दुनिया को साथ में मिलकर काम करना होता है। कोविड क्राइसिस ने हमें भली-भांति सिखाया है कि कोविड में

सामूहिकता में काम करने से कैसे रिजल्ट मिलता है, इसलिए सारी दुनिया हेल्थ सेक्टर में साथ में मिलकर काम करे। चाहे वह वैक्सीन की रिसर्च हो, चाहे वह रेयर डिसीज़ की मेडिसिन हो, चाहे कोई पेंडेमिक की स्थिति हो या पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस हो, सभी सब्जेक्ट्स में दुनिया साथ में मिलकर काम करे। उसके लिए कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और डब्ल्यूएचओ उसमें एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है।

महोदय, हेल्थ सेक्टर में हर देश में अपना-अपना मॉडल होता है और हर देश, हर कम्युनिटी की अपनी-अपनी जेनेटिकल बॉन्डिंग होती है। इसलिए इंडिया में डिसीज़ और डिसीज़ का स्प्रैड दुनिया के देशों से अलग भी हो सकता है। कई ऐसी रेयर डिसीज़ हैं, जिनके ऊपर दुनिया में काम हो और इंडिया में आकर उस डिसीज़ पर हमें ट्रीटमेंट या मेडिसिन मिले। उदाहरण के लिए देश में स्पाइनल एट्रोफी डिसीज़ है। ऐसी डिसीज़ के लिए इंडिया में मेडिसिन नहीं बनती है तो बाहर से लानी पड़ती है और उसकी कीमत 16 करोड़ रुपये है। आज सिकल सेल इंडिया में बहुत स्टेट और 200 से अधिक डिस्ट्रिक्ट्स में है। सिकल सेल में हाइड्रोक्सीयूरिया का यूज होता है। हाइड्रोक्सीयूरिया टेबलेट और हाइड्रोक्सीयूरिया सस्पेंशन इतना महंगा होता है, इसलिए उसका इलाज करना भी मुश्किल होता है तथा हमें दुनिया से लाना पड़ता है। इसलिए हमने अपने मॉडल को अपनाते हुए अपनी कंपनियों के साथ बातचीत करके कहा कि रेयर डिसीज़ के लिए जो मेडिसिन महंगी है, क्या उसके ऊपर इंडिया में रिसर्च हो सकती है? क्या हम इंडिया की मॉडलिंग के आधार पर काम कर सकते हैं? उसके लिए हमारी कंपनियों ने बढ़-चढ़कर काम करना चालू किया है।

महोदय, हमने कई टाइप्स की मेडिसिन्स देश में बना ली हैं। भविष्य में ऐसी कोई पेंडेमिक की स्थिति हो, लेकिन इंडिया की दूसरी विशेषता है, चूंकि यहां कोई मेडिसिन बनती है तो इंडिया को फायदा होता है, क्योंकि इंडिया में सस्ती बनती है। जब इंडिया में एक बार सस्ती मेडिसिन बन जाती है तो सारी दुनिया को फायदा होता है। आज हम एड्स की मेडिसिन के बारे में बात करें तो एड्स की मेडिसिन पहले बहुत महंगी होती थी, लेकिन जब से इंडिया में बननी चालू हुई, उससे इंडिया की रिक्वायरमेंट पूरी हुई और सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ और ग्लोबली सस्ती एड्स की मेडिसिन मिलने

लगीं। आज दुनिया में 70 परसेंट एड्स की मेडिसिन इंडिया से जाती हैं। वैसा ही वैक्सीन में भी है। दुनिया में वैक्सीन महंगी मिलती थी, लेकिन जब इंडिया में मैन्युक्चरिंग हो जाती है, जैसे कोविड की वैक्सीन 25 डॉलर, 28 डॉलर की वैक्सीन थी, लेकिन हमने ढाई और तीन डॉलर में सारी दुनिया को उपलब्ध कराई है। यह भारत में निर्मित वैक्सीन है। दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हम हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं। यह हमारे भी हित में है और दुनिया के भी हित में है।

माननीय अध्यक्ष : यह बात सही है। जब मैं अफ्रीकन देशों में गया था तो वहां के लोगों ने कहा कि हमें इंडियन मेडिसिन सस्ती मिलती है और इफेक्टिव भी है।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, इंडिया की मेडिसिन के चलते मौत भी हो चुकी हैं। ... (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : आप यह क्या कह रहे हैं? अगर पीठ से तारीफ हुई तो तारीफ कीजिए। हम सबकी ड्यूटी है। जब पीठ से तारीफ हुई है तो तारीफ करनी चाहिए। आसन से तारीफ हुई तो तारीफ करनी चाहिए। उसके अगेंस्ट में भी आपका रिएक्शन है। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : तारीफ क्यों नहीं करेंगे, हम तारीफ करेंगे। ... (व्यवधान)

श्री मनसुख मांडविया : वह न्यूज में क्यों आता है, मैं आपसे बाहर वन टू वन बात करता हूं, क्योंकि यह फ्लोर पर बात करने का विषय नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महामारी से निपटने के लिए अत्यंत जरूरी है कि इफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर्स की पूरी स्थिति बरकरार रहे और सभी डॉक्टर्स महत्वपूर्ण नंबर्स में उपलब्ध रहें। मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर के अंदर महामाया मेडिकल कॉलेज स्थापित है। उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की स्थापना के लिए एमसआई के पास एप्लीकेशन पड़ी हुई है। देश में डॉक्टर्स की उपलब्धि हो सके और महामारी जैसी स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टर्स की उपलब्धि पूर्ण रूप से मिल सके, उसके लिए ऐसे अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्रियां होना ज्यादा जरूरी है।

माननीय मंत्री जी से मुझे यह जानना है कि अंबेडकर नगर में महामाया मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री की एमसीआई के पास एप्लीकेशन पड़ी हुई है, वह कब तक पास हो जाएगी?

वह कब तक पास हो जाएगी, वहां कब तक इंसपैक्शन करवा दिया जाएगा ताकि आगे आने वाले समय में महामारी से निबटने के लिए सुचारू रूप से डॉक्टरों की व्यवस्था हो सके।

माननीय अध्यक्ष : सदन में कभी भी किसी मेडिकल कॉलेज का नाम लेकर, किसी संस्थान का नाम लेकर और उसमें ऐसा होना चाहिए, यह कभी भी प्रश्न काल में नहीं उठाना चाहिए। इससे हमारी संसदीय मर्यादाओं पर और इस प्रश्न काल पर बड़ा लम्बा इम्पैक्ट पड़ता है। आप पॉलिसी मैटर पर बोलें, लेकिन उस मेडिकल कॉलेज में ऐसा नहीं हुआ, यह बोलना भविष्य के लिए उचित नहीं है। अब आप इसका क्या जवाब देंगे, मैंने इसका जवाब दे दिया है।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के अम्बेडकर जिले का मैं प्रभारी मंत्री रह चुका हूं... (व्यवधान) मैं आपके पिताजी के साथ भी एमपी रहा हूं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग आपस में ही बात न करें कि कौन किसके साथ क्या है? आप केवल जवाब दें।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : अध्यक्ष महोदय, मैंने इनके मेडिकल कॉलेज का भी दौरा किया था, जब राज्य में था।

माननीय अध्यक्ष : आप उस मेडिकल कॉलेज से संबंधित जवाब मत दीजिए, मैंने इस बारे में मना किया है।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : महोदय, मैं पॉलिसी बता देता हूं कि माननीय सदस्य ने जो पोस्ट ग्रेजुएट या मान्यता की बात की है, एनएमसी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट संस्था है। नियमानुसार वह मान्यता देती है अथवा कैंसल करती है। लेकिन माननीय प्रधान मंत्री महोदय जी के दस साल के कार्यकाल में यूजी की संख्या बढ़ाकर के सौ परसेंट से ऊपर कर दी गयी है और पीजी की संख्या भी बढ़ाकर के 126 परसेंट कर दी गयी है। 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज' हो रहा है और उसी के साथ मेडिकल कॉलेजों की संख्या 350 से बढ़ाकर 700 कर दी गयी है। पीजी की संख्या जब बढ़ी है तो नीट पीजी का एग्जाम होगा और उसमें लोग सिलेक्ट होंगे तो निश्चित तौर से हर मेडिकल कॉलेज में पीजी ट्रैंड लोग जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 105,

श्री दिलेश्वर कामैत।

(Q. 105)

श्री दिलेश्वर कामैत : महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र सुपौल बिहार का सीमावर्ती अति पिछड़ा क्षेत्र है। कोसी नदी में प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ की वजह से क्षेत्र में भयानक महामारी एवं बीमारी लोगों में फैल जाती है तथा संक्रामक रोगों की वजह से गंभीर बीमारी जैसे- कैंसर, हृदय रोग, ट्यूमर, टीबी एवं अन्य और भी घातक बीमारी हो जाती है, जिसके इलाज के लिए स्थानीय लोगों को दिल्ली, मुम्बई, बैंगलोर तथा दूर-दूर के अस्पतालों में जाना पड़ता है। अति पिछड़ा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने की वजह से लोगों की आमदनी इतनी नहीं है कि वे अपना ठीक से इलाज करा सकें। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी की सुपौल जिला में इंटिग्रेटिड आयुष अस्पताल खोलने की कोई योजना है? अगर नहीं है तो इसका प्रस्ताव किया जा सकता है। इसी तरह से इसके आस-पास जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, उसमें भी क्या आयुष अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव है?

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : परम आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सभी माननीय सांसदों से और विशेष रूप से आयुष के सिलसिले में कई बार इस सदन में हमने जवाब के रूप में बात रखी है। Ayush is a traditional system of medicine. यह भारत का गौरव है। यह प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और देश के अंदर इसको स्वतंत्रता के बाद जो मान्यता मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली थी। लेकिन हमारे देश के आदर्शवादी नेता और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पिछले दस साल के अंदर आयुष को बढ़ावा देने के लिए जो भी कदम उठाए, आप लोगों ने खुद देखा है और महसूस भी किया है। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा, योगा, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी, हर एक सिस्टम को इक्वली प्रमोट करने के सिलसिले में उन्होंने नीतियां अपनायी हैं, कदम उठाए हैं और बजटरी सपोर्ट दिया है।

इसके अलावा रिसर्च फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, हॉस्पिटल फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स को बढ़ावा देने के लिए और एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए जो

कानून व्यवस्था लागू की गई है, उसकी वजह से आज इस सेक्टर ने दुनिया का तथा मानव समाज का ध्यान आकर्षित किया है।

आपने खुद ने देखा है कि हमारे देश के अंदर अलग-अलग सिस्टम्स हैं जैसे तमिलनाडु में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा है। बैंगलुरु में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी है। कोलकाता में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी है। जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है। दिल्ली के सरिता विहार में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है। साथ ही साथ सेटेलाइट इंस्टीट्यूशन्स भी हैं। इसके अलावा हमारे यहां पर प्रमुख रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैं।

देश के अन्दर जो पेरिफेरल इंस्टीट्यूशन्स बने हैं, उनकी वजह से आज परम आदरणीय प्रधान मंत्री जी के निर्देश के मुताबिक हमारे मंत्रालय को तथा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय, दोनों को इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बढ़ावा मिला है। उन्होंने जो निर्देश दिए हैं, उन्हीं निर्देशों का अनुपालन करते हुए मेरे परम आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख भाई और मैं हमारे अधिकारियों के साथ पिछले दो सालों से इसके लिए निरंतर कोशिश कर रहे हैं।

इसके लिए लोगों ने भी काफी सहयोग किया है। परम आदरणीय प्रधान मंत्री जी के आशीर्वाद से आज दोनों सिस्टम्स, मॉर्डन और ट्रेडिशनल को एक साथ जोड़ा गया है। एम्स से लेकर ग्रास रूट लेवल तक आयुष को ले जाने की व्यवस्था खड़ी की गई है। यह जनता के लिए निश्चित रूप से एक अच्छी सुविधा होगी। हमारे प्रिय मित्र दिलेश्वर जी ने सही सवाल किया है। उनके प्रश्न के जवाब में मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर आयुष संस्थान कुल 294 हैं। बिहार सरकार के सहयोग से अब उनको बढ़ावा देने के लिए हमने कोशिश की है। अब तक 113 आयुष संस्थान ऑपरेशनल हुए हैं।

मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हर प्रांत में हमारे इस सिस्टम को जनता के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। पूरे देश और विदेश में भी आयुष का प्रेजेंस हुआ है। चूँकि आपको यह जानकार खुशी होगी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस सिलसिले में, जो भी कदम उठाया है, आप देखिए कि मॉड्यूल 2 ऑफ इंटरनेशनल क्लासीफिकेशन ऑफ डिजीज में आयुष को इंटीग्रेट किया गया है। इसकी वजह से आज हमारे अलग-अलग सिस्टम में जिस भी बीमारी का नाम लिया जाता है

जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि डायरिया को आयुर्वेद में अतिसार बोला जाता है। सिद्धा में रेडी बोलते हैं। यूनानी में ईशाल बोलते हैं। एक ही बीमारी को अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। इसलिए मरीजों को कोई दिक्कत न हों उसके लिए डब्ल्यूएचओ ने उसमें एक व्यवस्था लागू की है। जिसकी वजह से आप चाहे अमेरिका में हो या यूरोप में हो, कौन सी बीमारी व्यक्ति को हो रही है और उसके लिए कौन सी दवाई जरूरी है, उपलब्ध हो जाएगी, चाहे वह सिद्धा सिस्टम में हो या यूनानी में हो।

मुझे लगता है कि यह हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। साथ-साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपिंग अथॉरिटी इंडिया ने भी अभी इंश्योरेंस कवरेज के लिए सारे इंश्योरेंस कंपनीज़ को आयुष सिस्टम में सभी बीमारियों को कवर करने के लिए एडवाइस दी है। पिछले 10 सालों में हमने इतनी सफलता हासिल कर ली है। यह सिर्फ हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के सही और मजबूत कदम की वजह से हुआ है। उनकी सही नीतियों की वजह से यह संभव हुआ है। मुझे लगता है कि आप सबको इस विषय पर खुश होना चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। यह सभी मनुष्यों का उद्देश्य होता है। अध्यक्ष जी, हमारे सभी सदस्य तंदुरुस्त रहें, मैं यही चाहता हूँ।

श्री दिलेश्वर कामैत : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न का जवाब नहीं मिला, फिर भी मैं एक सप्लिमेंट्री प्रश्न पूछना चाहता हूं। मंत्री महादोय ने आयुष की विशेषता पर बहुत सी बातें कही हैं। वास्तव में आयुष बहुत आवश्यक है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्री दिलेश्वर कामैत : सर, मेरा यह प्रश्न है कि क्या बिहार में आयुष मंत्रालय द्वारा एक सिद्ध-औषधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव का आश्वासन माननीय मंत्री जी दे सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत महत्ता है? आपने अभी इसके उद्देश्य के बारे में बताया है। वहां एक सिद्ध-औषधि विश्वविद्यालय खोला जाए, जिससे उत्तरी बिहार के लोगों को इसका फायदा मिले।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिलेश्वर कामत जी को यही बताना चाहता हूं कि कुछ देर पहले मैंने अपने जवाब में कहा था कि हम लोगों ने बिहार के लिए कुल मिला कर 294 आयुष्मान आरोग्य मंदिर एप्रुव किए हैं और मुझे लगता है कि आपके इलाके में भी शायद बिहार सरकार ने वहां जो भी हमारी एग्जिस्टिंग व्यवस्था है, जो भी हेल्थ सब-सेंटर्स हैं और डिस्पेंसरीज को अपग्रेड करने के लिए हम आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य सरकार को मदद करते हैं। राज्य सरकार का प्रस्ताव एनुअल ऐक्शन प्लान के मुताबिक होता है, हम उसको अनुमोदन देते हैं।

***SHRI DHANUSH M. KUMAR:** Hon. Speaker Sir, Father of Siddha Medicine, Saint Agasthiyar was living in Podhigai hills of Tenkasi district of Tamil Nadu. Medicinal herbs are available in abundance in that area. I had already raised this demand in this august House for setting up of a Central Siddha University in Podhigai hills area.

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : माननीय अध्यक्ष जी, ट्रांसलेशन नहीं आने के कारण, मैं प्रश्न समझ नहीं पाया। कृपया आप प्रश्न रिपीट कर दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : हां, यह प्रश्न रिपीट कर देंगे। आप प्रश्न रिपीट कर दीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगस्त ऋषि इसके जन्मदाता माने जाते हैं। ये उससे संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं।

***SHRI DHANUSH M. KUMAR:** I want to know whether the Government is considering the proposal for setting up of this Central Siddha University in that area?

माननीय अध्यक्ष : ये केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की मांग कर रहे हैं।

…(व्यवधान)

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी ने सिद्ध विश्वविद्यालय के संबंध में सवाल पूछा है कि क्या ऐसा हो सकता है?

माननीय अध्यक्ष : वे उसके जन्मदाता थे, इसलिए ये वहां विश्वविद्यालय खोलने की मांग कर रहे हैं।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : आप सभी को मालूम है कि यह सरकार सिद्ध-डे बड़े भक्तिभाव से मनाती है और सिद्ध को बढ़ावा देने के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, इनके साथ-साथ में दिल्ली हो या गोवा हो एवं असम में भी नॉर्थ-ईस्ट के लिए एक इंटीग्रेटेड आयुष वेलनेस सेंटर बन रहा है, हमने उसमें भी 'सिद्ध' की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। इसके प्रचार-प्रसार के लिए हमारी तरफ से भी कोशिश जारी है। अभी तक विश्वविद्यालय के संबंध में कोई निर्णय नहीं हुआ है। निश्चित रूप से इस विषय पर हमें कई लोगों ने चिट्ठी भी लिखी है। यह महत्वपूर्ण है। अभी तक ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है। इसके साथ-साथ मैं यह कहूंगा कि अभी सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली और ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, दिल्ली हर केन्द्र में सिद्ध सिस्टम को लागू किया गया है। हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में ओपीडी शुरू की है। साथ ही साथ सफदरजंग में भी यह शुरू हुई है। हमारे राष्ट्रपति भवन में भी इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक केन्द्र शुरू किया है, जहां 'सिद्ध' को भी इंटीग्रेड किया गया है।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 106,

डॉ अमर सिंह।

(Q. 106)

डॉ. अमर सिंह : सर, मेरे सवाल के दो हिस्से थे। क्योंकि एक हिस्से का जवाब तो बहुत सुंदर मिला है। मैं दोबारा थोड़ा सा एक सेंटेंस पढ़ना चाहता हूं। Does the Government propose to slash the cost of healthcare facilities and increase the supply of doctors? सप्लाई ऑफ डॉक्टर्स का बहुत ही सुंदर जवाब दिया है। मैंने जो सवाल पूछा था, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि इंडिया में जो हाइऐस्ट आउट-ऑफ-पॉकेट प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, वह 63 परसेंट है। 63 परसेंट लोग अपनी जेब से खर्चा करते हैं। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है और नीति आयोग ने कहा है कि 30 परसेंट पॉपुलेशन का एक मिसिंग मिडिल ऑफ इंडिया का हमें इंश्योरेंस करना है। हेल्थ एक्सपेंडिचर की वजह से इन्हीं में से पाँच साढ़े पांच करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय कम है।

डॉ. अमर सिंह : सर, यह मेरा एक पार्ट है। केवल पांच मिनट ही बचे हैं। इसलिए मैं दूसरा सवाल भी पूछ लेता हूं और मंत्री जी उसका जवाब दे दें। मेरे दूसरा सवाल यह है कि 75 per cent of the health facilities in our country. वह अर्बन एरियाज या मेट्रोज़ में हैं। वहां 27 परसेंट पॉपुलेशन रहती है, आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं? उसी का हिस्सा है कि आप रेगुलेटर क्यों नहीं बना रहे हैं? कोई एक कमरे का रात का 20 हजार रुपये ले रहा है और कोई 50 हजार रुपये ले रहा है। कोविड में लोगों का 20-20 लाख रुपये का बिल बना। मैंने सारी बातें एक ही बार में पूछ ली हैं, क्योंकि समय कम बचा है। मंत्री जी बता दे दें कि कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगी?

श्री मनसुख मांडविया : स्पीकर सर, लोगों की जेब से खर्च कम हो, सभी को हेल्थ सुविधा मिले, यह मोदी गवर्नमेंट की प्राथमिकता रही है। मोदी गवर्नमेंट ने कभी टोकन में नहीं सोचा है, हमेशा टोटल में सोचा है। हमारे देश में हेल्थ को कभी कॉमर्स के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि सेवा के रूप में देखा जाता है। इसलिए हेल्थ को सर्वव्यापी करने के लिए, जैसा आपने कहा कि हेल्थ की सुविधा गांव तक पहुंचे। देश में एक लाख 64 हजार आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं, ताकि सामान्य और गरीब

व्यक्ति को हेल्थ की सुविधा मिले। देश में हेल्थ एफोर्डेबल हो। देश में 12 करोड़ परिवार यानी 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के कवरेज के नीचे लाया गया है। 60 लाख लोगों को पांच लाख रुपये तक की प्रधान मंत्री मोदी जी द्वारा मुफ्त इलाज की गारंटी दी गई है। इसके अलावा देश में 10 हजार से अधिक जन औषधि केन्द्र खोले गए हैं। वहां एफोर्डेबल प्राइस में मेडिसिन मिल रही है। देश में नी इम्प्लांट्स, स्टैंट – सभी की प्राइस को कैप किया गया है। उसकी वजह से देश को 27 हजार करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। आयुष्मान भारत योजना की एक स्टडी ने बताया है कि लोगों का एक लाख 20 हजार करोड़ रुपये बचा है। कुल मिलाकर आज तक 3 लाख 56 हजार करोड़ रुपये लोगों की जेब से बच गया। आपने इश्यु रेज किया है कि मिडिल क्लास को हेल्थ सुविधा मिलनी चाहिए, एफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। मिडिल क्लास हो, गरीब क्लास हो या कोई भी क्लास हो, उसको सस्ता इलाज मिले। वह मोदी गवर्नमेंट की गारंटी रही है और नतीजा यह निकला है कि... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आप आउट-ऑफ-पॉकेट के बारे में बताइये।... (व्यवधान)

श्री मनसुख मांडविया : मैं बताता हूं। आप सुनिये।... (व्यवधान) मेरी जिम्मेवारी है और अधीर रंजन जी ने क्वेश्चन पूछा है, उसका तो मैं अवश्य जवाब दूंगा।... (व्यवधान)

स्पीकर सर, एक स्टडी यह बताती है कि... (व्यवधान) मैं बताता हूं। साढ़े पांच करोड़ लोगों को सस्ता इलाज नहीं मिलने से, उसका पॉकेट खर्च बढ़ जाने से वे गरीब रेखा के नीचे आ जाते थे। एक ही साल में, आपने नीति आयोग की स्टडी को क्वोट किया है, मैं उसका हवाला देते हुए बता रहा हूं कि 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे से बाहर इसलिए आए हैं कि उसमें से हेल्थ में भी खर्च कम हुआ है। कुल मिलाकर देश में जीडीपी का कुल खर्च वर्ष 2014 के पहले 1.13 परसेंट था, आज वह खर्च बढ़कर 1.35 परसेंट हो रहा है।... (व्यवधान)

12.00 hrs

वर्ष 2014 से पहले, देश में हेल्थ पर कुल खर्च 29 परसेंट होता था, आज वह खर्च कम होकर, भारत सरकार की ओर से आज वह खर्च बढ़कर 47 परसेंट हुआ है।

अभी आउट ऑफ पॉकेट खर्च की बात आई। आउट ऑफ पॉकेट खर्च के बारे में व्हाईट पेपर में है, उसे पढ़ लीजिए। वर्ष 2014 से पहले, वह 62 परसेंट था। जब बीमारी आती थी, तो गरीब और मध्यम वर्गों की जेब से 62 परसेंट खर्च होते थे। आज उसमें गिरावट आई है और 47 परसेंट आउट ऑफ पॉकेट खर्च बची है।

आने वाले दिनों में आउट ऑफ पॉकेट खर्च और कम हो, उसके लिए अभी और एम्स बन रहे हैं। हमारी आँगनवाड़ी बहनें, आशा बहनों की फैमिली के लिए भी हेल्थ कवरेज दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ रहा है ताकि देश में सस्ता इलाज मिले।

———————

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 107 to 120
Unstarred Question Nos. 1151 to 1380)
(Page No. 34 to 892)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त।

———————

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर 3, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Asiatic Society of Mumbai and The Library of the Asiatic Society of Mumbai, Mumbai, for the year 2022-2023, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Asiatic Society of Mumbai and The Library of the Asiatic Society of Mumbai, Mumbai, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11351/17/24]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Salar Jung Museum, Hyderabad, for the year 2022-2023, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Salar Jung Museum, Hyderabad, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11352/17/24]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Law Institute, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Law Institute, New Delhi, for the year 2022-2023.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 11353/17/24]

12.02 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Sethusamudram Corporation Limited, Chennai, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the Sethusamudram Corporation Limited, Chennai,

for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 11354/17/24]

(b) (i) Review by the Government of the working of the Sagarmala Development Company Limited, New Delhi, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the Sagarmala Development Company Limited, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 11355/17/24]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under Section 73 of the Major Port Authorities Act, 2021:-

(i) The Board of Major Port Authority for Mormugao Port (Meetings and Transaction of Business) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. GAD/MPA/REGS//001/2023(E) in Gazette of India dated 20th September, 2023 together with a corrigendum thereto (in Hindi version only) published in Notification No. F.No. GAD/MPA/REGS/001/2023, 20 December, 2023, dated the 4th January, 2024.

(ii) The Mormugao Port Authority (Stevedoring and Shore Handling)

Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. GAD/Legal-Amend/23/2023 in Gazette of India dated 9th November, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 11356/17/24]

श्री अश्विनी कुमार चौबे(बक्सर) : माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 435(अ) जो दिनांक 14 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 938(अ) जो दिनांक 23 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वन विहार वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 1173(अ) जो दिनांक 13 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा टॉडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 1191(अ) जो दिनांक 17 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ. 6212(अ) जो दिनांक 18 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जमवारामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(छह) का.आ. 6319(अ) जो दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बन्ध बारेठा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(सात) का.आ. 1220(अ) जो दिनांक 8 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(आठ) का.आ. 2606(अ) जो दिनांक 19 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केवलादेव राष्ट्रीय पार्क पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(नौ) का.आ. 107(अ) जो दिनांक 7 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र में संशोधन अधिसूचित किया गया है।

(दस) का.आ. 814(अ) जो दिनांक 21 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केवलादेव राष्ट्रीय पार्क पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) का.आ. 2631(अ) जो दिनांक 6 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जयसामंद वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(बारह) का.आ. 4047(अ) जो दिनांक 11 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(तेरह) का.आ. 4268(अ) जो दिनांक 27 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व (एमएचटीआर) पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(चौदह) का.आ. 1717(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बस्सी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(पंद्रह) का.आ. 1929(अ) जो दिनांक 18 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बन्ध बारेठा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र में संशोधन अधिसूचित किया गया है।

(सोलह) का.आ. 3683(अ) जो दिनांक 13 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भैनसोरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(सत्रह) का.आ. 4668(अ) जो दिनांक 3 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र में संशोधन अधिसूचित किया गया है।

(अठारह) का.आ. 3142(अ) जो दिनांक 14 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वन विहार वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र में संशोधन अधिसूचित किया गया है।

(उन्नीस) का.आ. 4843(अ) जो दिनांक 8 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र में संशोधन अधिसूचित किया गया है।

(बीस) का.आ. 5236(अ) जो दिनांक 10 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 31 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1260(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्कीस) का.आ. 2819(अ) जो दिनांक 21 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 421(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बाईस) का.आ. 3515(अ) जो दिनांक 7 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 31 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1257(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेईस) का.आ. 2818(अ) जो दिनांक 28 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2561(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौबीस) का.आ. 5313(अ) जो दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 31 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1259(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पच्चीस) का.आ. 5316(अ) जो दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 31 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1258(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छब्बीस) का.आ. 5237(अ) जो दिनांक 10 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2364(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्ताईस) का.आ. 4422(अ) जो दिनांक 11 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2483(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अट्ठाईस) का.आ. 5702(अ) जो दिनांक 7 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 608(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनतीस) का.आ. 3513(अ) जो दिनांक 7 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 221(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीस) का.आ. 3514(अ) जो दिनांक 7 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 607(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकतीस) का.आ. 6014(अ) जो दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 फरवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 652(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बत्तीस) का.आ. 4421(अ) जो दिनांक 11 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 7 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1811(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तैंतीस) का.आ. 4949(अ) जो दिनांक 16 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2166(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौतीस) का.आ. 2173(अ) जो दिनांक 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पंगोलखा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(पैंतीस) का.आ. 2172(अ) जो दिनांक 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बार्सी रोडोडेंड्रोन अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(छत्तीस) का.आ. 2171(अ) जो दिनांक 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा फैम्बोंगलो वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(सैंतीस) का.आ. 2170(अ) जो दिनांक 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मेनम वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(अड़तीस) का.आ. 2169(अ) जो दिनांक 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा शिंगबा रोडेंड्रोन अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(उनतालीस) का.आ. 2167(अ) जो दिनांक 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कीटम पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(चालीस) का.आ. 2168(अ) जो दिनांक 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्योंगनोसला अल्पाइन अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(इकतालीस) का.आ. 2166(अ) जो दिनांक 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कंचनजंघा पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(बयालीस) का.आ. 5693(अ) जो दिनांक 7 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा फैम्बोंगलो वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(तैंतालीस) का.आ. 5694(अ) जो दिनांक 7 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कीटम पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(चवालीस) का.आ. 3516(अ) जो दिनांक 7 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पंगोलखा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(पैंतालीस) का.आ. 4749(अ) जो दिनांक 31 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा शिंगबा रोडेंड्रोन अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(छियालीस) का.आ. 4748(अ) जो दिनांक 31 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्योंगनोसला अल्पाइन अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(सैंतालीस) का.आ. 1055(अ) जो दिनांक 11 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बीर मोती बाघ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(अड़तालीस) का.आ. 2277(अ) जो दिनांक 1 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बीर बुन्नेरहेरी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(उनचास) का.आ. 2275(अ) जो तथा दिनांक 1 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बीर गुरदियालपुरा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(पचास) का.आ. 2483(अ) जो दिनांक 21 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बीर भदसों वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(इक्यावन) का.आ. 2480(अ) जो दिनांक 21 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बीर दोसांझ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(बावन) का.आ. 2638(अ) जो दिनांक 5 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अबोहर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(तिरपन) का.आ. 3313(अ) जो दिनांक 26 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बीर ऐशवान वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(चौवन) का.आ. 3597(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा टखनी-रेहमापुर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(पचपन) का.आ. 4204(अ) जो दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कथलौर-कुशलिया वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(छप्पन) का.आ. 350(अ) जो दिनांक 6 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बीर महस वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(सतावन) का.आ. 839(अ) जो दिनांक 16 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा झाझर-बचौली वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(अठावन) का.आ. 840(अ) जो दिनांक 16 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नांगल वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(उनसठ) का.आ. 1568(अ) जो दिनांक 15 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरिके वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(साठ) का.आ. 4446(अ) जो दिनांक 12 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बीर गुरदियालपुरा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(इकसठ) का.आ. 3144(अ) जो दिनांक 14 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बीर मोती बाघ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11357/17/24]

(3) लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 7क के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि.756(अ) जो दिनांक 18 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 2024 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के उपबंध, जहां तक वे लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की क्रम सं. 28 और अनुसूची में तत्संबंधी प्रविष्टियों से संबंधित हैं, प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11358/17/24]

(4) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उप-धारा (2) के अंतर्गत वन्य जीव (संरक्षण) नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम, 2023 जो दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 5408(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11359/17/24]

(5) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 81(अ) जो दिनांक 5 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिनके द्वारा दिनांक 31 अक्तूबर, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4751(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11360/17/24]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): माननीय सभापति महोदय, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत गृह मंत्रालय, असम राइफल्स, सूबेदार मेजर (धार्मिक

शिक्षक), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2023 जो दिनांक 6 जनवरी, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 201 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 11361/17/24]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 913(अ) जो दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'कटिंग, मेकिंग या वेल्डिंग के लिए उपयोग की जाने वाली औद्योगिक लेजर मशीनों' पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को, डीजीटीआर द्वारा जारी नए अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 915(अ) जो दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और ओमान से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'कम से कम एक तरफ लेमिनेशन के साथ जिप्सम बोर्ड/टाइल्स' पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को, डीजीटीआर की सिफारिश पर पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 918(अ) जो दिनांक 27 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'व्हील लोडर' पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को,

डीजीटीआर द्वारा जारी नए अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 928(अ) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 अक्तूबर, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 782(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 41(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'मेटा फेनिलीन डायमाइन' पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को, डीजीटीआर द्वारा जारी सनसेट रिव्यू अंतिम निष्कर्षों के अनुसार पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 11362/17/24]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 904(अ) जो दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 13 अक्तूबर, 2021 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 734(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 909(अ) जो दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 328(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 925(अ) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 929(अ) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 904(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 40(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 11363/17/24]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 1(अ) जो दिनांक 1 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 584(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 2(अ) जो दिनांक 1 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 492(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 42(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 584(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 11364/17/24]

(4) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 11(अ) जो दिनांक 3 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि्. 666(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11365/17/24]

(5) संघ राज्य-क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 12(अ) जो दिनांक 3 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 710(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 11366/17/24]

(6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 30, 30क, 41,41क, 53, 54, 56, धारा 98 की उप-धारा (3) और धारा 158 की धारा उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 157 के अंतर्गत सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (पहला संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 923(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 11367/17/24]

(7) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.5492(अ) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) अधिसूचना संख्या 01/2024-सी.शु.(एन.टी.), दिनांक 4 जनवरी, 2024 जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की विनिमय दर को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ.177(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) अधिसूचना संख्या 04/2024-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 18 जनवरी, 2024 जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की विनिमय दर को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) अधिसूचना संख्या 90/2023-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 7 दिसम्बर, 2023 जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की विनिमय दर को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ.5350(अ) जो दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) अधिसूचना संख्या 92/2023-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की विनिमय दर को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) अधिसूचना संख्या 93/2023-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की विनिमय दर को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 11368/17/24]

(8) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) (सातवां संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/161 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2023 जो दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी- एनआरओ/जीएन/2023/162 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ((वैकल्पिक निवेश निधियां) (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 5 जनवरी, 2024 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी- एनआरओ/जीएन/2024/163 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 11369/17/24]

(9) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर संशोधन (28वां संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.898(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर संशोधन (29वां संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.900(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर संशोधन (30वां संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.908(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 11370/17/24]

(10) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 10(अ) जो दिनांक 3 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 673(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 1(अ) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसके द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नई दिल्ली में माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ नई दिल्ली में गठित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(11) अधिसूचना संख्या फा.सं.370142/43/2023-टीपीएल, दिनांक 28 दिसंबर 2023 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिसके अंतर्गत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-ण के अंतर्गत उप-धारा (4) के दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 11371/17/24]

(12) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन-वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालय/विभाग-(2022 का संख्यांक 4)-संघ सरकार (निष्पादन लेखापरीक्षा)।

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन- संघ सरकार (सिविल)- केंद्रीय स्वायत्तशासी निकाय-(2023 का संख्यांक 25)।

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2022-2023 के लिए प्रतिवेदन-संघ सरकार-रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे।

[Placed in Library, See No. LT 11372/17/24]

(13) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ, यूनीवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ, यूनीवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11373/17/24]

(14) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 11374/17/24]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Silk Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Silk Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2022-2023.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 11375/17/24]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अधिसूचना संख्या (एन-12011/01/2023-पीएंडडी) नई दिल्ली जो दिनांक 12 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के 01.07.2022 से 30.06.2024 तक की अवधि के लिए विस्तार को अधिसूचित किया गया है।

(दो) अधिसूचना संख्या यू-11/13/2/2019-मेडिकल I जो दिनांक 13 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा प्रयोक्ता शुल्क की दर और अन्य विवरणों को अधिसूचित किया गया है क्योंकि केन्द्र सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अथवा कर्मचारी राज्य बीमा योजना अस्पतालों में अल्प उपयोग में लाए जा रही चिकित्सा सेवाओं का आयुष्मान भारत/प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों द्वारा कतिपय शर्तों के अध्यधीन अन्य लाभार्थियों के रूप में लाभ उठाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

(तीन) अधिसूचना संख्या एन-12/13/1-2016-पीएंडडी जो दिनांक 15 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना में आशोधन, जिसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 06.09.2016 को आयोजित 169वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 26.05.2005 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, को अधिसूचित किया गया है।

(चार) अधिसूचना संख्या एन-12/13/1-2019-पीएंडडी जो दिनांक 22 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 73घ में उल्लिखित योजना के प्रयोक्ता प्रभारों की दर और अन्य ब्यौरों को अधिसूचित किया गया है।

(पाँच) अधिसूचना संख्या एन-12/13/1-2016-पीएंडडी जो दिनांक 2 दिसंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना में कतिपय आशोधनों को अधिसूचित किया गया है।

(छह) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारी और सेवा की शर्तें) विनियम, 2023 जो दिनांक 19 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेड-24/14/1/2020-डीपीसी(ई.आई.) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) अधिसूचना संख्या एन-12/13/1-2019-पीएंडडी जो दिनांक 16 नवंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा ईएसआईसी अधिकारियों को भारत में सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में कानूनी मुकदमा दायर करने के लिए अधिकृत करने हेतु अधिसूचित किया गया है।।

(आठ) का. आ. 2059(अ) जो दिनांक 24 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.615(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का. आ. 3215(अ) जो दिनांक 2 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.615(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11376/17/24]

(3) (एक) दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11377/17/24]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपुर्णा देवी): माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ।

(1) अधिसूचना संख्या एनसीटीई-सीडीएन016(13)/19/2021-सीडीएन-एचक्यू, जो दिनांक 20 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की चार क्षेत्रीय समितियों के लिए सदस्यों को नामित किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 11378/17/24]

(2) (एक) समग्र शिक्षा (महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद), महाराष्ट्र के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा (महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद), महाराष्ट्र के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11379/17/24]

(4) (एक) समग्र शिक्षा (हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा सोसायटी), हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा (हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा सोसायटी) के वर्ष 2022-2023 के वर्ष कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11380/17/24]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी प्रतिमा भौमिक): माननीय सभापति महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री ए. नारायणस्वामी की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ।

(1) (एक) डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11381/17/24]

(3) (एक) बाबू जगजीवन राम नैशनल फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाबू जगजीवन राम नैशनल फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11382/17/24]

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर): माननीय सभापति महोदय, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 11383/17/24]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा): माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) (एक) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11384/17/24]

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा): माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, एस.ए.एस नगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11385/17/24]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी प्रतिमा भौमिक): माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ।

(1) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11386/17/24]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक

लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11387/17/24]

(3) (एक) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद, प्रयागराज के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद, प्रयागराज के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11388/17/24]

(5) (एक) मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11389/17/24]

(7) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ताडेपल्लीगुडेम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ताडेपल्लीगुडेम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11390/17/24]

(9) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11391/17/24]

(11) (एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर के वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर के वर्ष 2022-23 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11392/17/24]

(13) (एक) राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, राँची के वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, राँची के वर्ष 2022-23 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11393/17/24]

(15) (एक) विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2022-23 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11394/17/24]

(17) (एक) झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11395/17/24]

(19) (एक) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11396/17/24]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD): Sir, with your kind permission, I rise to lay on the Table a copy of the Report (Hindi and English versions) of the Comptroller and Auditor General of

India – Union Government (Commercial) – Compliance Audit of Activities of Selected CPSEs (No. 15 of 2023) for the year ended March, 2022 under Article 151(1) of the Constitution.

[Placed in Library, See No. LT 11397/17/24]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR): Hon. Chairman, Sir, with your permission, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Education Society for Tribal Students, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Education Society for Tribal Students, New Delhi, for the year 2022-2023.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 11398/17/24]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AYUSH (DR. (PROF.) MAHENDRA MUNJAPARA): Chairman Sir, with your kind permission, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New

Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi, for the year 2022-2023.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 11399/17/24]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi, for the year 2022-2023.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 11400/17/24]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Naturopathy, Pune, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Naturopathy, Pune, for the year 2022-2023.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 11401/17/24]

(7) (i) A copy each of the Annual Reports (Hindi and English versions) of the Rashtriya Mahila Kosh, New Delhi, for the years 2018-2019 to 2022-2023.

(ii) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Mahila Kosh, New Delhi, for the years 2018-2019 to 2022-2023.

(8) Five statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 11402/17/24]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTINIG (DR. L. MURUGAN): Respected Sir, with your kind permission, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the Annual Reports (Hindi and English versions) of the National Fisheries Development Board, Hyderabad, for the years 2006-2007 to 2022-2023.

(2) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Fisheries Development Board, Hyderabad, for the years 2006-2007 to 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11403/17/24]

———

12.06 hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (Vote on Account) Bill, 2024, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 7th February, 2024 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(ii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation Bill, 2024, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 7th February, 2024 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(iii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Jammu and Kashmir Appropriation (No.2) Bill, 2024, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 7th February, 2024 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to

state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(iv) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Jammu and Kashmir Appropriation Bill, 2024, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 7th February, 2024 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(v) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Finance Bill, 2024, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 7th February, 2024 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

———

12.07 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE

156th and 157th Reports

DR. SANGHAMITRA MAURYA (BADAUN): Respected Sir, with your permission, I rise to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Health and Family Welfare:-

(1) 156th Report on Review of National Ayush Mission.

(2) 157th Report on Quality of Medical Education in India.

_____

12.08 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने विषय के अनुमोदित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं।

… (व्यवधान)

(i) Regarding four-laning of national highway and conversion of state highways into national highways in Tiruchirappalli Parliamentary Constituency

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (TIRUCHIRAPPALLI): I would like to place certain below mentioned important long pending demands in respect of Tamil Nadu and particularly from my Tiruchirappalli Lok Sabha Constituency:-

i) Upgradation of 2-lane national highway from Tiruchirappalli – Pudukottai Karaikudi – Devakottai – Devipattinam into 4-lane NH [130 km. approx];

ii) Upgradation of Thanjavur – Pudukottai – Aranthangi – Karaikudi – Kallal – Kalayarkoil – Maravamangalam – Ilayangudi – Paramakudi – Mudukulathur – Sayalkudi Road (SH 29) into National Highway (240 kms. approx); iii) Upgradation of Pudukottai – Aranthangi – Avudayarkoil – Mimisal Road (SH 26) into National Highway (70 kms. approx); iv) Upgradation of Aranthangi – Nagudi – Kattumavadi Road (SH 145) into National Highway; and v) Upgradation of Musiri – Kulithalai – Pudukottai – Alangudi – Peeravoorani – Sethupava Sathiram (SH 71) into

* Treated as laid on the Table.

National Highway (160 kms. approx). Please consider the above demands on top priority.

(ii) Regarding refund of money to people who invested in Sahara Group

SHRI SHYAM SINGH YADAV (JAUNPUR): Deposits of 10 crore individuals are stuck in the 4 cooperative societies of Sahara group. There has been a lack of initiatives by the Government in getting their refunds back in a timely and secure manner. On 30.03.2023, The Hon'ble Minister of Home Affairs assured that Government would initiate process to return their investments with interest in the next 3-4 months. On 18.07.2023, Union HM launched CRCS-Sahara Refund Portal. HM assured that 1.78 crore investors will get refund in first phase within 45 days. HM transferred Rs. 10,000 each to 112 depositors during the launch. But there is a capping of refund at Rs. 10,000 irrespective of the value of investment which has no rationale. There is no clarity on when the first phase will be completed. 99.99% of investors have not got their money back. Claims are being rejected on frivolous grounds. There is heightened sense of insecurity on the part of investors who are spread across 27 states who fear that their money would be transferred to Consolidated Fund of India in the name of unclaimed funds. The portal is yet to take off. I request that the Government should look into the matter and expedite the process.

(iii) Regarding revival of match factory in Dhubri, Assam

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): I wish to draw the attention of the House concerning Match Factory in Dhubri, Assam which has remained inactive since 1997. The factory, established in 1925 was once a thriving industrial unit, but was sold by ITC Limited to another company for Rs 74.25 crore, much below the estimated worth of Rs 200 crore plus. The factory was once a significant source of employment and pride for the region. The sale has triggered protests among the local community and former workers have been demanding to preserve the heritage and revival the factory for years. Allegations have surfaced that the deal was undervalued and done clandestinely to evade government revenue with the actual amount paid by the buyer being much higher.

The people of Dhubri are deeply concerned about the use of the land and have appealed to the buyer to consider setting up another industry. The government should intervene and explore alternative proposals for the revival of the match factory which will generate employment opportunity and contribute to the socio-economic development of the region. I urge upon the Hon'ble Minister of Labour and Employment to take cognizance of the matter and initiate an investigation to address the matter.

(iii) Need to constitute a committee to control shrimp prices in the country

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): For the last few years, Shrimp farming in the country particularly in Andhra Pradesh, has been suffering from unusual series of crises.

India produces about 9 lakh tons of shrimp every year and earning and is contributing $8 billion to the Indian economy. Indian shrimp farming and export market constitutes about Rs. 44,000 crores. Surat is the 3rd largest Shrimp Export Market in the country. China is the biggest importer of Shrimp from India followed by US and EU markets. In spite of Government's discounts and subsidies, there is no much growth in the business.

The aqua farmers are reeling under losses due to meagre support from the Government and unfavourable polices being formed by the Centre and State Governments. Shrimp farmers are mulling to go on culture holiday subsequent to slash in electricity subsidy and skyrocketing input costs, couple with an unexpected plunge in the prices of their produce.

Processing units have stopped procuring stocks as exporters are not paying the MSP prices fixed by the Government.

The fishing industry in Andhra Pradesh is facing problems as a result of syndicate formed by the shrimp processing and exporting companies to control the prices.

In view of the above, I suggest that the Government constitute a body in the lines of National Egg Coordination Committee to control shrimp prices in the Country.

(iv) Regarding restoration of Old Pension Scheme

SHRI VINAYAK BHAURAO RAUT (RATNAGIRI-SINDHUDURG): Old Pension Scheme (OPS) for Govt. employees was scrapped in January, 2004 and in its place New Pension Scheme (NPS) was introduced for employees recruited on or after January 1, 2004. Since then, Govt. employees and their unions are protesting that NPS is discriminatory against employees recruited after January 1, 2004 and they will be left in lurch after retirement. States Govt. Employees are also demanding restoration of OPS. Some of the States have restored OPS. Several Central Government Employees and State Government Employees Unions held massive protest rallies of employees in Delhi in August and October, 2023, respectively demanding restoration of OPS and submitted Memoranda to the Hon'ble President and Prime Minister in support of their demand. Maharashtra State Govt. employees including Teachers of Govt. Schools are also demanding for restoration of OPS. Keeping in view the genuine demand of Government employees, I urge upon the Central Government to consider their demand favourably.

(v) Need to introduce passenger train services in Kendrapara district, Odisha

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Even after more than 75 years of our Nation's Independence, people of my constituency, Kendrapada, have not yet seen passenger train in their soil. I had raised the issue that there are no passenger train services in Kendrapara several times in this August House. However, I got the reply from the Ministry of Railway that the Kendrapara Road railway station is just 5 km from Cuttack, so it is not operationally feasible for any rail connectivity. I was then assured by the Hon'ble Minister for a clarification on this in this House itself. I even wrote to the Parliamentary Committee on Government Assurances but, have not received any response yet. I want to clarify that 'Kendrapara Road' (Railway Station in Cuttack District) is not in Kendrapara district. And no passenger train services are operational even when it is 60 km away from Cuttack. The people of the district are yet to get passenger train services for the employment of youth, for revenue generation and for the development of Kendrapara. Thus, I along with the response of the Minister of Railways, demand passenger train services immediately on behalf of the people of Kendrapara Parliamentary Constituency, Odisha.

———

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सर, मुझे एक मिनट के लिए बोलने दीजिए ।... (व्यवधान) मैंने एड्जॉर्नमेंट मोशन दिया था ।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, इन्हें बस एक मिनट बोलने दीजिए ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ओ.के. ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि आज पूरा दिन भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के लोगों के जीवन पर उसके प्रभाव के बारे में श्वेत पत्र पर विस्तृत चर्चा होगी । इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सभा द्वारा समय का आवंटन किया गया है । यदि सभा सहमत हो तो चार घंटे का समय आवंटित कर दिया जाए ।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, समय और बढ़ा दिया जाए ।... (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, ठीक है । आगे कर लेंगे ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आगे कर देंगे ।

आइटम नंबर 24, माननीय वित्त मंत्री जी ।

12.09 hrs

MOTION UNDER RULE 342

White Paper on Indian Economy

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I rise to move:

> "That this House do consider the White Paper on the Indian Economy and its impact on lives of the people of India."

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, आप अपना सबस्टिट्यूट मोशन पेश करें।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I would like to move the Substitute Motion. I may be allowed to read the Motion. … (*Interruptions*) I will speak afterwards. Let me place the Motion on record. Under Rule 342 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I am moving the Substitute Motion. That for the original motion, the following be substituted, namely:-

> "Having considered the white paper this house disapproves the contents of the white paper on the following grounds.
>
> 1) This is a political attempt to ignore the valuable efforts of the previous UPA Govt and the contributions of the renowned economists Scientists and experts of the country during the period 2004-2014.
>
> 2) After 10 years of NDA govt in office, making baseless allegations against the pervious govt. is unfair, improper, unjust and against all basic tenets of parliamentary democracy.
>
> 3) During the 10 years of NDA govt country had experienced exponential growth of unemployment, inflation resulting price rise of essential

commodities, and increased actual poverty. Shifting the blame to the pervious govt for the abysmal failures of this govt. and thereby evading it's own responsibility is not proper.

4) NDA Govt in power for 10 years have devastated the country's economy and agriculture sector, abetted crime against women and committed grave injustice to Minorities."

. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, आपको बाद में बोलने का मौका मिलेगा।

… (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, secondly … (*Interruptions*) Sir, only three more points. … (*Interruptions*) Sir, I am not being allowed to read. … (*Interruptions*) Madam has already read the Motion. … (*Interruptions*) I may be allowed. … (*Interruptions*) There are only three more points left. … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, first of all he can only read the Substitute Motion. … (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: I am only reading it. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपको इस विषय पर बोलने के लिए पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।

… (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, there are only three more points left. … (*Interruptions*)

श्री प्रहलाद जोशी: अध्यक्ष जी, यही कम्युनिस्ट लोग हैं, जिन्होंने मनमोहन सिंह जी से अपनी सपोर्ट को विदड्रा किया था।... (व्यवधान) आप ही लोग हैं, जिन्होंने मनमोहन सिंह जी से सपोर्ट को विदड्रा किया था।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको मौका दूंगा।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: No problem. ... (*Interruptions*) We are with INDIA. ... (*Interruptions*) We are expressing our points. ... (*Interruptions*)

Secondly, after 10 years ... (*Interruptions*) Sir, I want it to come on record. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मोशन मूव करने के लिए मोशन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब डिटेल चर्चा होगी, तो आपको पर्याप्त अवसर दूंगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, under Rule 342, I move the following Substitute Motion.

"That this House disagrees with the conclusion reached by the White Paper on Indian Economy."

It is a total fraud on the Indian public. … (*Interruptions*) I move the Substitute Motion. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Motions moved:

"That this House do consider the White Paper on the Indian Economy and its impact on lives of the people of India."

"Having considered the white paper this house disapproves the contents of the white paper on the following grounds.

1) This is a political attempt to ignore the valuable efforts of the previous UPA Govt and the contributions of the renowned economists Scientists and experts of the country during the period 2004-2014.

2) After 10 years of NDA govt in office, making baseless allegations against the pervious govt. is unfair, improper, unjust and against all basic tenets of parliamentary democracy.

3) During the 10 years of NDA govt country had experienced exponential growth of unemployment, inflation resulting price rise of essential commodities, and increased actual poverty. Shifting the blame to the pervious govt for the abysmal failures of this govt. and thereby evading it's own responsibility is not proper.

4) NDA Govt in power for 10 years have devastated the country's economy and agriculture sector, abetted crime against women and committed grave injustice to Minorities."

and

"That this House disagrees with the conclusion reached by the White Paper on Indian Economy."

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, क्या आप प्रस्तावना रखना चाहती हैं?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष जी, एक मिनट बोलने दीजिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको बोलने का मौका मिलेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, thank you very much for giving me this opportunity to make my opening remarks regarding the White Paper. This is a White Paper on the Indian economy and its impact on lives of the people of India. … (*Interruptions*)

Sir, the White paper has been laid on the Table by the Government after 10 full years of pulling out the Indian economy, which was in a state of 'fragile 5', to reach the stage of top five economy and on the verge of reaching top three position. … (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: It is a false claim. … (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: It is a statement laid with responsibility so that the records of the Lok Sabha and the Rajya Sabha have the factual information on the economy. … (*Interruptions*) And that record shall be a record for our posterity, for our future, for entire India's youth so that they know what effort it took for a Prime Minister with a vision to restore India to its glory. … (*Interruptions*) And in the last 10 years that is exactly what has happened. … (*Interruptions*) And because it is my opening statement and because there shall be a discussion in the House, I shall speak more elaborately in my reply in the evening. … (*Interruptions*) But I would like to state a few facts to start the debate and put some facts again before the debate commences.

In the first two decades of this millennium, there are strange coincidences which are comparable. Both the decades suffered because of some serious global crises. There are stark stories. When there is a crisis, how a Government

with a feeling of the nation will have to pull the economy up in spite of it getting affected by such a stark, very difficult challenging crisis?

Ten years of one Government with some crisis and ten years of a different Government with a different crisis, the comparison shown in the White Paper clearly says, if the Government handles it with true sincerity, transparency, and putting the nation first, the results are there for everybody to see. Equally, when you do not put the nation first, when you put your first family first, when you have other considerations first, and then you put transparency, the results are out there for you to see. So, the picture of what happened after 2008 when there was a global financial crisis and what happened post-COVID-19 shows clearly that if the intent of the Government is sincere, अगर नीयत और नियम दोनों सही हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा ।... (व्यवधान) लेकिन, आपकी नीयत साफ नहीं थी और आपकी कार्यवाही भी साफ नहीं थी।... (व्यवधान) देश को जिस गम्भीर अवस्था में छोड़ कर आप चले गए, उसे सही करने के कार्य में माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के डेडिकेशन की वज़ह से आज देश उभर कर आ रहा है और इसका पूरी दुनिया में सम्मान हो रहा है ।... (व्यवधान)

सर, इसमें हमें दो उदाहरणों को देखना चाहिए । मैं एक सीरियस उदाहरण को ले रही हूं । ग्लोबल फाइनैंशियल क्राइसिस, 2008 के बाद, इकोनॉमी कोविड-19 जैसी उतनी बुरी नहीं थी । With the benefit of hindsight, I confess, with the benefit of hindsight, ग्लोबल फाइनैंशियल क्राइसिस के समय कोविड-19 जैसा उतना भयंकर और गम्भीर क्राइसिस नहीं था ।... (व्यवधान) It was not as serious as COVID-19. ... (*Interruptions*) But still, I would want to say that it was a crisis and the Government should have handled it with sincerity and transparency. They started something else and they ended up in something else. ... (*Interruptions*)

Sir, this kind of a running commentary does not help anybody. If they have the courage that they have done a good work, they should listen and confront. … (*Interruptions*) If they have the courage, they should listen and reply. … (*Interruptions*) If they have the courage, they should listen to what I am saying and respond.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपके पास बोलने का मौका आएगा, आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: They do not want to listen. … (*Interruptions*) उनमें सुनने की ताकत नहीं है, इसलिए मुझे यह बात नहीं कहने दे रहे हैं ।… (व्यवधान) लेकिन फिर भी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इस पर बात करूंगी।… (व्यवधान)

सर, जो ग्लोबल फाइनैंशियल क्राइसिस को हैंडल नहीं कर सके, वे आजकल यह लेक्चर दे रहे हैं कि इकोनॉमी को कैसे हैंडल करना है।… (व्यवधान)

सर, मैं बोल रही हूं कि ग्लोबल फाइनैंशियल क्राइसिस के समय भारत के इंटेरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो करना चाहिए था, वे सब कुछ नहीं किए गए, मगर उसके बाद भी स्कैंडल्स के ऊपर स्कैंडल्स चलते रहे।… (व्यवधान) उसके कारण देश को बहुत गम्भीर अवस्था में रख कर चले गए। अगर वे कंटीन्यू करते तो भगवान जाने इस देश की आज क्या हालत होती।… (व्यवधान) Sir, that was one story.

सर, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सरकार ने भारत देश को नहीं बचाया ।… (व्यवधान) मगर कोविड के बाद माननीय देश को कैसे संभाला, यह हमें पता है। … (व्यवधान) सबको वैक्सीन मुफ्त में दी और देश को प्रोटेक्ट किया। … (व्यवधान) वह कैसे हुआ। … (व्यवधान)

महोदय, मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैं इसको रीएंफसाइस कर रही हूँ कि यह एक सीरियस डॉक्यूमेंट है, इसमें सीरियस विषय है, इसको गंभीरता से लें। मेरी आवाज़ बंद करने की कोशिश करेंगे, तो वे फेल हो जाएंगे ही, मगर इस सच्चाई का सामना करना इनकी पार्टी के लिए जरूरी है । …

(व्यवधान) ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वर्सेज़ कोविड मैंने बोल दिया, शाम को डिटेल में भी बोलूंगी, मगर एक दूसरा उदाहरण देना चाहती हूँ। इस देश में 12 दिन दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स का हाल क्या हुआ था यह पूरी दुनिया जानती है। ... (व्यवधान) पूरी दुनिया ने देखा कि टॉयलेट नहीं बन पाए, फ्लैट्स नहीं बन पाए, गेम्स विलेज नहीं बन पाए, करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ। ... (व्यवधान) कॉमनवेल्थ गेम्स का इतना फ्लॉप शो हुआ, पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हुई। ... (व्यवधान) दिल्ली में ही 12 दिनों के कॉमनवेल्थ गेम्स के द्वारा पूरे विश्व में हमारी बदनामी हुई। ... (व्यवधान) मगर आज देखिए, जी-20 के द्वारा पूरे भारत देश में आयोजन किया गया। किसी एक राज्य को छोड़ा नहीं गया और कहा गया कि आप भी होस्ट करो, आपके चीफ मिनिस्टर भी उसमें बैठें और अपने लोकल प्रोडक्ट्स भी विदेशी मेहमानों को दिखाओ, अपना टूरिज्म बढ़ाओ। यह सब कर के पूरे देश को साथ ले कर जी-20 को इतने शानदार तरीके से मोदी जी ने आयोजित किया कि देश का सम्मान विदेश में बढ़ा है, न कि बर्बाद हुआ है।... (व्यवधान) इन दोनों का कम्पैरिज़न भी कीजिए। यह वाइट पेपर उसके ऊपर भी बात कर रहा है।

सर, एक विषय मैं और बोलना चाहती हूँ। यह मैंने दो उदाहरण देश के सम्मान के विषय में दिए हैं, इकोनॉमी के मैनेजमेंट के विषय में दिए हैं। सर, मैं विस्तार से और गंभीरता से एक विषय बोलना चाह रही हूँ, उदाहरण के तौर पर कोल स्कैम लीजिए मैं तीन हिस्से में इसका उत्तर देने वाली हूँ। सामने रख रही हूँ, कोल स्कैम का पूरा डायग्नॉसिस आपको समझना चाहिए। ... (व्यवधान) उसका करेक्टिव मेज़र्स कितना होना चाहिए, उसके ऊपर बात कर रही हूँ। ... (व्यवधान) उसका नतीजा क्या हुआ, मैं वह भी बोलना चाहती हूँ। सर, यूपीए सरकार ने कोल स्कैम के द्वारा भयंकर नुकसान किया। ... (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्टेटमेंट में यह कहा "The allocation method itself was wrongly set up." यह इल्लिगल बैक डोर रूट के द्वारा हुआ है। I am quoting now, 'The hands of private companies for commercial use was seen." क्योंकि पीछे के दरवाज़े से प्राइवेट कंपनीज़ को बेनिफिट दिलाने के लिए काम किया गया। ... (व्यवधान) मैं सुप्रीम कोर्ट के विषय में इसमें जोड़ रही हूँ, मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जोड़ रही हूँ, उसमें गुटखा कंपनी को, गुटखा

तैयार करने वाले को भी इन्होंने लाइसेंस दिलवाए। … (व्यवधान) इन्होंने इतना गंभीर काम किया है। … (व्यवधान)

सर, सीएजी की रिपोर्ट में कोल स्कैम के ऊपर यह बोला गया कि 1.86 लाख करोड़ रुपये का भारत को नुकसान पहुंचाया गया।

सर, सी.ए.जी. की रिपोर्ट में कोल स्कैम के ऊपर यह बोला गया कि 1.86 लाख करोड़ रुपये का भारत का नुकसान पहुंचाया। इनके कोल स्कैम की वजह से 1.86 लाख करोड़ रुपये का नुकसान भारत देश को भुगतना पड़ा।… (व्यवधान)

सर, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस सिचुएशन को इतना गंभीरता से लेकर 214 कोल ब्लॉक्स का लाइसेंस रद्द करवाया।… (व्यवधान) उसने रद्द कर दिया, सिस्टम बंद हो गये, सफाई हो गया, मगर उससे देश का क्या हुआ? … (व्यवधान) देश के लिए उसका असर कितना हुआ? आज आप उसका असेसमेंट देख लीजिए - जॉब लॉस हुआ, उसके कारण इस देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आया, एन्सिलरी इंडस्ट्रीज जैसे एमएसएमई के छोटे लघु उद्योग पूरी तरह से ठप पड़ गए।… (व्यवधान) इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोयला इम्पोर्ट करना पड़ा। देश में कोल भरपूर है, फिर भी इम्पोर्ट करना पड़ा।… (व्यवधान) इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद हो गया।

माननीय स्पीकर सर, आपको भी याद होगा कि उस जमाने के पत्रकार लोग कितने लिखते थे कि थर्मल कोल प्लान्ट में 3 दिन का स्टॉक है, चौथे दिन के लिए कोल नहीं है, कैसे प्रोड्यूस करेंगे। उस समय तक स्टॉक आएगा या नहीं आएगा, ऐसे टेंशन में उस जमाने में पावर प्लान्ट्स चलते थे।… (व्यवधान) स्टॉक नहीं है, कोल नहीं आ रहा है। 214 कोल ब्लॉक्स का लाइसेंस बंद हो गया। आप देश कैसे चलाएंगे? … (व्यवधान) उसका नतीजा देख लीजिए। There was loss in revenue for coal producing States. आज ये लोग क्रॉकोडाइल टीयर्स बहा रहे हैं। … (व्यवधान) ये सब पूर्वी भाग में हैं, चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, इन सभी स्टेट्स का रेवेन्यू लॉस हुआ।… (व्यवधान) इनकी जिम्मेदारी इसमें कुछ है या नहीं? उसके लिए इन्होंने क्या काम किया? वहीं माननीय प्रधानमंत्री

जी ने उधर पाइपलाइन गैस का कनेक्शन दिया। बरौनी रिफाइनरी का पुनर्निमाण किया। ये सब काम हम कर रहे हैं। मगर ये तो सत्यानाश करके गए।... (व्यवधान)

सर, हमने क्या करेक्टिव मेज़र्स किये, हमारे करेक्टिव मेज़र्स क्या है? हम ट्रांसपैरेंट तरीके से क्या कर रहे हैं – हमने कोल माइन्स स्पेशल प्रोविज़न एक्ट वर्ष 2015 में पास करवाया। एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट के तहत वर्ष 2015 में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी एस्टैब्शि हुआ। 100 परसेंट एफडीआई ओपन करके इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट में आने के लिए हर फैसिलिटेशन किया, जिससे इन्वेस्टमेंट आ रही है।

सर, कमर्शियल कोल माइनिंग, क्योंकि भारत देश को आत्मनिर्भर रहना है, इसीलिए कोल माइनिंग को कमर्शियली करने के लिए ओपन पॉलिसी करवाया। उस पॉलिसी के तहत वर्ष 2020 से ऑक्शन में 9 बार कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन हुआ, न कि पीछे के दरवाजे से मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरी बहन, मेरे परिवार को दिया।... (व्यवधान)

सर, आज ये हमें क्रोनी कैपिटलिज्म पर ज्ञान देते हैं। यह भी सोचना चाहिए, आपने कोयला को राख बनाया, जो कोयला भारत देश में है, उसको राख बनाया। हमने अपने नीतियों के तप से कोयले को हीरा बना दिया।... (व्यवधान)

सर, आज इनको सुनना चाहिए, थोड़ा सुनना चाहिए। आप सुनिए। मैं इंग्लिश में भी बोल रही हूं और हिन्दी में भी बोल रही हूं। आप सुनिए।... (व्यवधान) इससे आपके अच्छा होगा। मेरी हिंदी भी थोड़ी एंटरटेनिंग है। ... (व्यवधान) हल्का सा ब्रेक भी लीजिए। ... (व्यवधान) हमारे तप से कोयले से जो हीरा बना है, आज वही हीरा खनिज क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के रूप में अपनी चमक फैला रहा है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की कहानी मैं बोलने वाली हूं। ... (व्यवधान)

सर, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड हमारे कानून से स्टैब्लिश हुआ। उसके ऊपर पहले किसी ने नहीं सोचा था। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से 84,900 करोड़ रुपये कलेक्शन सभी स्टेट्स में हुआ है। यह केंद्र सरकार का नहीं, सभी स्टेट्स में है। ... (व्यवधान) वह डिस्ट्रिक्ट में रहता है। इसके कारण बहुत सारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स भी आज बेहतरीन और बेटर टाइम देख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट

मिनरल फंड के कलेक्शन की जानकारी मैं देना चाहती हूं, क्योंकि वह हमारी सरकार के द्वारा हुआ, पब्लिक के लिए हुआ, आम जनता के लिए हुआ, आदिवासी-वनवासी क्षेत्र में हुआ, उस जनता को उससे फायदा हो रहा है, इसीलिए मैं बोल रही हूं। छत्तीसगढ़ में 12 हजार करोड़ रुपये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का कलेक्शन हुआ, झारखंड में 11 हजार 600 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ। … (व्यवधान) कर्नाटक में, जहां पैसा नहीं जाता है हमारे यहां से, कर्नाटक में 4,467 करोड़ रुपये कलेक्शन हुआ। … (व्यवधान) ओडिशा में 24,600 करोड़ रुपये कलेक्शन हुआ, राजस्थान में 8,730 करोड़ रुपये कलेक्शन हुआ है और मेघालय जैसे नार्थ-ईस्टर्न स्टेट में 90 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ। … (व्यवधान) मैं खुशी से बोल रही हूं। मैं आनन्द से एक विषय बोलती हूं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपके कई माननीय सदस्य इस पर अपने विचार रखेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी अपने विचार रखें और आप अपने विचार रखें। देश तय करेगा। माननीय वित्त मंत्री जी।

… (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण: सर, मैं एक विषय जरूर बोल सकती हूं। व्हाइट पेपर नहीं, एक विषय बोल सकती हूं। कांग्रेस कभी भी विपक्ष में जब बैठी है, वह एक हजार प्रश्न उठाती है। हम क्षमता से सब्र रखकर सुनते हैं। … (व्यवधान) मगर जब हम जवाब देने के लिए खड़े होते हैं, वे या तो वाक आउट करके भाग लेते हैं, नहीं तो इधर बैठकर हल्ला करते हैं। They do not have the courtesy to hear the replies. … (*Interruptions*) I challenge them. If they have the courage, let them sit down, hear, and reply to me. … (*Interruptions*) आप बैठकर सुनने के बाद जवाब दीजिए, डिस्टर्ब न करिए। … (व्यवधान) वरिष्ठ, युवा और फ्यूचर को बहुत बढ़िया बनाने के लिए जितना पोटेंशियल जिन लोगों में हैं, वे लोग भी अपने आप ऐसा रोल बनाते हैं कि चिल्लाते रहो, महिला हो, पुरुष हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई और हो, चिल्लाते रहो, क्योंकि इधर से सच्चाई आ रही

है। … (व्यवधान) हम सच्चाई बोल रहे हैं। …(व्यवधान) ये नहीं सुनेंगे।…(व्यवधान) ठीक है, मैं बोलती हूं। डीएमएफ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या है? यह तरीका नहीं है। आपको मौका मिलेगा, आप प्लीज बैठिए। वित्त मंत्री जी।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): ये …* बोल रही हैं। … (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : अध्यक्ष महोदय, …* अनपार्लियामेंटरी है, कम से कम करेक्ट करने दीजिए। …* अनपार्लियामेंटरी है, करेक्ट करने के लिए बोलिए। … (व्यवधान) डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड … (व्यवधान) छत्तीसगढ़ में 12 हजार करोड़ रुपये, झारखंड में 11 हजार 600 करोड़ रुपये, कर्नाटक 4 हजार 467 करोड़ रुपये, ओडिशा में 24 हजार 600 करोड़ रुपये, राजस्थान में 8 हजार 730 करोड़ रुपये, मेघालय में 90 करोड़ रुपये, इससे ग्राउंड में क्या फायदा हो रहा है? इसे भी हमें समझना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से केओनझर ओडिशा में डिजिटल डिसपेन्सरी बनाया गया। As a result, बेसिक हेल्थ केयर, टेली मेडिसिन कन्सलटेशन, फ्री मेडिसिन, ओडिशा के केओनझर डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है। … (व्यवधान) इनको क्या तकलीफ है? Chaibasa Model Anganwadi Centre construction डीएमएफ के फंड से हुआ, उसको मालन्यूर्टिशन एड्रेस करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से वेस्ट सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट में बढ़िया काम हो रहा है।

करेंट फाइनेन्शियल ईयर में डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन के विषय को समझ लीजिए। ये सब 900 मिलियन टन तक पहुंचा है, highest ever coal production भारत देश में इस साल होने वाला है। वर्ष 2023-24 में 900 मिलियन टन तक पहुंच गया है। आने वाले साल में 1 बिलियन टन्स तक पहुंच रही है। … (व्यवधान) Production does not include imports.

अध्यक्ष महोदय, जरा सुनने की क्षमता रखने के लिए आप बोलिए। … (व्यवधान) I will tell you in English. Do not jump to conclusions. In 2013-14, what was the production?

* Not recorded.

It was 567 million tons. I am saying that this year, it was 900 million tons and one billion tons of production will be there in the coming year.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: So, what?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: What are you talking? … (*Interruptions*) अध्यक्ष महोदय, प्रोडक्शन भारत देश में हुआ, इम्पोर्ट करने की नेसेसिटी नहीं होगी, फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट नहीं करना होगा, सिंपल इकोनॉमिक्स है। … (व्यवधान)

पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): इनको समझ में ही नहीं आया, थोड़ा ध्यान से सुन लो।

श्रीमती निर्मला सीतारमण: पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कभी भी बोलते हैं, प्राइवेट को इतना प्रोत्साहन दे रही हो, इनकी पॉलिसी के द्वारा पब्लिक सेक्टर को बेनिफिट भी नहीं पहुंचा, आपको मालूम है कि कहां पहुंचता था। यह क्या हो रहा है? … (व्यवधान) Sir, what is this going on?

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिए**।**

श्रीमती निर्मला सीतारमण: अधीर रंजन जी, प्लीज सुनो, … (व्यवधान) पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कोल इंडिया लिमिटेड 2013-14 से 2022-23 तक कैपिटल एक्सपेन्डिचर इससे पहले के जमाने की तुलना में 4.3 टाइम्स हुआ है, So, public sector is also prospering and is also additionally investing and is also producing. ये जितना भी … (व्यवधान) प्राइवेट सेक्टर के ऊपर … (व्यवधान)।

श्री गौरव गोगोई : सर, ये …* बोल रहे हैं।

श्रीमती निर्मला सीतारमण : सर, ये …* क्या है, क्या ये पार्लियामेंटरी है? Sir, please remove the word …*. Please expunge it. ये …* क्या चीज है? मैं एक और एग्जाम्पल देती हूं। मैं एक और एग्जाम्पल देती हूं। ये सहन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार के कार्यकाल की इतनी सच्चाई बाहर आ रही है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं।… (व्यवधान) इनके पूर्व अध्यक्ष जी भी बैठे हैं,

* Not recorded.

उनको इम्प्रेस करना है कि मैडम, हम अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं। ... (व्यवधान) ...* यही कह रहे हैं। ... (व्यवधान)

सर, मैं बैंक्स की कहानी जरूर बोलना चाहती हूं। ... (व्यवधान) व्हाइट पेपर में जो भी है, उसमें मैं एक विषय के बारे में कहना चाहती हूं। ... (व्यवधान) कांग्रेस पार्टी का एक चरित्र बैंकों के साथ खिलवाड़ करने के लिए है। ... (व्यवधान) एक चरित्र है। ... (व्यवधान) They constantly misused their powers and played with the banks. ये बोलते हैं कि नेशनलाइज़ हमने ही किया, मगर मैं तीन उदाहरण देती हूं। ... (व्यवधान) वर्ष 1976 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के श्री आर.के. तलवार चेयरमैन थे। वह बहुत ही रिस्पेक्टेड चेयरमैन थे। ... (व्यवधान) इमेरजेंसी के समय, क्योंकि इनकी पसंदीदा पार्टी को लोन नहीं दिया, इसके कारण उनको सीबीआई के द्वारा सताया गया। ... (व्यवधान) आर.के. तलवार एकदम इंटिग्रिटी के साथ क्लीन व्यक्ति थे। ... (व्यवधान) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे।... (व्यवधान) एकदम क्लीन इंटिग्रिटी में हाई रहने वाले इस व्यक्ति ने इनके किसी रिश्तेदार या दोस्त को लोन नहीं दिया इसलिए सीबीआई द्वारा इन्वेस्टिगेशन कराकर हटा दिया। They wanted to somehow remove him. ... (व्यवधान) वर्ष 1976 की ये एसबीआई के आर. के. तलवार की स्टोरी है। ... (व्यवधान)

इससे पहले वर्ष 1956 की स्टोरी लीजिए, मुंद्रा स्कैम। इसमें हरिदास मुंद्रा जी कोलकाता बेस्ड इंडस्ट्रीअलिस्ट थे, उनको उनकी कंपनी में एलआईसी द्वारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन दिया। ... (व्यवधान) ... (*Interruptions*) I am coming to that, Madam ... (*Interruptions*) I will speak on the White Paper ... (*Interruptions*) एलआईसी इन्वेस्टमेंट कमेटी को इन्फ्लुएंस करके वर्ष 1950 में 1.26 करोड़ शेयर्स डूबने वाली कंपनी में डलवा दिए। इसके कारण जब यह स्कैम बाहर आया तो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर को बलि का बकरा बनाकर हटा दिया। ... (व्यवधान) श्री टी.टी. कृष्णामाचारी जी को हटा दिया। ... (व्यवधान) वह फाइनेंस मिनिस्टर बलि का बकरा बने।

* Not recorded.

… (व्यवधान) हमें यह चरित्र मन में रखना चाहिए।… (व्यवधान) हमें कांग्रेस पार्टी का यह चरित्र मन में रखना चाहिए। … (व्यवधान)

सर, मैं फिर बोल रही हूं वर्ष 2004 से 2014 तक फोन बैंकिंग की व्हाइट पेपर में जो बात है, उसका यह अंग है। … (व्यवधान) व्हाइट पेपर के बारे में बात करने के लिए रिक्वेस्ट आ रही है और मैं व्हाइट पेपर के बारे में ही बात कर रही हूं। … (व्यवधान) फोन बैंकिंग में 'फोन घुमाओ, लोन पाओ' यही एडवर्टाइजमेंट यूपीए की थी। पेपर में नहीं आया … (व्यवधान) लेकिन 'फोन घुमाओ, लोन पाओ'। उस समय यही हुआ। … (व्यवधान) सिफारिशों की सौगात से ही एनपीए संकट शुरू हुआ। … (व्यवधान) एनपीए का संकट उस समय से ही शुरू हुआ और कोलेटरल भी नहीं था या आधा कोलेटरल देकर पूरा लोन दिया गया। … (व्यवधान) अब हम एनपीए को सुधारने के लिए जा रहे हैं। अगर लोन एक करोड़ रुपये का था तो कोलेटरल 30 लाख रुपये तक भी नहीं था। इससे प्राब्लम्स और ज्यादा हो रही हैं। पहले फोन करके गलत पार्टी को लोन देने के लिए बैंक को कम्पेल किया और फिर जब वह एनपीए हो जाता है, उनके कोलेटरल के कागज के टुकड़े की कोई वैल्यु भी नहीं होती है। … (व्यवधान) फिर बैंक कैसे सुधरेगा? So, this is the *kahani* of Phone Banking, जो उस समय हुई।

इंडियन इकोनॉमी में कंपनीज का असर क्या हुआ, वह मैं बोल रही हूं। The gross non-performing asset ratio in public sector banks increased by 12.3 per cent in 2013 itself. उस समय ही 12.3 परसेंट ग्रॉस एनपीए इनक्रीज हुआ। … (व्यवधान) The gross NPA in public sector banks वर्ष 2009-10 में 2.2 परसेंट था, जो बढ़कर 4.4 परसेंट तक गया।

Sir, return on assets for public sector banks fell from 0.97 percent to 0.5 percent between 2009-10 and 2013-14. The cost of funds and cost of deposits सब इनक्रीज हो गया था। बैंक्स लोन देने के काम को बंद करके बैठे थे, क्योंकि उनसे आगे का काम हो नहीं पा रहा था। No recognition of bad loans, बैड लोन्स हो गए, आपको उसी समय पता चला, मगर बैंक ने बैड लोन्स को रिकग्नाइज तक नहीं किया और evergreening भी हुआ। … (व्यवधान)

Yes, माननीय मंत्री जी, but I have to set the context. In March, 2014, the top 200 hundred companies, this is absolutely important.

श्री अधीर रंजन चौधरी : हम यही सुनते-सुनते थक गए हैं।

श्रीमती निर्मला सीतारमण : हां, थक ही जाना चाहिए। देश की बर्बादी में आप कैसे थकोगे? … (व्यवधान) मार्च, 2014 में top 200 companies with an interest coverage ratio of less than one owed banks, … (व्यवधान) यह इम्पॉर्टेंट डेटा है। Top 200 companies … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिए। यह तरीका ठीक नहीं है।

… (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : टॉप 200 कंपनीज ने बैंकों को कितना बाकी रखा, ये नंबर इनको सुनने चाहिए। Top 200 companies in March 2014 owed about 8.6 lakh crore to the banks. बैंक को 8.6 लाख करोड़ का बकाया था। Nearly 44 per cent of those loans were yet to be recognized as problem assets. उस समय प्रॉब्लम एसेट्स की पहचान तक नहीं हुई। हमने क्या किया? चार शब्द कहकर मैं बैठ जाती हूं। बैंक्स का री-कैपेटलाइजेशन किया, एसेट क्वालिटी रिव्यू की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उसका ऑर्डर हुआ। प्रोविजनिंग की, बैंक ब्यूरो सेट-अप किया। डायरेक्ट लेंडिंग के लिए किसी को सीधे फोन करके यह नहीं कहा कि-'लोन दो।' ऐसा आदेश नहीं दिया। हमने 4R की स्ट्रैटजी फॉर्म की। रिकग्निशन, रेजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म्स। IBC ऐसे कानून ले आया, जिससे जल्दी-जल्दी केसेज से निपट लें और बैंक का पैसा वापस दें। मेजर ऑफ बैंक्स बनाए, बैंक्स को मर्ज किया फिर प्रोफेशनल बोर्ड्स एंड इंडीपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया। उसका असर क्या हुआ? हमारे इतने सारे स्टेप्स का प्रभाव क्या हुआ, यह भी व्हाइट पेपर में है। इतनी मेहनत करके आज उसका अच्छा रिजल्ट हम देख रहे हैं। There is a decline in the gross NPA ratio to a multi-year low of 3.2 per cent. Profitability of PSBs increased from Rs. 37,000 crore to Rs. 1.08 lakh crore. पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज प्रॉफिट कमा रहे

हैं । The banks are handing over record dividend to the Government, जिससे जनकल्याण के कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक डिविडेंड दे रही है। आज वही बैंक्स, जो कर्ज में डूबे हुए थे, आज पिलर ऑफ जनकल्याण बन रहे हैं । The consolidated balance sheet of scheduled commercial banks, not inclusive of RRBs, वर्ष 2023 में 12 परसेंट ग्रो हुआ है । This is the highest in nine years. आज रिवाइवल ऑफ क्रेडिट ग्रोथ, कैपिटल फॉर्मेशन और जन कल्याण के लिए मुद्रा स्वनिधि जैसे अच्छे-अच्छे कार्यक्रम बैंक के द्वारा हम कर रहे हैं।

अब ज्यादा कुछ न कहते हुए, मैंने एक विस्तृत रूप में, प्रॉब्लम क्या थी, बैड गवर्नेंस क्या था, बैड डिसीजन मेकिंग क्या था और उससे क्या असर पड़ा, उसके बारे में बोला। फिर, हमारी सरकार के द्वारा जो अच्छे कदम, पॉलिसी, लेजिस्लेशन मेजर्स, इन सबके ऊपर ट्रांसपरेंसी के साथ हमने जो किया, उसके कारण आज चाहे भारत देश के बैंक हों, कोल सेक्टर हो, पूरा इकोनॉमी ग्रोथ अच्छे स्तर पर पहुंचा है। एक जिम्मेदार गवर्नमेंट के नाते आनी वाली पीढ़ियों की इतनी गहरी सिचुएशन से अब अगर भारत देश इस कगार पर पहुंचा है तो उसके लिए इस 10 साल के कार्यकाल में बहुत मेहनत हुआ है। इसका विश्वलेषण व्हाइट पेपर मे है। अब से लेकर वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने वाले हम होंगे। जनता हमें सपोर्ट करेगी और ब्लेसिंग्स देगी। धन्यवाद

श्री मनीश तिवारी (आनंदपुर साहिब): अध्यक्ष महोदय, यह श्वेत-पत्र नहीं है, यह काला ब्रश है। This is not the White Paper; this is a black brush. माननीय वित्त मंत्री जी की जो उत्तेजना है, उसको पूरी तरह से प्रमाणित करती है। ... (व्यवधान) रवि शंकर जी बैठ जाइए। आप सुनने की क्षमता रखिए। आप बैठ जाइए। आप ऐसे ही बीच में खड़े हो जाते हैं। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, भारत का इतिहास वर्ष 2014 में शुरू नहीं हुआ था। भारत का इतिहास वर्षों और दशकों पुराना है। अगर आप श्वेत-पत्र लाना चाहती थीं तो आपको जुलाई, 2014 में लेकर आना चाहिए। मैं समझ सकता था कि आप श्वेत-पत्र फरवरी, 2015 में लातीं। लेकिन, फरवरी, 2024 में श्वेत-पत्र लाने का मतलब सिर्फ एक राजनीतिक उद्देश्य है। This is a political manifesto; this is not the White Paper. वर्ष 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी, जिसका नेतृत्व प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गाँधी जी कर रही थीं, हमने ऐसे मूलभूत सुधार किए जिससे इस देश की जो नींव है, हम लोगों ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नींव को मजबूत किया। सबसे पहला आरटीआई का कानून, सूचना का अधिकार, हम लोगों ने 130 करोड़ लोगों को सूचना का अधिकार दिया।

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Sir, there is no translation. … (*Interruptions*)

श्री मनीश तिवारी : महोदय, दस रुपये की अर्जी देकर आप ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक किसी भी सरकार से कोई भी सूचना मांग सकते थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं खेद के साथ यह बात कह रहा हूं कि वर्ष 2014 से वर्ष 2024 तक उस सूचना के अधिकार के किस तरह से परखचे उड़े, यह कहानी सबको मालूम है।

दूसरी बड़ी उपलब्धि मनरेगा का कानून, वर्ष 2005 में यूपीए की सरकार मनरेगा का कानून लेकर आई। हमने कानूनी तौर पर यह सुनिश्चित किया कि जिसको 100 दिन काम चाहिए, उसको काम मिलेगा। मैं आपसे यह बात पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2024 तक उस 100 दिन को 101 दिन क्यों नहीं किया? आपने उस 100 दिन को 101 दिन नहीं किया, हां उस कानून को आप कोसते रहे। उस कानून की जो असलियत है, उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा।

तीसरा, निःशुल्क शिक्षा का कानून है। पूरे देश में जात-धर्म से ऊपर उठकर 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के जिस बच्चे को भी शिक्षा चाहिए, उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। चाहे बड़े से बड़ा निजी स्कूल हो, चाहे कोई भी स्कूल हो, जो 25 प्रतिशत सीट्स थीं, जो आर्थिक रूप से कमजोर (इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन) परिवारों से आते थे, वे उनके लिए आरक्षित की गई थीं।

चौथा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। इस देश की जो 77 प्रतिशत जनसंख्या है, उस 77 प्रतिशत जनसंख्या को किफायती दामों पर गेहूं, चावल और मोटा दाना देने का काम किसने किया था, वह यूपीए की सरकार ने किया था।

पांचवा, 'आधार' है। जिसने मूलभूत आधार रखा, जिसके ऊपर इतना ढांचा बना हुआ है, वह किसने शुरू किया? जब यूपीए ने सरकार छोड़ी, तो उस समय 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के आधार कार्ड बने हुए थे।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पिछले 10 वर्षों की क्या उपलब्धि रही है? अगर आप नोटबंदी को अपनी उपलब्धि मानते हैं, तो उसको मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। आपने जीएसटी को जिस तरह से क्रियान्वित किया, अगर आप उसको उपलब्धि मानते हैं, जिसने भारत के सारे लघु उद्योग को कई सालों तक नष्ट कर दिया, तो फिर मैं उसको आपके विवेक पर छोड़ता हूं। मैं यह उम्मीद करूंगा कि जब वित्त मंत्री जी इस मोशन पर जवाब देंगी, तब वह इस सदन को जरूर बताएंगी की आपकी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल में ऐसी कौन-सी पांच बड़ी उपलब्धियां रही हैं।

अब मैं अर्थव्यवस्था पर आता हूं। जब वर्ष 2004 में हम लोगों ने सरकार संभाली थी, तब परिस्थिति क्या थी। वर्ष 2003-04 में जो फिस्कल डेफिसिट था, वह 4.5 प्रतिशत था। वर्ष 2007-08 में आर्थिक महामंदी, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक महामंदी की तुलना में घटकर 2.8 प्रतिशत हो गई। जो रेवेन्यू डेफिसिट था, सरकार के राजस्व में जो कमी थी, मैं यह इसलिए बता रहा हूं, मैं हमारी सरकार के बारे में भी बताऊंगा और आपकी सरकार के बारे में भी बताऊंगा। वर्ष 2003-04 में जो रेवेन्यू डेफिसिट था, वह 3.6 प्रतिशत था। वह वर्ष 2007-08 में घटकर 1.2 प्रतिशत रह गया।

जो सेविंग टू जीडीपी रेशियो था, आप जो बचत करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था चलती है, वह वर्ष 2003-04 में 29.8 प्रतिशत था, जो वर्ष 2006-07 में बढ़कर 34 प्रतिशत हो गया। जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो था, वह वर्ष 2003-04 में 28.2 प्रतिशत था, जो वर्ष 2006-07 में बढ़कर 35.9 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 1998 से लेकर 2004 तक जब आपकी सरकार थी, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) था, आपने उसको सिर्फ 30 रुपये बढ़ाया था। वर्ष 2004 से लेकर 2008 तक जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था, वह 300 रुपये बढ़ा था। वर्ष 1998 से लेकर 2002 तक, आपकी पहली एनडीए सरकार के जो चार साल थे, तब जो महंगाई दर थी, वह 5.15 प्रतिशत थी और जो वर्ष 2004 से 2008 तक में वह गिरकर 5.12 प्रतिशत हो गई।

वर्ष 1999 से लेकर 2004 तक अर्थव्यवस्था का जो एवरेज ग्रोथ रेट था, वह 5.8 प्रतिशत था, जो यूपीए के पहले चार साल में बढ़कर 8.9 प्रतिशत हो गया था। जिस अवस्था में हमको अर्थव्यवस्था मिली थी और जिस अवस्था में हमने चार साल में आर्थिक महामंदी से पहले अर्थव्यवस्था को संभाला था, ये आंकड़े उसकी कहानी बयान करते हैं और वह कहानी झुठलाई नहीं जा सकती है।

13.00hrs

किसी भी अर्थव्यवस्था के पांच मुख्य बिंदु हैं। There are five fundamentals. सबसे पहला बचत, खपत, सेविंग्स, कंजम्प्शन, निवेश, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन और फिर रोजगार है। इनकी जो कहानी है, वह आंकड़े अपने आप बयान करेंगे। वर्ष 2013-14 में जिसको आप कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल फाइव में पहुंच गई थी, अर्थव्यवस्था को लकवा मार गया था और कई-कई अलंकरण इस्तेमाल किए गए। रवि शंकर प्रसाद जी को याद ही होगा। अब उसकी असलियत क्या है। वर्ष 2013 में जो सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो था, वह 34 प्रतिशत था, लेकिन वर्ष 2022 में वह गिरकर 30 प्रतिशत रह गया। जो प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्प्शन एक्सपैंडिचर था, वर्ष 2013-14 में 60 प्रतिशत था, लेकिन वह वर्ष 2023-24 में गिरकर 56.9 प्रतिशत रह गया। जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो था, वह वर्ष 2013-14 में 33.8 प्रतिशत था। वित्त मंत्री जी, आपने जो जवाब दो दिन पहले

दिया था, उसमें आपने इस बात को कबूला है कि वर्ष 2023-24 में वह गिरकर 29.20 प्रतिशत रह गया है।

महोदय, इसका कारण यह है और मैंने यह बात फाइनेंस बिल के दौरान भी कही थी कि पिछले तीन साल से कोविड के बाद आपका वित्तीय घाटा 17-18 लाख करोड़ की रेंज में चल रहा है, वह प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड इन नहीं कर रहा है, वह प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड आउट कर रहा है। जब सरकार अपना खर्चा चलाने के लिए बाजार से इतना कर्ज लेती है, अपने बजट को बैलेंस करने के लिए लेती है, तो जिस निजी क्षेत्र को आपने वर्ष 2019-20 में इतने बड़े-बड़े कंसेशंस दिए थे, उस निजी क्षेत्र को वह मार्केट एक्सेस नहीं मिल पाता। वर्ष 2013-14 में जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन थी, वह 33.8 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2022-23 में गिरकर 31.4 प्रतिशत रह गई। अब आप बेरोजगारी की दर पर आइए। बेरोजगारी की दर वर्ष 2013-14 में 4.9 प्रतिशत थी। सीएमआई की जो चार महीने की मूविंग एवरेज है, चूंकि सरकारी आंकड़े आने तो बंद हो गए हैं, वह वर्ष 2023-24 में 8 से 9 प्रतिशत है। इस देश में पिछले दस वर्षों में बेरोजगारी बढ़ी है।

महोदय, आपने खुद अपने बजट के भाषण में 10वें पैरा में यह बात कही कि वर्ष 2014 से लेकर 2024 तक 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से मुक्त किया गया है। यह बात भी सही है कि वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया था। जो सरकार 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आती है, उस सरकार के बारे में आप कहते हैं कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। They were an absolutely incompetent Government. यह किस तरह का लॉजिक है? अगर आप अपनी पीठ थपथपाते हैं कि आपने 25 करोड़ लोगों को अपने दस साल के कार्यकाल में गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है तो जिस सरकार ने 27 करोड़ लोगों को उठाया है और इसका जिक्र आपने वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में भी किया था, उसकी निंदा करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। यह किस तरह की बहस है? आपने अपने बजट भाषण में यह कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। हम नेशनल फूड सिक्योरिटी का कानून लेकर आए थे। हम तो चाहेंगे कि आप 140 करोड़ लोगों को फ्री राशन दीजिए, हमें उस पर

कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि रोजगार का क्या हुआ? उसका सबसे प्रमाण यह है कि वर्ष 2013-14 में जब हमने सरकार छोड़ी थी तो मनरेगा का बजट 33 हजार करोड़ रुपये था। लेकिन जो एक्चुअल पैसा खर्च हुआ, वह 32992.83 करोड़ रुपये हुआ। वर्ष 2023-24 में वह बढ़कर 86000 करोड़ रुपये हो गया। अगर मनरेगा का बजट दोगुना हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं। लोग, जो मिनिमम वेज है, उस मिनिमम वेज पर काम करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए आपको मनरेगा का बजट दस साल में दोगुना करना पड़ा। मैं आगे प्रमाण देता हूं। वर्ष 2014-15 में 16572.1 लाख पर्सन डेज़ मनरेगा में क्रिएट हुए। वर्ष 2022-23 में वह बढ़कर 29564.15 लाख पर्सन डेज़ हो गए। जितने लोगों ने मनरेगा में काम ढूंढा, उनकी गिनती दोगुनी हो गयी। अगर अर्थव्यवस्था में रोजगार के साधन थे तो लोग जाकर मनरेगा के तहत मिनिमम वेज पर काम करने के लिए तैयार नहीं होते। आपको यूपीए का धन्यवाद करना चाहिए कि जिस स्कीम के लिए आप कहते थे कि यह गड्ढे खोदने और गड्ढे भरने की स्कीम है, इसी स्कीम ने आपको पिछले दस साल में बचाया है, नहीं तो इस देश में अराजकता होती। ... (व्यवधान) आप सुनने का धैर्य रखिए। जब आप बोलती हैं तो मैं कभी बीच में नहीं बोलता हूं। मैं पिछले पांच साल में किसी के बीच में नहीं बोला हूं। वर्ष 2013-14 में 5.3 प्रतिशत महंगाई दर थी। वर्ष 2023-24 में वह बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गयी है और आप कहती हैं कि हमारे जमाने में महंगाई बहुत थी और आपने महंगाई के ऊपर नियंत्रण रखा है। लेकिन आपकी एक उपलब्धि जरूर बताना चाहूंगा कि वर्ष 2013-14 में जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, वह 2.05 ट्रिलियन डॉलर की थी। जो भारत सरकार का कर्ज था, वह 5587149.33 लाख करोड़ रुपये था। वर्ष 2024 में वह अर्थव्यवस्था 3.75 ट्रिलियन की हो गयी। लेकिन भारत सरकार का जो कर्ज है, वह तीन गुना बढ़ गया। The total debt and liabilities of the Government on 31st of March, 2024 is Rs. 168,72,554.16 crore. मतलब 10 साल में आपने 11285394.83 करोड़ का कर्ज पिछले दस साल में लिया है। इसका यह मतलब है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, वह राजस्व बढ़ने से नहीं चली है, वह रेवेन्यू बोएंसी की वजह से नहीं चढ़ी है। वह इसलिए चली है कि आपने पिछले दस वर्ष में इतना ज्यादा कर्ज लिया है और उसका

सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आपके बजट को जब आप ब्रेकडाउन करें, जो आप ही के आंकड़े हैं, बाई द रूपी, तो जो सबसे बड़ा उसका कम्पोनेंट 28 पैसे का, वह बोरोइंगस हैं और जो सबसे बड़ा आउटगो है 20 पैसे का, वह ब्याज की पेमेंट्स हैं। यह जरूर आपकी उपलब्धि है कि भारत के ऊपर आपने पिछले दस वर्ष में 11285394.83 करोड़ का कर्ज बढ़ा दिया है। अब मैं जीडीपी की ग्रोथ रेट पर आता हूं। वर्ष 2005 से लेकर 2014 तक भारत की अर्थव्यवस्था क्युमलेटिवली 6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। वह अर्थव्यवस्था वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2024 तक 5.9 प्रतिशत से बढ़ी और आप ये कहती हैं कि हमने अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया, हमने अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, हमने सारे बैंक लूट लिए तो अगर वित्त मंत्री जी, ये सारी बातें सही हैं तो ऐसा क्यों है कि हमारे 10 सालों का जो कार्यकाल था, उसमें अर्थव्यवस्था आपके 10 सालों के कार्यकाल से ज्यादा बढ़ी? ये दोनों आँकड़े वर्ष 2011-12 की प्राइसेस के अनुसार हैं। इसमें कोई फर्क नहीं है कि वर्ष 2004-05 की प्राइसेस के ऊपर कोई आँकड़ा है और वर्ष 2011-12 के ऊपर कोई आँकड़ा है।

अब मैं डॉलर के ऊपर आता हूँ। आप भी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थीं। मुझे याद है कि डॉलर के बारे में बहुत बात हुआ करती थी। जब भी डॉलर ऊपर जाता था तो उसकी तुलना प्रधान मंत्री जी की उम्र से की जाती थी। जब हमने 26 मई, 2014 को सरकार छोड़ी तो एक डॉलर 58 रुपये 65 पैसे का था। 4 फरवरी, 2024 को वह डॉलर 82.93 रुपये पर है। उस समय तो डॉलर के ऊपर बहुत उत्तेजना होती थी। तब टेलीविजन पर बड़ी-बड़ी बहस होती थी। यह कहा जाता था कि डॉलर प्रधान मंत्री जी की उम्र से भी तेज गति से बढ़ रहा है। आज क्या हुआ? मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। मैं कभी किसी चर्चा का स्तर नहीं गिराता हूँ, लेकिन आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि आप जो तब बोलती थी और आज जो परिस्थिति है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती है?

अभी मैं आगे आता हूँ। पिछले 10 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमत गिरती रहीं, कच्चे तेल की कीमत गिरती रहीं और मैंने कल भी यह बात कही थी कि आपकी जो ऑयल और गैस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, वह बढ़ती रही है। इस साल के पहले नौ महीनों में यह 87.5

प्रतिशत है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरती रही और यहां पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती रही। वर्ष 2014 में 410 रुपये का सिलेंडर था। आज 903 रुपये का सिलेंडर है, यह 120 प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2014 में पेट्रोल 71 रुपये प्रति लीटर था, आज 97 रुपये प्रति लीटर है, 37 प्रतिशत बढ़ा है। डीजल 55 रुपये प्रति लीटर था, आज 90 रुपये प्रति लीटर है, 64 प्रतिशत बढ़ा है। सरसो का तेल 90 रुपये किलो था, आज 143 रुपये किलो है, 60 प्रतिशत बढ़ा है। आटा 22 रुपये किलो था, आज 35 रुपये किलो है, 60 प्रतिशत बढ़ा है। दूध 35 रुपये प्रति लीटर था, आज 60 रुपये प्रति लीटर है, 71 प्रतिशत बढ़ा है।

आप ये कहती हैं कि हमने अर्थव्यवस्था के परखच्चे उड़ा दिए। अगर आप इन सब आँकड़ों को संज्ञान में लें तो पिछले 10 वर्षों में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। मुझे याद है कि सुषमा स्वराज जी जब नेता प्रतिपक्ष होती थीं तो वे यहां बैठती थीं और कहा करती थीं कि गृहिणी के आँसू बह रहे हैं। आज सही रूप में गृहिणी के आँसू बह रहे हैं।

आखिर में, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने 10 वर्षों से फोन बैंकिंग की बात की है। आप तो एक बहुत पढ़ी-लिखी अर्थशास्त्री हैं। आपको यह बात मालूम है कि किसी भी लोन को सैंक्शन करने से पहले उसका चीफ जनरल मैनेजर ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट साइन करता है। उसके बाद उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अप्रूव करता है। मैं आपको यह पूछना चाहता हूँ कि आप फोन बैंकिंग की बात करती हैं। पिछले 10 वर्षों में आपने किसके खिलाफ एक्शन लिया? आपने कौन से चीफ जनरल मैनेजर के खिलाफ एक्शन लिया? कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया? कौन से राजनीतिज्ञ के खिलाफ एक्शन लिया? आप बड़ी-बड़ी बातें करती हैं, लेकिन आपने 10 सालों में एक भी चीफ जनरल मैनेजर के खिलाफ एक्शन नहीं लिया।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज समाप्त कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी : अध्यक्ष जी, एक मिनट दीजिए। 10 सालों की बात है। आप भी सुन लीजिए। इस सेशन के सिर्फ दो दिन रह गए हैं। आपने किसी राजनीतिज्ञ लीडर के खिलाफ एक्शन लिया? किस-किस ने फोन किए थे?

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी पार्टी की बहुत लंबी लिस्ट है।

श्री मनीश तिवारी : मैं आखिरी बात यह कहना चाहता हूं और यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनैंस की इसके ऊपर एक नहीं, बल्कि 15 रिपोर्ट्स हैं। आपका जो इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट है, उसमें बैंक लूट को इंस्टिट्यूशनलाइज किया है । The IBC process has institutionalized bank loot.

अध्यक्ष जी मुझे रोक रहे हैं, पर मेरे पास इतना मैटेरियल है कि मैं दो घंटे और जो अर्थवस्था की असलियत है, वह उजागर कर सकता हूं। धन्यवाद।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। बिहारी का एक दोहा है कि

सतसैया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर

देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर।

सर, यह केवल और केवल 59 पेजे का व्हाइट पेपर है। ...(व्यवधान) उनको जाने दीजिए, आप आराम से सुनिए। इस व्हाइट पेपर में माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने कांग्रेस एवं अपोजिशन में इतनी तिलमिलाहट पैदा कर दी कि आज एक महिला वित्त मंत्री जब अपनी बातों को इस सदन में बोल रही थीं, तो उनकी बातों को सुनने का धैर्य नहीं था। सर, हमने अपोजिशन के माननीय सदस्य मनीष तिवारी जी को बड़ी शांतिपूर्व सुना। मुझे आपका संरक्षण चाहिए, क्योंकि मैं बोलूंगा तो शायद इनको तिलमिलाहट हो जाएगी।

मैंने अपने बजट भाषण में तीन चीजों का जिक्र किया था कि आप भारत की इकोनॉमी को तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला भाग वर्ष 1947 से वर्ष 1990 तक है, जब इस देश में लाइसेंस, परमिट कोटा राज रहा। वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक लूट राज रहा और वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2024 तक राम राज रहा। आज मैं अपनी पूरी की पूरी स्पीच केवल और केवल लूट राज पर करूंगा, जो व्हाइट पेपर का पार्ट है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी जब अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के लिए गए थे, तो उन्होंने देश को एक अच्छा संदेश दिया था और देश को बताने की कोशिश की थी कि राम भारत की आस्था हैं। यह सभी जानते हैं कि राम भारत की आस्था हैं और राम भारत का आधार हैं, लेकिन इस व्हाइट पेपर को देखने के बाद मैं अनुभव कर पाया हूं कि अपोजिशन की आस्था भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार उनकी आस्था है और भारत ही भ्रष्टाचार है, इसी में उनकी पूरी की पूरी पार्टी और पूरा का पूरा अपोजिशन डूबा हुआ है। हमारे यहां एक कहावत है कि बांटी चुटी खाए, राजा घर जाए और दूसरा होता है कि '*सर्वनाशे समुत्पन्ने* ह्यर्धं त्यजति पण्डित:।' आज इन्होंने भारत की जो स्थिति पैदा कर दी है, उसमें आपको सभी अपोजिशंस के लोग एक साथ इकट्ठा दिख रहे हैं, उसका कारण केवल और केवल भ्रष्टाचार है, जो इस व्हाइट पेपर में है। उनको लगता है कि माननीय मोदी जी जो कह रहे हैं कि

'न खाएंगे, न खाने देंगे', भ्रष्टाचार के ऊपर पिछले 10 सालों में इतना बड़ा अटैक, उससे हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा, इसलिए उन्होंने बचने के लिए यह रास्ता चुना है कि सभी बाघ, बिल्ली, भेड़ एवं अन्य सभी इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय है, जो जनता के सामने चला जाएगा।

सर, मनीश तिवारी अच्छे वक्ता हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। मनीश जी एक कहावत है। शहजाद ने एक अच्छी शायरी लिखा है कि

"गुज़रने ही न दी वो रात मैंने
घड़ी पर रख दिया था हाथ मैंने।"

आपने अपनी घड़ी को शांत कर दिया। आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है, भाई-भतीजावाद नहीं दिखाई देता है, करप्शन दिखाई नहीं देता है। आपको केवल यह दिखाई देता है कि हम कैसे गलत चीजों को डिफेंड करें। वह अच्छे वकील हैं, स्वाभाविक है। व्हाइट पेपर के बारे में आपने कहा कि ब्लैक मनी के लिए वर्ष 2012 में यूपीए सरकार ने जारी किया था। ब्लैक मनी को लेकर एक कमेटी बनी थी। वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि एक स्पेशल कमेटी बनाओ, उसको कंटेन करने के लिए ब्लैक मनी को कैसे रोका जाएगा? ब्लैक मनी का कितना एस्टिमेट है, बाहर कितना पैसा जमा है? वह कमेटी आ गई, कमेटी की रिपोर्ट आ गई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। क्या आपने कभी ब्लैक मनी को रोकने के लिए कोई सीरियस प्रयास किया? उलटा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी आपने, वर्ष 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, उसको भी आपने इम्प्लिमेंट नहीं किया। किसने इम्प्लिमेंट किया? 26 मई, 2014 को जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने चार्ज लिया, उसी दिन पहली कैबिनेट में ब्लैक मनी पर टास्क फोर्स बनाई गई। आप किस तरह की बात कर रहे हैं?

सर, इन्होंने ऑयल के बारे में कहा। मैं जवाब देने के लिए नहीं खड़ा हूं, क्योंकि मेरा विषय लूट राज है, मैं उसी पर जाता हूं। लेकिन आप यह कह रहे हैं, यह ठीक है कि आपके समय पेट्रोल, डीजल का दाम बहुत बढ़ रहा था। आई एग्री। लेकिन आपने क्या किया? ऑयल बॉन्ड के तौर पर आपने इस देश के लोगों पर कितना बड़ा बोझ डाला है? यह आपको पता है, यह आपको जानकारी है। आपने अपने बजट से ऑयल कंपनीज़ को पूरा नहीं किया, बल्कि आपने ऑयल बॉन्ड सॉवरेन गारंटी के तौर

पर दे दिये और उसको रिटर्न करने की जिम्मेदारी मोदी सरकार को दे दी, जो आज भी दस साल से एक लाख करोड़ रुपये ऑयल बॉन्ड का पैसा दे रही है। उन्होंने एक लाख दस हजार करोड़ रुपये का ऑयल बॉन्ड अपनी पीढ़ी के ऊपर छोड़ दिया।

सर, एनपीए की, अर्थशास्त्र की बात करते हैं, जहां से माननीय वित्त मंत्री जी ने खत्म किया, मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं। सर, यह व्हाइट पेपर है। मैं मनीश तिवारी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। मुझे लगता है कि उन्होंने ब्लैक पेपर ज्यादा पढ़ लिया और वह व्हाइट पेपर नहीं पढ़ पाए। व्हाइट पेपर में वर्ष 2003-04 का आर्थिक सर्वे का जिक्र है। मैं उसे पूरा नहीं पढ़ना चाहता हूं। आर्थिक सर्वे में आप ही के वित्त मंत्री जब यह पेपर ले कर रहे थे तो उसमें वह कह रहे हैं कि हम पुरानी सरकार, वाजपेयी सरकार के आभारी हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था छोड़ी है, जिसके आधार पर हम गरीब कल्याण के कई काम कर सकते हैं। यह उनका व्हाइट पेपर है। दूसरा व्हाइट पेपर वर्ष 2013-14 का है, इसी व्हाइट पेपर में है, जो आप छोड़ कर गए और हमने ले लिया। उसमें यह कहा गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसा बिगड़ा हुआ है कि शायद हम अपने एम्प्लॉइज का पैसा दे पाने की भी स्थिति में नहीं है। यह पढ़ना चाहिए। आप जब कहते हैं कि वर्ष 1998 से 2004 तक 5.8 जीडीपी ग्रोथ रही, तो आपको यह बताना चाहिए कि वर्ष 1997 में क्या थी, 1996 में क्या थी, 1995 में क्या थी, 1994 में क्या थी– 2 परसेंट, 3 परसेंट, 3.5 परसेंट, 4 परसेंट? पांच परसेंट से ज्यादा कभी इकोनॉमी नहीं रही। जब हमने चार्ज लिया, वर्ष 1997 के बाद जब हमें चार्ज दिया गया तो वह इकोनॉमी केवल और केवल 3 परसेंट पर थी। उस तीन परसेंट की इकोनॉमी को, जब हम छोड़ कर जा रहे थे, उस वक्त देश की इकोनॉमी वर्ष 2003-04 की 8 परसेंट पर थी। आप उसे कहीं बाहर नहीं ले गए और हमारे किए हुए काम को आप वर्ष 2004 से 2009 तक बढ़ाते रहे। वर्ष 2009 के बाद से 2014 तक, यहां उदासी जी बैठे हुए हैं, हमारी कमेटी है, आपकी जीडीपी ग्रोथ, जब आप हमारे लिए छोड़ रहे थे, केवल और केवल 2.6 परसेंट थी। इस कारण से आपने उसके पूरे मापदण्ड को बदल दिया, जिसके कारण हम दुनिया को दिखा पाए कि हमारी इकोनॉमी 3.4, 3.5 परसेंट वगैरह थी। यही इकोनॉमी है और इसी पर आप चर्चा करना चाहते हैं।

सर, इनकी सरकार में बड़े अर्थशास्त्री थे। मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, चिदम्बरम साहब अर्थशास्त्री थे, रघुराम राजन साहब अर्थशास्त्री थे, रंगराजन साहब अर्थशास्त्री थे, मोंटेक सिंह अहलुवालिया जी थे मतलब आप यह समझिये कि इस देश-दुनिया में जितने अर्थशास्त्री हो सकते हैं, सब अर्थशास्त्री इस सरकार को चला रहे थे। हमारे यहाँ एक कहावत है- "ज्यादा जोगी, मठ उजाड़।" इतने अर्थशास्त्री हो गये थे कि पूरे देश की इकोनॉमी का इन्होंने भट्ठा बैठा दिया था। इनको कमेटी बनाने का बहुत शौक है। वर्ष 2007-08 में रघुराम राजन के नेतृत्व में फाइनेंशियल स्टैबिलिटी की एक कमेटी बनाई गई थी। इन्होंने वर्ष 2012-13 में केलकर जी के नेतृत्व में एक और कमेटी बनाई थी। दोनों कमेटीज ने कहा कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं, जिस तरह की फोनो-बैंकिंग कर रहे हैं, जिस तरह से एनपीए हो रहा है, वित्त मंत्री जी ने कहा, उसे मनीश तिवारी जी ने एंडोर्स किया। वित्त मंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2013-14 में जब हमारी सरकार ने चार्ज लिया तो बैंक का एनपीए लगभग 13 परसेंट के आसपास था, उन्होंने twelve point something का डाटा दिया और आज एनपीए लगभग 3 परसेंट के आसपास है। यही बात मनीश तिवारी जी ने भी कही। लेकिन आरबीआई के गवर्नर के रूप में जब रघुराम राजन साहब एस्टिमेट कमेटी के सामने आए, मैं उनका स्टेटमेंट लेकर आया हूँ, यदि हाउस चाहे तो मैं पूरा स्टेटमेंट पढ़ दूँ, लेकिन उस स्टेटमेंट का लब्बोलुबाब यह है कि वे कह रहे थे कि पॉलिटिकल करप्शन के कारण, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा सर, कमेटी ऑफ एस्टिमेट्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी है, उसके सामने रघुराम राजन कहते हैं कि पॉलिटिकल करप्शन के कारण बैंक्स की स्थिति बद-से-बदतर हो गई है। एनपीए 13 परसेंट के आसपास हो गया है। बैंक्स के एम्प्लाइज़ करप्शन में आकंठ डूबे हुए हैं। एसेट क्वालिटी रिव्यू यानी एक्यूआर के आधार पर कहीं भी कोई एसेट नहीं है। बिना कोलैट्रल के हमने लोगों को बैंक्स से लोन दे दिया है। यह रघुराम राजन का स्टेटमेंट है। यही तो व्हाईट पेपर में भी है। आपको बताना चाहिए कि 13 परसेंट एनपीए में आपने जिन बिज़नेसमेन को पैसे दिए, वे पैसे कहाँ डूब गये? आज आप कह रहे हैं कि आईबीसी से पूरा नहीं हो रहा है, आपने आईबीसी करप्शन और लूट के लिए बना दिया। हम तो कुछ पैसे लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपके समय क्या हुआ? सर, इनके पास आईबीसी नहीं थी, उस समय डीआरटी थी। मैं उसका डाटा

भी लेकर आया हूँ। रघुराम राजन ने कहा था कि यदि हमें 5 लाख करोड़ रुपए वापस लेने थे, तो 5 लाख करोड़ रुपए के बदले हम केवल और केवल 30 हजार करोड़ रुपए ही वापस ले पाए। आप यही इकोनॉमी दिखाना चाहते हैं?

13.28 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

सर, मेरी पार्टी के अन्य वक्ता भी बोलने के लिए हैं। मैं करप्शन से संबंधित दो-तीन बातें कहना चाहूँगा। एक स्कीम आई- 20:80. बाद में 80:20 आई। पहले 20:80 स्कीम आई। Show me the face, we will show you the law. क्या हुआ था, यह पूरे देश को जानने का सवाल है। आप कहते हैं कि ये करप्शन हो गया, ये भाग गया, वो भाग गया। I agree. हम से गलती हो गई। आप बड़े माई-बाप हैं। आप समझें कि वर्ष 2013 में इस देश में सबसे ज्यादा गोल्ड इम्पोर्ट होता था। यहाँ की महिलाओं को गोल्ड सबसे प्रिय है। वर्ष 2013 में यूपीए की सरकार एक पॉलिसी लेकर आई। उस समय चिदम्बरम साहब देश के वित्त मंत्री थे। उन्होंने कहा कि जो इतना गोल्ड इम्पोर्ट हो रहा है, इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत बिगड़ रहा है। बहुत अच्छी बात कही कि बिगड़ रहा है। हम एक पॉलिसी लाए, जिसके अनुसार यदि आप 80 परसेंट गोल्ड इम्पोर्ट करके लाएंगे, तो वह डोमेस्टिक यूज होगा और उसका 20 परसेंट एक्सपोर्ट होगा। यह सीएजी की रिपोर्ट है। वर्ष 2013 में कहा गया कि कुछ कमर्शियल बैंक्स या एमएमटीसी, एसटीसी, भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं, वे ही इसका इम्पोर्ट करेंगी। इसमें भी कोई परेशानी नहीं थी।

अब आ गया चुनाव। चुनाव में कांग्रेस को पैसे चाहिए थे। येन-केन-प्रकारेण यह लगने लगा कि माननीय मोदी जी अब इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको आश्चर्य होगा। चुनाव खत्म हो चुका था। 16 मई को रिजल्ट निकलना था। मैं यह बात ऑन रेकॉर्ड कह रहा हूँ। यह बात सीएजी की रिपोर्ट में है। पहले पीएसी की उस सब-कमेटी का चेयरमैन मैं था, बाद में श्री उदासी जी उस सब-कमेटी के चेयरमैन बने। 14 मई 2014, 16 मई को रिजल्ट निकलना था, ये देश को जानने का सवाल है। 14 मई 2014 को माननीय चिदम्बरम साहब की इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक आदेश आरबीआई को दिया कि हम और स्टार ट्रेडिंग कंपनी या जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ थीं, जिनसे कि पैसा लेना था या

लगता था कि कभी दोबारा हम सत्ता में वापस नहीं आएंगे तो कमीशनखोरी कहाँ से मिलेगी, वह आदेश आरबीआई को दे दिया। चिदम्बरम साहब बहुत ईमानदार, रघुराम राजन साहब बहुत ईमानदार हैं। 16 मई को रिजल्ट निकल लिया, 16 मई को तय हो गया कि माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, बिना किसी से पूछे हुए, बिना सरकार के रहते हुए, सरकार मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब 16 मई को तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, 21 मई को, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू रहते हुए, 21 मई 2014 को आरबीआई ने यह आदेश जारी कर दिया। उस आदेश के बाद जो हुआ, सर, आपको आश्चर्य लगेगा कि 5 घंटे के अंदर दिल्ली में इम्पोर्ट होकर गोल्ड आ रहा है, हरिद्वार चला जा रहा है, फिर हरिद्वार से वह एक्सपोर्ट हो जा रहा है, केवल 5 घंटे में। यह कांग्रेस ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। हमारी कमेटी ने सीबीआई इंक्वायरी की बात कही। हमारी सरकार ने नवम्बर, 2014 में इस स्कीम को बंद किया। उसको लगा कि इस देश में कम से कम एक लाख करोड़ रुपये का घोटाला हो गया। क्या आप यही देश चलाना चाहते हैं? क्या यही देश छोड़कर आप गए? घोटाले पर घोटाले, घोटाले पर घोटाले, करप्शन की, पैसा खाने की भी एक सीमा होती है।

सर, दूसरा, इसी श्वेत पत्र में है, एंट्रिक्स-देवास डील, मैं आपको बताऊँ कि चाहे सेना हो, दुनिया हो, देश हो, रक्षा हो, सुरक्षा हो, आम आदमी हो, इससे यूपीए की सरकार को कोई लेना-देना नहीं था। वर्ष 2005 में क्या हुआ? 28-01-2005 को इसरो के साथ एंट्रिक्स का देवास के साथ बिना किसी कोलैटरल के एक एग्रीमेंट साइन हुआ। उसका कारण यह है, यह मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ कि यह केस हम इंटरनेशनल कोर्ट में जब हारे, माननीय रवि शंकर जी, मेरी समझ से उस वक्त लॉ मिनिस्टर रहे होंगे, जब हमारी सरकार बन गई होगी, हम लोगों को लगभग-लगभग 15 हजार करोड़ रुपया विदेश को देना था, बिना किसी काम के, केवल एग्रीमेंट साइन होने के कारण। 28-01-2005 को चिदम्बरम साहब ने यह एग्रीमेंट साइन कर दिया और यह कह दिया कि आर्बिट्रेशन विदेश की धरती पर होगा। उसमें जो रामचन्द्रन नाम के आदमी थे, उनके साथ उनकी रिश्तेदारी थी। भारत का पूरा का पूरा इसरो का मैनेजमेंट फेल हो गया। आज भी भारत सरकार उससे कराह रही है। सीबीआई ने

केस किया है, हमने उसका 600 करोड़ रुपया अटैच किया है। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि आर्बिट्रेशन का जो यह क्लॉज भारत सरकार ने लगाया है, इसमें करप्शन की बू है और हम विदेशी धरती पर हुए किसी आर्बिट्रेशन को नहीं मानते हैं। उसके बावजूद भी यह एंट्रिक्स-देवास डील हुई। मनमोहन सिंह जी को डार्क में रखकर यह पूरी सरकार ऐसा करती रही। कांग्रेस सरकार का यह हाल था।

तीसरा, मैं आपको बताऊँ, इस देश में पिलाटस डील हुई। इसमें अगस्ता वेस्टलैंड और पिलाटस का जिक्र है। यह इस देश को जानने का सवाल है। मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि इसमें इनका जिक्र है। आप यह समझें कि जो एक ऑफसेट क्लॉज है, माननीय वाजपेयी जी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया करना चाहते थे, हम मेक इन इंडिया करना चाहते हैं और आज आपको पता है कि डिफेंस में हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। माननीय मोदी जी की नीतियों के कारण हम ऐसा कर पा रहे हैं। डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है, जहाँ हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं। एक लाख करोड़ रुपये का डिफेंस का एक्सपोर्ट हुआ। अब आप समझिए कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ। सभापति जी, संजय भंडारी भागा हुआ है और उसने एग्रीमेंट साइन किया कि पिलाटस का उसे ऑफसेट क्लॉज मिलेगा, एक कम्पनी उसने बनाई। वह कम्पनी काम नहीं की लेकिन उसका जो एकाउंट दुबई में है, उसका नम्बर 1021497657901 है और इसमें 13 जून, 2012 को लगभग 400 करोड़ रुपये जमा हुए। जैसे ही यह पैसा जमा हुआ।... (व्यवधान) मैं ऑन रिकार्ड कह रहा हूं। जितने भी पेपर कोई मांगना चाहेगा, वे मेरे पास हैं। इसके बाद एक मकान 12, ब्राइनसन स्क्वायर इसी एकाउंट से खरीदा गया। उसी कम्पनी ने लंदन में खरीदा। उस मकान की कीमत लगभग 50 करोड़ रुपये के आस पास थी, जो उस एकाउंट से ट्रांसफर हुआ। ठीक उसके तीन महीने बाद एक दूसरी कम्पनी ने उतने ही पैसे में वह मकान खरीद लिया, जिस कम्पनी का मालिक सी.सी. थम्पी था। अब तीन करेक्टर हो गए हैं – एक संजय भडारी जी हैं, जो आर्म्स डीलर हैं, जो पिलाटस के ऑफसेट पार्टनर हैं। दूसरा 12, ब्राइनसन स्क्वायर मकान है जो लंदन में है और तीसरे सी.सी. थम्पी आ गए। अब तीनों का मामला समझ लीजिए। इन तीनों का मेल अजीत के साथ मिलता है। अजीत मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि कई

फिल्मों में एक्टर अजीत ने रॉबर्ट का रोल प्ले किया था इसलिए आप अजीत को रॉबर्ट ही मान सकते हैं, जिससे इन्हें परेशानी न हो। मैं अजीत बोलूंगा तो पूरा देश इसे समझ लेगा। अजीत किसी का भी नाम हो सकता है, हमारे एक एम.पी. का भी नाम है। उस मेल में लिखा है कि इस मकान के मालिक अजीत साहब हैं/रॉबर्ट हैं, आप जो भी समझ लीजिए। वे पार्टी देते हैं और वह पार्टी दुबई में होती है। 13 अगस्त को एक पार्टी संजय भंडारी ज्यूरिक में देते हैं और उसका टिकट नम्बर ईके-71 से रॉबर्ट वाड्रा अपने दोस्तों के साथ, सॉरी अजीत अपने दोस्तों के साथ वहां जाते हैं और पार्टी करते हैं। उसके बाद वे 12, ब्राइनसन स्केयर में शिफ्ट हो जाते हैं। यह किसका पैसा है? कहां से पैसा आया और जो सी.सी. थम्पी है, ये कागज मेरे पास है और यह 23 दिसम्बर, 2023 का है। ईडी ने जो प्रेस रिलीज जारी की है, आपको आश्चर्य होगा कि सी.सी. थम्पी वह आदमी है जो रॉबर्ट वाड्रा की बेनामी सम्पत्ति का दुबई, लंदन, अमरीका में मालिक है और इतना ही नहीं, फरीदाबाद में जो जांच हो रही है, उस बेनामी प्रॉपर्टी का मालिक सी.सी. थम्पी है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : नाम को देख लेंगे।

... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : महोदय, मैं जानता था कि यही बोलेंगे। मैं यह पेपर लेकर आया हूं। अजीत साहब/रॉबर्ट... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अजीत से ही काम चलाइए।

... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : रॉबर्ट बोल सकते हैं, वाड्रा नहीं बोलते हैं। रॉबर्ट तो कोई भी हो सकता है।... (व्यवधान) महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईडी ने जो चार्जशीट पेश की है, उसमें जगदीश शर्मा कांग्रेस का कार्यकर्ता, जो रॉबर्ट साहब की बेनामी प्रॉपर्टी देखता है, संजय भंडारी, मनोज और उस वक्त के तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर, बहुत ईमानदार थे, मैं उनकी इज्जत करता हूं और उनके बेटे अब हमारी पार्टी में आ गए हैं, उन सभी का फोन टैप चार्जशीट में मौजूद है। ये इनका करप्शन है, यह वाइट पेपर है और इसी को माननीय प्रधान मंत्री जी बाहर लाना चाहते हैं। यही करप्शन है और

पूरी डिफेंस डील आपने कर ली। अभी सतपाल जी ने कहा कि एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर मेक इन इंडिया में खर्च किया है, लेकिन आपने क्या किया? आपने ऑफसेट क्लॉज़ के नाम पर किया, यही कारण है कि कभी आपको राफेल दिखाई देता है, कभी एच.ए.एल. दिखाई देता है। आपने कहा कि एच.ए.एल. डूब जाएगा। आज एच.ए.एल. मोस्ट-प्रॉफिट मेकिंग कम्पनी है, उसी बंगलुरू की कम्पनी है। आपको प्रधान मंत्री जी के ऊपर भरोसा होना चाहिए। आपकी तरह करप्ट शासन नहीं चल रहा है। आपने पूरे डिफेंस को दलालों के हाथों में डाल दिया। मैं और दलालों के नाम नहीं लेना चाहता। आपने इतना भी नहीं सोचा।

सर, आपको ध्यान होगा कि अगस्तावेस्टलैंड हेलिकॉप्टर केस में एयर फोर्स के चीफ को जेल जाना पड़ा क्योंकि उसकी जो हाइट थी, उसके स्पेसिफिकेशन को आपने चेंज किया। आपको भारत की रक्षा की चिंता नहीं है, सुरक्षा की चिंता नहीं है, आर्मी की चिंता नहीं है, नेवी की चिंता नहीं है। हम उसकी चिंता कर रहे हैं, माननीय प्रधान मंत्री जी उसकी चिंता कर रहे हैं। आपने केवल और केवल करप्शन किया है। मैं आपको दावे के साथ यह कह सकता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी की सरकार है, 'न खाएंगे, न खाने देंगे', जो भी भ्रष्टाचारी है, वह जेल के अन्दर जाएगा।

सर, दूसरा स्कैम सेना से ही संबंधित है। यहां सुप्रिया जी कांग्रेस पार्टी का साथ दे रही हैं। दूसरा स्कैम आदर्श सोसायटी स्कैम है। कारगिल युद्ध में जो बेचारे सैनिक शहीद हो गए थे, उनके लिए सेना की जमीन थी। वह नेवी की जमीन थी। इनके मुख्य मंत्री, जो इस संसद के सदस्य रहे हैं, पर अव दिवंगत हो गए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, विलास राव देशमुख ने 24 घंटे के अन्दर उसको लाइसेंस दे दिये। जयराम रमेश जी बहुत ईमानदार बनते हैं। सी.आर.ज़ेड. पॉलिसी में लक्षद्वीप का विकास नहीं हो सकता है, मुम्बई का विकास नहीं हो सकता है, गोवा का विकास नहीं हो सकता है, लेकिन सी.आर.ज़ेड. पॉलिसी को धता बताकर इस आदर्श स्कैम में काम किया गया। इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे? अशोक चव्हाण से लेकर कांग्रेस के कम से कम 50 ब्यूरोक्रैट्स का नाम ले सकता हूं, जिन सबको आदर्श सोसायटी में जमीनें दे दी गयीं, सभी को मकान दे दिए गए।

सर, जैसे आज हमारे राज्य के मुख्य मंत्री जेल गए हैं तो वे ऐसे ही सेना की जमीन बेच कर गए हैं। जब आपदा आती है, तो जैसा कि कहा गया है – 'सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धं त्यजति पण्डितः', तो चूंकि इन्हें लगता है कि भ्रष्टाचार में सब जेल चले जाएंगे, तो इसके आधार पर इन्होंने यह किया कि इससे बचो, बचो, बचो, और बचने के लिए क्या करें, तो मोदी का विरोध करो, मोदी का विरोध करो। किसी प्रकार की कोई आइडियोलॉजी इसमें नहीं है।

सर, मैं जब आगे की बात बताऊंगा तो आपको यह लगेगा। मैंने बताया कि इन्होंने आदर्श स्कैम किया, तो उसका क्या असर हुआ, उसमें कौन-कौन से लोग फ्लैटधारक हैं। उसी तरह से मैंने आपको कहा कि हेमंत सोरेन जी क्यों जेल में हैं, सेना की जमीन बेचने के कारण ही जेल में हैं।

सर, इसके आगे आई.एन.एक्स मीडिया केस है। इस देश में हर्षवर्धन जी से लेकर रविशंकर प्रसाद जी हैं, हमारी मंत्री स्मृति जी भी बैठी हुई हैं। सभी को भारत सरकार में एक अधिकार है कि सेक्रेटरी इतने रुपये तक का प्रोजेक्ट पास कर सकता है, मंत्री इतने रुपये तक का प्रोजेक्ट पास कर सकता है और कैबिनेट इतने रुपये तक के प्रोजेक्ट्स पास कर सकती है। इसमें सभी को अधिकार है, एक डिस्क्रेशन है। उसके आधार पर भारत सरकार बड़े पारदर्शी तरीके से काम कर रही है।

सर, आई.एन.एक्स मीडिया में एफ.आई.पी.बी. बोर्ड को माननीय चिदम्बरम साहब देख रहे थे। उनका अधिकार था कि वे 300 करोड़ रुपये से ऊपर के किसी प्रपोजल को पास नहीं कर सकते हैं। इसका प्रपोजल लगभग 800 करोड़ रुपये का आया। 800 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश आने के लिए एफ.आई.पी.बी. बोर्ड में गए। कायदे से इसे कैबिनेट में जाना चाहिए था, लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार तो मनमोहन सिंह जी चला नहीं रहे थे। अभी मनीश तिवारी जी ने खुद ही अपने भाषण में कहा कि इसे सोनिया गांधी जी चला रही थीं। हम तो यह नहीं कह सकते हैं। इस देश में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधान मंत्री थे, तो माननीय अटल जी सरकार चलाते थे और जब माननीय मोदी जी प्रधान मंत्री हैं तो मोदी जी अकेले चलाते हैं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : उन्होंने दोनों का नाम बोला था, केवल एक का नहीं।

... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, मैं भी वही बात कह रहा हूं कि मनमोहन सिंह जी चला रहे थे और सोनिया जी चला रही थीं। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं।

सर, आप यह बताइए कि जब इस देश में 'दो निशान, दो विधान, दो प्रधान' नहीं हो सकते तो फिर इस देश में दो प्रधान मंत्री कैसे हो सकते हैं? इस तरह देश कैसे चल सकता है? गौरव गोगोई जी ने तो बहुत अच्छी बात कह दी कि मनमोहन सिंह जी भी चला रहे थे, सोनिया जी भी चला रही थीं।... (व्यवधान) मुझे लगता है कि मंत्री बनाने का अधिकार मनमोहन सिंह जी को नहीं था तो उनके मंत्रालय में कोई उनकी बात नहीं मानते होंगे। इसके कारण कैबिनेट में जाने की आवश्यकता ही नहीं थी।

पीटर मुखर्जी का स्टेटमेंट है, जिसमें इस सदन के सदस्य का नाम है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मेरा एक उसूल है कि मैं अपने सदन के सदस्यों का नाम नहीं लेता, अब वे फंसे हुए हैं और इसमें कहा गया है कि कम से कम दो सौ करोड़ रुपये की रिश्वत ली गई है। सर, यह ईडी की चार्जशीट कह रही है। रोज समन कर के उनको बुलाया जा रहा है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि कितना पैसा खाओगे, कितनी चीज़ों में पैसा खाओगे? देश के बारे में भी तो कभी सोचो यार।

सर, चौथा केस एयरसेल-मैक्सिस का है। सब इसमें लिखा हुआ है। यहां डीएमके के सदस्य नहीं हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वे टेलिकॉम के मंत्री थे। मैं यह बात इसलिए बड़ी गंभीरता से कह सकता हूँ क्योंकि हमारे कई मित्र थे, जो एयरसेल को खरीदना चाहते थे। जब भी एयरसेल के लिए फाइल एक अच्छी डील के साथ जाती थी, उसका एक टाइम लिमिटेशन होता है कि जब आप किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करेंगे तब होता है कि 10 दिन में उसको खत्म करना है, 20 दिन में खत्म कर देना है। इसके लिए हमेशा तीन महीने का समय मिलता रहा। हचीसन भी इसको खरीदना चाहता था। हचीसन छह महीनों तक मंत्री जी के इर्द-गिर्द घूमता रहा, लेकिन उन्होंने कोई समय नहीं दिया और कहा कि बेचने की आवश्यकता नहीं है। सर, जब मैक्सिस आया, तब उसको मंत्री जी खुद ले कर आए। समझिए कि एक तरह से रिवॉल्वर सटा कर, उस वक्त के तत्कालीन इनवेस्टर शिव शंकर ने रोते हुए अपना स्टेटमेंट दिया था कि एक तरह से रिवॉल्वर सटा कर कहा गया कि तुमको इसी के साथ डील करनी है, अगर किसी और के साथ डील करोगे तो मैं उसको कदापि नहीं होने दूंगा। इसमें

लगभग-लगभग 3,565 करोड़ रुपये की डील हुई और ईडी की चार्जशीट यह कह रही है कि 742.58 करोड़ रुपये मारन परिवार को गया । सर, इसलिए ये लोग कांग्रेस को क्यो नहीं सपोर्ट करेंगे? … (व्यवधान) सर, मैं केवल चार्जशीट पढ़ रहा हूँ। मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: He is reading only the chargesheet. If you want to challenge it, challenge it. यदि वे उसको ऑथेंटिकेट करेंगे तो वह माना जाएगा।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, मैं इस चार्जशीट को टेबल पर प्रस्तुत करने को तैयार हूं। … (व्यवधान) इनके असेट्स ईडी ने जब्त किए हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : निशिकांत जी, आप जारी रखें।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, मैंने तो अभी कांग्रेस के बारे में कहा, मैंने रॉबर्ट के बारे में कहा, मैंने चिदम्बरम साहब के बारे में कहा, मैंने विलासराव देशमुख से ले कर अशोक चव्हाण की बात कही । डीएमके वाले इनके सहयोगी हैं, इसी कारण से इनको लगता है कि यदि 'बाटी चूटी खाए राजा घर' जाए मातलब कि यदि मिलजुल कर रहेंगे तो हमको बहुत पैसा मिलेगा, तो ये लोग एक साथ क्यों नहीं होंगे? यदि ये इस तरफ आ गए तो मोदी जी की न खाएंगे न खाने देंगे की थ्योरी में यदि खाते हुए पकड़े जाएंगे तो जेल चले जाएंगे। इसी कारण से … * 'इंडी गठबंधन' नाम से बन गया है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : यदि ऐसा कोई शब्द होगा तो उसको देख लेंगे।

… (व्यवधान)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, there is a Point of Order. Under Rule 353 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, it is mentioned that:

* Not recorded as ordered by the Chair.

"No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given [adequate advance notice] to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply:

Provided that the Speaker may at any time prohibit any member from making any such allegation if the Speaker is of opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House or that no public interest is served by making such allegation."

Sir, the Member whom he is alluding to is not here. Has he given you notice about bringing in a Member who is not here where he is going to make derogatory allegations? … (*Interruptions*) The matter is *sub judice* in the Supreme Court. … (*Interruptions*) You are permitting this. You should protect a Member. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Kalanidhi, he is ready to authenticate the paper. He is just quoting something. He is ready to authenticate this also.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please carry on.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: He is ready to authenticate that.

… (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे : सभापति महोदय, रॉबर्ट तो इस देश में बहुत लोगों का नाम हो सकता है न, उनको क्यों लड़ाई हो रही है, उनको क्यों झगड़ा-परेशानी हो रही है? उसी तरह से मैंने मारन परिवार

कहा, यह तो खुद ही अपने आप को एक्स्पोज कर रहे हैं। मैंने तो दयानिधि मारन जी के बारे में नहीं कहा। मारन तो कोई भी हो सकता है, किसी का टाइटल हो सकता है।... (व्यवधान)

सर, मुझे अपनी मर्यादा पता है। मुझे संसद में बोलते हुए 15 साल हो गए। मुझे पता है कि मुझे कितना बोलना है। यह तो कलानिधि जी हैं, आप पूछिए कि उनका नाम क्या है।... (व्यवधान) मैं आपको बताऊं कि वह खुद ही, 'अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल', हमारे यहां एक कहावत है- 'के चोर तो टेकना चोर'। किसी के बारे में कहिए तो चोर को लगता है कि मेरे बारे में ही बोल रहे हैं। मैं तो मारन परिवार के बारे में बोला, रॉबर्ट के बारे में बोला। ... (व्यवधान)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY: ...[#] . ... (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे : सभापति महोदय, इसी कांग्रेस के युवराज ने कहा कि मोदी ओबीसी ही नहीं है। सारे अपोजिसन्स को इतनी परेशानी है। वह ओबीसी नहीं है। ये लोग उनको कहते हैं कि वह तेली है। आप यह समझिए कि जाति सूचक शब्द बोलने में भी एक सम्मान होता है।

सर, हमारे यहां उस समाज का कंट्रीब्यूशन है। यदि वह समाज नहीं रहता तो आज यह समझिए कि लोगों का चक्का-चूल्हा नहीं चलता, घर-दरवाजा नहीं चलता। उन्होंने इस देश में कंट्रीब्यूट किया है। कोई ऐसा गांव नहीं है, जहां उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। उनके बारे में इस तरह के शब्द बोल रहे हैं।

सर, मैं केवल दो छोटी-छोटी चीजें और बोलना चाहूंगा, क्योंकि और भी वक्ता है। ... (व्यवधान) इसमें शारदा चिट फंड की बात आई। हम लोग जिस इलाके से हैं। माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने तक आप यह समझें कि बैंकिंग की स्थिति क्या थी। लोग कहते हैं कि जन धन अकाउन्ट खुल गया, 50 करोड़ लोगों अकाउन्ट मिल गया। आप यह समझें कि किसी को फायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हमारे इलाके में फायदा हुआ।

सभापति महोदय, हमारे इलाके में बैंक के ब्रांच नहीं थे। इस कारण से लोग चिट फंड कंपनी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव कंपनी या इस तरह के गुमराह करने वाली स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट

[#] Expunged as ordered by the Chair.

करते थे। यही कारण है कि बंगाल, बिहार और झारखंड का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। एक तो कैश डिपॉजिट रेशियो में हम लोगों का जो कैश जमा है, उसमें हम लोगों का क्रेडिट और डिपॉजिट का जो रेशियो है, उन दोनों में बहुत फर्क है। आज भी वह 30-35 परसेंट से ऊपर नहीं आ पाया। इसके बारे में रूडी जी भी बोल रहे हैं। रूडी जी भी बड़ा प्रयास करते हैं कि हमारे लोगों को क्रेडिट मिले। हम लोग भी लगातार प्रयास करते हैं। आज आप यह समझें कि उसी बंगाल में शारदा चिट फंड का एक कांड हुआ। मैंने आपको कहा कि ये सभी एक साथ इकट्ठा क्यों हो गए। उसमें जब रेड हो रहा है, बंगाल में रेड हो रहा है तो किसी मंत्री के यहां 50 करोड़ रुपये, किसी के यहां 40 करोड़ रुपये, किसी के यहां 20 करोड़ रुपये कैश पकड़ा रहा है। मैं बंगाल की बात कर रहा हूं। उस पैसे का क्या यूज हो रहा है? मैंने आपको कहा कि जिस तरह से तिरूपति से पशुपति तक एक नक्सलिज्म हो गया था, नक्सल का एक बेल्ट बन गया था, उसी तरह से आज की डेट में पूरा का पूरा बांग्लादेशी, चाहे वह बरपेटा-नवगाँव से शुरू कीजिए, धुबरी होते हुए, मालदा, मुर्शिदाबाद, किशनगंज, कटिहार, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा होते हुए एक कॉरिडोर बना है। ये सारे इलीगल पैसे एक पोलिटिकल पार्टी के हाथ में जा रहा है। उसका सिंगल प्वाइंट एजेंडा केवल मुस्लिम वोट बैंक है। यही व्हाइट पेपर है, यही इस देश को बताने की आवश्यकता है कि इस तरह की जो इल्लीगल व इलिसिट मनी है, उसका क्या उपयोग हो रहा है?

सर, अंत में, चूंकि हम झारखंड के हैं। 15 साल तक झारखंड और बिहार करप्शन से बहुत परेशान रहा। हमारे बच्चों का विकास नहीं हुआ, हमारे यहां रोड नहीं बना, हमारे यहां नाले नहीं बने। विस्थापन और पलायन के कारण बिहारी पूरे देश में लेबर हो गए। आज बिहार के लोग कहीं जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता और मद्रास कमाने के लिए जाए तो लोगों को लगता है कि हम पॉपुलेशन पर बोझ हो रहे हैं। जबकि 80-85 परसेंट से ज्यादा माइन्स और मिनरल्स हम देते हैं। हमारे कारण यह देश है। चाहे वह झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, ओडिशा हो, वेस्ट बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, यदि हम नहीं हों, तो शायद इस देश की इकोनामी नहीं बढ़ पाए। आज भी मैं दावे के साथ

कह रहा हूं कि रेलवे यदि चल रही है तो 40 पर्सेंट से ज्यादा रेवेन्यू केवल और केवल अकेला झारखंड देता है। हमारा इस देश को बढ़ाने में, आगे चलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है।

माननीय मोदी जी ने चतुर्थ वर्ग में साक्षात्कार को बंद कर दिया। तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग श्रेणी के कर्मचारियों को अब इंटरव्यू देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ... (व्यवधान) इस व्हाइट पेपर में है, लैंड फॉर जॉब स्कीम। मैं व्हाइट पेपर के अलावा कुछ नहीं कह रहा। यह मेरे लिए बाइबिल है, रामायण है, महाभारत है, इसके आगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं केवल यही बताऊंगा कि आपने किस तरह से लूट राज किया और किस तरह से यह इंडी गठबंधन ... [#] का एक गठबंधन बन गया है। जिन बच्चों ने पैसे दिए, उनकी ही नौकरी लगी। जिन बच्चों के माता-पिता पैसे देने की स्थिति में नहीं थे, उनकी जमीन जबरदस्ती लिखवा ली गई, अपने नाम से लिखवा ली गई, शैल कंपनी बना ली गई। दिल्ली से लेकर मुंबई और बाहर तक उन्होंने आलीशन मकान खरीद लिए। बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। आज उनके मां-बाप कराह रहे हैं। यह स्थिति है। उस कारण से हमारे बिहार में ऐसा हुआ कि वह व्यक्ति जेल गया। आज भी जो चार्जशीट चल रही है, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा परिवार जेल जाएगा। क्या इसी तरह की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। आप जो अर्थव्यवस्था छोड़कर गए, वह एक करप्ट अर्थव्यवस्था थी। जो देश का विकास होना चाहिए, उस विकास को आपने नहीं किया। वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल जो आपका शासन रहा, वह केवल और केवल लूट का इतिहास है। यह इस देश को जानने की आवश्यकता है। जब हम सरकार में आए तो वे एक ट्रांसपेरेंट सरकार देख रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देख रहे हैं। वे माननीय मोदी जी के विकास को देख रहे हैं। वे रेल देख रहे हैं, एम्स देख रहे हैं। वे ऐसी स्थितियां देख रहे हैं, जिसमें लगता है कि अमेरिका और लंदन हमसे पीछे हो जाएगा। वे ऐसी अर्थव्यवस्था देख रहे हैं जो आज 5 नंबर पर है और तीसरे कार्यकाल में हम तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। उन्हें यह नहीं पता है कि जब माननीय मोदी जी आए, किस तरह की अर्थव्यवस्था लेकर आए। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं था, सरकारी कर्मचारी को देने के लिए पैसे नहीं थे। कोई भी स्कैम ऐसा नहीं था, चाहे वह टू जी हो, चाहे वह कोलगेट हो, चाहे वह

[#] Expunged as ordered by the Chair.

आदर्श स्कैम हो, चाहे वह 20,80 हो, चाहे वह डिफेंस घोटाला हो, सारे स्कैम को यदि मिला लीजिए तो वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक इस सरकार ने बैंक के स्कैम से लेकर सब मिलाकर लगभग 60 लाख करोड़ रुपये का स्कैम किया था। ये सारे पैसे ब्लैक मनी के तौर पर स्विटजरलैंड से लेकर टैक्स हैवेन तक में जमा हैं।...(व्यवधान) जो पनामा पेपर से लेकर पेंडोरा पेपर तक आ रहा है, वह यह बता रहा है कि वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक किस तरह की अर्थव्यवस्था को हमने जन्म दिया। इसीलिए, यह सब जानने की आवश्यकता थी।

हम शुक्रगुजार हैं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस पर चर्चा कराके इस देश को बताने का प्रयास किया कि हम बहुत ही सलीके से इस देश को बचाकर लाए हैं, रामराज्य स्थापित करने आए हैं, राम हजार साल के बाद आए हैं। हम माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति शुक्रगुजार हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप जीते रहिए, आपकी जिंदगी बढ़ती रहे और जब तक आप जीते रहें, इस देश के प्रधान मंत्री रहें। यही हमारी कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।

14.00 hrs

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Hon. Chairperson, Sir, I thank you very much for giving me an opportunity to speak on this White Paper on the Indian economy. This title 'White Paper on the Indian Economy' has got me surprised because when we talk about White Paper on Indian economy, what timeframe we are talking about. They are talking only about the last twenty years. I would like to highlight what the status of the Indian economy has been probably pre-Independence period onwards. Look at the Mughal period. We boast by saying that India had about 25 to 30 per cent of the world's GDP. Subsequently, even when the Mughals were ruling here, they ensured that the wealth of the country stayed in the country and we were a prosperous nation. Subsequently, during the British Rule, we were systematically looted where when we got our

Independence in 1947, India's GDP was only about one per cent of the world's GDP.

Since then, from 1947, our late Prime Minister, hon. Jawaharlal Nehru, was having the biggest challenge of nation building. When we got our Independence, there were so many countries which raised aspersions and said that India would not stay as a nation and would disintegrate soon. This was the criterion under which the Government was functioning at that point of time. You also know the number of wars we had earlier with Pakistan and China. All these things had to be taken care of.

At that point of time, the biggest threat to our nation was poverty. During that period, things like Green Revolution and White Revolution to improve agricultural production and milk production needed to be focussed on. In fact, during those periods, our GDP growth was probably one per cent or 1.5 per cent. In fact, we used to be ridiculed by people saying that this is the Hindu rate of growth, but in 1991, the then Prime Minister, Mr. P.V. Narasimha Rao assumed office and the Finance Minister was Dr. Manmohan Singh who later went on to become the Prime Minister for ten years. Under these two capable leaders, the economy of the country was opened up and after opening up of the economy, our economy improved.

14.03 hrs (Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

This Government has given this White Paper where they have talked about twenty years. I would like to go ten years further back and talk about the things which have been happening from 1994. In 1994, India's GDP was USD 327

billion. In 2004, it went up to USD 709 billion, which is a growth of 115 per cent in that decade. What was USD 709 billion in 2004 grew up to USD 2.01 trillion in 2014, registering a growth of 180 per cent. But the GDP which was USD 2.01 trillion in 2014, has grown only up to USD 3.6 trillion in 2024 and the growth rate is around 75 to 80 per cent. So, it has not even crossed 100 per cent. Had they done a better job, probably the GDP of this country could have touched USD 5 trillion already.

Sir, there are certain people who make comments – who are not from our party – who are their own party persons. The Rajya Sabha Member, Dr. Subramanian Swamy has made comments saying that the hon. Prime Minister does not know anything about economics and the Finance Minister knows nothing about what economy is or finance is. So, this is a statement which has been made by their own party Member and they expect us to believe that from 2004 to 2014, when the country was being run by one of the brightest minds in economy and finance and where the growth was about 180 per cent, was a period with bad growth and this period, the ten-year period of their tenure, is a golden era and has seen great wonders.

In 2014, when the present Prime Minister's name was announced as a candidate, do you know what poll promises he had made? He promised that he would be able to get people two crore jobs every year and Rs. 15 lakh by bringing back all the money from Switzerland which has been stashed away by politicians. He also said that the prices of gas and petrol would be reduced to half. They had also said that the exchange rate of the US dollar would be reduced. Today, after

ten years, the Government is submitting a White Paper where there is no mention of any of these things.

This White Paper has no mention of demonetisation, the effects of it and what it achieved. All the opposition parties have been asking for that. When the Government brought in demonetisation, the concept of demonetisation was that, they were saying, the amount of black money which was being hoarded was huge, the amount of counterfeit money was huge. They said that they were going to bring all that money back into the Government. When this was said, everybody was under the assumption that counterfeit notes from Pakistan and Bangladesh were being pumped into this country whereby the economy was going to be totally smothered or smashed, but the RBI came out with a report and said that 99.7 per cent of the notes, which were printed by this Government, had come back. This only shows that the whole exercise of demonetisation was a huge failure of this Government and they have not mentioned a single word about that in this White Paper

Subsequently, we see how this Government has tried to take away the federal structure of this country. In 2014 after assuming the office of Prime Minister, the 14th Finance Commission came out with a recommendation saying that the devolution of funds to the States should be increased from 32 per cent of 42 per cent. The then Chairman, Mr. Y. V. Reddy, made a statement that the present Prime Minister opposed this and said that it should be increased only to 33 per cent. The Finance Commission's Chairman, Mr. Y. V. Reddy said that he had to put his foot down and ensure that 42 per cent was devolved. But this

Government surreptitiously to overcome this problem, what they have done from 2014 is they have increased the cess throughout the country. So, technically, they have increased the cess.

If you look at the price of petrol during the Congress period in 2014, the cost of petrol was Rs. 60, the actual cost of petrol was Rs. 40, the State tax was Rs. 10, the Central tax was Rs. 10, and cess would have been something around 0.5 per cent. But if you look at the present value of petrol, the cost of petrol is Rs. 50, the Central tax is Rs. 20, the State tax is Rs. 20, and cess is Rs. 20. So, they are taking away Rs. 20 throughout the country and they are not giving it back. In fact, if you look at the Government over the last two years, they have imposed something called windfall tax on oil companies. This windfall tax is for making excessive profits and they are saying that the cost of petrol and diesel is now market-driven and we will not be able to control that. Instead of calling this a windfall tax, you could have given the benefit to the people of this country where the price of petrol and diesel could have been brought down. The price of gas which was Rs. 400 has now crossed Rs. 1,200. It has seen a 300 per cent increase. This is what this Government has achieved in the last ten years.

Today, they are saying that they have alleviated poverty where 25 crore people have been brought out of poverty. If that is the true figure, I would really like to appreciate this Government. But in the same breath, they say that during COVID-19, the economy was very badly hit and the people were suffering. Eighty crore people had to be provided free rations. Eighty crore people were provided rations at that point in time, which is something commendable. Even in Tamil

Nadu, individuals, party people, and everybody was providing that kind of support to those who were needy. But you are now coming out and saying that for the next five years 80 crore people are going to be provided with free rations. So, you are saying that 80 crore people cannot even afford to buy their own food and you are saying that you have brought people out of poverty. Eighty crore people in a 140-crore population of India means it is more than 55 per cent. So, more than 55 per cent people dependent on the Government for their sustenance is a very, very sad state of affairs.

Sir, today, Nishikant Dubey ji was talking about scams. He was talking about the 2G scam, the coal scam, Aircel-Maxis scam, and all these scams. They have only been making these accusations. My question is this. They have been in Government for ten years. Why have they not taken any action against any of these people and put them behind bars? If you had proof or any kind of evidence, you should have taken some action about that.

They are only throwing accusations and it is very sad. This is my first term as a Member of Parliament. When I came here, I was hoping that we will be having great debates about how to take this country forward. But the only thing I see is just bickering happening about the ruling Government which has been in power for ten years accusing not only the past Government but they are talking about Jawaharlal Nehru. When Jawaharlal Nehru died in 1964, I think the present Prime Minister would have been ten or eleven years old. I do not know what kind of affixation or obsession he has with Jawaharlal Nehru that every time he says the reason why India is pathetic is because of Jawaharlal Nehru. It is actually very

sad to see that a person, a tall leader being belittled in such a fashion, which is actually very shameful.

Sir, this present Government is saying that opposition parties have corruption on them, they have nepotism on them. These are the accusations they are making and they are having a poll plan. When you are talking about this corruption, the C&AG has come out with a statement saying Rs. 7.5 lakh crore of irregularities have happened in the Ayushman Bharat cases and in road development. There was a ceiling of Rs. 18 crore to be spent per kilometre and they have shown that Rs. 250 crore were spent per kilometre and they have asked questions. This Government and the Treasury is silent on those kinds of issues. I wonder if they really want to be fair about having the truth brought out, they should have set up some kind of a Commission to inquire on this CAG Report and why is it that it has been brought out like this. Today, we are talking about scams and corruption whereas their own Party President, one Mr. Bangaru Laxman at one point of time was caught red handed taking bribe. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

… (*Interruptions*)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY: He was sentenced. … (*Interruptions*) Also, the present BJP President in Tamil Nadu openly makes a statement that every month he has an expenditure of Rs. 8 lakh, which is provided for by friends. What is this if not corruption? No action has been taken despite me writing to the Finance

Minister and the hon. Prime Minister to inquire into this matter about how he is getting this thing.

The only thing I am very surprised about when the Prime Minister spoke was saying that this is 'Modi's guarantee'. Are we trying to sell a product? I cannot even understand what kind of a language this is. To say that I am giving you some product and I am giving you a guarantee for this, what kind of language is being spoken?

What guarantee did you give when you said that you are going to give two crore jobs? Where did that guarantee go? What guarantee was there when you said that petrol and gas prices will be brought down? Where is that guarantee? Did you achieve that guarantee? You had also said that Rs. 15 lakh will be provided to each and every household by bringing money from Switzerland. Where is that guarantee? You have not answered the guarantees that you gave in 2014 and you have come out with a new set of 'jumla guarantees' in 2024 only for the sake of political appeasement. Thank you very much.

प्रो. सौगत राय (दमदम): सभापति जी, वित्त मंत्री जी ने बहुत लम्बे-चौड़े भाषण वाइट पेपर और आर्थिक स्थिति पर दिए। मेरे ख्याल से वित्त मंत्री जी को सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन के लिए सारे देश से माफी मांगनी चाहिए थी। इतना बड़ा स्कैम इतिहास में कभी नहीं हुआ। इन लोगों द्वारा कहा गया था कि सारा काला धन वापस आ जाएगा। डिमोनेटाइजेशन से पहले 16 लाख करोड़ रुपये कैश सिस्टम में था और डिमोनेटाइजेशन के बाद 16 लाख करोड़ रुपया वापस आ गया। यह रुपया कहां से आया? आप कहते थे कि पाकिस्तान से टेरेरिस्ट फंडिंग आती है, हम इसे बंद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 150 लोग बैंकों की लाइन में खड़े होकर मर गए, लेकिन इसके लिए सरकार की तरफ से कोई माफी नहीं मांगी गई और ये लोग यहां बड़े-बड़े भाषण दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि नीरव मोदी कहां है? मेहुल चौकसी कहां है? विजय माल्या कहां है? आपके पास कानून है, for fugitive economic offenders. जेटली जी जब वित्त मंत्री थे, तब वह लेकर आए थे। जेटली जी अब गुजर चुके हैं और नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या देश में वापस नहीं आए।

I do not say that corruption should be defended. You know that our Party was part of UPA from 2009-2012. When the coal scam came out, our Party decided that we quit the Government. In 2012, we quit the Government and we kept ourselves away, लेकिन हम चाहते थे कि डिमोनेटाइजेशन का पूरा हिसाब हो। हम इसे फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी में उठाएं। उसकी रिपोर्ट पर आज बहुत बड़े मेंबर ने बात की, लेकिन उनको करने नहीं दी। डिमोनेटाइजेशन की रिपोर्ट नहीं दी गई, जबकि उस समय वीरप्पा मोइली फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन थे। सर, मैं यह नहीं बताना चाहता कि यूपीए में सब ठीक था, लेकिन यूपीए ने गरीब लोगों के लिए महात्मा गांधी एनआरईजीए किया था। यदि आपने अपने समय में गरीबों के लिए एक भी बड़ा कदम उठाया है तो दिखाइए। यूपीए फ्री फूड देने के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (एनएफएसए) लेकर आई थी। यूपीए फॉरेस्ट राइट एक्ट और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाई थी। यूपीए वर्ष 2006 में आधार लेकर आई थी। वर्ष 2008 में जब सारी दुनिया में आर्थिक संकट था, तब हमारे

बैंकिंग सिस्टम ने यूपीए के समय में उसका मुकाबला किया। आज हम यह कहते हैं कि इस सरकार में कोई नहीं है जो ये सब संभाल सकते हों। इनके जमाने में इकोनॉमिक रिफॉर्म बंद हो गया। यह सरकार केवल ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। ये कहते हैं कि बड़े-बड़े स्कैम हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एक भी स्कैम में कन्विक्शन हुआ? दस साल हो गए, आप क्या कर रहे थे? केवल ईडी और सीबीआई से विरोधियों पर रेड कराते रहे। आप एक भी आदमी को कन्विक्शन नहीं कर पाए। क्या आप जानते हैं? आप बैंकिंग के बारे में बोल रहे हैं। अगर रघुराम राजन, वे रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, उन्होंने पहला एसेट क्वालिटी रिव्यू किया था। अगर वे नहीं करते तो बैंक डूब जाता। लेकिन, रघुराम राजन को इन लोगों ने टिकने नहीं दिया, क्योंकि वे एक नेक आदमी थे। वे आज भी हैं।

अडानी के बारे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई। उस रिपार्ट पर सेबी को रिपोर्ट देनी थी, लेकिन, इस सरकार से हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में कोई राय नहीं आई।

सर, ये डिफेंस डील की बात करते हैं। इनके जमाने में राफेल को खरीदने में क्या घोटाला हुआ? सरकार उसको क्यों नहीं सामने लाती या बताती है?

सर, इन्होंने शारदा चिटफंड के बारे में बोला है। मैं पूछना चाहता हूं, हम लोगों ने फाइनेंस कमेटी में इसके बारे में चर्चा की थी और हमने कलेक्टिव इंवेस्टमेंट की एक रिपोर्ट भी दी थी। शारदा चिटफंड का जो सबसे बड़ा बेनिफिशरीज था, वह आज ...* है। वह मोदी जी का घनिष्ठ है। ... (व्यवधान) वहां भी कोई कदम नहीं उठाया गया। आज तक एक भी आदमी कन्विक्ट नहीं हुआ। इसलिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार केवल ईडी और सीबीआई को लेकर सरकार चलाती है। मोदी जी के दो भाई 'ईडी और सीबीआई'। ये दोनों भाई को लेकर चलते हैं। ये देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं।

सर, ये लोग फोन बैंकिंग की बात करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। अडानी जी को आस्ट्रेलिया में माइन खरीदना था। जब मोदी जी आस्ट्रेलिया गये तो अडानी भी उनके साथ गए। उस

* Not recorded as ordered by the Chair.

समय स्टेट बैंक की जो महिला चेयरमैन थीं, वे भी साथ में गईं थीं, ताकि अडानी आसानी से कोल माइन खरीद सकें। कोल माइन खरीदने के बारे में इनकी कोई जांच नहीं होगी। मैं तो कहता हूं कि यह सरकार देश को आगे नहीं बढ़ा सकती है। मैंने तो पहले भी बताया है, इनके जमाने में लैटेस्ट इंफ्लेशन फीगर क्या है, retail inflation surged to 5.69 per cent in December. The CPI reading continues to cross the Reserve Bank of India's upper tolerance medium-term target of 4 per cent within a band.

महोदय, सब चीजों का दाम बढ़ रहा है, खासकर फूड और सब्जियां, जैसे प्याज इत्यादि। ये लोग इसको नहीं संभाल पा रहे हैं। मैं इस सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि इनके जमाने में रिफॉर्म्स बंद हो गए हैं। इस सरकार में ऐसा कोई नहीं है, जो यह बता सके कि वर्ष 2034 या 2044 में आर्थिक ढांचा कैसा होना चाहिए। इस सरकार में एक भी वर्ल्ड क्लॉस इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। वित्त मंत्री जी तो इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, उनको जानकारी भी नहीं है।

महोदय, इन्होंने जीएसटी लागू किया था, but GST has disrupted existing trade structure. ये इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्ट्सी कोड लाए थे, but 20 per cent of bank loans are being recovered. ये सरकार …* है। इसमें काबिल आदमी नहीं है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने 'श्वेत पत्र' में अनियंत्रित बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने यह नहीं बताया कि 30,000 किसानों और एग्रीकल्चरल लेबर्स ने खुदकुशी की है। उन्होंने यह नहीं बताया कि वर्कफोर्स में वूमेन का पार्टिसिपेशन काफी कम है।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि इनके जमाने में India's GDP grew at an average of 5.6 per cent. But India's growth rate was higher from 2000 to 2010 at 6 per cent. Economists say India's economy needs to grow at more than 6 per cent to 7 per cent. रघुराम राजन जी ने क्या बताया था? उन्होंने कहा था कि "India is poorest among the BRICS nations - Brazil, Russia, India, China and South Africa. It has also a larger

* Not recorded as ordered by the Chair.

distance to travel. Growth has to be set in perspective." Sir, India's unemployment is very high, compared to pre-pandemic levels.

सीएमआई ने कहा कि 10 प्रतिशत छूट गया और हमारे ऐसे नौजवान हैं, जिनकी उम्र 15 से 34 साल के बीच है, उनमें बेरोजगारी की दर 45.4 प्रतिशत है। लेबर फोर्स में वूमेन पार्टिसिपेशन कितना है? अभी एक महिला वित्त मंत्री हैं। India's female labour force fell from 25 per cent to 24 per cent in 2022. And we are lower than regional neighbours like Bangladesh, Sri Lanka and Pakistan. India's spending on research and development has fallen in the past decade. It is only 0.7 per cent of GDP, lower than BRICS, and far below the 5 per cent GDP spent by countries like South Korea and Israel.

वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम पूरी दुनिया में 161वें स्थान पर हैं। हमारा जो आर्थिक ढांचा है, वह गरीबों के लिए नहीं है। उसमें समानता नहीं है। विश्व बैंक ने ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी किया है। It measures the country's education and health outcomes. India's score is 0.49, below Nepal and Kenya, both poorer countries. In 2019, less than half of India's ten-year-old children could read a simple story, compared to 80 per cent of Chinese children and 96 per cent of Americans.

महोदय, मैं यह बोलना चाहता हूं। हां, भारत में एक अपर मिडिल क्लॉस है, जो लोकल स्टॉक मार्केट में जाता है, लेकिन वह हमारी जनसंख्या का केवल तीन प्रतिशत है। By comparison, 13 per cent Chinese and 55 per cent Americans have some investments.

By far the biggest beneficiaries of India's stock market are the political insiders. Best connected of all is Gautam Adani who has a long relationship with

Modi. Billionaire families like ...* in State building. But they are not globally competitive. India has failed to capitalise on rising labour cost in China. Bangladesh was more entrepreneurial and has higher GDP per capita. यह हमारे पास मौका था। हमारे पास चाइना से बिज़नेस छीनने का मौका था, लेकिन हम यह नहीं कर पाए हैं। वित्त मंत्री ने क्या भाषण दिया? हमारी आर्थिक स्थिति आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? हम चीन से पीछे क्यों हैं? हम ब्रिक्स कंट्रीज के पीछे क्यों हैं? हमारी ह्यूमैन कैपिटल इतनी खराब क्यों है? यह आपको बोलना पड़ेगा।

Extrapolating India's current growth into the future is a fraught exercise. The country's infrastructure still has many gaps in supporting a vibrant manufacturing sector. The education system is not equipping young people with the vocational skills needed for a modern economy. Job growth has been weak with little net employment in the manufacturing and service sectors. This will lead to risk of social instability. Only a few well-connected families have accounted for a significant share of growth.

जो ग्रोथ होती है, उसको कुछ फैमिलीज़ ले जाती हैं। चाइना के कंपेरिजन में हमारी जो ग्रोथ होती है, उसका बड़ा अंश ये बड़े लोग ले जाते हैं। यह जो बेरोजगारी है, जो असमानता है, इसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। सरकार के पास जवाब नहीं है कि इन्होंने डिमोनेटाइजेशन क्यों किया था? ... (व्यवधान) चार-पांच राज्य एक रास्ते पर उतरे हैं। उनमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, बंगाल हैं। हमारे मुख्य मंत्री ने कल अनांउस किया कि हर महिला, जिनकी 25 से 60 साल की उम्र है, उनको एक हजार रुपये महीने मिलेंगे। क्या मोदी सारे देश में ऐसा कर सकते हैं? ... (व्यवधान) हमें मनरेगा का पैसा नहीं मिला है। हम वाइट पेपर का विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि ये देश को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। धन्यवाद।

* Expunged as ordered by the Chair.

HON. CHAIRPERSON: Shrimati Vanga Geetha Viswanath

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Thank you Chairman, Sir, for giving me this opportunity. I would like to speak in Telugu.

*Sir I am fortunate to speak in the last session of 17th Lok Sabha. I also thank my leader and hon. Chief Minister of Andhra Pradesh Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy garu for giving me an opportunity to serve as a Member of Lok Sabha from 2019 to 2024. I appreciate and thank our Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman for presenting a White Paper on Indian economy. People should know about the economic conditions of our country. We have faced many difficulties during COVID Pandemic and faced many challenges at that point of time. Throughout the world there were many countries which were facing financial crisis but our Prime Minister had controlled the situation in our country. Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman also handled the situation effectively. Let it be in health sector or in economy, the Government had taken some effective steps.

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Sir, I am on a point of order. There is no quorum in the House. … (*Interruptions*)

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Sir, there is no quorum in the House. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kindly take your seat.

… (*Interruptions*)

* English translation of the speech originally delivered in Telugu.

HON. CHAIRPERSON: Madam, please wait for some time. You can take your seat.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The bell is being rung-

Now, there is quorum. The hon. Member, Shrimati Vanga Geetha Viswanath may continue.

अब काफी सदस्य आ गए हैं।

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Madam, you can now continue your speech. The number is more than sufficient.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH: Sir, now, I am continuing my speech.

***** Sir, this White Paper on Indian economy has been presented in the House and it is very important for the people of this country to understand these conditions. I commend this step taken by the government.*****

There are several reports of the reputed international bodies concerning the levels of economic and income disparity in the country. They highlight the large disparity in wealth distribution in India, mentioning that more than 40 per cent of the wealth created in the country from 2012 to 2021 had gone to just 1 per cent of the population while only 3 per cent had trickled down to the bottom 50 per cent.

***** …. *****English translation of this part of the speech originally delivered in Telugu.

*Sir, we all should appreciate timely steps taken by the Government to revive economy. At the same time, I also would like to add that there are many more measures to be taken by the government to make our economy more robust. Many members referred to so many points. Let it be regarding black money or let it be about 15 lakh rupees that were to be deposited in the accounts of people of this country or let it be regarding GST implementation.

After corona pandemic MSME industries were adversely affected, because they had taken heavy loans from the banks and due to corona pandemic and complete lockdown, they could not pay interest to the banks nor they could run their businesses. And they have reached a position where they have to auction their properties. They are yet to get the justice; they will have to get the settlements from the banks. But there is no mention about these issues in this White Paper. Similarly, if you look at the stability of our economy, our country has many professions which are dependent on agriculture. Agriculture sector is facing tough times due to extreme weather conditions. Let it be sugarcane, cotton, paddy or vegetables, all these crops incurred huge losses. In such a scenario, if we have a separate fund for agricultural produce, we can get relief. I would like to propose that we will have to take special steps for encouraging industrialization. In our country, 197 sugar factories were closed in the recent past. Sugarcane farmers, other workers depend on these factories. If you do not show alternative

* ....*English translation of this part of the speech originally delivered in Telugu.

livelihood to the workers and farmers who are dependent on those factories, that is not a good situation.

When it comes to Andhra Pradesh, at the time of bifurcation of Andhra Pradesh we were given so many promises. To meet expenditure of Polavaram project and other rehabilitation measures Central Government should release required funds. Though the central government released funds in line with funds that were allocated for other states, we did not get the funds that would have helped Andhra Pradesh to progress. We did not get support from union government for our progress. In this 'Amrit kaal' we are not even getting drops of *amrit* for our State. Polavaram project is a multipurpose project and Andhra Pradesh needs to develop and complete this project to progress in sectors like power, irrigation and agriculture. That project has the potential to generate 900 MW this development is not confined to the state of Andhra Pradesh. India means Union of States. if States progress and become financially strong only then our India will progress. States should be treated well and provided with adequate funds especially to bifurcated states. They should be provided with more support. We are all Indians and we need to treat all Indians equally. As far as many demands pertaining to the state of Andhra Pradesh we need support from union government. When we talk about the capital investment, we see that some of these funds were curtailed. I demand that these funds may be provided at the earliest. Lastly, I would like to refer to 2 points under AP Re-organisation act. Integrated Refinery and Petrochemical Complex and Integrated Steel Plant in Kadapa under section 93 of AP re-organisation act were promised. But these

projects are yet to be sanctioned to our state. Apart from this these, there are some colleges and universities that were sanctioned but funds are yet to be released. Lastly, we understand about economic situation in our country through this 'White Paper' from 2014 to 2024. We can understand what the challenges were since 2014. But we should come out with great planning for the next 10 years for our youth, our people, our farmers, workers and all people in our country.

How can we make them financially strong? How can we make them partners in our development? We will have to think in these lines. And my last point is on the basis of Jan Dhan, Aadhar and mobile phones. Jan Dhan accounts for financial inclusion, Aadhar for biometric identity authentication, and mobile telepathy for connectivity is probably the best achievement of this Government. Once again, I request full support from Union Government for the State of Andhra Pradesh. I request the Government to help our Chief Minister and people of our State. I request the Government to complete Polavaram Project. I request complete support from Union Government. Thank you.*

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): सभापति महोदय, आज आपने मुझे इस सदन में वर्तमान सरकार द्वारा दिए गए 'श्वेत पत्र' के संदर्भ में बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ।

सभापति महोदय, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्य मंत्री, पूर्व सांसद राज्य सभा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज वर्तमान सरकार द्वारा दिए गए 'श्वेत पत्र' और पूर्व में यूपीए सरकार के द्वारा दिए गए 'ब्लैक पेपर' के संदर्भ में अपने एक बयान में कहा है कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच अगले लोक सभा आम चुनाव से पहले गंभीर आरोप-प्रत्यारोप की आपाधापी तथा ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर जारी करके एक-दूसरे को गलत एवं जनविरोधी साबित करने का खेल चुनावी स्वार्थ के सिवाय कुछ भी नहीं है। ऐसी संकीर्ण राजनीति से देश व जनहित एवं जनकल्याण कैसे संभव हो सकता है?

महोदय, ख़ासकर ऐसे समय जब कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों को छोड़ कर देश के करोड़ों लोग जबरदस्त महंगाई, अपार गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली तथा ग्रामीण भारत की दुर्दशा आदि से तनावपूर्ण जीवन की मार से लगातार त्रस्त हैं जिससे देशहित भी लगातार प्रभावित है । सभी राजनैतिक दलों को स्वार्थ व विद्वेष आदि को त्याग कर देश की अति-चिन्तनीय राष्ट्रीय समस्याओं पर संगठित प्रयास बहुत जरूरी है। महोदय, वैसे तो हर सरकार समय-समय पर व्हाइट पेपर जारी करके आंकड़ों के माध्यम से अपनी वाह-वाही बटोरने के साथ ही पिछली सरकार को कटघरे में खड़ा करके आत्मसंतुष्टि का प्रयास करती है, किन्तु हर सरकार की नीति व उसके कार्यकलापों का सही आंकलन जनता की बेहतर रोटी-रोजी व इनकी खुशी एवं खुशहाल जीवन पर निर्भर करता है। जिस मामले में पहले कांगेस पार्टी की तरह ही वर्तमान की भाजपा सरकार का रिकार्ड भी न तो उल्लेखनीय है और न ही सराहनीय माना जायेगा । महोदय, इसीलिए वर्तमान भाजपा सरकार के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी द्वारा "ब्लैक पेपर" जारी करके इनके पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल को हर प्रकार का अन्यायकाल बताने से पहले कांग्रेस को यह जरूर सोचना चाहिए था कि अगर उनके अपने यूपीए के 10 सालों के कार्यकाल

का रिकार्ड, खासकर देश की गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन तथा भ्रष्टाचार दूर करने के मामले में शानदार रहा होता तो फिर भाजपा को देश की सत्ता में आने का मौका नहीं मिलता।

महोदय, इसी प्रकार, वर्तमान भाजपा सरकार का पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल अगर जनहित, जनकल्याण, देशहित, सामाजिक एवं धार्मिक सौहार्द, शान्ति-व्यवस्था आदि के मामले में बेहतरीन होता तो सर्वसमाज के करोड़ों लोग आज जीवन के हर क्षेत्र में इतने परेशान व बदहाल कभी नहीं होते और न ही महंगाई गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन आदि से तंग जीवन से गुजर रहे 80 करोड़ से अधिक मेहनतकश लोगों को थोड़े से सरकारी अनाज के लिए विवश, मजबूर व मोहताज जिन्दगी गुजारने का मौका नहीं मिलता।

महोदय, इतना ही नहीं बल्कि देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में अपेक्षित वृद्धि न होना, किन्तु बड़े-बड़े पूंजीपूतियों, धन्नासेठों का दिन दोगुनी व रात चौगुनी धनवान होना, एससी, एसटी व ओबीसी आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाना, इनके बैकलॉग को नहीं भरना, विश्व बाजार में रुपये का अवमूल्यन जारी रहने व आम जनजीवन में भ्रष्टाचार में उल्लेखनीय कमी नहीं आना, कुछ जनहित के ऐसे खास मुद्दे हैं, जो लोगों को विचलित करते रहते हैं। जो देश को उसके समतामूलक कल्याणकारी विकास के महत्वकांक्षी उद्देश्य से दूर कर रहे हैं और साथ ही भाजपा को कांग्रेस राज जैसी बुराइयों वाला साबित कर रहे हैं। महोदय, इसके विपरीत, भाजपा सरकार द्वारा 'श्वेतपत्र' के जरिए पिछली यूपीए सरकार पर अर्थव्यवस्था को दस साल में बर्बाद करने आदि का आरोप अगर सही है तो अब गड़ा मुर्दा उखाड़ने का क्या लाभ है? देश में जनहित की असली बात तो तब होती जब देश उन सारी कांग्रेसी सरकार की बुराइयों से पाक-साफ होकर जाता, उबर जाता और देश की अर्थव्यवस्था का विकास रोजगार-रहित न होकर रोजगार-युक्त होता और इस विकास का लाभ यहां सर्वसमाज के लोगों को मिल जाता, तब यह अच्छा होता।

महोदय, वास्तव में अगर देखा जाए तो केन्द्र में सरकार कांग्रेस की रही हो या फिर वर्तमान में भाजपा की सरकार है, देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़ों, धार्मिक अल्पसंख्यकों में भी खासकर मुस्लिम समाज तथा सर्वसमाज के गरीबों, बेरोजगारों, युवाओं, किसानों, महिलाओं एवं

अन्य मेहनतकश समाज का जीवन हर प्रकार से लाचार वह मजबूर बना हुआ है। वे लोग अपने थोड़े अच्छे दिन को लगातार तरस रहे हैं, जिस पर से ध्यान बांटने के लिए ही ये पार्टियां व इनकी सरकारें लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने आदि का राजनीतिक खेल लगातार खेलती रहती हैं, जो अति-दु:खद, दुर्भाग्यपूर्ण व देशहित के विरुद्ध है, इससे जनता जरूर सावधान रहे तो बेहतर है। क्योंकि देश का संविधान सेक्यूलर संविधान है अर्थात् सभी धर्मों को एक समान रूप से आदर-सम्मान व उनके जान-माल व मजबहब को सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी देता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने पिछड़ों के लिए काम किया है, उनको आपकी सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। सरकार बधाई की पात्र है। देश के पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय चौ. चरण सिंह जी को भी आपने 'भारत रत्न' की उपाधि देकर उनका सम्मान किया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह चाहता हूं कि देश में मान्यवर श्री कांशीराम जी ने 5400 किलोमीटर की अपनी साइकिल यात्रा निकाल कर देश में दबे, कुचले समाज को एक राजनीतिक प्लेटफार्म पर लाकर खड़ा करने का काम किया है। अगर आज आप मान्यवर श्री कांशीराम साहब को 'भारत रत्न' की उपाधि से सम्मानित करेंगे तो देश के करोड़ों दलित, पिछले, मुस्लिम, सर्व समाज के लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ेगी। मैं आपसे यह मांग करना चाहता हूं कि उनका 'भारत रत्न' से सम्मान किया जाए।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सभापति महोदय, आज हम इस श्वेत पत्र पर चर्चा करने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। यह सरकार इवेंट मैनेजमेंट में माहिर है। आज हमें इवेंट मैनेजमेंट का एक उदाहरण देखने को मिला, क्योंकि यह श्वेत पत्र एक श्वेत पत्र नहीं है, बल्कि एक इलैक्शन स्टंट है, एक चुनावी ड्रामा है। सरकार की जितनी भी विफलताएं हैं, उनको छिपाने का यह एक प्रयत्न है, एक साजिश है। लेकिन लोग इस साजिश में पड़ने वाले नहीं हैं। आपके श्वेत पत्र पर लोग विश्वास नहीं करते, शायद आप ही के दल के सदस्य विश्वास नहीं करते, इसलिए आज कोरम भी नहीं था और लोग बाहर चले गए। क्योंकि ये बातें न सिद्ध हुई है, न प्रमाणित हुई है और ये दस साल से बार-बार लोगों के सामने झूठी अफवाहें लेकर जाते हैं। उसके पश्चात भी इन लोगों ने भ्रष्टाचार पर बहुत बातें रखीं और हम पर बहुत आरोप भी लगाएं। सर, जिस प्रकार से आज ये दस साल से काम कर रहे हैं, अगर भ्रष्टाचारियों को किसी ने पनाह दी है, तो आपकी सरकार ने दी है। अगर भ्रष्टाचारियों को किसी ने पनाह दी है, तो आपके दल ने दी है। मैं भी सत्ता पक्ष की तरह कुछ उदाहरण देना चाहूंगा।

महाराष्ट्र तो इनका एक आदर्श उदाहरण है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को पनाह देते हैं। मुझे तो कभी-कभी अफसोस महसूस होता है। महाराष्ट्र के इनके एक पूर्व सांसद डॉ. किरीट सोमैया हैं, उन्होंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बहुत आवाज उठाई। लेकिन मुझे भी दु:ख होता है कि उन्होंने जिनके खिलाफ आवाज उठाई थी, आज उनके दफ्तरों में जाकर सलाम करना पड़ता है। महाराष्ट्र के एक नेता है, जो पहले शिव सेना और कांग्रेस के थे, उन पर 300 करोड़ रुपये का मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगा था। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उन पर अविघ्न ग्रुप को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया था। लेकिन उस व्यक्ति ने जब अपने दल को भाजपा के साथ वर्ष 2019 में शामिल किया तो वहीं की वहीं ईडी की फाइल बंद हो गई। सर, मैं पश्चिम बंगाल का एक और उदाहरण देता हूं। नारदा को लेकर स्ट्रिंग ऑपरेशन वहां पर बहुत चर्चित हुआ था। इन्होंने नारदा को लेकर बड़े नेताओं का नाम लिया था। एक विशेष नेता, जब बीजेपी में शामिल हो जाता है और उनके विधायी दल का सभापति बन जाता है, तो उस पर नारदा का कलंक साफ हो जाता है। सर, बीजेपी ने असम में वर्ष 2015 में सागा ऑफ स्कैम्स को लेकर एक बुकलेट निकाली थी। सागा ऑफ स्कैम्स में उन्होंने एक विशेष

व्यक्ति के नाम का उल्लेख किया था, लुईस बर्जर इंटरनेशनल स्कैम के साथ, वाटर सप्लाई स्कैम के साथ इन्होंने एक विशेष व्यक्ति का नाम लिया था। इन्होंने कहा था कि जब उनकी सरकार आएगी तो उस विशेष व्यक्ति पर बहुत कार्रवाई करेंगे और वह जेल में जाएगा। लेकिन हुआ क्या? वह विशेष व्यक्ति आज इनके दल में शामिल होकर अब असम का मुख्य मंत्री बन गया। आज ऐसा हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है। छत्तीसगढ़ में इससे पहले जब डॉ. रमन सिंह जी की सरकार थी, तो ये उस समय बहुत कहते थे कि हम कालेधन का पैसा बाहर से वापस ले आएंगे। लेकिन पनामा पेपर्स में जब उस समय के छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य मंत्री के बेटे का नाम का उल्लेख हुआ तो ये पनामा पेपर्स सब भूल गए। मेघालय में ऐसा दु:ख होता है, गृह मंत्री अमित शाह जी को भी शायद अपनी बातों को व्यक्त करते हुए अफसोस होता है कि उनके मुंह से क्या शब्द निकल गए। क्योंकि हाल ही में जब मेघालय में चुनाव हुआ तो गृह मंत्री अमित शाह जी मेघालय में जाकर बोलते हैं कि वहां की सरकार दुनिया में, देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है और फिर क्या हुआ? जब चुनाव में देखा कि भाजपा को एक विधायक मिला तो उसी सबसे भ्रष्ट सरकार में ये शामिल हो गए।

सर, अफसोस है कि मणिपुर में ड्रग्स से जुड़े हुए एक मुज़रिम की रिहाई का आदेश मुख्यमंत्री के कार्यालय से जाता है। कर्नाटक में इनकी 40 प्रतिशत की सरकार थी। कर्नाटक की प्रजा जागरुक हुई और उस सरकार को उखाड़ फेंका। ये बार-बार सीएजी रिपोर्ट के आधार पर कुछ अफवाहें निकलती थीं, उन बातों पर ये बहुत आपत्ति जताते थे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ महीने पहले सीएजी ने एक रिपोर्ट निकाली थी कि द्वारका एक्सप्रेस-वे को लेकर उसकी कॉस्ट बहुत ही ओवर-ऑन हुआ। तब तो आपने सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार कोई ऐक्शन नहीं लिया।

आयुष्मान भारत योजना को लेकर एक दूसरी रिपोर्ट आई। आज किस प्रकार का भ्रष्टाचार आयुष्मान भारत में हो रहा है। ऑडिट में लिखा गया कि about 7.5 lakh beneficiaries have been registered with the same mobile number और उसकी कोई इंवेस्टिगेशन नही हुई।

About 7.5 lakh people have been registered with the same mobile number. और यह सरकार सो रही है। उसी रिपोर्ट में लिखा है कि लगभग 90 हजार लोग, जो मर चुके हैं, उनके नाम पर क्लेम्स जा रहे हैं। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये लोग सो रहे हैं।

सर, मैं उसके और भी उदाहरण देना चाहता हूँ कि इनका वॉशिंग मशीन किस प्रकार से काम करता हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा।

मैं फिर से महाराष्ट्र की बात पर आना चाहूँगा। महाराष्ट्र में एक पब्लिक ट्रस्ट, जिसका नाम है- महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान। इस प्रतिष्ठान को लेकर ईडी को चार्ज दिया गया और कहा गया कि यह मनी लॉड्रिंग का एक जरिया बन गया है। उस ट्रस्ट को लेकर, जिस पर पहले ईडी कार्रवाई कर रही थी, जब शिंदे कैम्प में वह सदस्य शामिल हो जाता है, तो ईडी की फाइल बंद हो जाती है। इसी तरह से, शिंदे कैम्प में बहुत-से लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। बीएमसी के एक फॉर्मर चेयरमैन हैं, उन पर भी ईडी के द्वारा फेमा के तहत उन पर कार्रवाई चल रही थी, बांद्रा में उनके फ्लैट को ईडी ने जब्त कर लिया था, लगभग उनकी 40 प्रॉपर्टीज पर कार्रवाई चल रही थी, लेकिन जब वे बीजेपी के सहयोगी शिंदे कैम्प में चले जाते हैं, तो कार्रवाई बंद हो जाती है। उसी प्रकार से एक विधायक हैं, जो टॉप्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, उनको ईडी ने चार्ज किया कि उनको एमएमआरडीए में लगभग 7 करोड़ रुपए का किक-बैक मिला है। लेकिन जब वे भी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो कार्रवाई बंद हो जाती है। ये किस हैसियत से बोल रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं? ये किस हैसियत से बोल रहे हैं कि न खाऊँगा, न खाने दूँगा। जो भी खाता है, वह बीजेपी में शामिल हो जाता है, जो भी खाता है, वह बीजेपी का * ... बन जाता है। बीजेपी पनाह दे रही है। बीजेपी ने ...* के लिए एक आश्रम खोल रखा है और वह सबसे ज्यादा अमीर लोगों के लिए खोल रखा है।

एक व्यक्ति हैं, जिनके खिलाफ स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि यहाँ पर 70 हजार करोड़ रुपए का इरिगेशन स्कैम हो रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री जी यह बोलते हैं और फिर वह व्यक्ति ही प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं और वे कहते हैं कि मैं महाराष्ट्र का नया उपमुख्यमंत्री हूँ। यह हो रहा है। ये

* Expunged as ordered by the Chair.

70 हजार करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। हमने तो किसानों का 70 हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। आपने तो भ्रष्टाचार से लिप्त एक व्यक्ति का 70 हजार करोड़ रुपए माफ किया हुआ है।

सर, आज ईडी बीजेपी का एक दूसरा अंग बन चुका है। ईडी को लेकर, आज हम यह देख रहे हैं कि ये ईडी का किस प्रकार से मिसयूज कर रहे हैं। ईडी का काम भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है। लेकिन आज इन्होंने यह काम किया है कि ईडी के द्वारा किस प्रकार से लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज़ को कुचला जाए और भ्रष्टाचारियों को कैसे बीजेपी में शामिल किया जाए, उसके लिए ईडी इनका विशेष अस्त्र है।

सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेबिट में लिखा है-

"A clear trend of using ED raids as a tool of harassment has been indicated." … (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।

माननीय सभापति : आपका किस नियम के तहत पॉइंट ऑफ ऑर्डर है?

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, इनको बीजेपी पार्टी का नाम लेने के लिए नोटिस देना होगा।… (व्यवधान) मेरी सरकार के ऊपर इनको जो बोलना है, ये बोलते रहें। लेकिन ये मेरी पार्टी के ऊपर नहीं बोल सकते हैं।… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : आपने कांग्रेस का नाम लिया, तो क्या आपने नोटिस दिया था? … (व्यवधान) आपने नोटिस नहीं दी थी न, तो आप बैठ जाइए।… (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज़ नहीं किया, यह आपकी गलती है।… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : पहले नियम का पालन खुद कीजिए, फिर नियम सिखाइए।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप आगे बोलिए।

श्री गौरव गोगोई : माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ता हूँ।

So, a clear trend of using ED raids as a tool of harassment has been found. The action rate on raids during 2005-2014 was 93 per cent. Now, the action rate on raids has reduced to 29 per cent. मतलब जो ये सारी रेड्स ईडी कर रही है, ये सारी रेड्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। Only 23 convictions under the PMLA have been secured. Even the number of cases registered by the ED under the PMLA have risen exponentially. वर्ष 2013 में 209 और वर्ष 2021 में 1,180, लेकिन कन्विक्शन इतना कम क्यों है? ऐसा इसलिए है, क्योंकि ये सारी रेड्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। इस ईडी अब खुद सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी दे रही है। 23 अगस्त, 2023 को सुप्रीम कोर्ट कहती है कि The Court stated that ED cannot act as a law unto itself. 4 अक्टूबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ईडी पर कहता है कि The probe agency cannot be vindictive and must be seen to act with highest degree of fairness.

सर, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, कोर्ट ईडी पर यह कह रही है और ये बोलते हैं कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। अगर ये ईडी को काम करने देते तो जो भी लोग आज विदेश फरार हो चुके हैं, ये उनको पकड़ते। विदेश में लगभग ऐसे 31 लोग हैं, जिनके ऊपर 40 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है, लेकिन आज ईडी उनको नहीं पकड़ रही है। उनमें कौन-कौन हैं? उनमें पहले नीरव मोदी जी हैं। नीरव मोदी पर 12 हजार करोड़ रुपये का फ्रॉड है, लेकिन उनको ईडी नहीं पकड़ रही है। विजय माल्या पर 9 हजार करोड़ रुपये का फ्रॉड है, लेकिन उनको ईडी नहीं पकड़ रही है। मेहुल भाई तो आपके... * के करीब हैं। मेहुल भाई पर भी 12 हजार करोड़ रुपये का फ्रॉड है। जतिन मेहता, विनसम डायमंड, वित्त मंत्री जी ने हीरे का उल्लेख किया था, एक विनसम हीरा है।... (व्यवधान)

सर, मुझे बोलने दीजिए, मेरे पास मेरी पार्टी का समय है। जतिन मेहता, जो विनसम डायमंड्स है, 7 हजार करोड़ रुपये का उन पर कर्ज है, फ्रॉड है, लेकिन उन्हें नहीं पकड़ते हैं। ललित मोदी, 125 करोड़ रुपये का आज उन पर फ्रॉड है, लेकिन नहीं पकड़ते हैं। स्टर्लिंग बायोटेक के चेतन संदेसरा,

* Expunged as ordered by the Chair.

नितिन संदेसरा पर 5 हजार करोड़ रुपये का फ्रॉड है, लेकिन उन्हें नहीं पकड़ते हैं। आशीष जोबनपुत्रा, एबीसी कॉटस्पिन के मालिक हैं, उन पर 770 करोड़ रुपये का फ्रॉड है, लेकिन उन्हें नहीं पकड़ते हैं।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री गौरव गोगोई : डायमंड ट्रेडर रितेश जैन।

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री गौरव गोगोई : सर, मुझे बोलने दीजिए।... (व्यवधान) आज इन्होंने जो श्वेत पत्र निकाला है, उसके खिलाफ हमने जो काला पेपर निकाला है, थोड़ा उसका विवरण रखने दीजिए।... (व्यवधान) सत्ता पक्ष को डरने की जरूरत नहीं है।... (व्यवधान) नीलेश पारेख, गणेश ज्वैलरी पर 2,022 करोड़ रुपये का फ्रॉड है, लेकिन उसे नहीं पकड़ते हैं। यह बीजेपी है। जितने भी अमीर हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है, जाओ विदेश जाओ। अगर मोदी जी इतने बड़े विश्व गुरू हैं, आज अगर मोदी जी की दुनिया में इतनी ज्यादा ताकत है, तो वे विदेश में छिपे हुए इन लोगों को वापस क्यों नहीं लाते हैं? ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।

श्री गौरव गोगोई : वे इन्हें वापस क्यों नहीं ला सकते?

सर, मुझे 5 मिनट का समय और दीजिए **।**

माननीय सभापति : 5 मिनट का समय नहीं मिल सकता है। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री गौरव गोगोई : सर, हमारी पार्टी का समय है। आप हमारी पार्टी और हम पर छोड़ दीजिए। अगर मोदी जी इतने बड़े विश्व गुरू हैं तो ये जो लोग देश से बाहर गए हैं, जिन्होंने 40 हजार करोड़ रुपये लूटे हुए हैं, उन्हें वापस क्यों नहीं ला सकते हैं?

सर, अब मैं अडानी को लेकर बोलूँगा। आप मुझे 5 मिनट दीजिए।

माननीय सभापति : 5 मिनट नहीं हैं। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री गौरव गोगोई : सर, मेरी पार्टी का टाइम है। अभी तक हमारे पहले स्पीकर ने सिर्फ 20-25 मिनट लिए हैं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप समाप्त कीजिए **।**

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : बहुत अडानी हैं ।… (व्यवधान) अडानी परिवार ।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप समाप्त कीजिए ।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : आपने जैसे परिवार का नाम लिया तो मैं भी अडानी परिवार का नाम ले रहा हूँ ।… (व्यवधान) अडानी परिवार आज धारावी में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट करता है ।… (व्यवधान) धारावी में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट करता है ।… (व्यवधान) दो हजार करोड़ रुपये से कम उन्होंने बिड किया, उनको धारावी का प्रोजेक्ट मिल जाता है ।… (व्यवधान) ये कैसे होता है?… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप समाप्त कीजिए ।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : अडानी परिवार की कंपनी में,… (व्यवधान) एक फाइनेन्शियल टाइम्स न्यूज पेपर है ।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : गौरव जी, अब आप समाप्त कीजिए ।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : सर, मेरे पास पार्टी का टाइम है । मैंने 10 मिनट ही बोला है ।

सर, आप आवाज बंद नहीं कर सकते हैं ।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं अगले स्पीकर का नाम बोलता हूँ । 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं । आप 15 मिनट बोल चुके हैं ।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : सर, वह हम पर छोड़ दीजिए । वह हमारी पार्टी पर छोड़ दीजिए । मुझे 5 मिनट और दीजिए ।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You have taken about 15 minutes.

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : अदानी परिवार में एक चैंग-चुंग-लिंग हैं, उन्होंने 12 हजार करोड़ रुपये के कोयले का ओवर इनवॉइसिंग किया है। इसके कारण आज हमारे देश के ग्राहकों पर बिजली का रेट बढ़ चुका है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बोलिए।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, नियम 202 (ए) यह कहता है कि मोशन या रेजोल्यूशन जिस विषय पर है, वही बात करेंगे। 59 पेज का जो यह श्वेत पत्र है, उसमें संदेसरा कहाँ है, विजय माल्या कहाँ है, उसमें अडानी कहाँ है, उसमें अंबानी कहाँ है, यह ये बता दें, नहीं तो इनकी सारी बातों को एक्सपंज कीजिए।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है। अब मैं दूसरे स्पीकर का नाम बोलता हूँ।

श्री गौरव गोगोई : ये एसबीआई की बात करते हैं।… (व्यवधान) अडानी परिवार को एक बिलियन यूएस डॉलर्स का लोन मिलता है ताकि वह कोयला आस्ट्रेलिया से ले तब इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है। अब राजीव रंजन जी बोलेंगे।

15.00 hrs

श्री गौरव गोगोई : सभापति जी, आखिर में, मैं यह बोलना चाहता हूं कि ये अर्थव्यवस्था की बात करते हैं लेकिन इनकी सरकार के समय जो अर्थशास्त्री काम करते थे, मैं उनके बारे में एक-एक लाइन बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं पांच व्यक्तियों का नाम लूंगा। आईबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है। वे इनकी सरकार के इलेक्टोरल बॉंड की स्कीम के खिलाफ थे। सुभाष गर्ग… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री राजीव रंजन जी।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : सभापति जी, सिर्फ पांच वाक्य बोलने दीजिए।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैंने दूसरे वक्ता का नाम बोल दिया है।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : सिर्फ पांच वाक्य बोलने की अनुमति दीजिए।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है, आप जल्दी अपनी बात समाप्त कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : महोदय, उर्जित पटेल का वाक्य मैंने बोल दिया । दूसरा वाक्य फार्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन कहते हैं कि "Demonetisation was a draconian move." तीसरा वाक्य विरल आचार्य, पूर्व डिप्टी गवर्नर कहते हैं कि ये सरकार आज बड़ी-बड़ी कम्पनियों को फायदा दे रही है । यह हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है ।… (व्यवधान) चौथा वाक्य अरविंद पनगढ़िया, इन्हीं के समय नीति आयोग के एडवाइजर थे। वे इस्तीफा देते हैं और कहते हैं कि मैं डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ हूं। पांचवां वाक्य रघुराम राजन कहते हैं कि आज ये आर्थिक असमानता फैला रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): सभापति जी, देश की अर्थव्यवस्था पर माननीय वित्त मंत्री जी जो श्वेत पत्र लाई हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं क्योंकि देश में भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी और फैलाई भी जा रही थी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। इस परिस्थिति में जब माननीय वित्त मंत्री जी अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र लाईं, तो आज उस पूरे भ्रम की स्थिति का पटाक्षेप हो गया और आज स्थिति स्पष्ट हो गई। श्वेत पत्र में आंकड़ों का पूरा विवरण है। सभी तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर श्वेत पत्र जारी किए गए। मैं समझता था कि जब सदन में चर्चा होगी, तो श्वेत पत्र में जो आंकड़े हैं, वे कहां गलत हैं, इसका कोई विवरण प्रस्तुत किया जाता और खंडन किया जाता। लेकिन इसके बजाय पूरी चर्चा को दूसरी दिशा में मोड़कर ले जाने का काम किया गया। डॉ. मनमोहन सिंह जी देश के प्रधान मंत्री थे। उनके समय में देश में जो कुप्रबंधन था, उसकी उसमें विस्तृत चर्चा है। अलग-अलग भाग में उसकी चर्चा की गई है कि कहां-कहां वित्तीय कुप्रबंधन था। मुझे उनके प्रधानमंत्रित्व काल में इस सदन का सदस्य रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैंने देखा था, उस समय मैंने यह देखा था कि कहां-कहां कुप्रबंधन हो रहा है। हालांकि, इसके लिए मैं डॉ. मनमोहन सिंह जी को कुछ नहीं कह रहा, डॉ. मनमोहन सिंह जी बहुत साफ आदमी थे। लेकिन, उनके इर्द-गिर्द जितने लोग थे, वे समूचे घोटाले और कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे। डॉ. मनमोहन सिंह जी बेचारे मूकदर्शक बनकर देखते रहते थे। इसलिए, इसमें उसकी विस्तृत चर्चा है। कितना ऋण दिया गया, किसे कितना ऋण मिला, जो ज्यादा ऋण दिए गए, उसकी भी इसमें विस्तृत चर्चा है। जब आप ज्यादा ऋण दे दीजिएगा तो नैचुरली उसका कुप्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

महोदय, अभी इस पर चर्चा हो रही थी। माननीय गौरव गोगोई जी विजय माल्या जी की चर्चा कर रहे थे। विजय माल्या जी को 8,040 करोड़ रुपये का ऋण कब मिला था, यह भी आप कहते। गौरव गोगोई जी, अगर आप ईमानदारी से यह बात कहते कि मेरी सरकार ने विजय माल्या को 8,040 करोड़ रुपये का ऋण दिया और वह लेकर भाग गया, तब हम मानते कि आप ईमानदार हैं। पर, आप तो ईमानदार नहीं हैं। आपने चोरी करवा दी और जब चोर भाग गया, तब आप हल्ला कर रहे हैं कि चोर क्यों भाग गया, चोर क्यों भाग गया। वाह भाई!

आप नीरव मोदी की चर्चा कर रहे थे। नीरव मोदी का जो फ्रॉड था, जो गारंटीड डिफॉल्ट था, वह कब शुरू हुआ? वह वर्ष 2011 में शुरू हुआ, जब डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। 14,000 करोड़ रुपये का गारंटीड डिफॉल्ट हुआ। आप मूकदर्शक बने हुए थे। यह आपका वित्तीय कुप्रबंधन था। अगर आप यह कहते कि हमसे यह चूक हुई और हमारी सरकार ने यह गलत किया, तब हम मानते कि आप ईमानदार राजनेता हैं। पर, आज आप यह कह रहे हैं कि नीरव मोदी भाग कैसे गया और उसको पकड़ कर क्यों नहीं ला रहे हैं। आपने तो सारे इंतजाम कर दिए। जब आपने 14,000 करोड़ रुपये उसके जिम्मे लगा दिए, तब वह भाग गया। अब यह सरकार उसको वापस लाने के लिए प्रयास कर रही है। वह भाग कर विदेश में है। अगर आपका अभी भी कोई प्रभाव है तो उसे पकड़ कर ले आइए। फिर देखिए कि वर्तमान सरकार उसे जेल में बंद कर देती है या नहीं।

आप मेहुल चोकसी की चर्चा कर रहे थे। उसने नवम्बर, 2010 से अप्रैल, 2014 तक बैंकों के साथ 8,738 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया। उस समय किसकी सरकार थी? उस समय आपकी सरकार थी, डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। यही तो श्वेत-पत्र है। श्वेत-पत्र में और क्या है? श्वेत-पत्र में आपके वित्तीय कुप्रबंधन की चर्चा है। आपने जो काम किया है, उसी को इसमें दर्शाया गया है। इस श्वेत-पत्र में उसी का आइना है और आपको यह खराब लग रहा है।

महोदय, अभी मनीश तिवारी जी बोल रहे थे। उन्होंने चर्चा शुरू की। उन्होंने कहा कि 'राइट-टू-एजुकेशन' एक्ट हमारी सरकार ने शुरू किया। इस देश में सर्व शिक्षा अभियान किसने शुरू किया था? इस देश में सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2004 में नौवीं पंचवर्षीय योजना में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था। उस समय केन्द्र और राज्य की हिस्सेदारी में 85 प्रतिशत हिस्सेदारी केन्द्र सरकार की थी और 15 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकार की थी। वह दसवीं पंचवर्षीय योजना में भी लागू रहा, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी लागू रहा, लेकिन वर्ष 2010 में आपने उसको समाप्त कर दिया। आपने यही नहीं किया, वर्ष 2004 के बाद जब अटल जी ने इसे शुरू किया था, तो उस समय केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी थी और जब आपने उसे खत्म किया तो उसकी सारी लायबिलिटी राज्यों के माथे थोप दी। आपने जितनी बहाली की थी, सभी को स्टेट्स के माथे पर थोप देने का

आपने काम किया। वर्ष 2010 में आप एक नया कानून 'राइट-टू-एजुकेशन' लेकर आ गए। क्या यही आपका प्रबंधन था? क्या यही आपके जनहित के काम थे? क्या इसी तरह आप जनहित के काम कर रहे थे? यह कौन-सा तर्क हुआ? अगर आप ऐसे ही कुतर्क देते रहेंगे तो उसका तो कोई जवाब नहीं होगा।

आप मनरेगा की चर्चा कर रहे थे। जब आपने मनरेगा शुरू किया था, उस समय उसकी मज़दूरी 145 रुपये थी और इस सरकार में वही मज़दूरी 204 रुपये है। आप उसकी चर्चा तो नहीं कर रहे थे। आप कहते कि वर्तमान मोदी जी की सरकार ने मनरेगा के मज़दूरों की मज़दूरी बढ़ा कर 204 रुपये कर दी है और बिहार में तो 209 रुपये है।

आपने तथ्यों के आधार पर श्वेत पत्र का खंडन नहीं किया। आप घोटालों की चर्चा कर रहे हैं, भष्टचार की चर्चा कर रहे हैं। मैं भी इस सदन का सदस्य रहा, 14वीं लोक सभा में और 15वीं लोक सभा में सदस्य रहा। जब आपकी सरकार वर्ष 2004 से 2014 तक थी, तब सभापति महोदय, कोई ऐसा सत्र नहीं होता था, जब एक नए घोटाले की चर्चा उस सदन में और उस सत्र में नहीं होती थी। कोयला घोटाला हुआ, स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, कोयला घोटाले में कौन-कौन लोग थे, उन सबका पर्दाफाश हो गया है। स्पेक्ट्रम घोटाला कैसे हुआ, यह भी पर्दाफाश हो गया, सब जान गए हैं। रक्षा घोटाला हुआ, विमान की खरीद में, रक्षा के सामानों की खरीद में कहां-कहां सौदेबाजी हो रही थी, कमीशनबाजी हो रही थी, इसकी चर्चा हुई, उस सदन में चर्चा हुई। कॉमलवेल्थ गेम्स में आपकी सरकार की नाक के नीचे दिल्ली में जो घोटाला हुआ, उसको भी सबने देखा, पूरे देश ने देखा, हर व्यक्ति ने देखा। शारदा चिट-फंड कितना बड़ा घोटाला हुआ, वह चिट-फंड कंपनी किसका पैसा ले कर गायब हुई? वे कौन लोग थे, जिनका पैसा लेकर शारदा चिट-फंड वाले लोग गायब हुए? मध्यम वर्ग के लोगों, मज़दूर वर्ग के लोगों का पैसा ले कर गायब हुए। शारदा चिट-फंड घोटाला किसके राज में हुआ, इस पर आपको बोलना चाहिए था। आप नहीं बोल रहे हैं। कोई नहीं बोल रहा है। तथ्यों के आधार पर आपको बोलना चाहिए, वह भी आप नहीं बोल रहे हैं। कौन सी चर्चा करना चाहते हैं? एक बात तो आपको जरूर कहनी चाहिए थी, आपको यह बात ईमानदारी से कहनी चाहिए थी, आप

भी इस सदन के सदस्य हैं, आपको कहना चाहिए था कि इन दस वर्षों में, 2014 से 2019 तक मैं इस सदन का सदस्य नहीं था, लेकिन वर्ष 2019 से हूँ, आज तक कोई घोटाले की बात तो आप नहीं कर पाए। आज तक किसी घोटाले की बात तो आप नहीं कर पाए। बहुत होता है तो घूम-फिर कर एक ही आदमी का नाम उजागर करते रहते हैं। अरे भाई उनसे आपका कुछ व्यक्तिगत मामला है तो जा कर बाहर मिल-जुल कर मामला सुलटा लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। आप उसको यह संदेश कयों देना चाहते हैं कि मेरे पास आओ-मेरे पास आओ?

हमने अखबारों में देखा कि आप स्याह पत्र लेकर आए हैं, आज आप भी भाषण दे रहे थे, सभी भाषण दे रहे थे, आप स्याह पत्र की चर्चा कर रहे थे, अगर श्वेत पत्र में आंकड़े गलत हैं, जो मैंने पहले भी कहा तो उन आंकड़ों का खंडन करना चाहिए। उसमें तो तुलनात्मक है, वर्ष 2004-2014 और वर्ष 2014-2024 दोनों की तुलना टेबल बना कर दी हुई है। आप टेबल को कॉन्ट्राडिक्ट करते। एक-एक आंकड़े को आप कॉन्ट्रॉडिक्ट करते, जो आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? फिर वहीं घूम-फिर कर आ रहे हैं, सीबीआई और ईडी पर आ रहे हैं। सीबीआई और ईडी पर बाहर जितना बोलना है, बोलिए, लेकिन आप एक बात बताइए, मैं भी डेढ़ साल तक एनडीए से अलग रहा और एनडीए से जब मैं अलग रहा तब मेरे यहां कोई ईडी और सीबीआई पहुंची? मेरे यहां तो कोई सीबीआई और ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी के यहां तो कोई सीबीआई और ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी भी विपक्ष के सूत्रधार थे, जब हम एनडीए से अलग थे।

नीतीश जी के यहां तो कोई नहीं पहुंचा। हम लोगों के यहां तो कोई नहीं पहुंचा। लेकिन, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय। अगर करिएगा भ्रष्टाचार तो उसका कांटा तो गड़ेगा ही, मीठा आम कहां से मिलेगा। यह तथ्य है। इन तथ्यों के बजाय, आप कह रहे हैं कि यह जो श्वेत पत्र आया है, यह हमारी पूर्ववर्ती सरकार की इमेज को टार्निश करने के लिए लाया जा रहा है। काहे किसी का इमेज टार्निश करने के लिए लाया जा रहा है! जो तथ्य है, जो सही है, जो आंकड़े हैं, वे सदन और इस देश के सामने रखे गए हैं। इसमें इमेज कहां से टार्निश हो रही है? हाँ, अगर आपने कुकर्म किया है

तोस्वाभाविक तौर पर आपको इमेज टार्निश होने का भ्रम लगेगा। आप इस भ्रम के शिकार हैं। अगर आपको भ्रम है तो उसका क्या किया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय, जब कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसको भुगतना भी पड़ेगा। अगर वे भुगत रहे हैं तो उसके लिए श्वेत पत्र पर बोलने के बजाय आप राजनीतिक विलाप नहीं करिए। उन तथ्यों के आधार पर अगर कोई आंकड़े हैं तो उन आंकड़ों को आप रखिए। यही बात हम कहते हुए, फिर से माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देते हुए, श्वेत पत्र लाने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पूरे देश को अवगत कराने के लिए, मैं उनको बधाई देता हूं। इस बधाई के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रवि शंकर प्रसाद (पटना साहिब): माननीय सभापति जी, यहां पर आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो श्वेत पत्र प्रस्तुत किया है, उस पर अपनी टिप्पणी करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बहुत सारगर्भित कदम है और इसे देश को जानना चाहिए। देश को बताने के लिए यहां चर्चा भी हो रही है। मैं बार-बार उधर से सुन रहा हूं कि उन्हें बदनाम करने के लिए ये झूठे आंकड़े लाए गए हैं। भाई, हम क्या करें, देश की जनता ने आपकी छुट्टी वर्ष 2014 में कर दी। आपकी छुट्टी वर्ष 2019 में कर दी और वर्ष 2024 में हमें 400 के पार लाने वाले हैं। देश की जनता ही आपको रिजेक्ट कर रही है। आप हमारे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं? हम तो सच्चाई को बोल रहे हैं।

माननीय सभापति जी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म की भी चर्चा है। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करूंगा कि देश की अर्थव्यवस्था में रिफॉर्म के सुधारक नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने की उन्होंने घोषणा की है।

महोदय, आज मुझे बोलने के लिए अनुमति दीजिए। वह कांग्रेस के नेता थे। उस पार्टी के अध्यक्ष रहे, उस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके शव को कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में भी नहीं जाने दिया गया था। यह क्या है? आज उन्हें भारत रत्न मिला है। मैं आपकी अनुमति से एक और बात कहना चाहूंगा। सरदार पटेल वर्ष 1950 में मरे, लेकिन उनको भारत रत्न वर्ष 1991 में मिला। आप याद कीजिए, जो व्यक्ति देश का रत्न था, देश को जोड़ने वाला था, उसको वर्ष 1991 में भारत रत्न मिला। मौलाना आजाद वर्ष 1960 में मरे, लेकिन उनको भारत रत्न वर्ष 1992 में मिला। कौन थे प्रधानमंत्री – नरसिम्हा राव। अगर उस समय परिवार का प्रधानमंत्री होता तो यह काम भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को ही करना पड़ता। यह भी आज सदन में कहना जरूरी है।

महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है। आज चरण सिंह जी को भी भारत रत्न मिला है। वह किसानों के नेता, प्रधानमंत्री और लड़ने वाले व्यक्ति थे। महान कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी थे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि ये सब लोग आपके समय के थे। गोगोई बाबू, दिक्कत क्या है कि आपको भारत रत्न परिवार से बाहर दिखाई ही नहीं पड़ता है। यह हमारे प्रधान मंत्री की सोच है

कि जो हमारी पार्टी का नहीं भी होगा, देश के लिए काम किया है, तो हम उन्हें सम्मानित करेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया, गरीबों के लिए काम करने वाले बिहार के उस महान नेता को, चरण सिंह जी को, नरसिंहराव जी को, प्रणव मुखर्जी जी को सम्मानित किया।

सभापति जी, मैं बार-बार उधर से सुन रहा था कि आप अभी क्यों लेकर आए हैं? ये चुनाव का एजेंडा लेकर आए हैं। हमारे मित्र मनीश तिवारी जी ने भी कहा, कहां गायब हैं, मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूं, गौरव गोगाई जी ने भी इस बारे में कहा। सभापति जी, मैं सदन में यह बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि हमें क्या विरासत मिली थी और हमने क्या करके दिखाया। हमें पहले यह करके दिखाना था। हम लाए हैं 'तूफान से कश्ती निकाल के'। यह दस सालों में काम किया। जब हमारा दस साल सुधरा तो कहा देखो, आज हम ला रहे हैं, उनके दस साल और हमारे दस साल। इस पर आपको क्या परेशानी है?

महोदय, मेरा एक पर्सनल अनुभव है, मुझे आप बोलने की अनुमति दीजिए। वर्ष 2012 में मैं एक निजी काम से, एक सेमिनार को एड्रेस करने के लिए न्यूयार्क गया था। उस समय में मैं अपनी पार्टी का उस सदन का विपक्ष का उप नेता था, स्वर्गीय अरुण जेटली जी नेता थे। उन्हें मालूम हुआ कि मैं आया हुआ हूं, तो बहुत बड़ी संख्या में भारत में पूंजी निवेश करने वालों ने कहा कि हम रवि शंकर जी से मिलना चाहते हैं। एक लॉ फर्म में हमारी मीटिंग कराई गई। दो ढाई सौ लोग वहां आए, उन्होंने कहा कि क्या हमारा पैसा सेफ है? हम उनकी तरह नहीं हैं कि लंदन और अमेरिका में जाकर भारत की आलोचना करते हैं। हम अटल बिहारी वाजपेयी के संस्कार के लोग हैं। विदेश जाओ तो देश की आलोचना कम करो। इतना भ्रष्टाचार, इतनी लूट, हम क्या करें? "Is our money safe? 'Should we withdraw our money?" हमने समझाने की कोशिश की। उसके बाद एक व्यक्ति ने कहा, "Mr. Prasad, we know your Party. When is your Party coming to power?" मैंने कहा, "Have patience. In 2014, we are coming." उन्होंने कहा, "Is it so?". मैंने कहा, "Yes." उन्होंने कहा, "Then we trust you." यह कहानी वहां से शुरू होती है। यह जानना और समझना

जरूरी है । यह दस साल की कहानी क्या है? India has changed from 'fragile five to powerful five'.

मनीश जी बोल रहे थे कि आपने क्या किया? मनीश बाबू, हमने यही किया, आप जो ग्यारहवीं इकोनॉमी छोड़ कर गए थे, पॉलिसी पैरालिसिस, करप्शन, फ्रेजिलिटी, हम उसको दुनिया की पांचवीं इकोनामी पर ले गए और दो साल में तीसरे नंबर पर लेकर आएंगे। यह हमने करके दिखाया है। हमसे पूछ रहे हैं कि आपने काम क्या किया? मनीश बाबू, क्या आपने डिजिटल इंडिया का नाम सुना है? आप आधार की बात तो कर गए, मैं उस विभाग का मंत्री भी रहा हूं। आधार का कोई वैधानिक आधार नहीं दिया था, कोर्ट में चैलेंज हो रहा था। हमारे प्रधान मंत्री ने कहा कि रवि पहले कानून बनाओ। हमने आधार का कानून बनाया और जन-धन, आधार और मोबाइल को जोड़ा। लगभग 44 लाख करोड़ रुपये एकाउंट में भेजे और लगभग 3 लाख करोड़ रुपये बचाये। यह है डिजिटल इंडिया। मनीश बाबू, कभी आपने सुना है कि भारत यूपीआई पेमेंट के मामले में दुनिया में नंबर एक तक पहुंच गया है। मैं आपका नाम लेकर सुना रहा हूं। आप घर पर टीवी देख रहे होंगे, तो काइंडली सुनिए। मनीश बाबू, आपने कहा कि आपने क्या किया? आपने कहा कि आप राइट टू इन्फॉर्मेशन लाए। अपने भ्रष्टाचार का जवाब क्या कभी राइट टू इन्फार्मेशन में मिलता था? ललन बाबू ने एक बात कही। हम लोग उस सदन में थे, एक हफ्ता हाउस में बहुत चिल्लाए, फिर एक स्कैम खुल गया, फिर चिल्लाए, तो फिर एक और नया स्कैम खुल गया। हमने कहा क्या बात है, कहीं फुल स्टॉप नहीं है? हर हफ्ते एक स्कैम और हंगामा होता था। अगर आप स्कैम करेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अगर विपक्ष में हमारा यह हाल था, अब तो हमारे प्रधान मंत्री ईमानदार हैं, वे कभी नहीं छोड़ेंगे, आप चाहे जितना चिल्लाइए।

सर, यह दु:खती रग क्यों इतनी दु:खती है? आज गौरव बाबू ईडी पर इतने परेशान क्यों थे, क्या मामला है? साफ सुन लीजिए, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी का केस विदड्रा नहीं किया गया है। अगर किसी को फंसाया नहीं जाएगा, तो किसी को छोड़ा भी नहीं जाएगा। लेकिन मुझे आश्यर्च लगता है कि लोग बार-बार ईडी, सीबीआई कहते रहते हैं। मुझे यह बताइए पश्चिम बंगाल में किसी के घर से 60 करोड़ रुपये, किसी के घर से 70 करोड़ रुपये निकलता है, क्या उनको बेल

मिली? वे अभी भी जेल में ही हैं न? मैं बंगाल के मित्रों से पूछता हूं, कोथाए आचेन तो बोलते हैं कि जेल में ही हैं। छत्तीसगढ़ वाले भी जेल में हैं, झारखंड वाले जेल में चले गए। दिल्ली के डिप्टी सीएम एक साल से जेल में हैं, बेल नहीं मिली, एक सांसद मित्र जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, वह भी छह महीने से जेल में हैं। जेल में क्यों हैं? कोर्ट देख रहा है, हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो फसंगे। कृपा करके ईडी को आप इस तरह से श्राप देना बंद कीजिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा।

मैं आपको यह क्यों कह रहा हूं, इस ह्वाइट पेपर में भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी क्यों? भारत का विश्वास क्यों डोला? चर्चा बहुत हुई, गोड्डा के सम्माननीय सांसद निशिकांत जी ने चर्चा की, ललन बाबू ने की और बाकी लोगों ने की। इन्होंने क्या सोच लिया था, हर जगह घोटाला करेंगे? भारतीय संस्कार और संस्कृति में एक बहुत बड़ा शब्द है, पंचतत्व। ये जीवन पंचतत्व से बना है। यह पंचतत्व क्या है, नभ, जल, थल, अग्नि और आकाश। यहां कई बड़े-बड़े मित्र हैं, साधक भी हैं, वे इसकी शास्त्रीय व्याख्या करते हैं। हेमा जी सृजनात्मक प्रतिभा की है, वे अपने नृत्यों में इसकी चर्चा करती हैं।

कांग्रेस और उसके मित्रों ने पंचतत्व का नया सिद्धांत निकाला। पंचतत्व का सिद्धांत, जब तक सफल नहीं होगा तब तक पांचों तत्वों में भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। एक को भी नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने कमाल कर दिया, एक को भी नहीं छोड़ा। मैं गिनाता हूं, थल पर आइए, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श घोटाला, ये पाताल में भी चले गए, कोयला घोटाला, ये समुद्र के अंदर पानी में भी चले गए, सबमरीन घोटाला, ये आकाश में चले गए, पिलाटस घोटाला, हेलिकॉप्टर घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड, स्पेक्ट्रम घोटाला। अग्नि घोटाले के बारे में ये लोग बार-बार कहते हैं, एक व्यापारी का नाम लेते हैं। पता नहीं इनको क्या प्यार हो गया है? अगर वह केरल जाएंगे, बंगाल जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, इनकी सरकार में उस व्यापारी का हजारों करोड़ रुपये का काम अभी भी चल रहा है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा।

सर, अडानी की बात कर रहा हूं। आप छत्तीसगढ़ में जाइए, कोयले का कूप मिला कि नहीं, राजस्थान में गहलोत सरकार ने दिया कि नहीं, बंगाल मे जाइए, केरल में पोर्ट दिया कि नहीं? ये क्या बोलते हैं? अगर हिम्मत है तो अपने एलाएंस को निकाल दें, रिश्ता नहीं करना है। राहुल गांधी को

बोलने की हिम्मत हुई क्या कि राजस्थान में बंद करो, नहीं, That is a different matter. मुझे उनकी प्रेस की बातें याद हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, मैं अग्नि पर आ रहा हूं। मैं एक ही बात कहूंगा कि एक बार राहुल गांधी जी बीकानेर जाएं, अगर उनको उचित लगे तो माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी को भी ले लें, दूर से ले लें। उन गांवों में जाएं, जहां जमीन ली गई है। वहां उन किसानों से, दूर से भी सुनेंगे तो वहां से एक ही आवाज आएगी, वाड्रा, वाड्रा, वाड्रा, क्यों, क्योंकि उनकी जो जमीन सोलर पॉवर प्लांट के लिए ली गई है, हजारों एकड़ जमीन, सैंकड़ों एकड़ जमीन किसने ली, किसने दिलवायी? हरियाणा के मुख्यमंत्री हों या राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कार्मस? मैं एक ही बात कहता हूं, कॉमर्स, 'Vadra as Commerce' एक नया मॉडल है। देश में एन्टरप्रियोनर्स की बड़ी बात होती है।

सर, मैं संचार मंत्री था, मैं गया और कहा कि बताओ कि टूजी घोटाला क्या है? तब कहा गया – फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व था। संचार भवन में कहा गया कि इस समय जो आएगा, उसे घुसने दिया जाएगा और उस पर होगा – फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व। वहां बाउंसर्स बिठा दिए गए कि किसी को घुसने मत दो, मुक्का मारो, नाक तोड़ो। अफसर और कार्पोरेट कंपनी के बड़े-बड़े लोग थे, किसी की नाक पर चोट लगी तो कोई भाग गया। जिनको देना था, वे पहले ही घुसकर बैठे हुए थे और बहुत लोग तो एक दिन पहले यानी बैक डेट का चैक लेकर आए हुए थे। ये लोग क्या बात करते हैं? … (व्यवधान)

सर, कोयला घोटाला, क्या मैं खोलू? … (व्यवधान) क्षमा करें, आपके प्रधान मंत्री एक्यूज्ड हैं या नहीं, डॉ. मनमोहन सिंह? … (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट से स्टे है क्योंकि वह कोयला मंत्री भी थे। क्या मैं बताऊं कि किस तरह से उनको मंत्री चिट्ठी लिखते थे – 'Dear Prime Minister, he is my brother. Kindly give him coal block'. जब पार्टी के ट्रीजरर थे, वह कहते थे कि इनकी चिंता की जाए। … (व्यवधान) पहले एक चिट ट्रिजरर साहब के यहां निकलती थी, वहां से चिट दूसरी जगह जाती थी, फिर तीसरी जगह जाती थी और कोयला ब्लॉक मिल जाता था। … (व्यवधान) क्षमा करिए।… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : क्या आप आंथेटिकेट कर सकते हैं? … (व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : चलिए, सब दे दिया जाएगा। ... (व्यवधान) यह सब रिकॉर्ड की बात है। ... (व्यवधान) आप सीएजी की रिपोर्ट पढ़िए, सब कुछ सामने है ।... (व्यवधान) आप बैठिए। ... (व्यवधान) आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़िए। ... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : आप आरोप लगा रहे हैं। Can you authenticate it? ... (व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : उन्हें क्वाश किया। क्या मैं आरोप लगा रहा हूं? ... (व्यवधान)

श्रीमान, गौरव बाबू, आप देश के पूर्व कानून मंत्री, पूर्व कोयला मंत्री से बात कर रहे हैं। क्या समझ गए आप? आप पूर्व संचार मंत्री से बात कर रहे हैं। आप बैठिए। ... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : हम आपका सम्मान करते हैं, आपका निरादर नहीं करते हैं, आप भी निरादर मत करिए।... (व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : अच्छा, अब आप बैठ जाइए। ठीक है, छोड़िए। ... (व्यवधान)

एन्ट्रिक्स सर्वे तो और कमाल है। एस-बैंड सबसे कॉस्टली बैंड है। टूजी बैंड और बाकी बैंड्स में एस-बैंड सबसे कॉस्टली बैंड है। इसकी सैटिंग करके इन्होंने ले लिया। इसकी चर्चा निशिकांत जी ने की है, मैंने इसे एग्जामिन किया था। जब यह मामला हुआ था, हमने हाउस में भी उठाया था और यह बड़ा विषय बना था। सरकार डर गई और उसने कमेटी बनाई। कमेटी ने कहा कि इसकी जांच करेंगे, लेकिन इसे कैंसल कर दिया। यह नहीं कहा कि बिना ऑक्शन के दिया गया, बल्कि यह कहा कि सिक्योरिटी कारण से इसे हम कैंसल करते हैं। समझे। ... (व्यवधान) जब यह आर्बिट्रेशन में गया तो वहां उन्होंने कहा – 'What is the security concern? Show us the file'? उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ था। इस कारण भारत के ऊपर पेनल्टी लगाई गई। आज मैं कहूंगा, आर्बिट्रेशन चल रहा था, मुझे माननीय प्रधान मंत्री के प्रति कृतज्ञ होना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कहा कि आर्बिट्रेशन एक्ट में कानून बदलो और लिखो – 'If a particular award is vitiated by corruption and fraud, that is *non est*'. इसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे सेटिसफाई किया। मैं इनकी कितनी कहानी सुनाऊं? इससे देश का विश्वास डोला कि अब इस देश में पूंजी निवेश करना उचित नहीं है।

सर, मैं आंकड़े नहीं दूंगा क्योंकि आंकड़े बहुत आए हैं। क्या अब भारत में हाइएस्ट पूंजी निवेश हुआ है या नहीं? क्या अब भारत में हाइएस्ट फॉरेन रिजर्व आया है या नहीं? आज आईएमएफ और दुनिया की बड़ी कंपनियां कह रही हैं – India is a bright spot in the economy of the world. मैं यह बताना इसलिए जरूरी समझता हूं। निशिकांत जी ने भी विस्तार से बताया है कि माननीय अटल जी की सरकार ने एक रोबस्ट इकोनॉमी दी थी। इन्होंने पहले दो-तीन साल एन्जवॉय किया और बाद में डुबाया, फोन बैंकिंग, करप्शन, स्कैम से इकोनॉमी नीचे आ गई।

सर, आप हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी का नेतृत्व और मैनेजमेंट देखिए। हम सब जानते हैं कि कोरोना में देश में कितना तूफान आया था, कितनी परेशानियां आई थीं। पूरा देश लॉकआउट था। हमने लोगों को मेड-इन-इंडिया फ्री वैक्सीन दी। भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारा और फिर आगे बढ़ गए। आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेख से बाहर आ गए हैं, यह करके हमने दिखाया है। क्या यह सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए कि इतनी सड़कें बन रही हैं, इतने हाईवेज बन रहे हैं, इतने मकान गरीबों के लिए बन रहे हैं। आज भारत डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में कहां से कहां पहुंच गया? आज भारत दुनिया का सेकेंड बिगेस्ट मोबाइल मैनुफैक्चरर है या नहीं? आज एप्पल कंपनियां चाइना से उठकर हिंदुस्तान आ गई हैं या नहीं? लोगों को नौकरियां मिली हैं या नहीं मिली हैं? फिर चाहे चाहे कंडक्टर हो या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र हो।

सर, ये बार-बार महंगाई की बात बोलते रहते हैं। एक रिकॉर्ड मुझे दिखाने की इच्छा है, कृपया मुझे अनुमति दें। यह डेटा मैं रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी वाले महंगाई पर बहुत बोलते हैं। Best control of price situation in the past years. वर्ष 2004 में महंगाई दर 3.9 परसेंट थी, फिर 2005 में यह 3.8 परसेंट, 2006 में 4.4 परसेंट थी। इन तीन सालों में अटल जी का अच्छा काम जब खत्म हो गया, तब देखिए वर्ष 2009 में 9.1 परसेंट, 2010 में 12.3 परसेंट, 2011 में 10.5 परसेंट, 2012 में 8.4 परसेंट, 2013 में 10.2 परसेंट, 2014 में 9.5 परसेंट। इसके बाद जब मोदी जी सरकार में आते हैं, तब वर्ष 2015 में 6.0 परसेंट और आज 5.5 परसेंट है। यह यूनिवर्सिली एक्सेप्टेड डेटा है। इसको समझना चाहिए।

महोदय, मैं कांग्रेस के लोगों से एक ही बात कहूंगा कि ये भ्रष्टाचार करते भी हैं और भ्रष्टाचार का महिमा-मंडन भी करते हैं। पूरी सूची में एक सूची यह भी है कि रेलवे में किस तरह से नौकरी के बदले जमीन दी गई और ऐसे लोगों को दी, जो सजा-याफ्ता हैं। मेरा यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य है कि बिहार के कुछ बड़े-बड़े घोटालों पर बहस करने का मुझे अवसर मिला है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला। एकाध दिन ललन सिंह जी भी हमारे साथ थे। उसमें लोगों को जेल हुई। सजा हो गई, कनविक्शन हो गया। हमने कहा कि एक बार कनविक्शन हो गया, तो दोबारा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी भी हुआ चला जा रहा है। हमारे बिहार में एक कहावत है- "कापर करूं सिंगार" दूसरी लाइन जनार्दन सिंह जी बोल देंगे। आखिर क्या किया जाए? और इसका वे महिमा-मंडन धर्म-निरपेक्षता के नाम पर, समाजवाद के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर करते हैं। वह केवल आपके परिवार के लिए सामाजिक न्याय है।

सर, मैं बीस मिनट बोल गया, मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था। मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। यह बात दुनिया के सामने आनी चाहिए। मुझे भी संसद में काफी समय हो गया है और आपका भी काफी लंबा समय हो गया है। व्हाइट पेपर हाउस में काफी कम आता है। यह व्हाइट पेपर आने वाले संसदीय इतिहास के लिए एक मील का पत्थर बनने वाला है कि देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार थी। 10 साल का काम उनका और 10 साल का काम हमारा। आप आंकड़ों पर बात करें तो हम सुनने को बिल्कुल तैयार हैं। मैंने आपके सामने महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण नहीं रखा है। एक-एक चीज आंकड़ों पर है कि कितनी सड़कें बनीं, कितनी बिजली गई, कितने आवास बने, कितने नैशनल हाईवे बने, सब-कुछ इसमें लिखा हुआ है।

सर, हमने गजट में भी रखा हुआ है। मैंने जानबूझकर वह समय लिया। अत: आप आंकड़ों पर बात करिए, लेकिन आप करते ही नहीं हैं। हवा-हवाई कहना कांग्रेस की पुरानी आदत है। कभी तो आप सच्चाई पर आइए। आज हमें गर्व है कि मोदी जी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है। मैं निशिकांत जी की बातों को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन जिस तरह से गोल्ड बॉंड को लेकर खुराफात की गई, उसको मुझे हैंडल करने का अवसर मिला। ऐसी शर्मिंदगी मैंने कभी नहीं देखी। मैं रिपीट करूंगा

कि हमारी सरकार जीत गई है, रिजल्ट अनाउंस हो गया है। मोदी जी फॉर्मल पीएम का स्थान लेने वाले हैं और आपने एक्टिंग रूप में सब-कुछ पार कर दिया कि जाओ बाहर से गोल्ड ले आओ, डायमंड ले आओ और फिर गो बैक।

सर, उसमें कितना कट हुआ होगा, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल निशिकांत जी की उस अनुशंसा से सहमत हूं कि इस मामले की भी पूरी जांच होनी चाहिए। काफी हुई भी है, यह बात आनी चाहिए।

सर, एक टेफ्लान कोट होती है। यह अंग्रेजी का शब्द है। आप बहुत अनुभवी डॉक्टर हैं। आप टेफ्लान कोट खूब समझते हैं। टेफ्लान कोट का मतलब है कि आप कितना भी लगाओ इस पर कुछ लगेगा नहीं। नरेन्द्र मोदी जी की अगुवाई में आपको जितना बोलना हो बोलिए। इस पर भ्रष्टाचार नहीं लगेगा, क्योंकि यह सरकार ईमानदारी से काम करती है।

सर, मैं एक अंतिम बात कहकर समाप्त करूंगा। आदमी अपनी गलती के अनुभव से सीखता है। वर्ष 2014 में यही पूरी कहानी चली, इतना कसकर पिटे। वर्ष 2019 में राफेल पर क्या-क्या कहा गया, मैं वह बात रिपीट नहीं कर सकता हूं। जिस तरह की शर्मिंदगी भरी बातें की गईं, सुप्रीम कोर्ट में वह भी डिसमिस हुआ। भारत की सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश की गई थी। राफेल की खरीददारी को 12 साल रोका गया था, क्योंकि कमीशन तय नहीं हुई थी। क्या यह इनकी सच्चाई नहीं है? अगर राफेल पहले आ गया होता तो पुलवामा के लिए उसे सरहद के पार नहीं पड़ता। उसमें पावर है कि यहीं से बैठकर बटन दबाकर कर सकते थे। आज देखिए कि वह आ गया। अब नया क्या है? तो बस एक व्यक्ति का नाम है। मैं कहूंगा कि श्रीमान राहुल गांधी जी आपका रेकॉर्ड बहुत घिसा-पिटा हो गया है। कुछ तो नया रेकॉर्ड बजाइए या हम मान लें कि मोदी जी के खिलाफ बोलने के लिए आपके पास कोई रेकॉर्ड नहीं बचा है। आप वही बजाइए। जनता सुनने वाली नहीं है। ... (व्यवधान) जनता आपको और हराएगी। आपकी संख्या और कम होने वाली है। इस बार हम लोग निश्चित रूप से 400 के पार जाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

***SHRI OM PAVAN RAJENIMBALKAR (OSMANABAD):** Mr. Chairman Sir, thank you. I rise to speak on the white paper which is laid on the floor of the house.

Mr. Chairman, Sir, today I came to know that Dr. M.S. Swaminathan will be awarded the Bharat Ratna. I am really happy for it. But the recommendations made by the Swaminathan Commission have not been implemented yet. It is an important occasion for deep introspection by the Government.

Mr. Chairman, Sir, I would like to share some incidents and examples with the Government so that it would look into it seriously. How the Government's policy is ruining our farms and farmers is a matter of grave concern. On 7th December, 2023, the Central Government decided to ban onion export. The Government was totally indifferent when the farmers threw away onions on roads for not fetching fair and reasonable price for it. This Government is totally blind towards the hardships and challenges faced by poor farmers while doing farming. But, when the onion-growing farmers started receiving Rs.50 to Rs.60 per kilogram for onions, this government immediately banned onion export. As a result, the onion rates dropped drastically and onion-growing farmers landed in trouble. Mr. Chairman, Sir, is this the way the Government is going to double farmers' income? Their income has not doubled, but the farming cost has been doubled already.

Earlier, DAP fertilizer cost Rs.485 but it is now available at the rate of Rs.1350. The insecticide which was available at the rate of Rs.300 per litre now

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

costs Rs.700. The roundup herbicide earlier cost at the rate of Rs.250 is now at Rs.650. Earlier, farmer has to pay to Rs.600 for cultivation of 1 acre farm but now he is compelled to pay Rs.2000. Mr. Chairman, Sir, it means that the farming cost has grown double already but the income of farmers has not been doubled. Sir, soybean growers are also facing adversities. Earlier MSP for soybean was Rs.11000 per quintal. Government had reduced import duty on palm oil and I can understand the government's motive that the poor should get palm oil at cheaper rate but, at the same time government started importing soya cakes and that led to a further reduction in prices. It then reduced from Rs.11000 to Rs.4000.

Sir, it means the soybean growers had to incur a loss of Rs.6000 per quintal. Thus, the farmers had to bear the losses of lakhs of rupees due to Union Government's decision. But you are paying only Rs.6000 per year to these farmers and making tall promises of farmers' welfare. Is this the real 'Samman' of the farmers? Sir, same is applicable in case of milk too. The cow milk used to cost Rs.38 per litre but now it has been reduced to Rs.22. The sugarcane farmers would get good income but you have stopped ethanol production. Sir, Government should clarify on sugar usage and consumption. Only 15 per cent of total sugar production is needed for human consumption and rest of the 85 per cent sugar is being used by big companies like Cadburys and Coca Cola. If you want to give it at concessional rates to poor people, you can distribute it through PDS, but why are you providing it at cheaper rates to big companies? The Union Government should think about it.

Mr. Chairman, Sir, first of all, the Government should accept the existence of farmers. Whenever the farmers start fetching remunerative or fair prices for their agriculture produces, the government immediately intervenes and controls the price rise. Now, the grape-growing farmers have also landed in trouble as Bangladesh has imposed a higher import duty on grapes. This Government is working totally against farmers' interests. If you control the prices of agriculture produce, then why do not you control the prices of other, commodities? A cement bag earlier cost Rs.200, but now Adani is selling it at the rate of Rs.450 per bag. Why do not you intervene? Same is applicable in the prices of diesel, petrol and steel.

So, it is clear that this Government acts proactively only in cases of agricultural produce and not in other commodities. In this way, the Government is inciting the farmers to commit suicide. Sir, I have been listening to the BJP leaders since morning and they talk about infrastructure development, roads, highways and 5-trillion dollars economy. But, as you know, our 70 per cent population is dependent on agriculture. Agriculture boosts the other professions and our economy too. You are working on infrastructure, but you should also give priority to interlinking of rivers. The States like Bihar and Assam face the floods every year. But the other States need water for irrigation and it is to be considered by the Central Government. Sir, you are constructing highways for toll income. You have brought this White Paper, you should have brought a white paper on ED inquiries, only to show that you are impartial. At least you should book any of BJP leaders or Ministers. ED only targets the chosen ones and after joining BJP,

it automatically stops its inquiry. So, a white paper in this regard should also be brought.

Lastly, I would like to raise an issue regarding the reservation for backward communities like Maratha, Dhangar, Koli and Muslims. Sir, to provide reservation to these communities, the cap of 50 per cent should be removed by amending the law.

I would like to make an earnest request to the Union Government to amend the law accordingly to do justice to these communities.

Thank you.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, thank you very much for giving me this opportunity.

Actually, we call this as the White Paper but it is the paper by the BJP, of the BJP, and for the election of the BJP. You are trying to draw a rosy picture that everything in the country is okay.

Sir, today being Friday, I had gone for the congregational prayer in the mosque. With all the profound regret and pain, I would like say that people are weeping in the Masjid because of the recent development that took place in Uttarakhand where shoot-at-site orders have been issued. The initial report says that there are four deaths but according to the District Magistrate's report, two deaths have been reported. The authorities were demolishing a mosque and a madrasa which were present there for a long time. The latest report says that these kinds of incidents have been taking place there for the last one year. This is the place where you have taken up the trial run of the Uniform Civil Code. The whole nation is worried about this thing.

Sir, you keep this in mind that killing is possible, destruction and demolition is possible, physical and mental harassment is possible but nobody can scrap the identity and the ideology. … (*Interruptions*)

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट) : सर, जो मस्जिद की बात कही गई है, उसके लिए सरकार का कोई भी आदेश नहीं था, वह माननीय न्यायालय की तरफ से था। माननीय न्यायालय के आदेश पर हुआ है। …. (व्यवधान)

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER: Sir, what is this? … (*Interruptions*) What is the use of saying that? … (*Interruptions*) Do not disturb me. … (*Interruptions*)

When I am stating the fact, why are you interrupting in between? … (*Interruptions*) Let me state the sad story. … (*Interruptions*)

So, these kinds of things should not happen. There is every reason to believe that if these kinds of things happen, this country will go to the dogs. We have to be very careful about this. Regarding corruption, you have described many things.

Our former Prime Minister, Manmohan Singh very categorically spoke about the monumental mismanagement. It is a case of organized loot and legalized plunder. These are the correct words. In fact, that is happening in our country now.

The UPA Government made the historical legislation of Right to Information Act which was a revolutionary move for ensuring transparency and curb corruption. You have now clipped the wings and diluted it, and things are going from bad to worse.

The UPA Government made the historical legislation of MGNREGA. That is a very, very important legislation as far as the poverty eradication is concerned. There are many such things which the UPA did. But I would not go into all the details because of the time constraint.

Sir, we all know that illiteracy is the root cause of all problems. Realising this, we came up with an Act in 2009, called, the Right to Education Act. That was a landmark legislation.

You claim that India is a fast-developing economy. But we ask, for whose benefit? You say that India has become a healthy economy. We ask, for whose

benefit has it become a healthy economy? The truth is that it is a healthy economy for the rich people, corporates and that kind of sections of the society.

15.57 hrs (Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

Then, you talk about institutions. Sir, a lot many institutions were built soon after Independence. But what is happening right now? These big companies, PSUs, public properties, all are being sold to the big guns at throw away prices. This Government is humiliating minorities, as I told you. So, these things are happening in the country. I urge the Government to reconsider all these things and do justice to all whether they are Muslims, Christians or anybody else.

In respect of agriculture, you have failed miserably except in one thing and that is sowing the seeds of communalism. In that kind of agriculture, you have succeeded. Your Government was instrumental in Bilkis Bano case. We have to understand what happened there. Perhaps, that maybe the happiest day for you when you got release of the accused from jail. But, perhaps, the sad day in your period might have been the day when the Supreme Court of India ordered the culprits to be brought back to jail.

Then, you claim that there are enough welfare schemes for the people. You have highlighted certain figures also. I would like to give a few authentic figures in terms of India's ranking in the international order. In terms of universities ranking, India's position is at 220th in the world. In Inclusiveness Index, India stands at 117th rank in the world. In the Global Peace Index, India ranks at 126th position. In Global Gender Gap Index, India is at 127th position. In World Press Freedom

Index, we stand at 161st rank. In the World Happiness Index, our position is at 126th in the world.

You are instrumental in making the Executive a tool for your dirty politics. What is happening, Sir? We have gone backward in terms of judiciary, executive and freedom of Press. We have to improve. I am saying in the best interest of the nation that India should not have such a low position in global indices. India should come up with the help and cooperation of all concerned.

You can come up with many reports. You can publish a wonderful White Paper. Even if you publish 1001 White Papers, this kind of a bad name cannot be removed. So, you have to improve yourself. Take everybody into confidence.

If you go through certain figures, then only you can understand it. What has been the impact of demonetisation on our economy? What purpose has it served? Then, you have betrayed the farmers. You talk about Annadata. But what about their ill fate? They are suffering a lot. Farmers are the backbone of our economy.

16.00 hrs

Sir, unemployment is increasing day by day. In this country, our youngsters have got a lot of grievances with regard to unemployment. There also, the Government has miserably failed.

With regard to media, what is happening? As far as India is concerned, we call ourselves the biggest democracy. In this country, freedom of the Press is totally curtailed. That is what I want to say.

I would say that the biggest failure of this Government is the fact that there are wide-ranging disparities and injustice.

In this country, there is a very serious problem. India should stand united. Unfortunately, their interest is in spreading disunity in the country. They have to correct themselves. If that is not done, this country will be spoiled. In the best interest of the nation, I humbly request the Government to correct their mistake and get on to the right path.

Thank you.

***SHRI S. VENKATESAN (MADURAI):** Hon. Chairman Sir, Vanakkam. Some people live in darkness fearing brightness. Some people live in the past fearing the present. Same is the case of political parties. As elections are fast approaching, we are talking about development, unemployment and poverty. But they are speaking about the invasions that took place 400 years ago. They will talk about the encroachment that took place 600 years ago. If we talk about inflation; they will talk about Babur. If we talk about corporates, they talk about Mohammed Ghazni. If we take the 'past' out of them, then there is nothing or no instrument with them for facing the future. If we ask them to talk about India's and world's development in 2024, even at the beginning of election war, they stand 10 years behind and this is indicative of the failure of this government. What this 'White Paper" is all about? We want to say about the development of billionaires in this country. In the year 2014, there were 70 billionaires in the country. Today we have 170 billionaires. In the category of individual per capita income, India is at the 142nd position in the world.

As regards the human development index, it is in 132nd place. On Happiness Index, it is at the 136th place. This is a country where corporates live in ecstasy. People can only have a breathless dip deep into an ocean of happiness. That's why India is at 136th place in the World Happiness Index. In the Hunger Index of the World Food Policy, India occupies 107th place out of 122 countries in the list. If the opposition says these statistics, the Minister says, he doesn't accept them. You will appear for exams. You yourself will be the evaluator too. You will

*English translation of the speech originally delivered in Tamil.

award marks on your own. If we ask, you will bring a new legislation providing 10 year imprisonment for wrong doing for awarding marks. You talked here about inflation. This White Paper is full of graphs, charts and pictorial representations. But you have missed one chart. Can you release a chart on cooking gas? During last 10 years, the cess on petrol and diesel has increased 3.5 times; Cess on diesel has increased 9.5 times. Who is responsible for this? Jawaharlal Nehru is sleeping at Shantivan on the banks of Yamuna. Is he responsible? You ponder over it. Corporate tax was 33 per cent in 2014. During your regime it was just 20 per cent. You reduced the corporate tax by 11 per cent. One percent of this works out to Rs. 50000 crore Can the Hon. Finance Minister explain to this House how much was the loss on account of this reduction was in corporate tax? If you provide it to the people, it is concession. If you give so much to the Corporates then it is an incentive.

This nation is looking at your dictionary of terms time and again. Your 'White Paper' is filled with the tears of common man and with the smiles of the Corporates. At the height of this, Hon Prime Minister talks of making the foundation for next 1000 years. You have done something which was not there for the last 1000 years or more. It is in the tradition of Indians to offer prayers to God by lighting a piece of camphor. But what have you done? You have levied 12 per cent GST for camphor used for offering prayers to God. That's why you have secured your place in the History. Anyone who prays to God by lighting a camphor will pray against this government for unjust increase in tax. I wish to remind you, one more thing at this moment. *Muthamilaraingar* Dr. Kalaignar who

declared himself as atheist, gave exemption from tax for camphor in Tamil Nadu, as he considered camphor is associated with devotion. Be it a theist or an atheist, a government should give importance to the feelings of each and every human being. This is very important. In the same way, your schemes. The names of the Schemes implemented by the Union Government since 1975 to 2013 have been changed to Hindi names. During the last 10 years, all the schemes brought by you were named in Hindi. Not only schemes, even the laws including IPC were named in Hindi. Do you know the height of all your actions?

During demonetization you brought new 500 rupee and 2000 rupee notes. As a historical move you printed Devanagari numbers on such notes. I wish to say that, every Indian who used 500 as well 2000 rupee notes will get know about imposition of Hindi by this Government in an unjust manner. You talked about unemployment. How many are employed in the age group of 15 to 24? It is just 11 per cent in Pakistan, 12 per cent in Bangladesh and they say it is 24 per cent in India. Hon. Finance Minister should clarify in this House whether it is true or not? Similarly Start-up India Scheme. A member of NITI Aayog has expressed in an interview that this scheme has failed. Like a spendthrift son spending his forefathers' hard-earned money, you killed BSNL without giving 4G? Who privatised Air India? I want to ask that who brought a law to privatise LIC, some banks and other PSUs. Why the 'White Paper' is silent on human rights, state rights and devolution of funds to States? You are implementing a policy that crushes the non-BJP ruled States of the country.

If we talk about Kerala, Karnataka and Tamil Nadu Hon. Prime Minister himself says that we all create a divide between the north and south. We are not creating this divide. What did you say when you were the Chief Minister of Gujarat? Just hear your video once again and then speak. Do not destroy our Unity for the reason you want to destroy India's federal structure. Those institutions given up by you have been taken over and made functional by the Kerala Government. We want to ask the Union Government whether it is not ashamed. Hon. Finance Minister, I would like to say that Tamil Nadu provides you with more revenue receipts. But you have been deceitful to Tamil Nadu not one or two but on many occasions. What is the status of AIIMS in Madurai? What was the reply made by the Minister to the question raised by beloved friend Shri Manickam Tagore MP.? He said there is delay in land acquisition. There is a delay due to the agreement signed by JICA. There is a delay due to Covid. You are citing several reasons for the delay one after the other. Why is this not applicable to AIIMS in Himachal Pradesh? Why these reasons are not applicable to the States where BJP is in power? You want to show your disloyal attitude towards Tamil Nadu and nothing else. You do not want to allocate any fund to AIIMS in Madurai. NIPER in Madurai is still kept pending. I can list out several things. It is a long list. Tamil Nadu, even after it was affected by two floods, one after the other, you are still adamant in releasing any fund not even a single paise to Tamil Nadu. Floods have receded. But your policies of vengeance has not ended. People of Tamil Nadu will never forgive you for your deeds. Take all the aspects of this ‘White Paper’ and I want to conclude my speech with a quote from

writer Arundhati Roy. “Two are selling India and two are buying India.” The nation knows who these Four persons are. A total of 140 Crore people know who those four persons are. Breaking the alliance of these four persons, INDIA will definitely will. I conclude here. Thank you.

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): सभापति महोदय, आपने मुझे इस व्हाइट पेपर पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

The White Paper on the economy has exposed the dark truth of UPA. I think that this Paper should be renamed as 'Black Paper on Governance'. Many argue the need of a Paper on UPA now. Those who do not know history are doomed to repeat it. There are decades where nothing happens and there are weeks where decades happen. If we forget what they did to India, we will never understand how Prime Minister Narendra Modi ji saved India from sinking.

I would like to focus on the reasons behind the economic and policy stagnancy during UPA years and how dangerously it compromised our economic and social security. UPA was an organised loot and legalized plunder. A democratically-elected Government was run by unconstitutional authorities. There has never been a Government so unconstitutional in its daily conduct.

I would like to read from the book 'The Accidental Prime Minister' in which Shri Baru, the author wrote: "I have to come to terms with this. There cannot be two centres of power. That creates confusion. I have to accept that party president is the centre of power". Baru has quoted Dr. Manmohan Singh in this book. This is an example of how democracy turned into monarchy and how monarchy turned into anarchy leading to so much of corruption.

When UPA came to power, उनका आने के पहले स्लोगन था– 'कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ'। जब वह पावर में आए तब उनका स्लोगन था– 'कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ'। मुझे लगता है कि यूपीए ने इन दस सालों में जो भ्रष्टाचार किया, वह पूरा इस व्हाइट पेपर में आज हम सभी के सामने हैं। यह जो व्हाइट पेपर है, वह कांग्रेस की काली करतूतों का सबूत है। यह व्हाइट पेपर

एक तरफ कांग्रेस के भ्रष्टाचार का ब्यौरा देता है तो दूसरी तरफ हमारे प्रयासों का प्रमाण है। हम सब इस नई संसद में 17वीं लोक सभा के अंतिम सत्र में हैं। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं दस वर्ष इस सदन का सदस्य रहा हूं, जिसमें हमने डिकेड ऑफ डेवलपमेंट देखा। हमने यूपीए के कार्यकाल में डिकेड ऑफ डिजास्टर देखा। इन दस वर्षों में मैंने देश को फ्रेजाइल-5 से टॉप फाइव इकोनॉमीज़ में जाते हुए देखा। मैंने जी-20 के माध्यम से इस देश को एक ग्लोबल सुपर पावर बनते देखा। जब चन्द्रयान की सफल लैंडिंग हुई, तो मैंने इस दशक में गर्व की अनुभूति की। जब इस संसद में नारी शक्ति अधिनियम को कानून बनाया गया तो मैंने महिलाओं का सम्मान होते देखा।

मैंने स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी का सपना भी इस सदन में ही पूरा होते हुए देखा, जब गृह मंत्री जी ने अनुच्छेद 370 हटाने का काम इस सदन में किया। पूरे भारत की आस्था और वर्षों से चली आ रही माँग को भी पूरा होते हुए भी देखा, जब 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्रीराम जी की प्राण-प्रतिष्ठा की गई।

जो सरकार थी, जिन्होंने रेल में, तेल में और खेल में सबमें भ्रष्टाचार किया। ये सारे भ्रष्टाचार किये, वे गये जेल में और जो बाहर हैं, वे आये हैं बेल में। ये जिनकी वकालत करते हैं, वे आते हैं इस वेल में। आज यहाँ पर इनकी ऐसी परिस्थिति है।

मैं आज यहाँ पर सभी का भाषण सुन रहा था कि यूपीए के कार्यकाल में किस प्रकार से अच्छे काम हुए। हमारे सभी विपक्ष के भाई यहाँ पर उनके बारे में कह रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि जो व्हाइट पेपर है, यह इनके काले कारनामों का एक आइना है। इस व्हाइट पेपर को देखने के बाद आज इनको समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से इन्होंने इस देश पर शासन किया। इनके लिए मुझे एक शायरी याद आती है।

नज़र नहीं है, नजारों की बात करते हैं,
जमीं पे रहकर चाँद-सितारों की बात करते हैं,
वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले,
भरी सभा में, सुधारों की बात करते हैं।

मुझे लगता है कि आज विपक्ष, यहाँ पर जो सुधारों की बात कर रहा है, जिनके शासन में जमीन पर बोफोर्स से लेकर आसमान में अंतरिक्ष तक, अगर हम लोग इसमें कोल को गिन लेंगे, तो पाताल से आसमान तक भ्रष्टाचार करने का कारनामा यूपीए के शासन में किया गया था। हर संभव भ्रष्टाचार किया गया। विपक्ष ने गाय के चारे से लेकर शराब तक और 2 जी से लेकर सीडब्ल्यूजी तक सबमें घोटाला किया।

ये धोखा है उस किसान के साथ, जो आपसे बेहतर समर्थन मूल्य की अपेक्षा कर रहा था, यह धोखा है उस युवा के साथ, जो अच्छी शिक्षा और रोज़गार से वंचित रह गया, यह धोखा है उस जवान के साथ, जिसके लिए हथियारों की खरीद में भी आपने घोटाला किया। ये धोखा है उस महिला के साथ, जिसको सुरक्षित और सशक्त बनाने का आपने वायदा किया था, लेकिन 10 साल के कार्यकाल में इन सभी लोगों के साथ आपने विश्वासघात किया। इन सभी को सम्मान देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया। एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह और प्रधान सेवक की तरह उन्होंने सेवा की।

आज हम लोग अमृतकाल में और विकसित भारत के युग में हैं। हमारे सभी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉज़िटिव हैं। हमारी औसत मँहगाई दर 5 प्रतिशत थी, जो आपके कार्यकाल में 8.2 प्रतिशत थी। हमारा फोरेक्स रिज़र्व 303 बिलियन डॉलर से बढ़कर 617 बिलियन डॉलर हो गया है। हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 9.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है और नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) रेशियो 16 प्रतिशत से कम होकर 6 प्रतिशत पर आ गया है और जीडीपी ग्रोथ में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं।

मॉर्गन स्टैंली ने भारत को फ्रेजाइल इकोनॉमी कहा था। आज वही, वर्ष 2023 में, भारत को fastest growing economy with macro-economic stability कह रहा है। जिस चीन का उदाहरण और तारीफ कांग्रेस पार्टी करती है, उसके स्टेट-रन ग्लोबल टाइम्स ने भी भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फॉरेन पॉलिसी की प्रशंसा की है।

मैं विपक्ष वालों से यह कहना चाहूँगा कि आप इल्ज़ाम लगाते रहिए, हम यहाँ पर इतिहास बनाते रहेंगे। इस श्वेत-पत्र में बहुत विस्तृत रूप में हर सेक्टर की जानकारी दी गई है। मैं यहाँ पर कुछ सेक्टर्स का उदाहरण देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं डिफेंस सेक्टर की बात करूँगा। हम अपने जवानों पर गर्व करते हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन आज एक लाख करोड़ रुपये के पार हो गया है। हमने डिफेंस कॉरिडोर बनाया। आज हम देश में मशीनगन्स बना रहे हैं। हमारा डिफेंस का बजट 6 लाख करोड़ रुपये का है। डिफेंस कैपेबिलिटी की कमी के कारण क्या परिणाम होता है, उसका सबसे प्रमुख उदाहरण हमने मुम्बई में देखा। वहाँ पर 26/11 का हमला हुआ। वहाँ हमारे पुलिस कर्मियों के पास सिर्फ थ्री नॉट थ्री रायफल थी और आतंकवादियों के पास एके-47 थी। ऐसी परिस्थिति वर्ष 2008 में हमारे देश की थी। पहले हम आतंकवाद का जवाब नहीं देते थे, लेकिन आज पूरी ताकत के साथ, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट की एयर स्ट्राइक हो, दुश्मन को मुँहतोड़ जवाब देने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। आपने हमारे सैनिकों को बुलेटप्रूफ जैकेट भी नसीब नहीं होने दी और खुद अगस्ता वेस्टलैंड के चॉपर में यात्रा कर रहे थे। एंट्रिक्स-देवास में 500 करोड़ रुपये का घोटाला किया और न जाने ऐसे कितने घोटाले आप लोगों ने अपने कार्यकाल में किए।

दूसरा, आज हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हम गर्व करते हैं कि पूरे देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हाई-स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 500 किलोमीटर थी, जो आज 4 हजार किलोमीटर है। एयरपोर्ट्स की संख्या 74 थी, जो अब दोगुनी से ज्यादा होकर 149 हो चुकी है। सिर्फ 5 शहरों तक सीमित मेट्रो की सुविधा आज 20 शहरों में है। 25 हजार किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछाये गए हैं। 49 से ज्यादा रूट्स पर वंदे भारत ट्रेन चल रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,300 से ज्यादा रेलवे स्टेशंस का कायापलट हो रहा है। आज हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है और हम इस वर्ष कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 11 लाख करोड़ रुपये का खर्चा करेंगे। ये हमारी उपलब्धियाँ हैं। आपने क्या किया? आपने देश के रिसोर्स को कौड़ी के भाव में बेचा। 1.7 लाख करोड़ रुपये का 2जी घोटाला किया। कोयला घोटाला में 1.86 लाख करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया। इन दोनों घोटालों में सुप्रीम कोर्ट ने आपके भ्रष्टाचार की पुष्टि की और आपका

लाइसेंस कैंसिल किया। आज देश में अनेक कार्य डेवलपमेंट के हो रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। आज युवाओं को जॉब्स देने का काम हमारी सरकार कर रही है। स्टॉर्टअप्स में आज हम नंबर वन पर हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ उपलब्धियाँ महाराष्ट्र के बारे में कहना चाहूँगा। अब मैं मराठी में बोलना चाहूँगा।

माननीय सभापति : मेरा आपसे बस इतना ही निवेदन है कि आप अपनी बात जल्दी पूरा करें।

*DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE : Now, I would like to speak in Marathi. What Maharashtra did get during last ten years period? Well, Maharashtra got 25 lakh houses under PM Awas Yojana. Around 71 lakh poor got benefitted through Ayushman Bharat Yojana. During Covid period, 17 crore people got vaccinated. Around 1.10 crore farmers got benefits under PM Kisan Samman Nidhi Yojana. Around 1, 11, 74,000 households received Tap water connections under Jal Jivan Mission. Under PM Ujjwala Yojana, 38 lac women got gas connections and I can refer to such many more examples. Infrastructure works to the tune of Rs 8 lac crore are underway and Railway infrastructure projects worth rupees one lac four thousand crore are going on. Maharashtra is the foremost State and it is leading in all the infrastructure works throughout the country. My State Maharashtra has the highest contribution in our GDP and we are also at number one position in start-ups too. Our Maharashtra is the only State which has fetched the green hydrogen investment.

Sir, some people in Maharashtra keep on complaining about the transfer of businesses and industries to the other States, but they do not realize what they had done during their tenure. The numbers of farmers' suicide cases were highest during their regime and during last two and a half years period, they were only engaged in corruption even during Covid pandemic. You were completely busy in corruption when people were expecting something better and positive from you. Your near and dear ones were benefited from that corruption and you just ignored

* …. *English translation of this part of the speech originally delivered in Marathi.

it. Many people were involved in these scams and some of them have now landed in jail.

When we came to power, we changed the atmosphere totally. Today, Maharashtra tops the list of FDI and we have signed the MOUs worth Rs 4 lac crore at Davos. Around 85% of the projects would be executed in coming future in Maharashtra. We have also completed MTHS project under the guidance of our Hon'ble Prime Minister and Chief Minister Shri Eknath Shinde, Deputy CMs Shri Devendra Fadnavis and Shri Ajitdada Pawar. We have also completed the Nagpur-Mumbai Samruddhi Mahamarg project in record time. The construction work of Navi Mumbai Airport is also underway and it would be completed very soon. Dharavi Redevelopment project is also going to start very soon. Metro line projects covering the distance of around 350 km in Mumbai and Maharashtra are also going on under the leadership of Shri Narendra Modi ji. Hence, I would like to thank our Hon'ble Prime Minister and Finance Minister for bringing this white paper today to expose the real face of Congress Party. Thank you very much.*

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): सभापति जी, आपने मुझे आप व्हाइट पेपर पर चल रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सर्वप्रथम मैं परम आदरणीय प्रधान मंत्री जी को और आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के समक्ष व्हाइट पेपर को प्रस्तुत किया है। मैं माननीय सदन और सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि वाइट पेपर को प्रस्तुत करना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है क्योंकि जो घटनाएं हुईं, जो देश का इतिहास वर्ष 2004 से 2014 तक रहा, वह आज से बीस साल पहले हो चुका है। हमारा देश युवा देश है। आज के जो युवा मतदाता हैं, वे उस समय बच्चे थे। मेरे स्वयं का बेटा 23 वर्ष का है। 10 साल पहले वह 13 साल का था। आज के जो वोटर हैं, वे उस समय पढ़ाई-लिखाई में ध्यान दे रहे थे, खेल-कूद में ध्यान दे रहे थे। अर्थव्यवस्था में और देश में जो उस समय हो रहा था, उसमें बच्चे ध्यान नहीं दे रहे थे। इसलिए आज यह जरूरी है, जैसा कि शिंदे जी ने अभी बताया कि those who are not going to learn the lessons of history are condemned to repeat them. यह हमारी जिम्मेदारी थी कि the lessons of history have to be presented in this august House and in front of the nation. And once again, I am going to thank the hon. Prime Minister and hon. Finance Minister for presenting this White Paper to the people of India.

सभापति महोदय, जब हमारी सरकार बनी तो जो विकास की ट्रेन थी, उसे श्रद्धेय अटल जी की सरकार ने एक पैसेंजर ट्रेन से राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन बना दी थी। उस विकास की ट्रेन को यूपीए की सरकार ने राजधानी एक्सप्रेस से बदलकर पहले पैसेंजर ट्रेन बनायी और फिर पैसेंजर ट्रेन बनाने के बाद उस ट्रेन को खाई में गिरा दी। वर्ष 2014 में यह स्थिति थी, जब हमारी सरकार बनी थी। जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि तब हम एक व्हाइट पेपर ला सकते थे, जैसा यह व्हाइट पेपर है, दुनिया को यह बता सकते थे कि हमारी अर्थव्यवस्था खाई में आई हुई है, लेकिन हमने यह नहीं किया। मुझे लगता है कि माननीय प्रधान मंत्री जी को अटल जी की कुछ पंक्तियां याद आई होंगी। ये पंक्तियां वर्ष 2014 के समय के लिए बहुत ही अनुकूल है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसे सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। उस समय माननीय प्रधान मंत्री जी की सोच थी -

गीत नया गाता हूं,

टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी,

अन्तर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी,

हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा,

काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं,

गीत नया गाता हूं।

महोदय, हमने नया गीत गाया। हमारी अर्थव्यवस्था, जो उस समय खाई में थी, उसके लिए हमने एक नया गीत दिया। उस अर्थव्यवस्था को हमने फिर से पटरी पर चढ़ाया। हमने उसे राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन बनायी, वंदे भारत ट्रेन बनायी, इस 'विकसित भारत' के अन्तरिम बजट के द्वारा अमृत भारत ट्रेन बनायी और अगले कार्यकाल में हम इस अमृत भारत ट्रेन को बुलेट ट्रेन बनाकर एक विकसित भारत बनाएंगे। हम लोग यह 'नया गीत' गा रहे हैं।

भारत की जनता पूरे विश्व को जानना चाहती है, यह समझना चाहती है कि यूपीए सरकार ने विकास की ट्रेन को खाई में क्यों ढकेला, कैसे ढकेला। ऐसी तो कोई बात नहीं थी कि उनमें योग्यता की कोई कमी थी। अभी एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है कि हमारी सरकार ने पी.वी. नरसिम्हा राव जी को 'भारत रत्न' दिया है। वे लिब्रलाइजेशन लाए। उनके ही वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी थे। उनकी सरकार के बाद यूपीए की सरकार बनी। उसमें एक से बढ़कर एक अर्थशास्त्री थे। डॉ. मनमोहन सिंह खुद उसमें थे, डॉ. अहलुवालिया थे, डॉ. रघुराम राजन थे, चिदम्बरम जी थे। इतने योग्य लोग उस सरकार में थे। उनकी बराबरी में हमारे यहां कोई अर्थशास्त्री नहीं थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अर्थव्यवस्था को बदला।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : क्या यशवंत सिन्हा जी नहीं थे?... (व्यवधान)

श्री जयंत सिन्हा : वे मोदी जी की सरकार में नहीं थे, वे अटल जी की सरकार में थे, यह आपको अच्छी तरह से मालूम है।

मैं यह स्वीकार करता हूं, विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं कि हमारे पास ऐसे योग्य अर्थशास्त्री नहीं थे, जैसे आपके पास थे, लेकिन तब भी आपने अर्थव्यवस्था का क्यों कबाड़ा किया? उसका एक कारण है। कारण यह है कि आपकी विचारधारा और हमारी विचारधारा में आसमान-जमीन का अन्तर है। यह सुन लीजिए, जान लीजिए। देश को यह जानना जरूरी है कि आपकी विचारधारा और हमारी विचारधारा में आसमान-जमीन का अन्तर है। आप 'फैमिली फर्स्ट' करते हैं तो हम 'नेशन फर्स्ट' करते हैं। इसमें योग्यता का मामला नहीं है, इसमें आपके क्या इरादे हैं, आपकी क्या नीयत है, यह इसको दर्शाता है, क्योंकि आपने 'फैमिली फर्स्ट' को अपनाकर अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रद्धेय अटल जी के समय क्या-क्या हुआ। आपको मालूम है कि अटल जी की सरकार ने एक साहसिक कदम लिया। पोखरण में परमाणु विस्फोट किया गया और तब विश्व ने भारत पर सैंक्शन्स लागू किए। एशियन फाइनैंशियल क्राइसिस हुआ, इराक़ में युद्ध हुआ, तब भी ये सब संकट होते हुए भी अटल जी की सरकार ने जो आपको राजधानी एक्सप्रेस सौंपी, जो विकास की ट्रेन सौंपी, उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट 8 प्रतिशत था, फिस्कल डेफिसिट 3-4 प्रतिशत के आस-पास थी, इंफ्लेशन 3-4 प्रतिशत था। बहुत बढ़िया तरीके से, राजधानी एक्सप्रेस की गति से हमारी अर्थव्यवस्था चल रही थी, लेकिन आपने क्या किया?

लेकिन आपने क्या किया। मैं इसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु आपको बतना चाहता हूँ और उसकी तुलना माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम सबसे जरूरी यह समझना है कि मंहगाई का क्या हुआ। हर गृहणी, हर परिवार मंहगाई से कराहता है, मंहगाई को सबसे चुभने वाला विषय मानता है। आपके समय मंहगाई कमर तोड़ थी, अगर अटल जी की सरकार ने अपको 3-4 पर्सेंट इनफ्लेशन का रेट दिया तो आपने उसको 8-10 पर्सेंट कर दिया, जो भारत के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं था। हम लोगों ने उसको कम करते-करते अब 4-6 पर्सेंट पर ले आए हैं। यह मंहगाई इसलिए बढ़ रही थी, क्योंकि वित्तीय परिस्थितियों को आप संभाल नहीं पाए। फिसकल

डेफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आपके खर्चे ऐसे थे, जिससे अर्थव्यवस्था को कोई लाभ नहीं मिल रहा था। आपके खर्च सिर्फ मंहगाई को बढ़ रहे थे। आपने हमारी अर्थव्यवस्था में टिकिंग टाइम बम डाला, जिसमें ऑयल बॉन्ड्स का जिक्र किया गया है, एनपीए का जिक्र किया गया है और कैपिटल एक्सपेंडीचर पर आपने जो कटौती की, वह भी एक टिकिंग टाइम बम था, जो हमारी पोटेंशल को कम कर रहा था। हम लोगों ने इस मंहगाई की दर को 3-4 पर्सेंट कर दिया और आप यह जान लीजिए कि फिसकल डेफिसिट भी आप लोगों के ज़माने में 6-8 पर्सेंट चल रहा था, जो सामान्य परिस्थितियां में 6-8 पर्सेंट कभीं नहीं होना चाहिए। जब एफआरबीएम ने, अटल जी की सरकार ने तय किया था कि 3 पर्सेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपने फिसकल डेफिसिट को 6-8 पर्सेंट कर दिया, हमने 3-4 पर्सेंट रखा, सिर्फ कोविड के समय हम लोगों ने इसको बढ़ाया। जब आपकी फिसकल पोजिशन आउट ऑफ कंट्रोल थी, जब आप देश की वित्तीय परिस्थितियों को नहीं संभाल पाए और मंहगाई इस प्रकार से बढ़ती चली गई कि हर गृहणी के आंसू आने लग गए, जैसे सुषमा जी ने कहा था। जो आपका खर्चा था, जैसे मैंने कहा कि अगर आपका फिसकल डेफिसिट 6-8 पर्सेंट चल रहा था तो इससे क्या हम लोगों को लाभ मिल रहा था? क्या हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिल रही थी, रफ्तार मिल रही थी? बिल्कुल नहीं । उस समय आपका जो खर्चा था, उसमें कैपिटल एक्सपेंडीचर, आगे के दिन अर्थव्यवस्था को रफ्तार देता है, अर्थव्यवस्था को और मजबूत और दुरुस्त बनाता है, लेकिन आपका कैपिटल एक्सपेंडीचर ऐसा नहीं कर रहा था। जब अटल जी थे तब it was 31 per cent net of interest payments of the total expenditure. आपने क्या किया? आपने 31 पर्सेंट को घटा कर 16 पर्सेंट कर दिया, जब आपका फिसकल डेफिसिट भी बढ़ रहा था । This is pure fiscal mismanagement and it is shocking to see that you had the best economist that India has produced and you are engaging in this kind of fiscal mismanagement. हम लोगों ने उसको बदला। जो आप लोगों के समय कैपिटल एक्सपेंडीचर घट कर 16 पर्सेंट हो गया था, इसको हम लोगों ने गति दी और अब फिर 28 पर्सेंट हो गया है। उसका कितना प्रभाव हुआ, जहां आप लोगों के समय नेशनल हाइवेज़ का कंस्ट्रक्शन, जिन गोल्डल क्वाड्रीलेट्रल और नेशनल हाइवेज़

का अटल जी की सरकार ने बनाया था, उसमें सिर्फ 12 किलोमीटर प्रति दिन नेशनल हाइवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अगर हम लोगों को आप देखें, हमारे समय में 28 किलोमीटर प्रति दिन हो चुका है। बहुत तेज़ी से हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं। आज यहां सभी माननीय सांसद मेरे साथ बिल्कुल सहमत होंगे कि इसके द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था को क्या रफ्तार मिला है, उनके जीवन में रफ्तार मिली है। मैं खुद के जीवन के बारे में आपको बातना चाहता हूँ, हम लोग रांची से हज़ारीबाग जाया करते थे, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं थे, तब 5-6 घंटे हम लोगों को 120 किलोमीटर पार करने के लिए लग जाते थे। अब उसी रास्ते पर डेढ़ घंटे में हम लोग रांची से हज़ारीबाग पहुंच जाते हैं। लोग हज़ारीबाग से निकल कर शाम को रांची जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, खाना खाते हैं, फिर रात को हज़ारीबाग पहुंच जाते हैं। अगर आप राष्ट्रीय राजमार्गों को ठीक से बनाएंगे तो लोगों को इस तरह से लाभ मिलेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने अपने काम किए हैं। एयरपोर्ट के बारे में तो मैंने पहले भी ज़िक्र किया। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि आपके समय 70 एयरपोर्ट्स थे, हम लोगों एयरपोर्ट्स की संख्या 150 तक ले गए हैं। रेलवेज़ में जो काम हुआ है, अद्भुत काम हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, 'वंदे भारत' ट्रेन चलाई गई है। हज़ारी बाग में वंदे भारत ट्रेन आ गई है

हम लोगों ने अमृत भारत दिया है। आज बुलेट ट्रेन सहित सभी चीजों का निर्माण चल रहा है। पोर्ट्स में टर्न-अराउन्ड टाइम में हम लोगों ने गति दी है। यह जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पब्लिक गुड्स का जो इन्वेस्टमेंट है, यह बहुत ही जरूरी है। इसी के द्वारा आगे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलता है। हम लोग पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि आज जो हमारी अर्थव्यवस्था चार ट्रिलियन डॉलर की है, वह पाँच ट्रिलियन पार करेगी, दस ट्रिलियन पार करेगी, क्योंकि जो निवेश करना होता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होता है, वह हम लोगों ने किया है। इसे आपकी सरकार ने नहीं किया, इसलिए आप लोगों ने अर्थव्यवस्था को खाई में डाला।

अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो एक बहुत जरूरी क्षेत्र है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के बारे में कहा। कोयले का जो उत्पादन हो रहा है, पहले इसका फायदा हम लोगों के क्षेत्र में जहां-जहां कोयले का उत्पादन या

कोई भी माइनिंग होता है, हम लोगों को अपने जिले में कोई फायदा नहीं मिलता थ। आज के समय जिला खनिज मद के द्वारा झारखंड को लगभग 12,000 करोड़ रुपये मिले हैं। जहां हम लोग 5 करोड़ रुपये के लिए अपने जिले में परेशान रहते थे, आज हजारीबाग को करीब 125 करोड़ रुपये सलाना मिल रहा है। रामगढ़ मेरा अपना जिला है। हम लोगों को 125 करोड़ रुपये सलाना मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से हम लोगों ने इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। हमारे हजारीबाग और रामगढ़ में 28 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। हम लोगों ने इन 28 आंगनवाड़ी केंद्रों का सौन्दर्यीकरण किया है। स्कूलों में हम लोग नए भवन बनवा रहे हैं। वहां पर चारदीवारी दे रहे हैं। जहां हमारी बच्चियाँ अपने को असुरक्षित महसूस करती थी, आज सब जगह हम लोग चारदीवारी डीएमएफटी के द्वारा बनवा रहे हैं। यह भी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर का आप लोगों को फायदा दिखाया है। हर स्वास्थ्य केंद्र का हम लोग सौन्दर्यीकरण कर रहे हैं, नव-निर्माण कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हजारीबाग और रामगढ़ में हम लोग 220 मेडिकल स्टाफ की बहाली डीएमएफटी के माध्यम से करा रहे हैं। 140 हजारीबाग में और 80 रामगढ़ में डॉक्टर, नर्स, टेक्निशियन की बहाली कर रहे हैं। इनकी बहाली जेएमएम-कांग्रेस की सरकार नहीं करा पाई है। इनको हम लोग डीएमएफटी के द्वारा बहाली करके लाभ दे रहे हैं। इस प्रकार हम लोगों ने अर्थव्यवस्था को बहुत गति दी है।

महोदय, अगर हमें बुलेट ट्रेन बनाना है तो एक क्षेत्र बहुत ही जरूरी है। मैं विपक्ष के साथियों को पूरे विनम्रता से बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने जिस बैंकिंग सिस्टम को एकदम खत्म कर दिया था, उस बैंकिंग सिस्टम को हम लोगों ने बहुत ही मजबूत बना दिया है। हम लोगों ने इसे बहुत ही सुदृढ़ बना दिया है।

साथियों, मैं आपको बता दूं, यह जो बैंकिंग सिस्टम है, आपके जमाने में जो फोन बैंकिंग चल रहा था, इस कारण जो नेट एनपीए होते थे, उसे अटल जी के सरकार में हम लोगों ने कम करके करीब 6-8 परसेंट किया था। उसको आप लोग बढ़ाते-बढ़ाते 16 परसेंट कर दिया था। वास्तव में जो एसेट क्वालिटी रिव्यू निकला, जब मैं वित्त मंत्रालय में था, हम लोगों ने एसेट क्वालिटी रिव्यू किया। तब यह निकल कर आया कि आप लोगों द्वारा जो लोन्स दिए गए थे, बिना सोचे-समझे लोन्स दिए गए थे।

उनको एवरग्रीन किया जा रहा था। एक बार जब सच्चाई निकली, पारदर्शिता से हम लोगों ने उसको समझा तो हमारे जो नेट एनपीए था, वह और बढ़ते चला गया। बैंकिंग सिस्टम में सुधार लाने के लिए हम लोगों को कई वर्ष लगे। हमें बैंकों का कंसोलिडेशन करना पड़ा। उनको रिकैपिटलाइज करना पड़ा। हम लोगों को इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड के द्वारा क्रेडिटर कल्चर बदलना पड़ा। तब जाकर आज हम लोगों के बैंक्स फिर एक बार मजबूत बने हैं। इस कारण हमारे पास वह फाइनैंशियल इंटरमीडिएशन क्षमता है, हम लोग सेविंग को रिसाइकल करके इन्वेस्टमेंट और लोन बनवा सकते हैं। इस प्रकार हम लोग अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं।

माननीय सभापति : प्लीज़, आप कंक्लूड कीजिए।

श्री जयंत सिन्हा : आज बैंक एनपीए चार परसेंट के आसपास हो गया है। जो प्रॉफिट है, वह एक लाख करोड़ रुपये के आसपास आ गया है। मनीष जी ने पहले कहा था कि हम लोगों ने जिस आईबीसी के बारे में सोचा है, वह सफल नहीं हो पाया है। लेकिन, मैं उस बात को बिल्कुल खारिज करता हूं। वास्तव में आईबीसी के द्वारा क्रेडिटर कल्चर में क्रांति आई है। जहां पहले बॉरोअर सोचते थे कि वे बैंकों के साथ कोई भी खिलवाड़ कर सकते हैं। आज उनको मालूम है कि अगर वे डिफॉल्ट करें तो उनकी कंपनी को हम लोग वापस ले लेंगे। आज एनपीए की जो संख्या है, वह गिरती चली जा रही है। इस तरीके से हम लोग अपने बैंकिंग सिस्टम में बहुत सुधार लाए हैं। अपने बैंकिंग सिस्टम में जिन लोगों को हम लोन दे भी नहीं सकते थे, चाहे वे किसान हों, चाहे वे मछुआरे हों, चाहे डेयरी फार्मर्स हों, चाहे स्वनिधि के द्वारा रेहड़ी व ठेले वाले हैं, उनको हम लोन नहीं दे सकते थे।

हम लोगों ने जन-धन के खाते चालू किए, यूपीआई को चालू किया। जो अनबैंक्ड थे, जिनको लोन मिलता ही नहीं था, जो आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। आज उन लोगों को हम लोन दे रहे हैं। इस कारण हमारा फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत बना है, कैपिटल एक्सपेंडीचर मजबूत हुआ है। इस कारण हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा मूल मंत्र रहा है। इस पर हम लोगों ने अमल भी किया है। एक और इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसको हम लोगों ने इसमें जोड़ा है और वह महत्वपूर्ण कड़ी है सबका विश्वास। आज जो निवेशक देश से बाहर भाग रहे थे,

जो यूपीए के समय में देश में रहना नहीं चाहते थे, आज वे निवेशक भारत में आ रहे हैं और भारत में निवेश बढ़ता चला जा रहा है।

रुपया जो आपके जमाने में बिल्कुल एकदम कमजोर हो गया था, जो दो वर्षों में 36 पर्सेंट गिर गया था, वह रुपया बिल्कुल मजबूत है। आज विश्व में सबसे मजबूत जो करेंसीज़ हैं, उनमें रुपया भी है। जब फेड ने टेपर वन किया था तो 15 पर्सेंट रुपये में घाटा हुआ था। जब फेड का टेपर टू हुआ, जब वे इंट्रेस्ट रेट बढ़ाने लगे, हमारा सिर्फ वन पर्सेंट रुपया कम हुआ। यह दिखाता है कि निवेशकों का कितना विश्वास हम लोगों की सरकार और मोदी जी की सरकार पर है। मोदी जी की सरकार में जो वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी जो ऐट रिस्क इनवेस्टमेंट था, वह आपके जमाने में 10, 15 बिलियन डॉलर था, हम लोगों के जमाने में सालाना 60 से 70 बिलयन डालर है, क्योंकि निवेशकों का विश्वास है।

यहां आप लोग निफ्टी के बारे में जान लीजिए। जो हमारे पब्लिक मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने क्या किया? वर्ष 2007 से लेकर 2014, 7 वर्ष में निफ्टी 6 हजार पर अटका रहा। निवेशक मार्केट को बिल्कुल आगे नहीं ले जा रहे थे, क्योंकि उनका आप पर कोई विश्वास ही नहीं था कि भविष्य में आप कुछ सुधार ला सकते हैं। जब यह स्पष्ट हो गया कि हमारी सरकार वर्ष 2014 में बन रही है, उस वर्ष 2014 में ही शेयर बाजार 33 पर्सेंट ऊपर चला गया। जो शेयर बाजार 10 साल पहले 6 हजार पर था, आज वह 22 हजार के आसपास हो गया है, क्योंकि सबका विश्वास है, सब निवेश में अपना पैसा देने को तैयार हैं, देश को अपना पैसा देने को तैयार हैं।

अंत में, मैं इंडी एलायंस को, घमंडिया एलायंस को यही कहना चाहूंगा कि आप अकेले ही चल रहे हैं, जानिब-ए-मंजिल, मगर आप अकेले ही चल रहे हैं, हमारे साथ जनता आती गई है और कारवां बनता गया है। हमारे साथ जनता आती चली जा रही है, कारवां बनता चला रहा है। चुनाव हम जीतते चले जा रहे हैं। चाहे वह हमारी जनता हो या विश्व के पटल को देखें, चाहे जी-20 हो, यूएन हो, कॉप हो, सब जगह भारत का कारवां बढ़ता चला जा रहा है। सब हमारे साथ हैं। हम एक विकसित भारत को बना रहे हैं। हमारे और आपमें आसमान-जमीन का अंतर है। जहां विचारधारा का सवाल है, आप

परिवार को सर्वोपरि मानते हैं, हम देश को सर्वोपरि मानते हैं, आप वंशवादी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। आप फेमिली फर्स्ट की पार्टी हैं, हम नेशन फर्स्ट की पार्टी हैं। यह हममें और आपमें अंतर है।

* **SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BATHINDA):** I thank you, Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak on the White Paper on Indian Economy under Rule 342.

Sir, Punjab has always been ahead of the country in all fields. We had suffered also due to this. Sir, in 2014, Aam Aadmi Party could not win a single seat in Lok Sabha elections in the entire country despite Kejriwal ji contesting elections from Varanasi, but in Punjab, they won 4 seats of Lok Sabha. When Himachal Pradesh, Gujarat, M.P. and Maharashtra did not repose faith in AAP, in Punjab, they won 92 seats out of 117 seats in State Assembly elections.

Sir, I want a White Paper on Congress because Congress and corruption are two sides of the same coin. Wherever Congress Government is there, corruption follows. History tells us. Let me warn the country that if Congress seems corrupt, please consider this fact that AAP is the father figure of corruption. You ask Punjabis. They will tell you this fact. AAP leaders are ... # . They make tall promises. But, they have sold Punjab and made it a poor State.

Sir, when Congress Government ruled Punjab, there would be power cuts for 11 hours. People faced inconvenience. There were no jobs. No new schools, or hospitals. Then the SAD Government came to power in Punjab. From 2010 to 2017, in the seven years, our Government made Punjab from an electricity-deficit to electricity-surplus State. Three new thermal power plants were started. A wonderful network of roads was created and four-lane and six-lane roads were

---

*English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

Expunged as ordered by the Chair.

constructed. Punjab became a developed State and seemed like a foreign country. Sir, we developed Punjab in all sectors. Schools, colleges and universities were opened. AIIMS Centre was onstructed; 28 Stadiums were constructed. We gave a fillip to agriculture. Over 1950 industries came and set up their units in Punjab. Infosys, ITC – these big industries set up their offices in Punjab. 1000 new flyovers were constructed. Drinking water facility was provided to every household.

Ours was an honest Government. We utilized the revenue judiciously. People were provided food. Now, 80 crore people get ration. This scheme was started by Punjab in 2012. 34 lakh ration cards were given to the poor people. 2.5 lakh jobs were provided.

But in 2017, the corrupt Congress Government came to power in Punjab. In 5 years, this corrupt Congress Government put Punjab under the burden of debt of one lakh crore rupees. No development work was done in Punjab by the Congress Government. No schools, colleges or hospitals were set up. Progress took a back seat. No roads were constructed. No thermal plants were set up. There was only loot and plunder of Punjab's resources.

The Congress Chief of Punjab is an accused in the bus purchase scam. Their Minister who looked after ration distribution indulged in ration scam. Cases have been filed against them. Some of the accused are in jails. Government land scam took place. Covid medicines PP Kit scam took place. SC students could not get scholarship because their money was siphoned off by the corrupt Congress. Punjab never saw corruption of this dimension. There was all-out loot

and plunder. No facilities were provided to the people. Punjab reeled under debt of one lakh crore rupees. Drugs were rampant under Congress rule. Illegal mining was going on. Revenue was being looted.

Then their companion AAP came to power. Sir, Punjab has fallen to very bad days under the rule of Bhagwant Mann ji and Kejriwal ji. Sir, today you will be shocked to know that Punjab has a debt of Rs. 3.4 lakh crore, the highest in the country. Punjab has the maximum debt on it in the entire country. We have got a debt of 48 per cent against our GDP, all thanks to the Aam Aadmi Party. If Congress took 1 lakh crore in 5 years, put as debt, this Aam Aadmi Party has put Rs. 70,000 crore of debt in Punjab in two years. It is shameful. AAP has ... * Punjab on all fronts. 70,000 crore worth of debt is there. Sir, when Kejriwal came to Punjab, he promised to give Rs. 1,000 per month to every woman. It has been two years now, and Rs. 24,000 should have reached the account of every woman, as they have taken such a big loan. But not a single rupee has been credited. Not a single penny has been given to any women. They said Rs. 2500/- pension would be given. We used to give 'Shagan' Scheme. This Government stopped it. Prices of eatables have sky-rocketed.

Over 10 lakh ration cards of poor people were disbanded. Sir, they put Punjab under thousand crore rupees worth of debt. They have utilized Punjab's revenue to brighten the image of Mr. Kejriwal throughout the country. Advertisements of full page have been planted in all newspapers regarding false achievements of AAP. Punjab's money was misused to hire aircraft for Mr.

* Expunged as ordered by the Chair.

Kejriwal to go hopping to various States for electioneering. इल्लीगल माइनिंग इतनी हो रही है that the military had to go to the court and complain about the collapsing bridges. बॉर्डर पर सारे ब्रिज कौलेप्स करने लग गए हैं । This is the state of affairs. Why does the Ministry of Environment not intervene? Rampant illegal mining is going on at the cost of exchequer. The same liquor scam is going to happen in Punjab. The same policy of Delhi has been implemented in Punjab by Kejriwal. Identical liquor policy by identical people is being adopted in Punjab. In the liquor scam, people have been caught and sent to jail. But the same thing is happening in Punjab till date, and nobody is touching them.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: I was given an assurance in the Parliament that they would be investigated. But they have not been touched till date. So, I appeal to the Government to stop the ... * in Punjab also. Sir, please catch hold of Kejriwal. Arrest him. The money of Punjab will be saved.

In the end, let me say the ... *.

HON. CHAIRPERSON: This will not go on record.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Drug menace is rampant in Punjab. Our welfare Schemes have been closed. High Court had to intervene due to drug menace. Gangsters are ruling the roost. From Ferozepur jail, 45,000 calls were made. The alliance partner, Aam Aadami Party has ... *Punjab, has ruined Punjab

* Expunged as ordered by the Chair.

and has demolished Punjab. *....(Interruptions)* चाहे ...[#] कांग्रेस हो या ...[#] आम आदमी पार्टी, देश की जनता इनसे बचकर रहे। मैं यही निवेदन करती हूं। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Asaduddin Owaisi ji, before you speak, I just want to inform the House that the reply by the Minister would be at 5:30 pm. We have around 10 Members yet to deliver their speeches. So, one can understand how much time one can give to the respective Members.

....(Interruptions)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, you should consider to extend the time of the House. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: I cannot decide that. I am just communicating to the House what has been informed. There are certain Members who will be speaking for the first time from their party. But still, this is the instruction which has come and I have communicated it to you. Please be aware about the time constraint and accordingly conclude your speech.

Actually, intelligent people speak for three minutes, and we are giving five minutes to each.

Shri Asaduddin Owaisi.

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): सर, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने तीन मिनट में बोलने वालों को इंटेलिजेंट कहा और ज्यादा बोलने वालों को क्या कहेंगे? यह आप ही चेयर से बोल देंगे तो अच्छा रहेगा।

[#] Not recorded as ordered by the Chair.

माननीय सभापति: मैं बोल देता हूं। जो तीन मिनट में बोल देते हैं वे इंटेलिजेंट तो हैं ही, लेकिन जो ज्यादा बोलते हैं, उनका ज्ञान ज्यादा होता है।

… (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं पहले यह बात वाज़े कर देना चाहता हूं कि मैं इंडिया में नहीं हूं, मगर वतन-ए-अज़ीज़ का हूं। मेरा मामला ऐसा है कि मैं लाइन ऑफ एक्शन पर हूं। भारत की राजनीति में अगर कोई लाइन ऑफ एक्शन पर है तो मैं हूं।

सर, मेरे चंद सवालात हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि मोहतरमा वज़ीर साहिबा जब जवाब देंगी तो मेरे इस सवाल का भी जवाब देंगी। यूपीए में एवरेज जीडीपी ग्रोथ 6.8 परसेंट थी और नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में एवरेज जीडीपी ग्रोथ 5.9 परसेंट हो गई। इसका जिम्मेदार चीन है या पाकिस्तान है? बता दीजिए। यूपीए के समय में फिसकल डेफिसिट एज़ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 4.7 थी और नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में एवरेज 5.1 परसेंट हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? … (व्यवधान) हां, पाकिस्तान है। … (व्यवधान) आप सही कह रहे हैं। मान लिया, मैं आपकी अक्ल की तारीफ करता हूं।… (व्यवधान)

17.00 hrs

इन्फ्लेशन यूपीए की हुकूमत में 8 परसेंट था, जबकि मोदी सरकार में 5 परसेंट है, मगर क्या यह बात सच नहीं है कि जो ग्लोबल तेल की कीमतें वर्ष 2008 से 2014 थीं, जो एक बैरल 100 डॉलर से ऊपर बिकता था, वह वर्ष 2015 से 2021 तक एक बैरल ऑयल 55 डॉलर से 70 डॉलर के दरम्यान था। यह क्रेडिट आप नहीं ले सकते, यह आपकी मेहनत नहीं है, इसमें एक्सटरनल रीजन्स हैं। मेरा चौथा सवाल यह है कि अगर जीडीपी 5.9 परसेंट एनडीए सरकार का रहा, तो फिर अन-इम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? आखिर वर्ष 2011 से इम्प्लॉयमेंट सर्वे मोदी जी क्यों नहीं कराते, वे डेटा को क्यों छिपाते हैं? आप सर्वे करवाइए। एनएसएसओ का सर्वे लाकर दे दीजिए। पीएलएफ वर्ष 2018 में हुआ था, उसके बाद अब कहां हो रहा है? आप ला दीजिए, कम से कम एनएसएसओ को बोलकर आप सर्वे करवा दीजिए।

सर, कन्जम्पशन सर्वे वर्ष 2017 से रुका हुआ है। आप अगर वित्त मंत्री होते, तो शायद आ जाता। आपकी काबिलियत और अहमियत वहां पर नहीं है, यह मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं। मेरा चौथा सवाल यह है कि वर्ष 2005 में डॉलर 43 रुपये था, जबकि वर्ष 2014 में यह 83 रुपये हो गया। मैं इकोनॉमी में इतना माहिर नहीं हूं। अब डॉलर 83 रुपये है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 83 रुपये डॉलर क्यों हो गया? नेट इनक्रीज 40 रुपये का है। अब डॉलर की डिमांड इतनी क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब शायद मोहतरमा देंगी? फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बोलते हैं कि वर्ष 2011 में बिल्कुल सही है। यह 294 बिलियन डॉलर था। वर्ष 2013 तक यह 256 बिलियन हो गया। आप व्हाइट पेपर पढ़ेंगे, तो New channel opened by RBI, नंबर क्या है भाई? नंबर तो बता दीजिए। New channel opened by RBI में नंबर ही नहीं मालूम होता है।

सर, मेरा एक और सवाल है। health expenditure from pocket ठीक है। वर्ष 2005 में 69 परसेंट था, जो वर्ष 2014 में 64.2 हो गया। आपका नंबर क्या है, बताइए? आपके दौर में क्या नंबर है, वह नहीं बताया। मेडिकल कॉलेजेज खोल दिए, लेकिन खर्च का नंबर क्या है? अत: यह जो व्हाइट पेपर है, ऐट-लीस्ट इसमें आप वर्ष 2020 का डेटा दे दीजिए। यह व्हाइट पेपर more rhetoric than substantive है। डिमोनेटाइजेशन की ये बात ही नहीं कर रहे हैं, जिसने देश के गरीबों को बर्बाद कर दिया, लेकिन उसका जिक्र ही ये नहीं करेंगे। वह तो आपका मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन लोग बर्बाद हो गए।

सर, चूंकि आपने कम टाइम में बोलने वालों को अकलमंद कहा है, तो मैं सरकार से आपके जरिए मुतालबा करता हूं कि व्हाइट पेपर यह निकालिए कि वर्ष 2014 में अखलाक के मॉब लिंचिंग से वर्ष 2024 तक कितने मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई? कितने घर बुलडोजर से तोड़े गए। इसके साथ ही साथ आप एक व्हाइट पेपर जारी कर दीजिए कि चीन 2000 स्क्वायर किमी तक कब्जा करके बैठा है या नहीं बैठा है? डेपसांग, डेमसाक हमारे पास है या नहीं है? अंत में यूपीए के वक्त में माइनॉरिटीज बजट में फ्री कोचिंग थी, जिसे आपने बंद कर दिया। मौलाना आजाद फाउंडेशन आपने बंद कर दिया, मौलाना आजाद फेलोशिप आपने बंद कर दी। फाउंडेशन में तो माइनॉरिटीज के 9वीं, 10वीं, 12वीं

तक के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप आपने 9th क्लास से रेस्ट्रिक्ट कर दी। मदरसा एजुकेशन आपने खत्म कर दी। यह आपने क्यों किया? हद तो यह हो गई कि आपके पास वर्ष 2014 में एक मुस्लिम वजीर था, लेकिन अब तो एक भी नहीं है। मामला अजीब है। ये बातें हैं, इसके अलावा आप व्हाइट पेपर में देखिए कि उसमें बिजनेस स्टैंडर्ड में शंकराचार्य जी के एक आर्टिकल का जिक्र है। शंकराचार्य जी न rhetoric पर rhetoric लिख रहे हैं, आपने उसको तोते की तरह लिखवा दिया। वे नंबर्स नहीं देते हैं। यह जो व्हाइट पेपर है, वह more rhetoric than substantive है। मैं उम्मीद करता हूं कि कल तक देश के प्रधान मंत्री वह व्हाइट पेपर जारी कर देंगे कि कितने मुसलमानों को आपने मार्जिनलाइज कर दिया, बुलडोजर से घर तोड़े गए, कितनों का एनकाउंटर हुआ, कितने जेल में हैं और कितनी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है।

बहुत-बहुत शुक्रिया।

[جناب اسدالدین اویسی (حیدرآباد): محترم چیرمین صاحب، شکریہ آپ نے مجھےبولنے کا موقع دیا میں، میں پہلے یہ بات واضح کردینا چاہتا ہوں کہ میں اِنڈیا میں نہیں ہوں، مگر وطنِ عزیز کا ہوں۔ میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں لائن آف ایکشن پر ہوں۔ بھارت کی سیاست میں اگر کوئی لائن آف ایکشن پر ہے تو میں ہوں۔

سر، میرے چند سوالات ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ محترمہ وزیرِ صاحبہ جب جواب دیں گی تو میرے سوال کا بھی جواب دیں گی۔ یو۔پی۔اے۔ میں ایوریج جی۔ڈی۔پی۔ گروتھ 6.8 فیصد تھی اور نریندر مودی جی کی سرکار میں ایوریج جی۔ڈی۔پی۔ گروتھ 5.9 فیصد ہو گئی۔ اس کا ذمہ دار چین ہے یا پاکستان ہے؟ بتا دیجیئے۔ یو۔پی۔اے۔ کے وقت فِسکل ڈیفِسیٹ ایز پرسنٹیج آف جی۔ڈی۔پی۔ 4.7 تھی اور نریندر مودی جی کی سرکار میں ایوریج5.1 فیصد ہو گئی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ (مداخلت)، ہاں پاکستان ہے۔ (مداخلت) آپ سہی کہہ رہے ہیں۔ مان لیا میں آپ کی عقل کی تعریف کرتا ہوں۔ (مداخلت)

انفلیشن یو۔پی۔اے۔ کی حکومت میں 8 فیصد تھا، جبکہ مودی سرکار میں 5 فیصد ہے، مگر کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جو گلوبل تیل کی قیمتیں سال 2008 سے 2014 تھیں، جو ایک بیرل 100 ڈالر سے اوپر بِکتا تھا، وہ سال 2015 سے 2021 تک 1 بیرل آئل 55 ڈالر سے 70 ڈالر کے درمیان تھا۔ یہ کریڈِٹ آپ نہیں لے سکتے، یہ آپ کی محنت نہیں ہے، اس میں ایکسٹرنل ریزنس ہیں۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر جی۔ڈی۔پی۔ 5.9 فیصد این۔ڈی۔اے۔ سرکار کا رہا، تو پھر بے روزگار ریٹ کتنا ہے؟ آخر سال 2011 سے ایمپلائمنٹ سروے مودی جی کیوں نہیں کرواتے، وہ ڈاٹا کو کیوں چھپاتے ہیں؟ آپ سروے کروائیے۔ ایم۔ایس۔ایس۔او۔ کا سروے لا کر دیجیئے۔ پی۔ایل۔ایف۔ سال 2018 میں ہوا تھا، اس کے بعد اب کہاں ہو رہا ہے؟ آپ لا دیجیئے، کم سے کم این۔ایس۔ایس۔او۔ کو بول کر آپ سروے کروا دجیئے۔

سر، کنزمپشن سروے سال 2017 سے رُکا ہوا ہے۔ اگر آپ فائننس منسٹر ہوتے، تو شاید آ جاتا۔ آپ کی قابلیت اور اہمیت وہاں پر نہیں ہے، یہ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ سال ل2005 میں ڈالر 43 روپیے تھا، جبکہ سال 2014 میں یہ 83 روپے ہو گیا۔ میں ایکونومی میں اتنا ماہر نہیں ہوں۔ اب ڈالر 83 روپئے ہے، تو اس کے لئے کون ذمہ دار ہے؟ 83 روپئے ڈالر کیوں ہو گیا؟ نیٹ انکریز 40 روپئے کا ہے۔ اب ڈالر کی ڈیمانڈ اتنی کیوں ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا جواب شاید محترمہ دیں گی؟ فورن کرنسی ریزروس بولتے ہیں کہ سال 2011 میں بالکل سہی ہے۔ یہ 294 بلین ڈالر تھا۔ سال 2013 تک یہ 256 بلین ہو گیا۔ اب وہائٹ پیپر پڑھیں گے، تو New Channel open by RBI میں نمبر ہی نہیں معلوم ہوتا ہے۔

سر، میرا ایک سوال ہے۔ Health expenditure from pocket ٹھیک ہے۔ سال 2005 میں 69 فیصد تھا، جو سال 2014 میں 64.2 ہو گیا۔ آپ کا نمبر کیا ہے، بتائیے؟ آپ کے

دور میں کیا نمبر ہے، وہ نہیں بتایا۔ میڈیکل کالجز کھول دیئے، لیکن خرچ کا نمبر کیا ہے؟

اس لئے یہ جو وہائٹ پیپر ہے، اٹلیسٹ اس میں آپ سال 2020 کا ڈاٹا دے دیجیے۔ یہ وہائٹ پیپر more rhetoric than substantive ہے۔ ڈیمونی ٹائزیشن کی یہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں، جس نے ملک کے غریبوں کو برباد کر دیا، لیکن اس کا ذکر ہی یہ نہیں کریں گے۔ وہ تو آپ کا ماسٹر اسٹروک تھا، لیکن لوگ برباد ہو گئے۔

سر، چونکہ آپ نے کم ٹائم میں بولنے والوں کو عقلمند کہا ہے، تو میں سرکار سے آپ کے ذریعہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہائٹ پیپر یہ نکالئے کہ سال 2014 میں اخلاق کی ماب لنچنگ سے سال 2024 تک کتنے مسلمانوں کی ماب لنچنگ ہوئی؟ کتنے گھر بلڈوزر سے توڑے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ ایک وہائٹ پیپر جاری کر دیجیئے کہ چین 2000 اسکوائر کلو میٹر تک قبضہ کرکے بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا ہے؟ ڈیپسانگ، ڈیمساک ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ آخر میں یو۔پی۔اے۔ کے وقت میں مائنوریٹیز بجٹ میں فری کوچنگ تھی، جسے آپ نے بند کر دیا۔ مولانا آزاد فاؤنڈیشن آپ نے بند کر دیا، مولانا آزاد فیلوشِپ آپ نے بند کر دی۔ فاؤنڈیشن میں تو مائنوریٹیز کے 9 کلاس، 10 کلاس، 12 کلاس تک کے بچوں کو اسکالرشِپ ملتی تھی۔ پری میٹرک اسکالرشِپ آپ نے 9 کلاس سے ریسٹرِک کردی، مدرسہ ایجوکیشن آپ نے ختم کر دیا۔ یہ آپ نے کیوں کیا؟ حد تو یہ ہو گئی کہ آپ کے پاس سال 2014 میں ایک مسلم وزیر تھا، لیکن اب تو ایک بھی نہیں ہے۔ معاملہ عجیب ہے۔ یہ باتیں ہیں، اس کے علاوہ آپ وہائٹ پیپر میں دیکھیئے کہ اس میں بزنیس اسٹینڈرڈ دیکھئے کہ اس میں بزنیس اسٹینڈرڈ میں شنکر آچاریہ جی کے ایک آرٹیکل کا ذکر ہے۔ شنکر آچاریہ جی نے نہ rhetoric پر rhetoric لکھ رہے ہیں، آپ نے اس کو طوطے کی طرح لکھوا دیا۔ وہ نمبرس نہیں دیتے ہیں۔ یہ

جو وہائٹ پیپر ہے، وہ more rhetoric than substantive ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ کل تک ملک کے وزیر اعظم وہ وہائٹ پیپر جاری کر دیں گے کہ کتنے مسلمانوں کو آپ نے مارچِنلائز کر دیا، بلڈوزر سے گھر توڑے گئے، کتنوں کا انکاؤنٹر ہوا، کتنے جیل میں ہیں اور کتنی زمین پر قبضہ کرکے بیٹھا ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ]

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, hon. Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak on this very important debate on the release of White Paper by the Central Government.

It is very important for us to know our history of at least the last 20 years in terms of how the financial discipline was maintained in our country so that we can differentiate good from the bad and also learn from the past mistakes so that we do not repeat it in the future also. What I am surprised about right now is that White Paper talks about the corruption before 2014, and if there was corruption happening in the country from 2004 to 2014, the biggest corruption happened in the State of Andhra Pradesh which was not mentioned in the White Paper. It is very surprising in fact. The period between 2004 and 2014 were the days of *raja* of corruption in the State of Andhra Pradesh. That was the time when the *yuvraj* of corruption came into politics also. The *yuvraj* of corruption who claims that he is a first-class student in college, I want to mention the value of his assets. In 2004 when his father was holding the most important position in the State of Andhra Pradesh, his assets were worth Rs. 1.7 crore. From 2004 to 2011, his increase in asset was stupendous. It increased to a whopping sum of Rs. 356 crore. In seven years, it rose from Rs. 1.7 crore to Rs. 356 crore. There was a 20,800 per cent increase. Nobody in the world, no Warren Buffet or no Rakesh Jhunjhunwala can predict this kind of increase in any business that is happening in the country or in the world. In seven years when you can have this kind of growth, everyone is curious. Of course, I am sure that Members in this House are also very curious that how can a person be growing his wealth at such a stupendous rate. Even the

ED, the IT, and the CBI were also curious. That is why they have attached Rs. 43,000 crore worth of assets of this very own person. Almost 32 cases under CBI, ED have been registered against him.

It is very important when the Central Government talks about the picture of the country. It also needs to talk about what is happening in the States. I think Rs. 43,000 crore is a huge number. If you tell some of the people in the House or in the country to write Rs. 43,000 crore, they would not even know how many zeroes are there. It is such a big number. Such big number of corruption cases happened in the State of Andhra Pradesh. Now, so many cases have been filed. This was the situation in Andhra Pradesh from 2004 to 2014. That is why the people of Andhra Pradesh voted against corruption and brought in Shri Chandrababu Naidu as the Chief Minister of Andhra Pradesh. In the country also, they have brought in Narendra Modi ji as the Prime Minister so that they can deal with this kind of corruption that is happening in the country and in the State also.

From 2014 to 2019, not a single case of corruption has come in the State of Andhra Pradesh. There might have been differences between the State and the Centre. They were purely in terms of how to make progress in the country and in the State. Naidu ji was more interested in development of the State. Modi ji was interested in the development of the country. They might have had differences but the differences were always based on development and not regarding corruption or anything else.

Then, in 2019, this first-class student of college who he claims to be – but now we know that he is not a first-class student of college but first-class student of

corruption – has come back to power by fooling the people of Andhra Pradesh, by giving them false assurances. He comes back to power and now the same culture which was happening from 2004 to 2014 is prevailing again in the State of Andhra Pradesh. Now, what is happening is he is at the helm of affairs. At one time, when his father was at the helm of affairs, Rs. 43,000 crore of assets were attached by the ED. Now, imagine what would be happening when he is at the helm of affairs. He has legalised, he has centralised, he has organised the mafia, the crime in the State and he is now trying to earn money out of it. Liquor mafia has started in the State of Andhra Pradesh. If you see, Sir, today with the inclusion of digital payments, you can buy tea also by paying through Google Pay. But in Andhra Pradesh, the State Government is selling liquor but you cannot buy using Google Pay, you cannot buy using UPI, you cannot buy using a card, and you cannot get a bill also. So, imagine how much illegal wealth is being generated by the Government itself by selling liquor today.

Then, we have this issue. The entire sand tender is being given to one company with dubious tenders. Nobody knows how it ended up being in the hands of one company but that is the situation in the State of Andhra Pradesh today. There is J-tax which has been specially brought in for illegal mining, for land grabbing, for drugs, and for different kinds of activities.

HON. CHAIRPERSON: Mr. Naidu, you have to conclude. Already, five minutes have passed.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU: Sir, I am concluding in one minute.

The point that I want to make here is that the Central Government is releasing White Papers and just letting us know what happened and what has not happened right now, but I would say that they should have zero tolerance about people who are involved in corrupt practices also. At one point of time they were talking about bringing in fast track courts, judicial laws and all so that people who are so corrupt should not be in politics even sitting as Chief Minister in Andhra Pradesh or sitting in Rajya Sabha. Now, if these kinds of people are running the State and the country, then how can we progress? We would need to release White Papers every year also. Hence, I would request the Central Government to get these new fast track courts.

Sir, I will complete in one minute.

HON. CHAIRPERSON: Okay.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU: Sir, the last point that I want to make is regarding Visakhapatnam Steel Plant. It was said to be privatised. I resist against it. I have mentioned it earlier also. Nagarnar Steel Plant in Chhattisgarh was taken back from privatization. In the same lines, the Steel Plant in Vizag, which is under RINL should be merged with SAIL. SAIL is trying to maximise its production capacity. So, why do you not include Vizag Steel Plant with SAIL? There is a good opportunity to do it. Vizag Steel Plant is the jewel of the crown.

Last point I will mention and I am concluding. I would like to thank the Central Government for announcing Bharat Ratna for three most important people of the country.

HON. CHAIRPERSON: You want to conclude your speech on a good tone. It is good.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU: Sir, Narsimha Rao ji hails from Telangana State, there is also Chaudhary Charan Singh ji and M. Swaminathan ji. It is a very good gesture from the Central Government. But I, from our State, on our behalf and on behalf of the Telugu people would like to request Yugapurusha Vishwa Vikyatha Nata Swar Swargeeya Nandamuri Taraka Rama Rao Garu who is dearly called as Anna Garu by all the Telugu people not just in the country, but outside also should also be granted Bharat Ratna. He deserves it. He was an excellent actor who has been treated as God even till today by people of Andhra Pradesh. He had been working for the backward classes. He had brought in numerous reforms for the poor. So, I would definitely put that request in front of the Central Government to grant Bharat Ratna to him. Thank you.

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Vanakkam Chairperson! Thank you for giving me this opportunity.

I would like to see this White Paper as a wolf in a sheep's clothing. This White Paper is nothing but a concoction of twisted facts and selective memory conveniently ignoring the failures and shortcomings of the present administration.

Our hon. Prime Minister seems to have a penchant for blaming the Congress and Nehru for everything under the sun. They have been in power for the last 10 years and they are supposed to talk about their merits and their successes. But still, they want to talk about the Congress and Nehru. It would have been better if they had presented a White Paper on pre-Independence period now because they would have shown a thousand-fold increase in economic development, in the number of jobs created and so on. This is not something sarcastic because if they wanted to present a White Paper and if it was to be between 2014-2019 and now, then too there would be an increase in all that they are saying now. So, it always shows that what the Congress and the Nehru had done then, it is that momentum which is being carried on now also and that is why we are seeing success.

Why is there a deafening silence on the peoples' issue of price rise, unemployment and economic inequality? Whatever little success this Government has, it likes to chest-thump and always say that it is due to Modi. But if there is any failure, they want to attribute it to the Congress and they want to attribute it to Nehru.

The Periodic Labour Survey has indicated a decline in job quality with monthly earnings remaining stagnant since 2017. The White Paper proudly mentions India's stint as one of the 'fragile 5' economies in 2013. So, it conveniently forgets the global financial crisis of 2008 during which India stood resilient while other economies, even like that of the US had stumbled. Was the BJP in power then? It was Dr. Manmohan Singh who had stood there.

It is not only this Government that can bring a report card or give comparison of 10 years. We also would like to give a comparison of 10 years before. The petrol price then was Rs. 72, now it is Rs.101. Diesel was Rs. 55, now it is Rs. 92. Gas cylinder was below Rs. 400, now it is Rs. 1,000. The value of rupee against the US dollar was around Rs. 60, now it is Rs.83. Groundnut oil was Rs. 130, now it is Rs. 300. Gingely oil was Rs. 300, now it is Rs. 500. Toor Dal was Rs. 74, now it is Rs. 140. The price of the garlic which the Finance Minister proudly said in this very House that she does not consume but the common man eats rose from Rs. 110 to Rs. 400.

HON. CHAIRPERSON: The time allotted to your Party is over. Please conclude in two minutes.

DR. DNV SENTHILKUMAR S.: Sir, I would like to place on the record that this Government has failed on bringing back black money, demonetisation, printing of Rs. 2000 notes and withdrawal, farmers laws, creation of PSUs, giving Rs. 15 lakh which they promised, two crore jobs, bullet train, price rise, making railways on a par with the airports, and Madurai AIIMS. Everything above was a big failure. The list goes on and on. We find only empty promises and hollow rhetoric. It is

time we held this Government accountable for its failures and demand real solutions to the pressing issues that are plaguing our nation. I am just finishing. I want to quote something:

“For in the heart of every strategic lies,

a tale of struggle of struggle, of dreams that rise.

Let not numbers obscure the human plight,

Let compassion guide us, in truth’s pure light.

Beyond the white papers and political storm,

Lies the essence of why we were born.

To serve the people, to uplift the weak,

To find solutions, when hope seems bleak.

So rise, my friends, with courage anew,

Let us build a tomorrow that is bright and true.

For in the end, it is not power we seek,

But a world where every voice can speak.

HON. CHAIRPERSON: Senthilkumar ji, you spoke very wise words.

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Although I have already been restricted by you to conclude as quickly as possible but I am the only speaker for my Party, I will briefly speak on ten points that I have made. I will be very clear and brief.

The Government while placing this White Paper has focused on nation first. I still believe in nation first. This is something which we all love and we all follow. The same way, when this White Paper talks about ten years of UPA Government and the last ten years of the NDA Government, my State of Odisha has experienced both the ten years of UPA and NDA by our Naveen ji-led BJD Government in Odisha. Odisha's longstanding demands have not been addressed by both the Governments. I want to place these points on record today. I urge upon both the sides and especially the ruling Government to look into these matters.

The first issue is regarding not sharing cess and surcharge with the State. If cess and surcharge were part of the Gross Divisible Pool, States would have got Rs. 7,32,141.91 crore in total and Odisha would have got Rs. 33,151.38 crore. The second issue is regarding not giving any portion of the clean energy or coal cess despite being the second largest producer of coal in the country. My State of Odisha is the second largest coal producing State in the country but still, we are not getting anything. We are not getting adequate funds. My third point is the neglect shown towards the plight of the poor in Odisha. Seven lakh houses to be given under PMGAY are still pending and we are expecting the Government to expedite this as early as possible. Even in 2013, the UPA Government's Cabinet

Committee on Economic Affairs allocated only Rs. 1000 crore to Odisha for its poverty-stricken KBK for four years during the Twelfth Plan Period whereas Bihar was allocated Rs. 12,000 crore during the same period. We do not mind if any State is given more funds but Odisha deserves it and we demand that. Now, there is neglect towards the tribals, farmers and artisans of Odisha. There is delay in payments under Fasal Bima to small farmers. The sharing of premium subsidy under PMFBY is in 60:40 proportion. There should be inclusion of paddy crop in 'inundation peril' of localised calamity of PMFBY. There is sharing of administrative expenses of PMFBY in 60:40 ratio and the same scenario is there in sharing of premium subsidy for attack due to wild animals under PMFBY. Not increasing MSP in the true spirit of the recommendations of the Swaminathan Committee is one of the major points that we have been raising time and again.

I want to highlight some of the points, which are failure to remove 18 per cent GST on Kendu leaves; not having any rail infrastructure in six districts of Odisha even after 75 years of Independence; six districts are still uncovered in any kind of Railway network; there has been a long pending demand for passenger train service at Kendrapara.

Sir, the Khurda Road - Bolangir Rail Line project was sanctioned in the Financial Year 1994-95, but still it is not completed. Three projects including Gopalpur-Rairakhol railway link project, Buramara-Chakulia rail link project and Badampahar-Keonjhar rail link project also require Centre's help for expeditious implementation.

The next point is regarding not increasing teledensity and internet density, particularly in rural areas. I will not go deep into that, but I just want to cite that as per the TRAI Report of March 2023, the overall teledensity of Odisha was 75.89 per cent, which was within the bottom five of all the Indian States. I first cited March 2023 Report and now I am citing the report of December, 2023. It is extremely disappointing that despite BJD MPs repeatedly raising this issue with the Government and in both the Houses of Parliament, the teledensity of Odisha as per the TRAI report in December 2023 decreased to 75.87 per cent. There has been a decrease. The rural teledensity in Odisha is still low and it is around 63 per cent. The national average is 84.76 per cent. So you can imagine that when there is not even access to telephone services, talking of 4G or 5G services is beyond dreams. … (*Interruptions*) Sir, I am about to conclude. There are just three or four more points. … (*Interruptions*)

Sir, not building new National Highways and poor maintenance of the existing highways is the other point. I will not go into the details because of the time constraint. Failure to allocate sufficient funds towards the enhancement of sports infrastructure, particularly given the State's efforts to rejuvenate hockey and build state-of-the-art infrastructure for all sports is another point which I want to highlight.

Finally, the most important point is regarding not giving adequate funds for the management of disasters and building disaster resilient power and road infrastructure. Odisha has faced this neglect consistently by the Central Government irrespective of the Parties in power. In 2013, the UPA Government

neglected the people of Odisha during calamities. The State required at least Rs. 2,000 crore immediately to carry on its ongoing restoration and rehabilitation activities in the cyclone and flood hit districts. However, not even a single penny, let it be noted and recorded that not a single penny was released to Odisha even after 24 days of destruction by the Cyclone Phailin and subsequent floods in the State.

Sir, I want to highlight that we have been demanding special category status for Odisha, whether voicing our demand through a rally of thousands of people at Ramlila Maidan in Delhi in June, 2013 led by hon. CM Shri Naveen Patnaik ji or through various Parliamentary interventions by the BJD MPs inside the Parliament in both the Houses. Since 2014 till date, we have only been assured of at least being given a special focus status. We have been demanding for that, but till date, we are not seeing any sunrise. There has been no sunrise to this.

While ending, I would thank the Government for considering three legendary people, and we can say that so wonderfully they have chosen Swaminathan ji, Charan Singh ji and P.V. Narasimha Rao ji for Bharat Ratna. But while closing my speech I would like to say that Biju Babu cannot be confined within a single political Party. Biju Babu is a national hero who is loved and worshipped internationally, a person who had three national flags during his last rituals. Such a person is still waiting, and we Odiya people are still waiting for the correct honour that he and Odisha very much deserve. So, considering Biju Babu for the Bharat Ratna has been pending since so many years. Neither this Party

nor that Party, whichever Party has been in power, has done anything in this regard.

Sir, I would urge, through you, upon the Government to kindly think on considering this. Biju Babu getting a Bharat Ratna would not only make Odisha proud, not only would make India proud, but also would make the entire world feel happy and proud for this.

Jai Jagannath. Vande Utkala Janani.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I stand here to make my very small intervention. I even want to flag my disappointment on this White Paper. You know better than me what is a White Paper. A White Paper is something which provides information on a specific issue in the sense that when the Paper was presented to all of us, it was not exactly a White Paper. It was a comparison of two Government tenures of a decade of each. What is expected really is that a Government may present a White Paper say on any issue to make people aware of the nature and the scope of a problem and possible ways to resolve it. There was nothing but allegations on the previous Government. So, there is no suggestion. Nothing new is coming up.

As you are aware, globally today artificial intelligence is really going to come straight from agriculture to education to industrialisation. It is going to change all our lives. You call it disruption; you call it change. We will all have to adapt to this. So, I actually expected from this Government to come up with a White Paper at the fag end of five years and spend this entire day – not be a prisoner of the past and the history – talking about something on which we can all put our minds together today to create something new for a better India and the future of India. But clearly, from the entire Treasury Benches, there is same rhetoric of some 10 years, allegations and mud-slinging. I think, my friend Shri Jayant Sinha, as he used the word cherry picking against us today, today cherry-picked the data. It is quite disappointing that his entire speech was illusionary. He kept talking about a bullet train. I was really confused because I am not aware of a bullet train in India. So, I do not know which bullet train he was talking about

three times in his speech. But this White Paper is not a White Paper. It is a politically coloured paper.

HON. CHAIRPERSON: The paper was white!

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: The paper was white but the data is probably politically coloured. I would like to go into the details of it. I would be very short. They have not called it a White Paper; it is a comparison paper. The unemployment rate during UPA was 2.2 per cent, while during the present Government it is 6.6. per cent. The average GDP growth rate during the previous Government was 8.13 per cent which is 5.6 per cent now. My friend Jayant Sinha is so much more learned in finance than I am. But with my limited knowledge of finance, regarding the fiscal deficit data if you take the entire tenures together, the fiscal deficit during Dr. Manmohan Singh ji's Government was 4.48 per cent while during Narendra Modi ji's Government it is 5.8 per cent. The disinvestment data is 0.026 during UPA Government while it is 0.1 per cent during NDA Government. The number of bank accounts was 34 crores. So, we have a lot of credit to what we did. Jan Dhan was a product which was started earlier and there were 34 crore bank accounts. Well, eventually they took it to 51 crore accounts which is not a great achievement. Average expenditure during the UPA Government was 14.68 per cent of the GDP while during Narendra Modi ji's Government, it is 12.94 per cent. During this discussion, I expected the Finance Minister to take a larger picture rather than just making it a mud-slinging match and allegations from the Treasury Benches, take into consideration either health care or education or water or anything and the comparison of the total Budget. They always say that

spending has gone up which is not the case. Be it education and health care during the earlier Government, if you comparatively take the cumulative figure, the budget outlay of the whole year, the spending on health care and education is much lesser now than it used to be before.

Another question which I want to ask the Government which they keep flagging about is corruption. I do not want to go into तू-तू, मैं-मैं, आपकी सरकार, हमारी ई.डी., सी.बी.आई. Let us move on. But the point is this. They have started a cashless economy that they wanted to and they have started a digital economy. In the digital sphere, you know what has happened to Paytm. I spoke about it last week also. It is very alarming to us. It is almost like money laundering through Paytm. This is not what I am saying. This is what the Government is saying. But Google Pay, PhonePe are also two sitting time bombs in that case. So, what is the Government doing for the economy? There is a Bhim app now. The Bhim app is hardly used by people. The IT Committee report has already flagged this. When we are talking about a digital economy, when we are talking about a cashless economy, what intervention is the Government doing on this considering that the Government's report itself is flagging it and red flagging it?

So, these are very serious concerns. I hope that in the reply she gives us, she sticks to solutions for all the forecast that she likes to talk about which is youth, women, farmers and the poor. That is what we expect from the Government. We are at the fag end. अभी तू-तू, मैं-मैं का मुद्दा खत्म हो गया है। Let us do something constructive and serve this nation.

Thank you.

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा): सभापति महोदय, आपने मुझे मोशन अंडर रूल 342 के अंतर्गत माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतरमण जी द्वारा लाए गए श्वेत पत्र पर बोलने का समय दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

सभापति महोदय, हमारा परम सौभाग्य है कि 17वीं लोक सभा के अंतिम सेशन में अंतिम दिन की पूर्व संध्या पर हमें बोलने का मौका मिल रहा है। यह भी हमारा परम सौभाग्य है कि हमें पुरानी लोक सभा में एवं इस नए परिसर में पवित्र सेंगोल की उपस्थिति में भी बोलने का अवसर मिला है। मैंने श्वेत पत्र पर पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को ध्यान से सुना है। इसमें बहुत से वरिष्ठ नेताओं ने अपने अनुभव साझा किए हैं। मैं पहली बार यहां पर एक माननीय सांसद के तौर पर आई हूं, तो एक आम नागरिक की भांति, 10 साल पहले सरकार ने जो काम किए थे, इसके साथ-साथ आयकर विभाग में काम करने के लिए दोनों प्रकार के अनुभवों को सदन के सामने रखना चाहती हूं।

सभापति महोदय, एक आम नागरिक के तौर पर मुझे ध्यान है कि उस समय के कोयला मंत्री कोयला घोटाले में संलिप्त थे। उन्होंने उस समय जिस तरह की टिप्पणी महिलाओं के ऊपर कही थी कि शादी जितनी पुरानी हो जाती है, उतनी बेकार हो जाती है। मैं सौगत दादा को इस बात के लिए मुबारकबाद देती हूं कि उन्होंने वर्ष 2012 के अंदर समय रहते ही उससे पीछा छुड़ा लिया। कोयले की दलाली में मुंह, कुछ इस तरह से कहा जाता है, वह इनके साथ भी होता।

सभापति महोदय, पिछली सरकार में जिस तरह के घोटाले हुए हैं, उसमें माननीय प्रधान मंत्री जी ने जब शपथ ली थी, तो उनसे किसी ने पूछा था कि आपकी क्या इच्छा है, तो उन्होंने यह बताया था कि मेरी जो जाति है, मतलब पॉलिटिक्स के अंदर जो लोग हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह की आंच न आए। उनकी इमेज ठीक होनी चाहिए। ऐसे-ऐसे पहले कांड हुए हैं, जिस तरह की उनकी टिप्पणियां रही हैं, मुझे लगता है कि मुवीज बनाने वाले डायरैक्टर्स को अच्छा मसाला मिल जाता है। आपने देखा होगा कि पहले के नेताओं की छवि किस प्रकार की होती थी। खासकर, युवा बिल्कुल ही पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे। आज हाल यह है कि परीक्षा की चर्चा से संबंधित माननीय प्रधान मंत्री जी की बातों को सुनिए। यह विपक्ष को भी सुनना चाहिए, ताकि प्रधान मंत्री जी जो कह रहे हैं, उसे सुन कर

अच्छा विपक्ष बन सके। युवाओं के अंदर माननीय प्रधान मंत्री जी को लेकर बहुत उत्साह है। वे माननीय प्रधान मंत्री जी को अपना रोल मॉडल मानते हैं। आज बहुत सारे युवा राजनीति में आना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि

जो नेता कुछ नरेन्द्र से, देश में चंद हो जाएं
युवा सारे देश के फिर विवेकानंद हो जाएं।

ऐसे हमारी माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं। आप किसानों की बात करें, तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत उनको लगभग दो लाख, अस्सी हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। अगर मैं सिरसा लोक सभा क्षेत्र की बात करूं तो तीस हजार करोड़ रुपए का प्रीमियम देने के बाद उनको करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपए वापस मिले हैं।

मैं 'विकसित संकल्प भारत यात्रा' का जिक्र करना चाहती हूं। 'विकसित संकल्प भारत यात्रा' ने एक सैचुरेशन लेवल लाने के लिए ठिठुरती ठंड में अधिकारियों को गांव-गांव में जाने को मजबूर कर दिया। मैंने खुद बहुत 'विकसित संकल्प भारत यात्रा' में पार्टिसिपेट किया है। मैं हरियाणा के माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने जगह-जगह उस विकसित संकल्प भारत यात्रा में हेल्थ कैम्प भी लगाए। वहां पर हमारे बहुत से बहनों को गैस के कनेक्शंस मिले, हमारे बहुत से भाइयों को वहां पर आयुष्मान कार्ड्स मिले।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, जिस तरह का कार्य हमारी सरकार ने किया है, मैं तिवारी जी की बात सुन रही थी। वे बॉरोइंग के बारे में बता रहे थे। मैं बॉरोइंग के बारे में यह कहना चाहती हूं कि अगर आपकी बैलेंस शीट अच्छी होती है, तभी तो कोई आपको लोन देता है, नहीं तो आप किसी से भी 10 हजार रुपए उधार लेकर दिखाइए। कोई आपको यह नहीं देगा।

सभापति महोदय, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आजकल यात्रा पर जा रहे हैं। पिछले पांच राज्यों के विधान सभा के चुनावों के समय एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान वे कह रहे थे कि राजस्थान की सरकार जा रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार जा रही है। देखिये, कोई समय ऐसा होता है कि जब सरस्वती आपकी जिह्वा पर बैठती है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका भाषण हो गया। धन्यवाद।

सुश्री सुनीता दुग्गल : उनके जो अध्यक्ष हैं, वह यह कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। मुझे लगता है कि … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लास्ट लाइन बोल दीजिए।

सुश्री सुनीता दुग्गल : मैं अंत में एक बात कहना चाहती हूं कि हम सब लोग चुनाव मोड में जा रहे हैं। मैं सभी कार्यकताओं से कहना चाहती हूं कि–

जीतेंगे हम यह वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो,

किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो।

अब की बार 400 पार।… (व्यवधान) सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विजय कुमार हांसदाक (राजमहल): सर, आपने मुझे श्वेत पत्र पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जिस तरह से कम्पेरिजन किए गए, मुझे लगता है कि दस साल के अंदर काले बदल इस देश में जो छाए हुए हैं, यह उसका श्वेत पत्र है। नोटबंदी पर ये लोग कुछ बोलेंगे नहीं। इकोनॉमी को जो सेट-बैक, यह कहिये कि कोरोना तो एक नेचुरल पेंडेंमिक था, लेकिन दो बार नोटबंदी इस सरकार के द्वारा इस देश को दी गई, वह सोची-समझी पेंडेंमिक थी। आपकी फॉरेन पॉलिसी की वजह से लगातार विश्व के तमाम देशों के साथ संबंध खराब हो रहे हैं। चाइना हमारे देश के अंदर लगातार घुसता चला आ रहा है। उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। फेलियर्स पर फेलियर्स हैं, लेकिन एक्सेप्ट करने की इनकी कोई इच्छा नहीं है। ईडी का जो मिस-यूज है, एक श्वेत पत्र उस पर भी होना चाहिए।

हमारे झारखंड में, आदिवासी बाहुल्य राज्य में एक आदिवासी मुख्य मंत्री बने, उसे जबर्दस्ती उतारने का प्रयास किया। आज कई राज्यों में ईडी के भय से ये जिस तरह से सरकार दबोचने का काम कर रहे हैं, उस पर एक बढ़िया श्वेत पत्र आना चाहिए। माननीय हेमंत सोरेन जी झारखंड में झुके नहीं और आदिवासी का जो व्यक्तित्व है, उन्होंने बिना झुके दिखाया।… (व्यवधान) उन्होंने दिखाया कि इनके सामने नहीं

झुकेंगे।... (व्यवधान) मैं कहना चाहूंगा कि ... * एग्जिक्यूटिव, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो मिस-यूज है, ये अपने आपको कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं हो सकता है। ...* एग्जिक्यूटिव, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी का इन लोगों ने जितना मिस-यूज किया है।... (व्यवधान) दस साल बनाम, ये शुरू से बता रहे हैं। दस साल बनाम, ये शुरुआत से कर रहे हैं, जब से देश आज़ाद हुआ था।... * (व्यवधान)

माननीय सभापति : इस शब्द को निकाल दीजिएगा।

... (व्यवधान)

श्री विजय कुमार हांसदाक : उस समय की परिस्थिति क्या थी और किस तरह से उस समय उन लोगों ने देश को आगे बढ़ाया।... (व्यवधान) आज जब इन्हें अच्छी स्थिति में देश मिला है, तो इन्होंने उसे गर्त में ले जाने का काम किया है। इनको स्वीकारना पड़ेगा।... (व्यवधान) दूसरी बात यह है कि वर्ष 2004 से... (व्यवधान)

माननीय सभापति : विजय जी, आप व्हाइट पेपर के ऊपर बोलिये।

श्री विजय कुमार हांसदाक : सर, मैं बोलता हूं और भी आगे बढ़ता हूं। वर्ष 2014 से पहले जिन-जिन बातों को लेकर ये सरकार में आए, चाहे वह 15 लाख रुपये की बात हो, प्रत्येक वर्ष दो करोड़ रोजगार की बात हो या पेट्रोल, डीजल और गैस की बात हो, सभी चीजों में ये लोग फेल हुए हैं।... (व्यवधान) इनको यह स्वीकारना पड़ेगा कि ये सभी चीजों में फेल हुए हैं। उसके बावजूद देश की जो व्यवस्था बनाई गई थी, रिजर्वेशन क्यों दिया गया? रिजर्वेशन इसलिए दिया गया कि हजारों साल से जिन पर अत्याचार हो रहे थे, उस समाज को आगे लाया जा सके, चाहे वह एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो। इन्होंने प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से सबसे ज्यादा उनका हक मारने का काम किया है। हम ईडी के मिस-यूज की जो बात कर रहे हैं, ईडी और जितने संस्थान हैं, उनके मिस-यूज की बात कर रहे हैं, नाम लेंगे तो इनको थोड़ा सा दु:ख हो जाएगा, बहुत ज्यादा दु:ख हो जाएगा। इनके जो व्यवसायी मित्र हैं, उनको ठेका, पट्टा दिलाने के लिए और कंपनीज के फेरबदल, हैंडओवर, टेकओवर करने के लिए उनके

* Expunged as ordered by the Chair.

विरोधियों के ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का प्रयोग किया गया। ये कहां से अपने आपको भ्रष्टाचार मुक्त कह रहे हैं।

मुझे लगता है कि 75 वर्ष के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई भ्रष्टाचारी पार्टी खड़ी हुई है तो यह भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है।... (व्यवधान) ये इसे चाहे जितना भी लपेट लें, शहद में चाहे जितना भी लपेट लें, इनकी सरकार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की वजह से चल रही है, वरना किसी भी पार्टी से लड़ने के लिए इनमें दम नहीं हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इनका कष्ट समझ सकता हूं। वर्ष 2014 के बाद जितने भी घोटालेबाज हैं, चाहे वह दिल्ली सरकार के हो या झारखंड सरकार के, सब जेल जा रहे हैं, बेल भी नहीं हो रही है तो कष्ट तो समझ में आएगा ही।...(व्यवधान) महोदय, यहां पर जो हो रहा है, ऐसा वर्ष 1940 में अमेरिका में भी हुआ था। वहां पर जितने भी आर्थिक अपराधी थे, घोटालेबाज थे, सब पकड़े जा रहे थे। सभी ने मिलकर वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम Organisation of Plunderers, Offenders, Looters, Intimidators, Cheaters, Extortionists रखा। ये सब लोगों ने मिलकर कहा कि हमें ये सरकार बदलनी है। यह हुआ कि हम पर कौन भरोसा करेगा, हम सब तो घोटालेबाज हैं। कहा गया कि उससे क्या हुआ, जब हमारा नाम ही है- Organisation of Plunderers, Offenders, Looters, Intimidators, Cheaters, Extortionists ... * इसलिए हम कहेंगे, ...* चाहती है कि यह सरकार चली जाए, ...* चाहती है कि यह सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। इस प्रकार से, न अमेरिका में वह साज़िश सफल हुई थी और न 'इंडी' गठबंधन नाम रख लेने से भारत में इस तरह की कोई साज़िश सफल होने जा रही है।... (व्यवधान)

मनानीय सभापति महोदय, वर्ष 2004 से 2014 तक का कार्यकाल जरूर याद रखा जाएगा। इन्होंने जितने घोटाले 10 वर्षों में किये, उतने दुनिया में कभी नहीं हुए। वर्ष 2004 से पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो मजबूत नीतियों और मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में भारत को बनाया था, पहली बार फोर लेन रोड्स बने, हर गांव में सड़कें बनीं, सर्व शिक्षा अभियान दिया गया।... (व्यवधान)

इन्होंने एक ऐसी सरकार बनाई, वे तो अटल जी के कारण 5 साल तक राज करते रहे, लेकिन उसके बाद का जो 5 साल रहा, वह पूरे तौर पर घोटालेबाजी का रहा। मुद्रास्फीति दहाई अंक में चली गई। ये उसकी चर्चा ही नहीं करते हैं। ये वर्ष 2008 के बाद आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि इनके कुकर्मों के कारण यूपीए-2 की सरकार बनी थी।

* Expunged as ordered by the Chair.

उस समय के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गठबंधन धर्म की कुछ मजबूरियाँ होती हैं । यही मजबूरी थी कि कोल आवंटन में 1.86 लाख करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने किया, उसमें 14 लोगों पर चार्ज शीट है और वे जेल भी जा चुके हैं । गठबंधन की यही मजबूरी थी कि इन्होंने राष्ट्रमंडल घोटाला कर दिया, 2 जी टेलीकॉम घोटाला कर दिया, आईएनएक्स मीडिया घोटाला कर दिया, एमराल्ड डील घोटाला किया, पिलेटस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट घोटाला कर दिया, हॉक विमान घोटाला कर दिया, आदर्श हाउसिंग घोटाला कर दिया, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला कर दिया । इतने घोटालों से मन नहीं भरा, तो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जब वे रेल मंत्री बने, तो उन्होंने चपरासी घोटाला भी कर दिया । जमीन लेकर चपरासी की नौकरियाँ दी गईं । हमने बंगाल में भी देखा कि वहाँ पर किस तरह से शारदा चिट फंड घोटाला हुआ । जिस 20:80 की स्कीम के बारे में निशिकांत जी बता रहे थे, वह तो बेशर्मी की सीमा है । सरकार बदल गई । सरकार बदलने के बाद भी स्टार ट्रेडिंग हाउसेज के द्वारा सोना का घोटाला कर रहे हैं ।

अभी हमारे विरोधी दल के नेता ने और एक बुढ़ाते हुए युवा नेता भी बार-बार नीरव मोदी की बात करते हैं । लेकिन क्या यह सही बात नहीं है कि नीरव मोदी को बैंक ने लोन देने से इंकार कर दिया था । जब इम्पीरियल होटल में रैम्प वॉक में वे बुढ़ाते हुए युवा नेता गए और उसके अगले दिन फिर बैंक्स ने नीरव मोदी को लोन दे दिया । यह बात सही है या नहीं, यह इनको बताना चाहिए । यूपीए सरकार का एक ही काम था, खूब उधार लो और उसके बाद वे पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर मत खर्च करो, बल्कि उसे अपने लोगों को, चहेतों में बाँट दो । सरकार उद्योगपतियों को पिक्निक मनाने के लिए पैसे देती थी । जैसा चार्वाक ऋषि का कहना था कि उधार को घी समझकर भूल जाओ । इनके जितने गुर्गे थे, उन सबको यही बोला जाता था कि उधार लो, एंजॉय करो और हमें भी एंजॉय कराओ । उधार लेकर भूल जाओ ।

महोदय, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ । हमारे यहाँ गोला-बारूद नहीं था, नाइट विज़न गोगल्स सामान ये लोग उपलब्ध नहीं करा पाते थे । जब हमारी सरकार आई, तो हमने 26 हजार करोड़ रुपए के हथियार एक्सपोर्ट किए । हमने 1 लाख करोड़ रुपए के हथियार यहाँ बनाए । पहले अगर दुश्मन देश

से गोलियाँ चलती थीं, तो केन्द्र सरकार कहती थी कि धैर्य से काम लो। गोली का जवाब नहीं दो। लेकिन आज मोदी जी की सरकार कहती है कि अगर पहले एक गोली चले, तो तुम एक सौ गोलियाँ चलाओ, उसके बाद आकर हम से बात करो कि मामला क्या है। दोनों सरकारों में यह अंतर है।

माननीय सभापति जी, हम लोगों ने वर्ष 1992 का भी कार्यकाल देखा है, जब श्री जोशी जी और श्री मोदी जी को लाल चौक पर झण्डा फहराना था, तो हजारों भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी थी। दोनों व्यक्तियों ने सेना के साथ जाकर लाल चौक पर झण्डा फहराया था। आज देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में कोई पप्पू निकलता है और लाल चौक पर झण्डा फहराकर चला आता है। अनुच्छेद 370 के खत्म होने से इस सरकार में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है।

HON. CHAIRPERSON: Now, I will take the name of next speaker - Shrimati Navneet Ravi Rana.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप समाप्त कर दीजिए।

डॉ. संजय जायसवाल : महोदय, इन्होंने ब्लैक पेपर निकाला है, लेकिन हमारी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में हमारे मंत्रियों के खिलाफ उसमें एक भी शब्द नहीं है। यह बताता है कि हमारा कार्यकाल कैसा रहा है। इन्हीं के ब्लैक पेपर में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ये देश से माफी माँगे और शपथ लें कि आगे से कभी कोई घोटाला नहीं करेंगे।… (व्यवधान) धन्यवाद।

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): महोदय, यह मेरे पहले लोक सभा कार्यकाल का 5वां वर्ष और शायद आखिरी दिन है।... (व्यवधान) आज यहाँ हम यह चर्चा कर रहे हैं कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया?... (व्यवधान)

महोदय, मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी कि हम तो इस देश के युवा हैं।... (व्यवधान) हम तो सिर्फ कैलकुलेशन पर और किसने कितना अच्छा बेहतर काम किया है, उसके ऊपर ही ध्यान देकर आगे काम करते हैं।... (व्यवधान) महोदय, मैं तो इतना ही बोल सकती हूँ, क्योंकि जो आंकड़े हम देख रहे हैं, कांग्रेस की सरकार के 50 वर्षों के कार्यकाल में 75 एयरपोर्ट्स बने और पिछले 10 वर्षों में 74 एयरपोर्ट्स बने हैं। रोड एंड हाइवेज में 50 वर्षों में 98 हजार किलोमीटर और मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में 50 हजार किलोमीटर के हाइवेज बने हैं। कांग्रेस की सरकार में मॉडल रेलवे स्टेशन का नाम इस देश के युवाओं, लोगों ने कभी सुना ही नहीं। 400 वंदे भारत ट्रेन्स चल रही हैं, अमृत भारत स्टेशन और मॉर्डन रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं।

महोदय, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। इधर से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। जब इनकी सरकार थी तो बैंकों में जाने के लिए, बड़े-बड़े सभी जैसा हमारी वित्त मंत्री मैडम ने कहा कि फोन पर ही लोन हो जाते थे, फोन पर भी सभी को सब चीजें अवलेबल हो जाती थीं। Nowadays, such people are scared to go to banks because if they do corruption there, this Government is not going to leave them. यह मोदी जी की सरकार है और कोई भी इस देश का एक रुपया भी कहीं लेकर नहीं जा सकता है। इस तरीके की कार्रवाई इस देश की सरकार, हमारे मोदी जी कर रहे हैं। पिछले 100 वर्षों से ब्रिटिशकालीन पार्लियामेंट में बैठते थे। हमारा सौभाग्य है कि हम इस नयी पार्लियामेंट में भी मोदी जी की सरकार के टाइम पर बैठे हैं। ये आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासियों के बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनको पढ़ाने के लिए वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक इन्होंने 90 एकलव्य स्कूल बनाए थे, लेकिन मोदी जी की सरकार ने आदिवासियों के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए 600 एकलव्य स्कूल बनाए हैं। यह मोदी सरकार की उपलब्धि है। ये व्हाइट और ब्लैक पेपर बोलते हैं। आज मैंने सभी कांग्रेसियों के हाथ में

काले पेपर पर लिखा हुआ देखा है। जिन्होंने आज इस व्हाइट पेपर की घोषणा की है और इसे लायी हैं, उनके हाथों में सिर्फ व्हाइट पेपर है।

Sir, please give me just two or three minutes. ये मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। जब इतनी बड़ी महामारी हमारे देश में आयी तो 50-60 वर्षों में इनकी क्या तैयारी थी? आने वाले समय में अगर ऐसी कोई महामारी आती है तो उसके लिए इनके कार्यकाल में 380 मेडिकल कॉलेज बने थे, जहाँ पिछले 10 वर्षों में 262 मेडिकल कॉलेज बने हैं। इनके कुल कार्यकाल में 50 एम्स बने थे, हमारी इस सरकार ने, हमारी मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 17 एम्स बनाए हैं। यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। पिछले कई वर्षों से हमारे महाराष्ट्र में, हमारे सभी लोग इंदु मिल की जगह चाहते थे कि वहाँ बाबासाहेब आंबेडकर के नाम से बहुत बड़ा स्मारक बने, लेकिन ये उसमें भी कामयाब नहीं हो सके। वह काम भी हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है, यह उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।

सर, आज 5 लाख रुपये की बीमा कराकर हर गरीब की हेल्थ व्यवस्था करने का काम भी हमारी यह सरकार कर रही है। आईआईटीज, 50 साल में सिर्फ 16, पिछले 10 वर्षों में 7 बनाए गए हैं। पीएम आवास योजना के माध्यम से वर्ष 2014 से आज तक 4 करोड़ लोगों को आवास दिए गए हैं, जिनके पास घर नहीं था, जो आज भी मिट्टी के घरों में रहते थे। हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। वहाँ किसान, मजदूर आदि लोग रहते हैं। जब हम देखते थे कि उनके पास घर नहीं है तो उनकी पीड़ा हमें ही मालूम है, क्योंकि जमीनी स्तर पर जाकर हमने देखा है। महलों में रहने वाला राजा क्या जाने कि मिट्टी के घर में रहना किसे बोलते हैं। इसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जानते हैं और उन्होंने पिछले 10 वर्षों में उनके लिए काम किया है। It is very easy to say that we should move on. I heard one of my colleagues when she was simply saying: “We should not fight. We should move on.” No, Sir, we cannot just move on, क्योंकि इस देश के जो युवा हैं, वे इस देश का विकास चाहते हैं, वे इस देश में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, वे इस देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, वे इस देश की बेरोजगारी हटाना चाहते हैं। इस देश के युवा ऐसा

चाहते हैं। मुझे केवल दो मिनट दीजिए। आज कांग्रेस एससी समाज की बात कर रही है, हम एससी समाज से संबंध रखते हैं। एससी को राष्ट्रपति के पद पर बिठाने वाली यह मोदी सरकार है। एसटी, आदिवासी समाज से संबंध रखने वाली हमारी मुर्मू मैडम को भी उस पद पर बिठाने वाली यही सरकार है। महोदय, मैं अंत में एक मिनट में महाराष्ट्र के बारे में बोलना चाहूँगी।

महोदय, महाराष्ट्र के बारे में सिर्फ एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी। हनुमान चालीसा पर ...* हनुमान चालीसा का पठन किया तो उन्होंने जेल में डाला। उन्होंने कई एलिगेशन्स हमारे आदरणीय ...* पर लगाए कि वे बाबरी पर चढ़े, इसलिए बाबरी टूटी। मुझे उनसे इतना पूछना है कि जब कार सेवक वहां अपनी जान त्याग रहे थे और धर्म के प्रति अपना योगदान दे रहे थे, तब ...* कौन-सी बिल में बैठे थे।

HON. CHAIRPERSON: The person who is not a Member of this House, his name should not go on record. मैं कह रहा हूं कि नाम नहीं जाएगा।

... (*Interruptions*)

श्रीमती नवनित रवि राणा : महोदय, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि जिस दिन राम मंदिर बना। मुझे लगता है कि जितने भी कारसेवकों ने अपनी जान गंवाई, जितने भी कार्यसेवक वहां थे, उसमें एक कारसेवक हमारे राज्य के ...* भी उस समय वहां थे। उनका भी योगदान है और जितने भी कारसेवक हैं, उनको मैं दिल से प्रणाम करना चाहूंगी क्योंकि इस देश के युवाओं की आंखों में और जितने भी लोग उस दिन अयोध्या में थे, उनकी आंखों में आंसू थे। मैं सभी को इतना ही कहूंगी कि श्री राम मंदिर और काशी सिर्फ झांकी थी, ज्ञानवापी और मथुरा अभी बाकी है।

* Not recorded.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सभापति जी, आज इस अमृतकाल के अंदर देश के पांच सौ साल के कुशासन और पांच सौ साल की लूट के बाद यह सौभाग्य 140 करोड़ लोगों को प्राप्त हुआ कि इस अमृतकाल में राम राज्य की स्थापना हुई, जिसमें धर्म, स्वाभिमान, समृद्धि और सुरक्षा, तीनों की गारंटी देने का काम हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि भारत के 500 साल के वनवास के बाद देश को अमृतकाल में मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ लोगों को सौभाग्य मिला। वर्ष 1526 से लेकर वर्ष 1759 तक मुगलों ने देश को लूटा। वर्ष 1757 से 1947 तक अंग्रेजों ने लूटा। वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 2013 तक कांग्रेस ने देश को लूटा। यह जो देश लुटता चला गया। सत्ता संग्राम के अंदर स्वराज पाने के लिए, जहां देशवासियों ने आहूति दी, परंतु जो स्वराज करोड़ों लोगों को मिलना था, वह एक खानदान को ही मिलकर रह गया। यह देश का दुर्भाग्य रहा। कांग्रेस ने 60 वर्षों तक सिर्फ भ्रष्टाचार किया। नेहरू जी से लेकर सोनिया जी तक अगर मैं गिनवाऊं तो वर्ष 1948 में जीप घोटाला, वर्ष 1974 मारूति स्कैम घोटाला, वर्ष 1976 में तेल घोटाला, वर्ष 1986 में बोफोर्स घोटाला, वर्ष 1992 में हर्षद मेहता घोटाला, वर्ष 1994 में शुगर इम्पोर्ट घोटाला, वर्ष 2005 ऑयल एंड फूड घोटाला, वर्ष 2008 में 2जी घोटाला, वर्ष 2009 में सत्यम घोटाला, कैश फोर वोट घोटाला, वर्ष 2010 में कॉमनवैल्थ गेम्स घोटाला, देवास एंटरिक्स स्कैम घोटाला, अगुस्टा वेस्टलेंड घोटाला, वर्ष 2012 में कोल घोटाला, वर्ष 2013 शारदा चिट फंड घोटाला, वर्ष 2014 में ईनेक्स मीडिया घोटाला, रेलवे में भर्ती घोटाला, हेलिकॉप्टर घोटाला। 60 वर्षों में 60 लाख करोड़ की लूट जो इस देश में हुई है। इसलिए श्वेत पत्र लाना पड़ा। मनीश जी कह रहे थे कि यह वर्ष 2014 में आना चाहिए। यह तो डिफरेंस दिखाना था कि तुमने दस साल में क्या कुकर्म किए और पिछले दस वर्ष में देश को क्या मिला। इसलिए श्वेत पत्र लाया गया है ताकि दोनों का अंतर बताया जा सके।

यह जो घमंडिया गठबंधन के लोग बैठे हैं। टीएमसी- शिक्षक भर्ती घोटाला, चिट फंड घोटाला, रोज़ वेली घोटाला, शारदा घोटाला, कोयला घोटाला। आरजेडी – चारा घोटाला, रेल भर्ती में जमीन घोटाला, बाढ़ राहत में घोटाला। एसपी – लेपटॉप घोटाला, भर्ती घोटाला। एनसीपी – कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला। बोने दुर्योधन की दिल्ली पर आ जाता हूं।

लिकर स्कैम घोटाला, दो-दो मंत्री और एक एमपी जेल में है। दिल्ली वक्फ घोटाला। दिल्ली में 52 करोड़ रुपये का शीश महल घोटाला। डीटीसी बस का घोटाला। जल बोर्ड का घोटाला। स्कूलों में कमरे बनाने का घोटाला। सुशासन के साथ-साथ समृद्ध भारत बनना चाहिए, यह नींव वर्ष 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में रखी गई और भारत समृद्धता की तरफ बढ़ रहा है। चार करोड़ गरीब लोगों को मकान देना हमारी सरकार का ही काम है। मुझसे पहले संजय जी कह रहे थे। एक बुड्ढा नौजवान युवराज, 50 साल की उम्र में युवराज नौजवान। वे कह रहे थे ओबीसी की बात। वे ओबीसी के अर्थ को ही नहीं समझते। अदर बैकवर्ड क्लास का मतलब है कि वह किसी विशेष जाति से नहीं है, जिसकी माँ घरों में जाकर काम करती है तो उससे ज्यादा बैकवर्ड क्या होगा, यहीं से आपको अंदाजा लगाना चाहिए। जिन्होंने गरीबों के लिए 13 करोड़ शौचालय बनाए। पेंशन के रूप में 61 करोड़ लोगों को फायदा दिया। डीबीटी का फायदा लोगों को दिया। जन औषधि केंद्रों की संख्या कई गुना बढ़ गई। मैटरनिटी बेनिफिट 53 डिस्ट्रिक्ट्स में दिया जाता था, आज पूरे देश में 3.6 करोड़ लोगों को दिया जाता। मेट्रो की संख्या में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। हर घर जल की सुविधा दी गई। स्टार्ट-अप पहले 300 लोगों के पास था, अब 1 करोड़ 70 लोगों के पास है।

सर, मैं मनीश जी की बात पर कहना चाहता हूं। वे किसानों के बहुत हितैषी बन रहे थे। वे किसानों की बात कर रहे थे, गलत डेटा पेश कर रहे थे। वे बता रहे थे कि वर्ष 2014 में क्या भाव था। आप वर्ष 2014 के भाव को नहीं बताते, पर वर्ष 2004 में क्या रेट्स थे, उन्हें इसे बताना चाहिए था।

सर, वर्ष 2004 में देशी घी 140 रुपये प्रति किलोग्राम था, आपने बढ़ाकर उसे 400 रुपये प्रति किलोग्राम किया। यह कितना प्रतिशत बढ़ा? आज यह केवल 500 रुपये प्रति किलोग्राम है। वर्ष 2004 में चावल 25 रुपये प्रति किलोग्राम था, आपने बढ़ाकर उसे 100 रुपये प्रति किलोग्राम किया। आज यह केवल 110 रुपये प्रति किलोग्राम है।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude, I am calling the next speaker.

श्री रमेश बिधूड़ी : वर्ष 2004 में गेहूं का आटा 10 रुपये प्रति किलोग्राम था, आपने भ्रष्टाचार में बढ़ाकर उसे 30 रुपये प्रति किलोग्राम किया। आज यह केवल 38 रुपये प्रति किलोग्राम है। वर्ष 2004 में सोना

6300 रुपये प्रति दस ग्राम था, वर्ष 2009 में आपने बढ़ाकर उसे 27,400 रुपये प्रति दस ग्राम किया। वर्ष 2004 में दाल 8 रुपये प्रति किलोग्राम था, आपने बढ़ाकर उसे 87 रुपये प्रति किलोग्राम किया। वर्ष 2004 में प्याज 10 रुपये प्रति किलोग्राम था, आपने उसे 30 रुपये प्रति किलोग्राम में बेची। वर्ष 2004 में दूध 17 रुपये प्रति किलोग्राम था, आपने उसे 48 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचा। आज यह केवल 60 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है। इसका एवरेज लगाइए।... (व्यवधान) सर, इसी प्रकार से पेट्रोल के दाम हैं। वर्ष 2004 में पेट्रोल के दाम 33 रुपये थे, ये बढ़ाकर उसे 78 रुपये तक ले गए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए। I have already called the next speaker.

श्री रमेश बिधूड़ी : सर, ये 15-15 लाख रुपये की बात करते हैं। मैं बताता हूं कि गरीबों को 15 लाख रुपये कैसे मिले। मोदी साहब ने नहीं कहा था कि आपके खाते में डालेंगे। जब जन-धन खाते खुले थे तो यह कहा गया था कि यह नौटंकी की जा रही है। जन-धन खाते खुलने के बाद आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हर गरीब को 5 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। गरीब को घर बनाने के लिए ढाई लाख रुपये दिए जा रहे हैं। इस तरह साढ़े सात लाख रुपये हो गए। पी.एम. जीवन ज्योति योजना के अन्तर्गत हर गरीब को मात्र दस रुपये की योजना में दो लाख रुपये मिलते हैं।... (व्यवधान)

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मैं हाउस के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं, that this House will continue till the discussion is over. I believe that the House will agree with my proposal.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, by seizing the opportunity of delving into this discussion under Rule 342, I would like to highlight some of the important issues because most of the issues have already been covered here over the long discussion.

Sir, I feel very sad and depressed while observing the attitude of this ruling dispensation. The intent and purpose of bringing this kind of a White Paper is simply not convincing. It is nothing but a sheer concoction. Rather it can be said to be a granary of concoctions and a mountain of lies presented before us. What is the need of it, I do not understand?

If the Government or the ruling dispensation is enthusiastic enough to exercise the vilification campaign and indulge in use of competitive abusive language against the Opposition parties, that is upto them, that is upto the virtue of the ruling dispensation. I cannot offer homilies upon them because they are all well-experienced, well-educated and well-erudite persons.

At the fag end of this Session, this kind of a White Paper brought only with an objective to tarnish the 10-years of UPA Government does not cut much ice.

18.00 hrs

It is nothing but an election manifesto with the objective of securing electoral brownie points. This is what has prompted this Government to bring this kind of White Paper.

18.0½ hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

Sir, Rome was not built in a day. We must keep this in mind. आप या हम जो भी यहां हैं, हम कभी माँ के गर्भ में थे, अपनी-अपनी माँ ने पाला-पोसा, बड़ा किया और यहां तक हम

पहुंचे हैं। यहां तक पहुंचने के बाद अगर हम लोग सारे अतीत को अस्वीकार करें, नकार दें तो लोग क्या कहेंगे। अतीत को भूलना नहीं चाहिए। ... (व्यवधान) आपने जरूर कुछ कमाया होगा, लेकिन आपने जो कुछ कमाया, उस पर घमंड न करें क्योंकि शतरंज की पारी खत्म होने के बाद राजा और मोहरे, दोनों को डब्बे में रख दिया जाता है। इसलिए हम लोग घमंड नहीं करते हैं, आप लोग घमंडिया बन चुके हैं।

हर बात में फैमिली, परिवार, नेहरू इन सब को गाली देने में क्या फायदा है? वे लोग अभी इस दुनिया में नहीं हैं। एक परिवार को दिन-रात गाली दी जाती है। लोक सभा में, राज्य सभा में, हर जगह गाली दी जाती है। इसमें हमारा मकसद क्या है? Simply, we need to have an introspection into all this. आप मेरी बात का बुरा न मानें। हम कौन सी परंपरा को अपनाते हैं? कौन से शिष्टाचार को अपनाते हैं। यह मैं सोच रहा हूँ। यह मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी ने शहीद होने के दो दिन पहले एलान किया था कि 'Even if I die in the service of the nation, I would be proud of it because I am sure that every drop of my blood will contribute to the growth of the nation and to make it strong and dynamic.' इसमें क्या गलत है? उन्होंने मौत होने के दो दिन पहले यह कहा था। उन्होंने बंग्लादेश बनाया और छाती पर गोली खाई, शहीद हुईं। उन्होंने कौन सा पैसा कमाया? वे कितने करोड़ रुपये की मालिक थीं? उन्होंने कितना पैसा कमाया, आप लोग बताइए, आप लोग दस साल से सरकार में हैं, अटल बिहारी जी की सरकार छह साल थी। क्या आप लोग कभी बता सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने इतना पैसा कमाया? राजीव गांधी चुनावी प्रचार में गए and he was virtually blown to pieces. उनको आतंकवाद ने मारा। उनको आप लोग गाली दे रहे हैं। अगर हम इस तरीके से शिष्टाचार का पालन करेंगे तो भविष्य में हमारे बच्चे हमें क्या कहेंगे? यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ।

आप लोग नेहरू जी को गाली देते हैं न, मैं नेहरू जी की एक बात आपको बताता हूँ, यह बात 21 जून, 1954 की है, about ten years before he passed away, Nehru penned his last will and testament. नेहरू जी की अंतिम विल और चाहत क्या थी आप जानते हैं? मैं आपको

बताता हूँ। उन्होंने यह कहा था कि 'A handful of my ashes be thrown into the Ganga at Allahabad …..' मौत होने के बाद इलाहाबाद में जा कर एक मुट्ठी अस्थि को विसर्जित कर देना। '….to be carried to the great ocean ...' समुद्र में चली जाएगी। '….that washes India's shores' सारे देश की हमारे जो तट है, उन तटों पर जो काम करते हैं, उनसे हम मिल जाएंगे, सिमट जाएंगे, मिट जाएंगे। The major portion of my ashes be carried high up into the air and scattered from that height over the fields where the peasants of India toil so that they mingle with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India. मेरे अस्थि को आसमान से छोड़ देना, वह जमीन पर गिरेगी, जहां हमारे किसान मेहनत करके हमें खिलाते हैं, उस जमीन से हम मिल जाना चाहते हैं। हमारी कोई अलग पहचान नहीं रहेगी। उनकी इस भावना को अगर आज हम गाली दें तो क्या यह शोभा देगा? आप हमें बताइए।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप श्वेत पत्र पर अपना विषय रख दें।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, अगर आप हमें ब्लैक पेपर ऑन रिकॉर्ड रखने का मौका दें तो मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, मुझे दो-चार मिनट बोलने दीजिए। इसीलिए, मैं कहता हूं कि आज हम एकदम यहाँ पहुंचे हैं, ऐसा नहीं है। हमें आजादी की जंग लड़नी पड़ी। लाखों की तादाद में लोगों को जेल जाना पड़ा। उन्हें शहादत देनी पड़ी। जब हमें आजादी मिली, तभी हम यहां पहुंचे हैं। आजादी के पहले हमें वोट देने का अधिकार नहीं था। अगर हमें वोट देने का अधिकार नहीं मिलता तो आपके नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, हम यहां नुमाइंदे बनकर नहीं आ पाते। उनकी भी सराहना करना चाहिए था। ऐसा है कि नहीं, आप बताइए। हमें गद्दार नहीं होना चाहिए। किसी ने हमारे लिए कुछ किया, अगर हम उनको नहीं मानते हैं, तो अलग बात है, लेकिन उनसे गद्दारी नहीं करनी चाहिए। आप सुन लीजिए।

यह सही है कि आजादी की जंग में आपका कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो शहीद हुआ, जिनको हम नेशनल आइकॉन मानते हैं। आप लोग politics of appropriation, politics of co-optation, politics of narcissism करते हैं और यही आपका तरीका है। वर्ष 1947-48 में हमारे देश की पर-कैपिटा इनकम क्या थी, क्या आप जानते हैं? यह 247 रुपये थी। इसे आप मान कर चलिए। धीर-धीरे जब हम वर्ष 2011-12 में पहुंचे, तब हमारी पर-कैपिटा इनकम बढ़ कर 64,361 रुपये आ गयी। पॉवर्टी की क्या स्थिति थी? Poverty decreased from 65 per cent in 1956. वर्ष 1956 में 65 फीसदी लोगों को खाना नहीं मिलता था। वर्ष 2011-12 तक गिरते-गिरते 21.9 परसेंट पर आ गये। हमारी जो life expectancy थी, जब हमें आजादी मिली थी, तब हमारी आयु 32 साल थी। वर्ष 2011 में हमारी आयु बढ़ते-बढ़ते 67 साल तक आ गयी।

वर्ष 1951 में हमारे देश में लिटरेसी रेट 12 परसेंट था। वर्ष 2011 में यह 73 परसेंट पर आ गया। अगर हम यह कहें कि वर्ष 2011 में यह 73 परसेंट है तो आपका फर्ज है कि आप इसे और आगे बढ़ाइए। आगे जो सरकार आएगी, उसका भी फर्ज होगा कि इसे और आगे बढ़ाए। कभी हम रेडियो देखते थे, अब हम इंटरनेट देखते हैं। अभी हम इंटरनेट देख रहे हैं, फिर ए.आई के साथ चलेंगे। अभी रोबोट चल रहे हैं। आज हम समय को दिन, रात और घंटे में विभाजन करते हैं। ऐसा समय आ सकता है कि यह विभाजन डिजिटली होगा। यह दिन, रात और घंटा भी नहीं रहेगा। बदलाव तो दुनिया का नियम होता है। इसके लिए हमें अपने predecessor को गाली नहीं देना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कल या 10 साल बाद आप सत्ता में नहीं रहें, उस समय अगर हमारी तरफ से या जो दूसरी पार्टी सत्ता में आए, उसकी तरफ से एनडीए सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी सरकार के खिलाफ गाली-गलौज किया जाए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। देखिए, हम लोग कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ कुछ गलत नहीं बोलते हैं। मान लीजिए कि आपके पिताजी ने जो काम किए हैं, बड़ा बेटा होने के नाते आपको और ज्यादा काम करना पड़ेगा।

आपका बेटा और आगे जाएगा। यह तो नियम है। नियमों की परम्परा हमें माननी पड़ेगी। …(व्यवधान)

SHRI RAJENDRA AGRAWAL (MEERUT): Sir, let him speak on the policies. … (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : The UPA Government established the Right to Education Act in 2009 ensuring education as a fundamental right for every child. Famine is now eradicated with India achieving self-sufficiency in food grain production and becoming a significant agricultural exporter. The National Food Security Act implemented by the UPA Government ensures right to food for every individual.

अगर सही बात बताऊं तो मुझे मजबूरन यह कहना पड़ेगा कि यह सरकार वादाखिलाफी सरकार है। इसलिए वादाखिलाफी है, अच्छे दिन लाएंगे, वादा किया था, 15 लाख रुपये जेब में भर देंगे, वादा किया था, याद करिए। दो करोड़ नौकरी देंगे, वादा किया था, किसानों की डबल इंकम करा देंगे, वादा किया था, सी टू प्लस फिफ्टी पर्सेंट, वादा किया था न। डीमोनेटाइजेशन और काला धन नहीं रहेगा, वादा किया था। आज तक क्या एक भी सत्य हुआ है? आप बताइए। फाइनेंस मिनिस्टर जी यहां हैं। मैडम निर्मला सीतारमण जी से पूछ लीजिए। आपने डीमोनेटाइजेशन कर दिया। उस समय नगदी का प्रचलन 16 लाख करोड़ रुपये था। अभी नगदी का प्रचलन बढ़ते-बढ़ते 34 लाख करोड़ आ पहुंचा है। क्या बताऊं, क्या कहेंगे आप? यह आपका फेल्योर है, सरासर फेल्योर है। डीमोनेटाइजेशन के चलते 15 लाख लेबर्स की चार महीने के अंदर नौकरी चली गई। जीएसटी हाफ हर्टेड है। 800-900 बार हो चुका है, आप कानून बदलते रहते हैं। यह हाफ हर्टेड थी।

India's infrastructure has grown remarkably since Independence including extensive rail and road networks, connecting numerous villages and towns with electricity and all-weather roads. India leads in mobile subscription globally thanks to the telecom revolution initiated by Prime Minister Rajiv Gandhi. यह सही है या गलत, बताइए।… (व्यवधान) देश में पंचायती राज कौन लाया था?… (व्यवधान) The Congress

believed that inclusive governance is crucial for inclusive growth. Mahatma Gandhi envisioned panchayat raj as the cornerstone of our democracy. In 1959, Prime Minister Jawaharlal Nehru launched nation-wide Panchayat Raj in Nagaur, Rajasthan on Gandhi Jayanti. Prime Minister late Rajiv Gandhi emphasised the need for constitutional recognition and empowerment of Panchayat Raj. It was implemented by another stalwart of our political fraternity, late Narsimha Rao. … (*Interruptions*)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): व्हाइट पेपर पर बात करिए। वर्ष 2004 से 2014 में जो आपने किया, उस पर बोलिए। … (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Through the 73rd and 74th Constitutional Amendments we now have nearly 32 lakh grassroot elected representatives including around 14 lakh women making India the world's most representative democracy.

आईआईटी, आईआईएम किसकी सोच थी, बताइए। एजुकेशन में अगर हम लोग तरक्की न करते, तो क्या आज डिजिटल इंडिया का सपना देख सकते थे? … (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : आईआईटी अंग्रेजों की सोच थी, इनको पता नहीं है।… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : हिंदुस्तान में लैंड रिफॉर्म किसने किया? हरित क्रांति कौन लाया? आप बताइए।… (व्यवधान) आज जो हम फूड में सेल्फ सफीशिएंट हैं, यह हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लाया? कांग्रेस के जमाने में और स्वामीनाथन के योगदान ने हरित क्रांति को सफल किया। क्या यह कोई अस्वीकार कर सकता है?

माननीय अध्यक्ष : कंक्लूड करिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, क्या कंक्लूड करें? मैडम सीतारमण जी तो इतना सारा भाषण दे चुकी हैं। मैं सिर्फ सीतारमण जी से कहना चाहता हूं कि आपने बहुत सारे स्कैमस की बात कही है। मैं इसमें दो-चार मुद्दे उठाऊंगा।

निर्मला सीतारमण जी आप कोल स्कैम की बात करते थे, ये कोल इम्पोर्ट स्कैम की बात करते थे न? एक तरफ आप कहते हैं कि कोल मिनिस्ट्री में इतना सारा काम होता है कि इतना प्रोडक्शन बढ़ चुका है, दूसरी तरफ कोल इम्पोर्ट करना पड़ता है। किसके लिए कोल इम्पोर्ट करना पड़ता है, इसमें एक घोटाला है, इसको कोल इम्पोर्ट स्कैम कहते हैं। Coal import scandal is traced back to December 2021. Despite global environmental notoriety of Carmicheal Coal Mine in Australia, the project secured significant loans including from the State Bank of India. The Modi Government instructed public sector entities like NTPC to procure coal purportedly contributing to the power shortage of April, 2022.

माननीय अध्यक्ष : यह विषय आ गया है।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, मैं एक और घोटाले की बात करता हूं, सीतारमण जी उसका जवाब देंगी। विजय माल्या लोन डिफॉल्ट, दस हजार करोड़ रुपये लूट कर 2016 में भाग गया। Despite assurances from the Finance Minister to bring him back, no action has been taken by SBI, PNB and IDBI to which Kingfisher Airlines owed more than Rs. 10,000 crore.

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, 2012 में विजय माल्या को इन्होंने लोन दिया था।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य कन्कलूड कीजिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, बिल्कुल खत्म करने की कगार पर हूं। विजय माल्या के बाद नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और पीएनबी स्कैम। इसके बाद जतिन मेहता और विनसम डॉयमंड्स स्कैम, कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड और स्टारलिंग बॉयोटेक लिमिटेड स्कैम, उसके बाद रोटोमैक स्कैम, उसके बाद, आईसीआईसीआई-विडियोकॉन फ्रॉड स्कैम, इतने सारे स्कैम लेकर आप किस पर

दोषारोपण करते हैं। इसके पहले स्कैम की बात सुनो, यूटी यूएस-64 स्कीम घोटाला, खिलौनी कोल स्कैम, स्टॉक मार्केट स्कैंडल, डिसइन्वेस्टमेंट स्कैम, इंडियाज बराक मिसाइल स्कैंडल, तहलका स्टिंग ऑपरेशन स्कैंडल, भूल गए क्या? उस समय मैं भी सदन में था, कॉफिनगेट स्कैम, भूल गए क्या? हम जो भी करें समाज में सोशल स्टैबिलिटी बरकरार रहना चाहिए। आप समाज में विभाजन करते हुए कुछ नहीं कर सकते, 20 करोड़ मुसलमानों को धकेलते हुए और समाज से निकालते हुए देश की तरीक्की नहीं कर सकते। मैं इसलिए कहता हूं, Social stability, social cohesion, and social peace are the fundamental conditions for the growth of an economy. मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूता हूं।

मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है
कोई कहता है कि राधा की चुनरी बेगम सलमा सीती है।
मैंने सुना है रफी साहब महफिल में रघुपति राघवा गाता था।
मैंने सुना है पंडित प्रेमचंद ईदगाह बच्चों को सुनाता था।

इस देश को आप कहां ले जा रहे हैं।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, considering the White Paper and my Substitute Motion which I have already moved in the morning, my Substitute Motion is to disapprove the contents of the White Paper on the following four grounds.

Number one, this is a political attempt to ignore the valuable efforts of the previous UPA Government and the contributions of the renowned economists, scientists and experts of the country during the period between 2004 and 2014. After 10 years of NDA Government in office, making baseless allegations against the previous Government is unfair, improper, unjust and against all basic tenets of Parliamentary democracy.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): You yourself are a Leftist. If you are so proud of UPA Government, why did you withdraw the support in 2008? Can you please enlighten us on this? Why did you withdraw the support?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Definitely. My Party and the Left Parties had withdrawn the support from the first UPA Government on the nuclear issue. … (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: Then you did not support it. … (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Yes, we did not support it. … (*Interruptions*) I do agree. That happened on the basis of a political issue. We had withdrawn the support from the UPA-I for that reason and not because of any other reason. Now, we have become the part and parcel of the Indian National Developmental Inclusive Alliance. All the Left parties are partners. … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): What is happening in Kerala? … (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: What is happening in Kerala? … (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I will elucidate the question put by hon. Parliamentary Affairs Minister. You have to see the difference. During the period between 2004 and 2009, all the Left Parties were supporting the Government from outside. They were not part of UPA. Now, all the Left Parties have become part and parcel of the Indian National Developmental Inclusive Alliance led by the Indian National Congress. … (*Interruptions*) So, that difference is there. … (*Interruptions*)

SHRI V. MURALEEDHARAN: What is happening in Kerala? … (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: In Kerala, there was a *lathicharge* on the Congress workers by the Left-led Government? What is happening there? Where is the INDI Alliance? … (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: I can understand that you are afraid of the Alliance. … (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Pralhad Joshi ji, the basic purpose and the basic intention of the formulation of INDI Alliance is to keep BJP out of power in the 2024 Parliament elections. … (*Interruptions*) So, whatever be the outcome in Kerala, you will see, INDI Alliance will get 20 out of 20 seats in Kerala. … (*Interruptions*) There is no doubt about it. … (*Interruptions*)

The third point which I would like to highlight is, after ten years of NDA Government in office … (*Interruptions*)

SHRI V. MURALEEDHARAN: Both of you fight together. … (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: It is not required. … (*Interruptions*) Muraleedharan ji, I will tell you frankly … (*Interruptions*)

श्री प्रहलाद जोशी : तिरुवनंतपुरम में कुश्ती और दिल्ली में दोस्ती, यह प्रॉब्लम है। … (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: No, No. In Kerala, the best strategy that we have adopted is to keep BJP out of Parliament in 2024. In Kerala, it is better to have this position. That is a strategic position taken by both the LDF and the UDF. There is no doubt about it. … (*Interruptions*)

SHRI V. MURALEEDHARAN: It is a political strategy.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Yes, it is a political strategy. … (*Interruptions*) Yes, it is absolutely a political strategy. … (*Interruptions*) There is no point of difference in this. … (*Interruptions*)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY: Sir, on that note, what is happening with Ajit Pawar? … (*Interruptions*) What is happening with Nitish Kumar? … (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: There are so many contradictions within the NDA also. … (*Interruptions*) Sir, my time is going. … (*Interruptions*) Sir, during the ten years' tenure of NDA Government, the country had experienced exponential growth of unemployment, inflation resulting in price rise of essential commodities and increase in actual poverty. Shifting the blame to the previous Governments for abysmal failures of this Government and thereby evading its own responsibilities is not proper.

The fourth point is, the NDA Government in power for ten years have devastated the country's economy and agricultural sector, enhanced crimes against women and committed grave injustice to minorities. These are the four points which I wanted to highlight.

I would like to appeal to the whole House to disapprove the Motion for approving the White Paper moved by the hon. Finance Minister.

What is the main intent of the White Paper? Most of the hon. Members have already explained it in detail. A White Paper is issued whenever there is a confusion, where there is some cloud of suspicion, some clarity is required so as to explain the position so that the people will be getting the best and transparent knowledge about the political situation or the economic situation. In the President's Address as well as in the Budget speech and also in the reply to the President's Speech by the hon. Prime Minister, they are very confident. Even the Prime Minister and the Finance Minister are very confident that BJP will come back with 400 in number. So, what is the confusion among the BJP and the NDA front? What is the reason for which a White Paper is brought to this Parliament? What is the *bona fide* intention of the Government when there is no confusion? You are over-confident that you will come back. The economy is in a better position and India will become the third largest economy by 2029. If you are very hopeful and confident of all these political situations and the economic situation, what are the things to be disclosed to the public by means of this White Paper? It is totally untimely. It is well and good if you had brought this White Paper at the time of assuming the office, in the year 2015. That was the right time by which

you would have brought a White Paper so as to explain what are the failures of the Government during the 10 years of the Government from 2004 to 2014 led by Dr. Manmohan Singh ji. Instead of doing it, after 10 years since you are in office, you are coming up with baseless allegations against the Government which was in office 10 years back since then. It is lacking *bona fides*. It is with an intention to make political allegations against a Government which had run it in a good way during the last 10 years.

Another reason I expect is that you are very much apprehensive about the ground reality. The ground reality among the electorate is different than the rosy picture that you have given through the White Picture as well as through the Budget and through the President's Address. What are the ground realities? You are very apprehensive about the electorate, about the basic elements regarding exponential growth in unemployment. Independent India has never seen such an exponential growth in unemployment. There is spiralling rise in prices of petrol, diesel, cooking gas and other essential commodities due to inflation. Actual poverty is increasing. These are the three basic issues the ordinary people, the majority of the people are facing. You are very much apprehensive about it. So, you want to shift the responsibility. You want to shift the blame to the previous Government which was in office 10 years back, which was in power 10 years ago. That is the real intention of the Government in bringing such a White Paper. As far as these three issues are concerned, it is an absolute failure of the Government now in office.

Regarding the guarantees I would like to state something. Further, you are apprehensive and worried about the assurances which you had given during the 2014 general election and the 2019 general election. What were the assurances and guarantees given at that time by the BJP? The first one is that black money stacked in foreign countries will be brought back and Rs.15 lakh will be deposited in very household's account. That is a promise which was made in 2014. Another was that two crores of employment will be given every year. Petrol and diesel prices will be brought back to Rs.50 per litre; cooking gas price will be brought back to Rs.320; and farmers' income will be doubled by 2022 were the other promises. There were other promises like housing for all, water for all. But what happened to all these warrantees which you have already mentioned and about which you have assured the public? At large, nothing has happened. As far as these issues are concerned, there is no proper statistics and there is no proper review in the White Paper. You have already mentioned all those when you talk about the achievements of the NDA Government in power for the last 10 years.

Coming to the White Paper, we are ready to have a comparative study of 10 years of the UPA Government as well as 10 years of the NDA Government. The first speaker Manish Tewari ji has already very clearly and categorically given the statistical data. One main sentence in the White Paper is this and I quote: "The decade of the UPA Government was a lost decade because it failed to capitalise on the strong foundational economy and pace of reforms left behind by the Vajpayee Government." This is the observation made in the White Paper. If

you go through the comparison between the Vajpayee Government and Dr. Manmohan Singh Government, with all the fiscal norms and the fiscal indicators, it can be very well seen that the performance was much better earlier.

Hon. Speaker, Sir, there are so many other issues like GDP, etc. Just now Supriya Sule ji has mentioned about statistics. When you allocate money for each and every portfolio or Department or Ministries, that has to be compared on the basis of the total plan outlay. Now, if you examine MGNREGA, and if you compare it with the total plan outlay or the budget outlay, it has declined from 1.85 per cent in the financial year 2014-15 to 1.33 per cent. Same is the case with the healthcare sector and almost all the sectors. So, I am not going into all these details.

Hon. Speaker, Sir, now I would like to speak on the performance of the previous Government. The legislative history of the Indian Parliament has never seen revolutionary legislations which had happened during the Government under Dr. Manmohan Singh. One of those revolutionary legislations was Right to Information Act. Through that Right to Information Act, you could get most of the information and could file cases against the UPA Government at that time because of the revolutionary change that took place in the democratic process of India. All such other revolutionary legislations like Right to Education as a Fundamental Right, Forest Rights Act, MGNREGA, Food Security Act, show that though the Government was having minimal and nominal majority, still the Government had performed in a good manner. Instead of appreciating the wonderful performance of the previous UPA Government during the period from

2004 to 2014, the present Government is blaming and making allegations against that Government after ten years in office. It is not proper. Since the White Paper is lacking *bona fides* and brought with a bad intention to defame the previous Government, I appeal to the House to disapprove the White Paper. Also, the motion moved by the hon. Finance Minister be disapproved. And I appeal to the House to approve the Motion moved by me today in the morning.

With these words, I conclude. Thank you very much, Sir.

माननीय अध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री जी।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, मैं एक बात बोलना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हुई है।...(व्यवधान) बजट और सप्लीमेन्ट्री डिमांड्स फॉर ग्रॉन्ट्स इत्यादि पर जो चर्चा हो चुकी है, अगर इसके अलावा कुछ और है तो आप बोलिए, लेकिन हम लोग जो सुन चुके हैं, उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, क्या बोलेंगी, उसके बारे में आप गाइड नहीं कर सकते हैं।

… (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : मुझे समझ में नहीं आ रहा है।...(व्यवधान) Even if I want to respond to whatever Leader Adhir Ranjan ji said or mentioned, I am not clear what it was, 'Rashtrapati, Budget'. Please say it again.

माननीय अध्यक्ष : आप आपस में चर्चा मत कीजिए।

… (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Already ten or eleven President's Addresses have happened in the House during the last ten years. Each and every year, there is a discussion on the Budget, Supplementary Budget in the House.

Even this year also, discussion on the President's Address and Budget has taken place. Everything has been covered. So, I will suggest you… … (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Thank you very much, hon. Speaker, Sir, for giving me this opportunity.

This morning, I had the opportunity to say somewhat many things which I could have said during the reply. But because the document has so many different things, I did not want to leave everything for the reply, and I said a few things in the morning. I thank you for that opportunity.

Now, looking at the way in which very many Members have spoken, I will try to answer some of the issues raised by the hon. Members but also focus on some of the critical aspects of the White Paper. Sir, I repeat the White Paper is a serious document with documentary evidence for everything that is said in it, and is prepared with an intention of informing the House … (*Interruptions*)

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Can you say who has authored it? Is it the Revenue Secretary or Finance Secretary? Who authored it? I just want to know who is the author of this document? … (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Hon. Speaker, Sir, it is a serious document. It is a document placed by this Government. Sir, it is a document placed in this House so that the hon. House is informed as to what effort it took and what effort of transparent ways in which … (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: This is nothing but a sinister design made by you to tarnish the Congress Party. … (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, this is a bit too much. It is a bit too much. Every time all of us sit here and listen to each of their speeches. When I stand up to answer, when any Minister stands up to answer, absolutely no etiquette is being maintained by them, and even if you tell them, they do not seem to obey.

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

SHRI GAURAV GOGOI: Madam, I want to know who is the author of this White Paper. You are using tweet as a source. You are using blog as a source.

HON. SPEAKER: Please sit down.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, this is too much. In spite of your saying, people seem to take their own turns to speak and give running commentary without you allowing them.

Sir, I did say this morning and I repeat it now that this is a serious document. … (*Interruptions*)

No, it cannot be like this. You are asking them to sit. I am not saying anything and they do not want to sit. Everytime honest answers are being given to all the speakers who raise it. They seem to be on their own to keep running commentaries going. They are not interested in my answer but that will not stop me. I will still give it.

Therefore, this document is a serious document which we want to place here, and it is placed with an intent that the House will be informed of the ten years' literally dedicated effort to get this Government work in such a way that the

economy is back on rails and also progresses in such a way that our aspirations can be met.

There are two rails, I want to leave this as a strong part, two rails on which we want this economy to move forward. One is to correct all the misgovernance which happened during the ten years, and the second is just not to focus on that but also aim to do a lot of reforms and also push the economy in such a way, nudge the economy in such a way, where necessary to incentivise the economy in such a way that the movement forward is smooth. So, the two tracks which we have followed since 2014 are one to remove all the hurdles, all the misgovernance and equally focus on reforms so that the economy can move forward.

Hon. Member N. K. Premachandran said in the morning as well and now repeated baseless allegations on this White Paper. Not at all. Documentary evidence is given. Supreme Court verdicts which have come have been quoted. CAG Reports have been quoted. Somewhere, their own steps to cancel orders. For example, Antrix Devas where it was a fraudulent deal and they cancelled it themselves. Some of their own statements have all been quoted. Nothing is a figment of anybody's imagination. Therefore, to constantly say that it is baseless allegation, from a learned Member like N. K. Premachandran, is surprising. It is surprising that a document is being placed and is open for everybody's discussion and a person like N. K. Premachandran who I respect a lot, says it is a baseless allegation. Not at all. I challenge anyone. I challenge anyone who says that this document has anything which is baseless. Everything is backed with evidence.

Everything is backed with evidence. I challenge anyone who would say that we have kept a White Paper which has no proof. So, that is one thing. And therefore, why now?

श्री गौरव गोगोई : इतना सीरियस डॉक्यूमेंट किसने लिखा है? … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह तरीका नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है और सब को अवसर दिया गया है। जब माननीय मंत्री जी जवाब देती हैं तो बीच में बैठकर कमेंट्री करते हैं, यह उचित नहीं है। आपको पर्याप्त समय दिया गया है और पर्याप्त अवसर दिया गया है।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : उन्होंने सारे जवाब सुबह दे दिए हैं। यह पिछले दस सालों से चर्चा हो रही है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण: यह डॉक्यूमेंट, व्हाइट पेपर अभी क्यों? इसका जवाब मैं अभी भी दे रही हूं। सबको मालूम भी है और हमारे व्हाइट पेपर में भी वह है। वर्ष 2015-16 में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था। It is not that I am standing here to say this right now. Even in 2015-16, hon. Prime Minister had made a statement: “There are a lot of suggestions coming that I should bring a White Paper on the *haalat* of the economy. But I am not doing it because of national interest. I put the nation first.” If the truth of the state of affairs of our economy had been revealed at that time, not one investor would have come to India. Our own

citizens would have started feeling - what is happening in this country! All institutions have broken down! No proper decision making is happening!

There were total big-ticket corruptions, leave the small ones. There were big-ticket corruptions in their ten years. On an average, there was a big-ticket corruption in every year. Common people were really disillusioned. यह इस देश में क्या हो रहा है?

Our own people would have lost faith seeing the White Paper. Prime Minister very clearly said that we did not want to bring this at that time.

Why has it been brought now? We have completed ten years of governance, ten years of sincere effort to clear up the economy, ten years of sincere effort to make sure that we are not going to stagnate because of the legacy which has been left behind us. We wanted to make sure that we do reforms. We also took every step which had to be taken for cleaning up the system.

Today, from that 'Fragile Five' situation, we have reached the place of 5th largest economy and sooner we will be becoming the 3rd largest economy. Now, our economy is stabilised; people are coming in; our foreign exchange reserve has improved; FDIs are coming in; a lot of Sovereign Wealth Funds are coming and having joint venture investment in green field projects. Our ten years can, therefore, be periodically compared with their ten years so that people cannot say that you came in, you came in by saying big things but you know that you cannot implement those things and therefore, you are doing this.

Some of the State Governments after having given false promises, now are not able to administer their States and are putting the blame on the Central Government. They come and protest at Jantar Mantar instead of administering their States properly. So, we would have easily been accused of such things had the White Paper been brought at that time. We did not do that.

Responsibly we took the challenge of getting everything sorted out. Now, having sorted out and placed the economy in a proper position, we have, with documentary evidence, brought this White Paper. This is why, now this White Paper has been brought. सर, वह सब मैं करना चाह रही हूं।

Sir, in the morning I gave a detailed explanation on Coal Scam and also on the way Banks as institutions were misused. I also explained how, if you were to compare the Commonwealth Games with the G20 Summit, they were organised and what the difference was.

Now, I would just focus myself on three issues and I will elaborate those issues. I am sure you all have seen them in the White Paper. I want to explain three issues: how the national security was compromised in those ten years; how Environment Ministry had become a bottleneck, chock-a-block; how not one proposal was able to move, and how the country's development programmes suffered because environment clearances were not obtainable and details of that; and finally how the leadership failed the country. I want to elaborate on these three issues. After that, I will obviously respond to individual Members and their questions.

Critical shortage of ammunition and defence equipment was the main feature of 2014 when we inherited the economy. Maanniya Raksha Mantri ji is here and I am saying this before him. What was the situation at that time? Bulletproof jackets were not available for our soldiers.... (*Interruptions*) जब सामने बंदूक लेकर दुश्मन खड़े रहते थे तो उनके पास अपने प्रोटेक्टिव गियर्स तक नहीं थे ।... (व्यवधान) Night vision goggles were also not available. During nights they could not do anything. They were exposing themselves like sitting ducks in pitch-dark. That was the attention given at that time. Now it is alright. You can always say: "Oh, no, no, that is the only case you are talking about."

Look at that attitude on how they want to place the national security. I am quoting somebody's words. I will tell you who he is. I am quoting: "Independent India has had a policy for many years that the best defence is not to develop our borders. An undeveloped border is safer than a developed border. So many years, there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas." सर, यह किसने कहा था? यह तब के रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी जी ने कहा था ।... (व्यवधान) सर, उनके बेटे हमारे पास हैं या नहीं हैं, इस बात का कोई मतलब नहीं है । मैं रिकॉर्ड में डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ ।... (व्यवधान) Okay, Sir. ... (*Interruptions*) This has nothing to do with father, son, and brother. This was the statement of a Raksha Mantri. ... (*Interruptions*) Thank you, Gajendra Shekhawat ji. ... (*Interruptions*)

Sir, A.K. Antony ji also stressed a number of times that his Ministry had used up 92 per cent of Defence Budget. All major acquisitions had to wait, and there was no money. ... (*Interruptions*) डिफेंस एक्सपो को इनोग्रेट करते हुए रक्षा मंत्री जी प्रगति मैदान में बोल रहे हैं: "There is no money left. All major projects will have to wait

till 1st April." … (*Interruptions*) मतलब गवर्नमेंट बदल रही है, उनको समझ में आ गया है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ में पैसे नहीं है इसलिए आप अप्रैल फर्स्ट तक वेट कीजिए। वे बॉर्डर पर सोल्जर्स को मैसेज दे रहे हैं कि तब तक कैसे भी लड़ो, लेकिन मेरे से नहीं होगा। यह उनका एटीट्यूड था।

सर, इसके अलावा मेरे पास लिस्ट है। मैं बता सकती हूँ कि डिफेंस में कितना करप्शन होता था। The AgustaWestland VVIP Chopper Scam of 2013 was of Rs. 3600 crore. सीएजी, 2011 में डिफेंस के विषय के कुछ और संदर्भ में pulled up the Army, the Ministry of Defence, for delay in buying artillery guns. लगातार हमारी डिफेंस का कंप्रोमाइज हुआ। Our Armed Forces were totally ignored.

उसके बाद हमारी तरफ से करेक्टिव मेजर्स हुए। The Defence Budget is doubled during the last ten years. वर्ष 2013-14 में 2.53 लाख करोड़ रुपये का बजट था और अभी वर्ष 2024-25 में 6.22 लाख करोड़ रुपये का बजट है। डिफेंस बजट बढ़ गया है। Apart from that, the defence capital budget, including for border roads and for defence forces, equipment investments, has been increased from Rs. 86,741 crore in 2013-14 to Rs. 1.72 lakh crore this year.

Sir, 75 per cent of the capital acquisition budget is earmarked.… (*Interruptions*) ये मुख्य बिन्दु हैं।

Sir, 75 per cent of capital acquisition, मतलब खरीदारी के लिए जो पैसा देते हैं, उसमें 75 प्रतिशत डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए खर्च करना पड़ेगा। यह नहीं है कि विदेश से इम्पोर्ट करते रहो।…(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : अनिल अंबानी की कंपनी कैसी चल रही है?

श्रीमती निर्मला सीतारमण : उसके अलावा हम डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में ले आए**,** उसकी वजह से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में भी डिफेंस का प्रोक्योरमेंट उधर

से ज्यादा हो रहा है ।...(व्यवधान) The launch of Innovations for Defence Excellence (iDEX) framework supports indigenous MSMEs. ... (*Interruptions*)

Sir, apart from this, the FDI limit in defence production has been raised to 74 per cent. All the production units of Ordnance Factory Board have been converted into seven Defence PSUs. सर, गर्व की बात है कि मेक इन इंडिया पुश की वजह से आज INS Vikrant, Light Combat Aircraft Tejas, Akash and BrahMos Missiles, Main Battle Tank Arjun, Artillery Gun System Dhanush इन सभी का भारत में उत्पादन हो रहा है ।...(व्यवधान) इसके अलावा आज महिला राफेल भी उड़ा रही है ।...(व्यवधान) वे बॉर्डर पर भी बंदूक लेकर खड़ी हैं ।...(व्यवधान) महिला पूरे के पूरे डिफेंस में हैं ।...(व्यवधान)

सर, बार-बार रोते थे कि एचएएल को क्या हुआ, एचएएल को ऑर्डर नहीं दिया । 10 सालों में एचएएल को एक कॉंट्रैक्ट नहीं दिलवाया ।...(व्यवधान) हम ने एचएएल का बिजनेस चार लाख करोड़ रुपए का कर दिया ।...(व्यवधान) उधर बहुत सारे वेरायटीज, हेलीकॉप्टर्स का उत्पादन होने वाला है । चार लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर्स दिए गए । एचएएल की नई फैक्ट्री है, जिसका फाउंडेशन स्टोन माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2006 में ले किया, वह एचएएल मॉडर्न तेजस फाइटर जेट्स को अभी इंडिया सेल्फ डिफेंस के लिए प्रोडक्शन कर रहा है । यह एचएएल है, जिसके बारे में वे आंसू बहाते थे । उन्होंने इसे एक ऑर्डर भी नहीं दिलवाया, लेकिन हम एचएएल के लिए इतना कर रहे हैं । आत्मनिर्भर भारत का विषय यही है ।

सर, जब डिफेंस का अच्छा खर्च होता है और उसको ठीक से संभालते हैं, तो no terrorist attack happens in the country. ... (*Interruptions*) लेफ्ट विंग एक्स्ट्रमीज्म को कंट्रोल कर पा रहे हैं ।...(व्यवधान) मैं चाइना के बारे में बोलती हूं । चाइना के विषय में आपको जरूर बोलना है । Sir, there is a decline of more than 52 per cent in Left Wing Extremism-related violence, a decline of 72 per cent in deaths among security forces, and a decline of 68 per cent in civilian deaths between 2014 to 2023. हम यह कंपेयर करके बोल रहे हैं

कि इंटरनल सिक्योरिटी में भी असर पड़ रहा है, क्योंकि डिफेंस के इक्विप्मेंट का परचेज...(व्यवधान) The value of defence production in 2022-23 has crossed one lakh crore rupees....(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : मणिपुर में क्या हो रहा है?

श्रीमती निर्मला सीतारमण : डिफेंस प्रोडक्शन का इस देश में जो काम हो रहा है, अभी उसका वैल्यू एक लाख करोड़ रुपए से अधिक है। Defence exports are at an all-time high. इस देश से 16 हजार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हो रहा है। हमारे इक्विप्मेंट्स एक्सपोर्ट 85 देशों तक पहुंच रहा है। सर, कांग्रेस का glaring mismanagement of defence issue, इसमें मैं एक और विषय जोड़ रही हूं।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आप अग्निवीर के बारे में कुछ कहिए।...(व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : डिफेंस का इतना मिसमैनेजमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे कुछ और विषय है। कुछ और विषय क्या है, हमें तो मालूम नहीं है। मगर मैं यह पूछना चाहती है कि वर्ष 2008 में चाइना में जाकर कुछ एमओयू दस्तख्त हुआ, उसका विषय क्या है?...(व्यवधान) अब तक उसका खुलासा क्यों नहीं हो रहा है?... (व्यवधान) उसका खुलासा आज तक क्यों नहीं हुआ है? उसकी वजह से डिफेंस में रोड नहीं बनाएंगे, बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं खरीदेंगे, बुलेट्स नहीं खरीदेंगे, आर्म्ड फोर्सेज को छोड़ देंगे, पैसा नहीं है कहेंगे, क्या ये सब उसके कारण हो रहा है? कांग्रेस को उसका स्पष्टीकरण देने के लिए कहिये।... (व्यवधान)

सर, रेलवे के विषय बहुत हैं, मगर समय की लिमिटेशन है, इसलिए मैं जयंती टैक्स के विषय पर आ रही हूं। Delay in grant of environmental clearances increased on an average from 86 days to 316 days. वह वर्ष 2011 से 2014 के बीच 316 दिन हुए। एनवायर्नमेंट क्लियरेंस के लिए कागज एक साल से ज्यादा ऑलमोस्ट 316 डेज तक वेट करने के बाद भी नहीं मिलता था। उनके पास 350 फाइल्स पेंडिंग थीं और मूव नहीं हुईं।... (व्यवधान) रविशंकर जी, पूछ रहे हैं कि who was the Minister?

सर, मैं उसके बारे में बोलूंगी और एक क्वोटेशन से उसका जवाब रविशंकर जी को मिल जाएगा। अभिषेक मनु सिंघवी जी उनके ही कुलीग हैं, लॉ प्रेक्टिस करने वाले एक बड़े सीनियर लॉयर हैं और कांग्रेस के सपोक्सपर्सन थे। रविशंकर जी की बात के लिए मैं उनका क्वोट पढ़ रही हूं। एक प्रेस कांफ्रेंस में मनु सिंघवी जी ने बोला– "The term Jayanti Tax was well-known and understood by business circles." जयंती टैक्स की यही डेफिनेशन है। जयंती टैक्स का मतलब क्या है? अभिषेक मनु सिंघवी जी प्रेस कांफ्रेंस में बोल रहे हैं कि पूरे बिजनैस वर्ल्ड को इसके ऊपर पूरी समझ है, आप समझ लो।... (व्यवधान) मैं डेट भी बोल रही हूं, टाइम भी बोल रही हूं और सोर्स भी बोल रही हूं। यह मेरा इमेजिनेशन नहीं है। इकॉनोमिक टाइम्स न्यूजपेपर में 31 जनवरी, 2015 को इसकी रिपोर्ट हुई। जयंती टैक्स का मतलब पूरे बिजनैस वर्ल्ड को समझ है। आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। यह कॉमन वर्ड है। आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। इस तरीके से जवाब दिया गया।... (व्यवधान) यह उनके एनवायर्नमेंट क्लियरेंस का घपला है। इसके विषय में आइये।... (व्यवधान) कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतने बढ़ गए, प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटशन नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में रुकावट पैदा की, जॉब अपॉर्च्युनिटीज पूरी ठप पड़ गईं, यूथ को इससे बहुत नुकसान हुआ, कोस्टल एरियाज में, माइनिंग एरियाज में काम आगे ही नहीं बढ़ा। Big ticket projects like POSCO and Vedanta were completely affected. Image of India as a business destination went for a toss completely. सर, मैं यह बात बोलना चाहती हूं कि आंदोलनजीवी और भ्रष्टाचारजीवी की सरकार ने जयंती टैक्स को जन्म दिया। वह जज़िया था। एक जमाने में जज़िया बोलते थे, यह जयंती टैक्स जज़िया था। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए आप जज़िया दो, आप पैसा दो, फिर देंगे। यह जयंती टैक्स जज़िया था। एनवायर्नमेंट के ऊपर व्हाइट पेपर में ये विषय आ रहे हैं।... (व्यवधान) एनवायर्नमेंट टैक्स के द्वारा लाइसेंस परमिट राज वापस ले आए। हमने क्या किया?

बैलेंस्ड प्रकृति एंड प्रगति – इसको बैलेंस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें प्रगति भी चाहिए और प्रकृति भी चाहिए। We brought in transparency. ग्रीन क्लियरेंस के लिए 'परिवेश' ऑनलाइन सिस्टम ले आए। वह जल्दी हो और समय पर हो। We standardized and

streamlined Environmental Impact Assessment studies. फिर डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज – यह गुजरात में पहले आया, सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले उधर आया, फिर भी हमने एनवायर्नमेंट के लिए प्राथमिकता दी है।

19.00 hrs

इसके अलावा, प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2015 में इंटरनैशनल सोलर एलायंस बनाया, वर्ष 2021 में पंचामृत एक्शन प्लान लाये, वर्ष 2022 में मिशन लाइफ लाये, वर्ष 2023 में नैशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लाये।... (व्यवधान) Namami Gange Programme successfully arrested pollution in our holy river. इतने सारे प्रोजेक्ट्स एंवायरमेंट को क्लियर करते हैं।... (व्यवधान) रूफ टॉप सोलर, पीएम कुसुम, उजाला आदि स्कीम्स भी एंवायरमेंट के लिए लाये गये।... (व्यवधान) मैंने एवरेज टाइम 316 दिन कहा। Average time for clearance, average time for approvals to be cleared at the Central level has been reduced to 70 days. 316 दिनों से ये घटकर 70 दिनों तक आ गया। Forest cover increased by 50,000 square kilometres. वर्ष 2014 में, प्रोटेक्टेड एरिया की संख्या 745 थी। अभी 998 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं।

वर्ष 2014 में, कम्युनिटी रिज़र्व्स की संख्या 43 थी, ये अभी 220 हैं।

भारत में 12 बीचेज को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। इसका मतलब है कि they are environmentally clean and good beaches.

Sir, globally India stands 4th in renewable power, 4th in wind power and 5th in solar power. We have progressed so much that there has been a 30-fold increase in solar energy capacity since 2014. ... (व्यवधान)

Also, the railway station in the capital of Assam, the Guwahati Railway Station is the first solar-powered railway station in India. ... (व्यवधान)

Sir, the target of achieving 40 per cent renewable capacity addition, which was a target set in COP21, has been fulfilled nine years ahead of time. मान लीजिए

कि वर्ष 2020 में करना है, तो हमने वर्ष 2011 में ही फुलफिल कर दिया। Nine years ahead of schedule, हमने 40 परसेंट रिन्यूएबल एनर्जी की कपैसिटी को बढ़ाने के लक्ष्य को अचीव कर लिया।

सर, मैं विस्तार से हरेक घोटाले के ऊपर बोल सकती हूँ। लेकिन टाइम की कमी के कारण मैं अंत में लीडरशिप के विषय पर आ रही हूँ।... (व्यवधान) लीडरशिप का जो विषय है, वह at the heart of the problems है। यूपीए का मिसमैनेजमेंट, यूपीए का घोटाला ड्रिवेन 10 वर्ष, क्रोनी कैपिटलिज्म, इन सबका केन्द्र-बिन्दु लीडरशिप की प्रॉब्लम है - rudderless and leaderless.

Sir, hon. Sonia Gandhi ji was super Prime Minister as the Chairperson of the National Advisory Council, an extra-constitutional and unaccountable person. ... (*Interruptions*) Of course ... (*Interruptions*)

सर, सुबह में मैंने एसबीआई चेयरमैन के विषय में कहा, आर.के. तलवार जी के विषय में कहा, वह मेंशन नहीं है। मैंने वह कांग्रेस के डीएनए में करप्शन और बैंक्स का मिसयूज करने के संदर्भ में कहा था। ... (व्यवधान)

इसी तरह से, मिसमैनेजमेंट और फ्रेजाइल फाइव इकोनॉमी में आने के क्या कारण हैं? हम हरेक घपले का एक्सप्लानेशन दे रहे हैं। मगर इन सबका कारण क्या है? मैं उसके बारे में जरूर बोलना चाहूंगी। अगर लीडरशिप सही होता, तो ऐसी हालत होती क्या?

सर, मैं यह बात इसलिए बोल रही हूँ कि गवर्नेंस के ऊपर मेजर दबाव था, क्योंकि उनको extra- constitutional authority मिली हुई थी।... (व्यवधान) 710 फाइल्स एनएसी की परमिशन लेने के लिए सरकार से भेजी गयी। क्या वह कैबिनेट है? क्या वह अप्रूव्ड पार्लियामेंट है? क्या वह स्टैंडिंग कमेटी है? 710 फाइल्स उनके पास क्यों भेजे गए? क्या वह constitutional authority था? ... (व्यवधान) वह अनअकाउंटेबल पावर थी।... (व्यवधान) वह अनअकाउंटेबल, अनआंसरेबल पावर थी।... (व्यवधान) पार्लियामेंट में उसके जवाब देने का स्थान ही नहीं था।... (व्यवधान) उनके पास क्यों 710 फाइल्स गईं।... (व्यवधान) ऐसी ही अनअकाउंटेबल पावर के कारण ये घपले हुए और साल

में एक बड़ा घपला होता रहा है ।... (व्यवधान) यह अनकांस्टीट्यूशनल यूज ऑफ पावर था ।... (व्यवधान)

महोदय, आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी की सब रेस्पेक्ट करते हैं। उनके ही प्रधानमंत्री रहते हुए, ये इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बात करते हैं, हमें लेक्चर देते हैं, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और विदेश के पर्यटन पर थे, इधर कांग्रेस के तब के, शायद जनरल सेक्रेटरी थे या अध्यक्ष थे ।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : यह पुरानी बात हो चुकी है ।... (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : 10 साल पुरानी बात को भी अभी बोलने की आवश्यकता है ।... (व्यवधान) अध्यादेश को फाड़कर प्रेस कांफ्रेंस में फेका ।... (व्यवधान) क्या वह मर्यादा नहीं है? ... (व्यवधान) क्या वह प्राइम मिनिस्टर की अवमानना नहीं है? ... (व्यवधान) insulting his own Prime Minister, देश का प्रधानमंत्री, ऐसा घमंड और गर्व मतलब very arrogant who did not care for his own Prime Minister. ... (व्यवधान) ये इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आजकल इतना चिल्ला रहे हैं ।... (व्यवधान) हमें लेक्चर दे रहे हैं ।... (व्यवधान) when insulting his own Prime Minister, जब वे प्राइम मिनिस्टर विदेश में थे, उन्होंने अध्यादेश को फाड़कर फेंका, तब हमारे एन.के.प्रेमचन्द्रन जी कहाँ गए थे ।... (व्यवधान) बेसलेस-बेसलेस हमें बोलते हैं ।... (व्यवधान) एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, तब आपको उठकर बोलना था कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्यों इंसल्ट कर रहे हो, यह गलत है ।... (व्यवधान) क्या यह बोलने के लिए तब आरएसपी नहीं थी ।... (व्यवधान) क्या एन.के.प्रेमचन्द्रन जी की रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी तब नहीं थी? ... (व्यवधान) आपने तब क्यों उठकर नहीं पूछा?... (व्यवधान) ये अभी हमसे बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं ।... (व्यवधान) अभी बहुत सारे ग्रेट लेजिस्लेशंस हुए हैं ।... (व्यवधान) वे उनके कुछ अल्टरनेटिव प्रपोजल के लिए बात कर रहे थे। वे कह रहे थे कि उस समय अच्छे कानून बने, राइट टू इन्फॉरमेशन, राइट टू फूड। मैं उस विषय में बताना चाहती हूँ ।... (व्यवधान) इतने सारे अच्छे कानून, ऐसा एन.के.प्रेमचन्द्रन जी बोल रहे हैं ।... (व्यवधान) क्या एनएसी के द्वारा कानून आपको मंजूर है? ... (व्यवधान) एनएसी कौन है? ...

(व्यवधान) एनएसी कौन सी बॉडी है? ... (व्यवधान) जब उसके द्वारा कानून आता है, वह एन.के.प्रेमचन्द्रन जी को मंजूर है ।... (व्यवधान) नॉन कांस्टीट्यूशनल बॉडी, worse than kitchen cabinet... (व्यवधान) ऐसे सिलेक्टिव मोरालिटी को हाईलाइट करने वाले से मैं विनम्रता से माँग करती हूँ कि कृपया आप अपने हाई मोरल ग्राउंड का इस पार भी उपयोग करो, उस पार भी उपयोग करो ।... (व्यवधान) एनएसी से कानून बन सकता है, हम व्हाइट पेपर इधर रख नहीं सकते । यह इलेक्टेड गवर्नमेंट है । Can the elected Government not keep a White Paper here? You had a super Prime Minister worse than a kitchen cabinet. उनके एनएसी के द्वारा एक्टिविस्ट, आंदोलनजीवी कानून बना रहे हैं ।... (व्यवधान) आप उनको मंजूरी दे रहे हो ।... (व्यवधान) उसे आप अच्छा कानून बता रहे हो ।... (व्यवधान) तब वह आपको आपत्तिजनक नहीं लगा ।... (व्यवधान)

Sir, I want to also say this.... (व्यवधान) अभी हर विषय में बोलते हैं ।... (व्यवधान) बोलते हैं कि आधार हम ले आए ।... (व्यवधान) मनरेगा हम लेकर आए ।... (व्यवधान) आधार यूआईडी पेमेंट हमारा है ।... (व्यवधान) इसलिए डीबीटी हो रहा है ।... (व्यवधान) ये ऐसा सब बोलते हैं, हर बार क्लेम करते हैं ।... (व्यवधान) ये कहते हैं कि हमें रिकग्नाइज करो, हमने भी अच्छा किया ।... (व्यवधान) हमें एकनॉलेज क्यों नहीं कर रहे हैं? ... (व्यवधान) ये ऐसा बोलते हैं ।... (व्यवधान) सिर्फ यूआईडीएआई का उदाहरण लेते हुए मैं बोल रही हूँ कि वह उधर मंजूर नहीं था । हर डिपार्टमेंट में झगड़ा था कि यूआईडीएआई नहीं, इसे नहीं लाना है, ऐसा बोलते थे ।... (व्यवधान) ठीक है जी ।... (व्यवधान) हाँ-हाँ, मैं इसे पढ़ रही हूँ ।... (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: You should not mislead the House, Madam.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I would not mislead the House. I am not Congress. हाउस को मिसलीड करने वाली कांग्रेस है ।... (व्यवधान) यह कॉपीराइट आपका है ।... (व्यवधान) Patent and copyright on misleading is yours. ... (व्यवधान) यह इकोनॉमिक

टाइम्स की 17 अप्रैल, 2012 की रिपोर्ट है ।... (व्यवधान) It states: "UIDAI's parent, the Planning Commission, was rejecting its Rs. 15,000 crore funding proposal"...(*Interruptions*) A Parliamentary Panel examining a legislation gave the UIDAI legitimacy. ... (*Interruptions*) आज सुबह इधर भी सुना, कल राज्य सभा में भी सुना। आप जल्दी में लेकर आते हो ।.... (व्यवधान) जल्दी में कानून पास करवाते हो ।.... (व्यवधान) हाउस जब आर्डर में नहीं होता है, तब कानून पास करवाते हो ।.... (व्यवधान) स्टैंडिंग कमेटी में भेजने में आपको क्या आपत्ति है, ऐसा बोलते हैं। उसके बारे में मैं बताती हूं : "A Parliamentary Panel examining a legislation that gave the UIDAI legitimacy was dismissing the project as one "conceptualized with no clarity of purpose". ... (*Interruptions*) आधार हमारा है, उस समय बोलने वाले बोले कि इसका कोई परपस ही नहीं है ।.... (व्यवधान) : "At least three Central Ministries of that time, namely Food and Civil Supplies, Rural Development and Labour also had reservations with real-time biometric authentication". इसके खिलाफ ये सभी मिनिस्ट्रीज थीं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि आधार हमारा है। हर मिनिस्ट्री का आपस में झगड़ा हो रहा है लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि आधार हमारा है।.... (व्यवधान) न्यूज पेपर में रिपोर्ट हो रही है और यह बोले कि "Connectivity is unreliable ..." जैसे उनके पूर्व वित्त मंत्री ने भाषण और बयान दिया कि गांव में क्या इंटरनेट होगा, क्या बिजली होगी? वहां डिजिटल पेमेंट से क्या फायदा होगा, उन्होंने ऐसा कहा और हमारे प्रधान मंत्री जी का हंसी-मजाक उड़ाया कि डिजिटल पेमेंट के ऊपर इतना क्या बात कर रहे हो। विलेज में इलेक्ट्रीसिटी नहीं है, विलेज में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, यह उनके पूर्व वित्त मंत्री ने कहा। वैसे ही इधर भी बोले। इधर बोला कि "Connectivity is unreliable in rural areas, especially below gram-panchayat levels. So, I do not see this changing for the next 10 years". वर्ष 2012 में रिपोर्ट हो रही है कि अगले दस साल तक ऐसा बदलाव होना असम्भव है इसलिए डिजिटल आधार वगैरह छोड़ दें, लेकिन आज कहा गया कि आधार हमारा है। इम्प्लीमेंट करने वाले हम हैं, स्केल-अप

करने वाले हम हैं, पूरी दुनिया में डीपीआई के ऊपर जी-20 में हमें बोला जाता है कि you are doing it right. आपने इसे नकारा, आपने इसे रिजेक्ट किया।.... (व्यवधान)

महोदय, मैं सीधे प्वाइंट पर आती हूं कि आधार और बॉयोमैट्रिक आथैंटिकेशन की वजह से कोविड के समय में भी हम डायरेक्टली बेनिफिशियरी को पैसा भेज पाए, जिसे डेवलप कंट्रीज भी नहीं कर पाईं। सिर्फ कोविड के समय ही नहीं, आज डीबीटी सरकार की योजनाओं में चल रही है और आधार आथैंटिकेटेड डीबीटी की वजह से 2.7 लाख करोड़ रुपये सरकार ने बचाए हैं। यह लीडरशीप की ताकत है, लीडरशिप का विजन है, जो यूपीए के समय में नहीं था।.... (व्यवधान) बहुत माननीय सदस्यों ने ब्लैक मनी, सीबीआई, ईडी के दुरुपयोग के बारे में कहा है। मैं डेटा देती हूं।

पी.एम.एल.ए. कानून को एन्फोर्स करने वाले एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हैं। वर्ष 2005 से 2014 तक उनके समय में प्रॉसिक्यूसन 102 हुआ, मतलब उस कानून का ख्याल ही नहीं रखा गया। पी.एम.एल.ए. मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यह एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए है। उसको एन्फोर्स करने वाले एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के काम को रोकने वाले को उस समय कंट्रोल करके रखा गया था कि नहीं, नहीं, आप चुप बैठो, मनी लॉन्डिंग होते रहना चाहिए, आप क्यों एक्टिव हो रहे हैं, ऐसा करके उसे 'बंद पिंजरे में चिड़िया' की तरह रखा गया।... (व्यवधान) जब ई.डी. को पूरा इंडिपेंडेंस देते हैं कि आपको अपने कानून के तहत जो भी करना है, कीजिए, तब उनके समय में 102 केसेज ही प्रॉसिक्यूसन कम्प्लेंट तक ले जाए गए थे। हमने जब ई.डी. को पूरा इंडिपेंडेंस दिया कि आप अपना काम कीजिए, आप पी.एम.एल.ए. यानी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकिए तो 1,200 केसेज का प्रॉसिक्यूसन कम्प्लीट हो गया।... (व्यवधान)

सर, चूंकि जल्दी में हैं, उनके समय में कन्विक्टेड पर्सन्स की संख्या ज़ीरो थी। उनके समय में कन्विक्शन ज़ीरो था, मगर वे हमसे पूछ रहे हैं कि कितना कन्विक्शन हुआ। हमारे समय में 58 कन्विक्शन्स हुए हैं।... (व्यवधान)

सर, जब मैं किसी बात का उत्तर देती हूं तो वह उन्हें सूई की तरह लगता है, इसलिए वे कुछ और प्रश्न पूछने लगते हैं।... (व्यवधान) मैं सभी का जवाब देती हूं।... (व्यवधान)

सर, मैं पूरी लिस्ट तो नहीं पढ़ रही हूं। इसमें अमाउंट ऑफ रेस्टीट्यूशन है, मतलब जहां मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से पैसे बनाए गए, बैंकों को लूटा गया, उस पैसे को रेस्टीट्यूशन कहते हैं, जब वे पैसे पकड़ में आते हैं और फिर वे पैसे असली ऑनर को चले जाते हैं। उनके समय में रेस्टीट्यूशन कितना था? जहां मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उससे पैसे निकालकर कानूनन जिन लोगों को न्यायबद्ध तरीके से उसे वापस करना है, उसे रेस्टीट्यूशन कहते हैं, यह उनके समय में शून्य था। उनके समय में इस भारत देश के खजाने में एक पैसा वापस नहीं आया, मगर हमारे समय में, वर्ष 2023 तक, नौ सालों में यह कितने आये? हमारे समय में इसके 16,333 करोड़ रुपये वापस आए। अब वे पैसे उन्हें वापस जा रहे हैं, जिन्हें इसे जाना है।... (व्यवधान)

सर, 'रेड कॉर्नर नोटिस' से जुड़े हुए बहुत सारे मामले उठाए गए, मैं उनका भी उत्तर देती हूं। उनके समय में जो लोग गलत काम करके बाहर भाग गए, तो उस समय कितने लोगों को रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू किया गया? यह ज़ीरो था। मगर, हमारे समय में, 9 सालों में 24 लोगों के ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू किया गया।... (व्यवधान)

सर, इनके समय में बैंकों को चीट करके, उनसे पैसे लेकर जो लोग बाहर चले गए, उनके ऊपर भी हमने एक्स्ट्राडीशन ऑर्डर्स पास करवाया, उन्हें बाहर से यहां वापस ले आएंगे, उसके ऑर्डर हो गए हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी और संजय भंडारी के मामले में ऑर्डर हो गए हैं। अब बस उन्हें एक्स्ट्राडाइट करना ही बाकी है। इनके समय में यह ज़ीरो है।... (व्यवधान)

सर, दूसरा विषय है कि इनके समय में कितने लोगों को फ्यूजिटिव डिक्लेयर किया गया? किसी ने यहां एक गुनाह कर दिया, इकोनॉमिक ऑफेन्स कर दिया, और यहां से भाग गए, तो कम से कम उनका नाम 'कानून से भागने वाले' लोगों की सूची में डालते हैं, तो उसे फ्यूजिटिव कहते हैं, भगोड़ा कहते हैं। इनके टाइम कितने लोगों को फ्यूजिटिव डिक्लेयर किया गया, मतलब किसी ने एक इकोनॉमिक ऑफेंस किया और भाग गया, कम से कम उनको एक नाम देना है कि ये लोग कानून से भागने वाले हैं। उनको हम फ्यूजिटिव बोलते हैं, भगोड़ा बोलते हैं। इनके काल मे कितने लोगों को भगोड़ा घोषित किया गया? ज़ीरो लोगों को घोषित किया गया। हमारे समय में 12 लोगों को हम

फ्यूजिटिव घोषित कर चुके हैं। ... (व्यवधान) इनका रिकॉर्ड क्या है? ... (व्यवधान) सर, regarding number of persons extradited, ये बालते हैं कि एक्ट्राडिशन ऑर्डर हो गया है, विजय माल्या आया नहीं, नीरव मोदी आया नहीं है। वे आएंगे, ऑर्डर पास हो गया है। मगर हमने लोगों को एक्स्ट्राडाइट भी किया है। इनके समय पर ज़ीरो लोगों को एक्स्ट्राडाइट किया गया। सर, हम चार लोगों को ऑर्डर पास करवा कर एक्सट्राडाइट कर रहे हैं। So, the total amount confiscated from the Fugitive Economic Offender (FEO) उनकी प्रॉपर्टीज से कितना पैसा हमने वसूल किया? इनके समय पर ज़ीरो पैसा वसूल किया गया। हमारे समय में 906.74 करोड़ रुपये फ्यूजिटिव ऑफेंडर से वापस आए हैं। ... (व्यवधान)

सर, एक महत्वपूर्ण विषय है। ये लोग बहुत सारे विषयों पर बोलते हैं। हमें बोलते हैं कि पीडीएस में कितना पैसा दे रहे हैं। राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट हम ही लाए थे। मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ कि वर्ष 2013 में बाली में जा कर, डब्ल्यूटीओ में एक मिनिस्ट्रियल डेक्लरेशन में इनके कॉमर्स मिनिस्टर दस्तखत कर के आए। विषय क्या था? भारत देश में पीडीएस के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे कर के किसान से ले कर, एफसीआई गोदाम में बफर स्टॉक रख कर, पीडीएस के द्वारा गरीब के लिए पहुंचाने के लिए प्रोक्योर करते हैं। ... (व्यवधान) इनके मंत्री बाली में, डब्ल्यूटीओ में डेक्लरेशन साइन कर के आए, उसके मुताबिक इस देश में प्रोक्योरमेंट वर्ष 2017 से बंद होना था। वर्ष 2014 में मोदी जी ने आने के बाद, कॉमर्स मिनिस्टर के नाते मैं नौरोबी में गई और झगड़ा कर के पर्मानेंटली एक सॉल्युशन जब तक नहीं मिलता, यह अप्लाई नहीं होना चाहिए, हम वह कानून ले कर आए। इन्होंने भारत के किसान के हित को बेच दिया। ... (व्यवधान) भारत के कंज्यूमर के हित को बेच दिया। ... (व्यवधान) पीडीएस हम इस देश में दे नहीं सकेंगे, अगर उस बाली डेक्लेरेशन के अंतर्गत, वर्ष 2017 के बाद भारत देश का यह राइट पूरा का पूरा खत्म हो जाता। ... (व्यवधान) यह था बाली डिक्लेरेशन। ... (व्यवधान) आप वहां पर यह कर के आए और यहां पर बोलते हैं कि फूड राइट के लिए हमने कानून बनाया। ... (व्यवधान) विदेश में जा कर उस कानून को बेकार कर के आए हैं। ... (व्यवधान) उसके बाद आंसू बहा कर यह कानून बना रहे हैं। ... (व्यवधान)

हमारे किसान को, हमारे गरीब को, उनके खाने के लिए अनाज का जो हक़ था, उसको ये लोग गिरवी रख कर आए हैं और आज यहां बात करते हैं। … (व्यवधान)

सर, मनीश तिवारी जी और वीरास्वामी कलानिधि जी, गिरीश चन्द्र जी, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर और श्री एस. वेंकटेशन ने लेबर मार्केट के ऊपर बहुत सारे विषय उठाए हैं। अभी तक मनीश तिवारी जी बैठे थे, लेकिन अभी नहीं हैं, फिर भी मैं जवाब देती हूं। मैं उनके लेबर मार्केट के जवाब में बोल रही हूं। Labour markets have witnessed falling unemployment rates declining from 5.8 per cent in 2018-19 to 3.2 per cent in 2022-23. अनएम्प्लाएमेंट कम हो रही है। वर्ष 2018-19 में 5.8 परसेंट थी। अभी वह 3.2 परसेंट है। Unemployment rate particularly for graduates has also declined. वर्ष 2017-18 में 17.2 परसेंट थी। अभी वर्ष 2022-23 में 13.4 परसेंट है। The decline has been even sharper for female graduates. Their unemployment rate has declined from 27.5 per cent to 20.6 per cent over the same period. हम पीएलआई स्कीम के बारे में बात करते हैं। मैं उसके डायरेक्ट एम्पैक्ट एम्प्लाएमेंट के ऊपर बोलना चाहती हूं।

सर, पीएलआई स्कीम में 1.07 लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट आया है। यह एक्चुअली 8.7 लाख करोड़ रुपये का प्रोडक्शन या सेल करता है। उसमें एम्प्लाएमेंट जेनरेशन 7 लाख है। पीएलआई से डायरेक्ट्ली 7 लाख लोगों को जॉब मिला है। ईपीएफओ में ईयरी नेट पे रोल एडिशन- नए लोग जो ईपीएफओ से जुड़ रहे हैं, उसका नंबर ट्रिपल हो गया है। वर्ष 2018-19 में 61 लाख था। अभी वर्ष 2022-23 में 139 लाख में हो गया है। इसका मतलब है कि जो नए जॉब सीकर्स हैं, वे जॉब में आने के बाद ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मनीश तिवारी जी के इस प्वाइंट को मैं जरूर एड्रेस करना चाहती हूं।

सर, दूसरा एक और विषय गवर्नमेंट जॉब के बारे में है। Sir, 8,82,191 Central Government vacancies have been filled up in the last nine years. यह बहुत अच्छा प्वाइंट है। नाइन ईयर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सैंक्शन्ड पोस्ट्स हैं, उनको वैकेंसी में न रखते हुए हम

भरपूर फिलअप कर रहे हैं। 8,82,191 सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी का विद आउट वन पैसा रिश्वत लिए ट्रांसपैरेन्ट्ली रिक्रूटमेंट हुआ है। Regional Recruitment Boards gave Government jobs to 4,30,592 youth between 2014 and 2023. गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2022 में रोजगार मेला लॉन्च किया है। उसके द्वारा 10 लाख गवर्नमेंट जॉब्स की रिक्रूटमेंट हो रही है। 6.32 लाख लोगों का अप्वाइंटमेंट लेटर उनके हाथ में पहुंच गया है। ये सब भी बिना रिश्वत, बिना घूम-फिर करके, इधर जाना, उधर जाना, रिकमेंडेशन ले आना, भाई-भतीजावाद बोलना, कुछ भी नहीं हुआ।

सर, जो दूसरी चीज है, इकोनॉमी में ऐसा माहौल पैदा हुआ है by which gig economy has emerged as a noteworthy job generator. उसमें आज 77 लाख वर्कर्स को, आज मतलब फाइनैंशियल ईयर 2021 में नीति आयोग की रिपोर्ट बोलती है, जॉब मिला है।

सर, मनीश तिवारी जी, वीरास्वामी कलानिधि जी, गीता विश्वनाथन जी और सौगत राय ने इंफ्लैशन के ऊपर प्रश्न पूछे हैं। मैं एक बात बोलना चाह रही हूं, from 2004 to 2014, average annual inflation in the economy was 8.2 per cent. 10 ईयर्स में एवरेज 8.2 परसेंट था। लास्ट थ्री ईयर्स, मतलब वर्ष 2011-2012, 2012-13 और 2013-14 में एवरेज रिटेल इंफ्लैशन 8.2 परसेंट से उठकर 9.8 परसेंट हो गया। यह यूपीए के लास्ट थ्री-फोर ईयर्स में था।

सर, उस समय एवरेज ग्लोबल इंफ्लैशन कितना था? यह 4 टू 5 परसेंट ही था। मगर हमारे देश भारत में 9.8 परसेंट है।

Under UPA, the retail inflation was more than 9 per cent. 28 महीने, जो उस समय उनका कार्यकाल था, उसमें वर्ष 2012 से 2014 तक 22 महीने 9 पर्सेंट से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट थी, कई बार 9 पर्सेंट से भी ज्यादा हुई। पांच सालों में इनकी एनुअल एवरेज इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में थी। इनका रिकार्ड इन्फ्लेशन के ऊपर ऐसा है। हमारी रिटेल इन्फ्लेशन ज्यादातर 5 पर्सेंट थी। It never crossed 8 per cent.

8-9 पर्सेंट और डबल डिजिट पर्सेंट में इन्फ्लेशन रखने वाले हमारे ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन ऐसे हुई, इन्फ्लेशन वैसे हुई। मैंने पार्लियामेंट के क्वैश्चन ऑवर में सरकार

ने जो कदम उठाए, उनके बारे में बताया। मुख्यत: कुकिंग गैस सिलेंडर मोर दैन 10 लाख लोगों को, उज्ज्वला के द्वारा जिनको मिलते हैं, उनको 300 रुपये तक सब्सिडी देते हैं। 12 सिलेंडर तक भी वे लें, फिर भी सब्सिडी उनको हर बार 300 रुपये मिलती है। सब्सिडी उनके एकाउंट में डायरेक्टली चली जाती है। डबल डिजिट इन्फ्लेशन का मैनेजमेंट रखने वाले का दूसरे से प्रश्न पूछना उचित नहीं है। ... (व्यवधान)

मैं इस पॉइंट को बोलकर अपनी बात खत्म करूंगी। Per capita consumption of PM Ujjwala Yojana beneficiaries is 3.84 cylinders. मतलब एक साल में करीब चार सिलेंडर्स गरीब अपने घर में उपयोग करने के लिए लेते हैं। मैं प्रोरेटा बेसिस पर बोल रही हूं। From 2016, more than 180 crore refills have been taken by Ujjwala beneficiaries. हर दिन उज्ज्वला फैमिलीज़ 11 लाख रिफिल्स लेते हैं। हर दिन 11 लाख उज्ज्वला बेनीफिशियरीज़ रिफिल के लिए आते हैं। हमें बोला जाता है कि उज्ज्वला में कोई सिलेंडर लेने नहीं आते हैं, आजकल लोग रिफिल नहीं करा रहे हैं, आप गलत बयान बोल रही हैं। No, every day, 11 lakh refills are being taken by Ujjwala beneficiaries in the last financial years.

मान लीजिए, एलपीजी कंजंप्शन्स नॉन उज्ज्वला, उज्ज्वला सब इकट्ठा करके 100 सिलेंडर्स का कंजंप्शन है तो उसमें 20 उज्ज्वला सिलेंडर्स वाले हैं। इसीलिए सरकार उनकी स्कीम्स को सही तरह से इंप्लीमेंट करती है और उसको मॉनीटर करती है।

लीडरशिप स्पष्ट है कि भारत देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत की मंजिल तक पहुंचाना है। भारत में सबको साथ लेकर जाना है, सबके विकास के लिए काम करना है, अपने आप के लिए नहीं, देश को सामने टॉप में रखकर जाना है। यही प्रधान मंत्री मोदी जी का गोल है, न कि परिवारवाद या देश की लूट करो और अपने आपको अच्छा रखो, देश बर्बाद हो जाए, परवाह नहीं, वह एटीट्यूड हमारा नहीं है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के साथ यह देश आगे बढ़ेगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत किए गए स्थानापन्न प्रस्ताव को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

स्थानापन्न प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा रखे गए स्थानापन्न प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

स्थानापन्न प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही शनिवार, दिनांक 10 फरवरी, 2024 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

19.35 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Saturday, February 10, 2024/Magha 21, 1945 (Saka).

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following address:

www.sansad.in/ls

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)